रजिस्ट्री सं. डी. एल-33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9, 1993/पौष 19, 1914
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9, 1993/PAUSA 19, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1992

का.आ. 56.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय लखनऊ की सहमति से, जो आदेश सं. 321-जी-6-पी-3-5 (37)/8/92 तारीख 27-9-92 द्वारा दी गई थी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 409, 419, 420 और 468 के अधीन दंडनीय अपराध और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में पुलिस थाना कवि नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अपराध मामला सं 93/92 (उच्च स्तर दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद कपट संबंधी मामला) की बाबत किए गए किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है।

[संख्या 228/12/92-ए.वी.डी.-II]

ए. सी. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(Deptt. of Personnel & Training)

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 1992

S.O. 56.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow, accorded vide No. 321-G-I/VI-P-3-5(37)8/92 dated 27-9-1992 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of offences punishable U/s. 409, 419, 420 and 468 of Indian Penal Code 1860 (Act 45 of 1860) and attempts abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transactions arising out of the same facts, in regard to case in crime No. 93/92 (Advanced Level Telecom Training Centre, Ghaziabad, fraud case) of Police Station, Kavi Nagar, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.

[No. 228/12/92-AVD.II]

A. C. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1992

का.आ. 57.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (जी.आर-V) विभाग के आदेश सं. एफ. 24(8)गृह/जी. आर-5/92 तारीख 23-10-92 द्वारा प्राप्त राजस्थान सरकार की सहमति से थाना बस्सी, जिला जयपुर में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) की धारा 323, 376, 379 और 147 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामला सं. 399/92 या उक्त मामले से उत्पन्न ऐसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अन्य अपराध के संबंध में अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य पर करती है।

[संख्या 228/60/92-ए.वी.डी.-II]

ए. सी. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd December, 1992

S.O. 57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government with the consent of the State Government of Rajasthan vide Home (Gr. V) Department Order No. F. 24(8)Home/Gr. V/92 dated 23-10-92 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Rajasthan for investigation of case No. 399/92 under Sections 323, 376, 379 and 147 Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Bassi District Jaipur of the Code of Criminal Procedure Code (Act No. 2 of 1974), or any other offences committed in the course of same transaction arising out of the said case.

[No. 228/60/92-AVD.II]

A. C. SHARMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1992

का.आ. 58.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 9 के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा वर्तमान में इलाहाबाद बैंक के मुरादपुर शाखा, पटना में तैनात श्री कमला प्रसाद राय, प्रबंधक (एम. एम. जी स्केल-III) को 22 दिसंबर, 1992 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे इलाहाबाद बैंक के एक अधिकारी रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ 9/13/91-बी. ओ.-I]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd December, 1992

S.O. 58.—In pursuance of sub-clause (c) of clause 3 read with clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Kamala Prasad Rai, Manager (MMG Scale-III) presently posted at Muradpur Branch, Patna, Allahabad Bank, as a Director on the Board of Allahabad Bank with effect from the 22nd December, 1992 for a period of three years or until he ceases to be an officer of Allahabad Bank whichever is earlier.

[No. F. 9/13/91-B.O.I.]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1992

का.आ. 59 : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के खंड 9 के उपखंड (2) के साथ पठित खंड 3 के उपखंड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन. एम. बर्मन, विशेष सहायक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली को दिनांक 23 दिसंबर, 1992 से 22 दिसंबर, 1995 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिये या जब तक वे ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के एक कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इनमें से जो भी पहले हो, श्री योग राज गुप्त, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) की अधिसूचना सं. एफ. 15/2/89-आई. आर. दिनांक 1-8-1989 के अनुसरण में नियुक्त किये गये थे, के स्थान पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है।

[सं. 15/2/92-आई. आर.]

सतपाल भाटिया, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd December, 1992

S.O. 59.—In pursuance of sub-clause (b) of Clause 3 read with sub-clause (2) of Clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 the Central Government hereby appoints Shri S. M. Burman, Special Assistant, Oriental Bank of Commerce , Head Office, New Delhi as a Director on the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce for a period of three years with effect from 23rd December, 1992 to 22nd December, 1995 or until he ceases to be an employee of Oriental Bank of Commerce whichever is earlier in the place of Shri Yog Raj Gupta appointed under Notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) No. F. 15/2/89-IR dated the 1st August, 1989.

[No. F. 15/2/92-IR]

S. P. BHATIA, Under Secy

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहरणालय

अधिसूचना सं० 10/1992

नागपुर, 18 दिसंबर, 1992

का.आ. 60 :—श्री सी. जी. सोनटक्के, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ब" समाहरणालय नागपुर निर्धारित की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-11-1992 को अपराह्न में शासकीय सेवासे निवृत्त हुए।

[फा. सं. II(3)3/92/स्थापना-I/27798]

हरजिंदर सिंह, उप समाहर्ता

(कार्मिक एवं सतर्कता)

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

NOTIFICATION NO. 10/1992

Nagpur, the 18th December, 1992

S.O. 60.—Shri C. G. Sonikke, Superintendent, Central Excise Group 'B' of Nagpur Collectorate having attained the age of Superannuation retired from Government service on 30-11-1992 in the Afternoon.

[C. No. II(3)3/92/Estt. I/27798]

HARJINDER SINGH, Dy. Collector (Per. and Vig.)]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 1992

का.आ. 61.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के निम्नलिखित स्वायत्त संगठन को जिसमें 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
हौजखास, नई दिल्ली—110016

[सं. 11011/2/92-रा.भा. ए.]

रमेश कुमार आंगिरस, निदेशक
(राजभाषा)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Deptt. of Education)

New Delhi, the 22nd December, 1992

S.O. 61.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following autonomous organisation of the Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education), more than 80 per cent staff of which has acquired working knowledge of Hindi :—

Indian Institute of Technology,
Hauz Khas,
New Delhi-110016.

[No. 11011/2/92-OLU]
R. K. ANGIRAS, Director (O.L.)

MINISTRY OF COAL

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 1992

S.O.—62— In the notification of the Government of India in the Ministry of Coal Number S.O. 934(E) dated the 27th December, 1991, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(ii) dated the 27th December, 1991, the following corrections are made: —

S.No.	Page Number	Reference	For	Read
1	2	3	4	5
1.	9	In notification, line 1	force–	force
2.	9	Table-I, Serial Number 1, Coluum 2, line 3 and 4	the Union Territory of Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh
3.	10	Table-I, Serial Number 2, line 2 and 3	the Union Territory of Arunachal Pradesh.	Arunachal Pradesh
4.	10	Table-I, Serial number 4, Column 2, line I	Weekly	Weakly
5.	11	Notes, item 1 (i) line 1 (ii) line 3	ben ben	been been
6.	11	Notes, item 2: (i) line 1 (ii) line 3	'Blendable coals 'semi coking'	'Blendable coals' 'semi coking'
7.	11	Notes, item 4, line 1, after the words "formula"	;	:
8.	11	Notes, item 4, line 7 after the word "reduced"	of	by
9.	11	Notes, item 4, line 10	causes	clauses
10.	11	Notes, item 5, line 2	equilibrative	equilibrating
11.	11	Notes, item 5, line 3	40°C	40°C
12.	11	Notes, Point 6, in table: (i) in column heading 1 (ii) in column heading 2	 Grou olatile	 Group volatile
13.	12	Table II, Serial number 1, column 1, line 2	Union Territory of Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh.

1.	2	3	4	5
14.	12	Table II, Serial number 2, column 1, line 2	Meghalaya	Meghalaya,
15.	12	Table II, serial number 2, column 1, line 2 and 3	Union Territory of Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh
16.	13	Table II, serial number 4, column 1, line 1 and 2	Union Territory of Arunachal Pradesh.	Arunachal Pradesh
17.	13	Table IV, headline	WEEKIY	WEAKLY
18.	14	Notes, item 2, line 1	comprising	comprising of
19.	14	Notes, item 5, line 2	segregation/into	segregation into
20.	14	Notes, item 6(i), line 3, between 'at the' and 'ratio'.	average rate of prices of steam and slack coal in these	
21.	14	Notes, item 7, line 1	weekly	weakly
22.	14	Notes, item 8, line 2	Rs	Re
23.	15	Notes, item 9 (ii) , line 1 and 2	Union Territory of Arunachal Pradesh.	Arunachal Pradesh
24.	15	Notes, item 9(ii), line 2	Per tonne,	per tonne
25.	15	Notes; item 11, line 2	bodies;	bodies,
26.	15	Notes, item 12: (i) line 1 (ii) line 3 (iii) line 4 (iv) line 7	hard coke soft coke ad coal 1.35	Hard Coke Soft Coke and Coal by 1.35
27.	15	Notes, item 16, line 1	soft coke	Soft Coke
28.	15	Notes, item 16: (i) line 1 (ii) line 3	Beheive percent	Beehive percent
29.	16	Notes, item 19: (i) line 1 (ii) line 3	price percent	prices percent,
30.	16	Notes, item 20, line 3	Annexur	Annexure
31.	16	ANNEXURE, Area-KENDA, under heading COLLIERY, line 8	Chora ODP	Chora OCP
32.	16	ANNEXURE, Area-KAJORA, under heading COLLIERY, line 15	Jambac OCP	Jambad OCP
33.	17	ANNEXURE, Area-BAIKUNTHPUR, under heading COLLIERY: (i) line 3 (ii) line 4	 Bhatgaon OCP Bisrampur UG	 Bhatgaon Bisrampur OCP Bisrampur UG
34.	17	ANNEXURE, Area-CHIRIMIRI, Under heading COLLIERY; (i) line 11 (ii) line 12	 CHIRIMIRI OC+Ug 1&3 CHIRIMIRI OC+Ug 2&4	 CHIRIMIRI OC+UG 1&3 CHIRIMIRI OC+UG 2&4

[No. 28012/6/90-CA]

R.C. MISRA, Director

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 1992

का.आ. 63.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

(1) एच. एम. टी. लिमिटेड,
पिंजौर-134 101
जिला—अम्बाला (हरियाणा)

(2) एच. एम. टी. घड़ी कारखाना,
रानीबाग—263 126
नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

[सं. ई-11012/(1)/92-हिंदी]

ओ. पी. शरवर, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 11th December, 1992

S.O. 63.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices, the 80 per cent staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. H.M.T. Limited,
Pinjore-134101
Distt. Ambala (Haryana).

2. H.M.T. Watch Factory,
Ranibag-263126
NAINITAL (Uttar Pradesh).

[No. E-11012(1)/92-Hindi]

O. P. SHARVAR, Dy. Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1992

का.आ. 64.—भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 36(क) की उपधारा 2(क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री वाई. पी. गम्भीर को श्री कृष्ण स्वरूप के स्थान पर केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है।

[संख्या 25/13/92-डी. (एम. ई. बी.)]

एम. एल. शर्मा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 21st December, 1992

S.O. 64.—In pursuance of Sub-section 2(a) of Section 36A of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), the Central Government is pleased to nominate Shri Y. P. Gambhir, Chairman, Central Electricity Authority as Chairman of the Central Electricity Board vice Shri Krishna Swarup.

[No. 25/13/92-D(SEB)]

M. L. SHARMA, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 1992

का.आ. 65.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) प्रथम अनुसूची में, "मद्रास विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डिप्लोमा इन मेडिसिन (जठरांत्र विज्ञान)	डी. एम. (ज. वि.)"

(2) "डॉ. एम. जी. आर. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डिप्लोमा इन मेडिसिन (जठरांत्र विज्ञान)	डी एम. (ज. वि.)"

(3) "महात्मा गांधी विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (समुदाय आयुर्विज्ञान)	एम. डी. (सम. आ.))"
डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (शरीर रचना विज्ञान)	एम. डी. (श.र.वि.)"

(4) "गौहाटी विश्वविद्यालय" शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"डॉक्ट ऑफ मेडिसिन (न्याय आ.)	एम. डी. (न्या. आ.)"

[सं वी. 11015/33/92-एम.ई. (यू.जी.)]

आर. विजयकुमारी, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 15th December, 1992

S.O. 65.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

(1) In the First Schedule, under the heading "UNIVERSITY OF MADRAS" after the entries, the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Medicine (Gastro-enterology)	.. D.M. (Gastroenterology"

(2) under the heading "Dr. M.G.R. MEDICAL UNIVERSITY, MADRAS", after the entries, the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Medicine (Gastro-enterology)	.. D.M. (Gastroenterology)"

(3) under the heading "MAHATMA GANDHI UNIVERSITY", after the entries, the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Community Medicine)	.. M. D. (Comm. Med.)
Doctor of Medicine (Physiology)	..M.D. (Physiology)"

(4) under the heading "UNIVERSITY OF GAUHATI", after the entries, the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Forensic Medicine) .. M.D. (Forensic Medicine)

[No. V. 11015/33/92-ME(UG)]

R. VIJAYAKUMARI, Desk Officer

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अनुश्रवण संगठन

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1992

का.आ. 66.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के अनुश्रवण संगठन में प्रभारी अधिकारी अनुश्रवण केन्द्र, हैदराबाद के कार्यालय को जिसके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है।

[सं. ई-11011/11/90-हिन्दी]

के. वरदराजन, निदेशक, (बेतार अनुश्रवण)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecom.)

(Monitoring Organisation)

New Delhi, the 1st December, 1992

S.O. 66.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Office of the Officer-in-Charge, Monitoring Station, Hyderabad in the Monitoring Organisation of the Ministry of Communications, Department of Telecom. the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi.

[No. E.-11011/11/90-Hindi]

K. VARDARAJAN, Director, (Wireless Monitoring)

(डाक विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1992

का.आ. 67.—दिनांक 4 नवम्बर, 1992 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में क्रमांक 3 पर उल्लिखित कार्यालय को निकाल दिया गया समझा जाए।

[सं. ई-11017/1/92-रा.भा.]

डॉ. गिरिवरधारी सिंह, निदेशक (राजभाषा)

(Department of Posts)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 1992

S.O. 67.—In continuation of the notification of even No. dated 4th November, 1992, the name of the Office appeared at serial No. 3 may be treated as deleted.

[No. E-11017/1/92-OL]

DR. G. D SINGH, Director (OL).

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1992

का.आ. 68.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इंडियन एयर लाइन्स के उत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत स्टेशन प्रबन्धक का कार्यालय, गोरखपुर को जिसके कर्मचारी-वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[संख्या ई-11011/6/88-हिन्दी]

रघुनाथ सहाय, उप निदेशक (रा.भा.)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 12th November, 1992

S.O. 68.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Office of Station Manager, Gorakhpur under Northern Zone of Indian Airlines under the administrative control of Ministry of Civil Aviation and Tourism (Department of Civil Aviation), the staff of which have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E.-11011/6/88-Hindi]

RAGHUNATH SAHAI, Dy. Director, (O. L.)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1992

का. आ. 69.—केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 27 के अनुसरण में पश्चिमी बंगाल राज्य के बर्द्धमान जिले में मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (जो कोल इंडिया लिमिटेड का समनुषंगी है) की महावीर कोयला खान में 13 नवम्बर, 1989 को होने वाली दुर्घटना से संबंधित कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन उसे प्रस्तुत निम्नलिखित रिपोर्ट को इस अधिसूचना के उपाबंध के रूप में प्रकाशित करती है।

"पश्चिमी बंगाल राज्य के जिला बर्द्धमान में महावीर कोयला खान में 13 नवम्बर, 1989 को होने वाली दुर्घटना की बाबत जांच न्यायालय की रिपोर्ट।"

[फाइल सं. एन-11015/2/92-आईएसएच-II]

आर. टी. पाण्डेय, उप सचिव

मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की महावीर कोलियरी में पानी भर जाने के कारण 13 नवंबर, 1989 को हुई घातक दुर्घटना पर खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत प्रतिवेदन।

भूमिका

श्रम मंत्रालय ने 3 जनवरी, 1991 को खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करके 13 नवंबर, 1989 को हुई घातक दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच के लिए यह नियुक्त किया था। इस दुर्घटना में आसनसोल के निकट महावीर खान में छः व्यक्तियों की जान चली गई थी। श्री सी एन. तिवारी,

महानिदेशक, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद तथा प्रो. ए. के. घोष प्रोफेसर, खान इंजीनियरिंग, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद को जांच न्यायालय का निर्धारक (असेसर) नियुक्त किया गया था।

2. मैंने दुर्घटना स्थल के दौरे के साथ 7 अप्रैल, 1991 को जांच न्यायालय का कार्य प्रारंभ कर दिया। आरम्भ दिन मैंने सम्बन्धित सभी पक्षों को सुनवाई की तथा न्यायालय की प्रक्रिया निर्धारित की, साथ ही पक्षों को वकीलों के माध्यम से प्रस्तुत होने की अनुमति प्रदान की।

3. कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के संसद के लिए होने वाले आम चुनावों तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनावों में व्यस्त रहने के कारण मैंने मई और जून, 1991 में सुनवाई की कोई तारीख निश्चित नहीं की। चुनावों के हो जाने के बाद ही गवाहों से पूछताछ तथा जिरह का कार्य शुरू हो सका। मैंने जुलाई से अक्तूबर, 1991 के बीच आसनसोल में सभी गवाहों से पूछताछ की तथा निर्धारकों और कुछ गवाहों के साथ एक बार फिर महावीर खान का दौरा किया, ताकि उन घटनाक्रमों की पुनः संरचना की जा सके जो दुर्घटना के लिए उत्तरदायी थे।

4. मुझे श्रम मंत्रालय में अपर सचिव के कार्यों के अतिरिक्त जांच न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद जुलाई से अक्तूबर, 1991 तक सुनवाई पूरी कर ली गई। पक्षों ने लिखित तर्क नवंबर 1991 में प्रस्तुत किया उसके पश्चात् मैंने साक्ष्य तथा तर्कों के विश्लेषण के लिए निर्धारकों के साथ बैठक आयोजित की।

5. मोटे तौर पर महावीर कोलियरी में घातक दुर्घटना उस समय हुई जब 55 मीटर की गहराई में स्थित एक गैलरी जिसमें काम चल रहा था। एक पुरानी, बेकार पड़ी हुई शैफ्ट जिसमें पानी भरा हुआ था से जुड़ गई। शाफ्ट के ऊपर स्थित सीम के पानी भराव स्थानों से बहुत तेजी के साथ पानी अंदर आ रहा था। छः खनिकों की जान गई। उस सीम में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे 65 खनिक फंस गए क्योंकि उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। इन खनिकों ने कार्यस्थल के ऊंचाई वाले भाग में शरण ली, इस हिस्से में पानी नहीं था। उन्हें दुर्घटना के लगभग 75 घंटे के भीतर बाहर निकाला गया। इसके लिए स्थानीय तौर पर निर्मित कैप्सूल की सहायता लेनी पड़ी जिसे एक पहिए की सहायता से इस कार्य के लिए भूमि में किए बड़े छिद्र के माध्यम से खान में उतारा गया था। इस अद्वितीय बचाव कार्य ने, जिसे पहली बार भारत में इस्तेमाल किया गया और जिसे इससे पहले संसार में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया।

संचार माध्यम का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया गया।

6. मेरा मानना है कि घातक दुर्घटना का कारण उस गली में जिसमें खनन कार्य चल रहा था और उसका खनन करते हुए एक पुरानी बेकार, पानी से भरी शैफ्ट की ओर बढ़ा जा रहा था, में एक केन्द्रीय तथा पार्श्व छिद्र (बोर होल) की व्यवस्था का न होना था। अगर पहले से ही ऐसा बोर होल होता तो खान के अधिकारियों का आगे आने वाली पानी से भरी शैफ्ट के बारे में पूर्व चेतावनी दे दी जाती और खतरा टल जाता। कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 के अंतर्गत ऐसे एडवांस बोर होल का होना अनिवार्य है। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा काम की अनुमति प्रदान करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि इस प्रकार के बोर होल्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गली उस क्षेत्र में बढ़ रही थी जिसे खान सुरक्षा निदेशालय ने काम के लिए अनुमोदित नहीं किया था बल्कि यह अनुमोदित क्षेत्र से 100 मीटर आगे थी। घटनावश घातक दुर्घटना गैर अनुमोदित क्षेत्र, जिसमें असामान्य जल रिसाव के कारण जनवरी 1988 में काम रोक दिया गया था, की गैलरी में काम प्रारंभ होने के केवल पांच दिन के अंदर हो गई थी। इस प्रकार यह दुर्घटना भारी लापरवाही के कारण है जिसकी जिम्मेदारी महावीर खान के एजेंट और प्रबंधक तथा उनके अधीन काम करने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर है।

7. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि क्या इस वर्तमान कोयला और हमारे देश की कोयला खानों में पानी भर जाने के कारण हुई अन्य बड़ी दुर्घटनाओं में कुछ समानता है और क्या पानी भर जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं तथा विपदाओं की रोकथाम के लिए कोयला खान विनियम, 1957 में आगे संशोधन करना अपेक्षित है। समीक्षा से यह पाया गया है कि भारत में भूमिगत कोयला खानों में पानी जमा होने के कारण हुई कुछ बड़ी दुर्घटनाएं निम्नलिखित हैं—

(i) न्यूटन चिकली कोलियरी (मध्य प्रदेश) में 10 दिसंबर, 1954 को घटित दुर्घटना जिसमें 63 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ii) सेंट्रल भौंरा कोलियरी (बिहार) में 20 फरवरी, 1958 को घटित दुर्घटना जिसमें 23 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(iii) दमुआ कोलियरी (मध्य प्रदेश) में 5 जनवरी, 1960 को घटित दुर्घटना जिसमें 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(iv) सिलेवारा कोलियरी (मध्य प्रदेश) में 19 नवंबर, 1975 को घटित दुर्घटना जिसमें 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(v) चासनाला कोलियरी (बिहार) में 27 दिसंबर, 1975 को घटित दुर्घटना जिसमें 375 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और;

(vi) हुरिलाडीह कोलियरी (बिहार) में 14 सितंबर, 1983 को घटित दुर्घटना जिसमें 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन दुर्घटनाओं की जांच करने के उद्देश्य से नियुक्त जांच न्यायालय की रिपोर्टों से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं परिहार्य मानवीय असफलताओं और गंभीर लापरवाही के कारण हुई। जांच न्यायालयों में से कुछ की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने समय-समय पर कोयला खान नियमावली में संशोधन किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश गंभीर लापरवाही और सांविधिक विनियमनों की अवहेलना के कारण भूमिगत कोयला खानों में पानी जमा हो जाने के कारण दुर्घटनाएं और विपदाएं होती रही हैं। अतः मेरा विचार है कि इस स्थिति में कोयला खान नियमावली, 1957 में आगे किसी संशोधन से अपने आप ऐसी दुःखद दुर्घटनाएं बन्द नहीं हो जाएंगी और विनियमन 127 में भूमिगत पानी से बाढ़ के खतरों से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपायों की व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्यवश चासनाला में (27 दिसंबर, 1975) घटित सबसे दुःखद दुर्घटना में भी गंभीर लापरवाही के कारण इस विनियमन, 127 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इस घातक दुर्घटना को कारण कहानी भी कुछ भिन्न नहीं है।

8. अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे प्रयास और उन लोगों के प्रयास जिन्होंने इस जांच में मेरे साथ सहयोग किया है, तभी सफल माने जाएंगे यदि कोयला खान विनियमन के सभी प्रावधानों का पालन कोयला खान के प्रबंधन और उनके कर्मचारियों द्वारा किया जाए और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक जागरूकता पैदा की जाए।

9. मैं मूल्यांकनकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत व्यस्त होने के बावजूद इस जांच के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं संबंधित पक्षकारों का भी उनके स्वैच्छिक सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

ह./-
(पी. सी. होता)
महावीर जांच न्यायालय
श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

अध्याय		विषय	पृष्ठ
I		जांच न्यायालय	
	1.1	भूमिका	48-49
	1.2	श्री के.सी. शर्मा का जांच न्यायालय	52
	1.3	श्री पी.सी. होता का जांच न्यायालय	52
	1.4	न्यायालय की प्रक्रिया	53
	1.5	न्यायालय में सुनवाई	53
II		सामान्य सूचना	
	2.1	महावीर खान	54
	2.2	प्रबंधतंत्र	54
	2.3	भू-विज्ञान	54
	2.4	इससे पूर्व का खनन कार्य	54
	2.5	वर्किंग	55
III		कानून की समीक्षा	
	3.1	कोयला खानों में जल भरने के खतरे के विरुद्ध सांविधिक उपबंध	55
	3.2	भारत	55
	3.3	विकसित देश	56
IV		जल प्लावन विपदा	
	4.1	भारत में जल प्लावन के कारण होने वाली दुर्घटना का सामान्य विश्लेषण	56
	4.2	जल प्लावन के कारण भारत में हुई प्रमुख दुर्घटना	56-57
V		दुर्घटना	
	5.1	दुर्घटना	57
	5.2	लापता व्यक्तियों की छानबीन	59
	5.3	सहायता कार्य	58
VI		निरीक्षण	
	6.1	दुर्घटना स्थल का प्रथम निरीक्षण	58
	6.2	भूतल निरीक्षण	59
	6.3	विशेष निरीक्षण	59
	6.4	निष्कर्ष	59
VII		मुद्दे	
	7.1	न्यायालय के समक्ष विचारणीय विषय	59
	7.2	शाफ्ट नं. 34 का विस्तार	60-61
	7.3	पानी का असामान्य रिसाव	61-62
	7.4	पूर्व में स्थापित लंबा बोरहोल	62-63
	7.5	कामकाज की अनुमति	63-64
	7.6	एडवांस बोरहोल्स	64-65
	7.7	दुर्घटना से संबंधित अन्य मुद्दे	65-66

अध्याय		विषय सूची	पृष्ठ
VIII		कारण	
	8.1	गवाही का विश्लेषण शाफ्ट नं. 34 का विस्तार	66
	8.2	पानी का असामान्य रिसाव	66
	8.3	40 डिप का पुनः चालू किया जाना	66
	8.4	एडवांस बोरहोल्स	67
IX		उत्तरदायित्व	
	9.1	उत्तरदायित्वों का विश्लेषण	67
	9.2	एजेंट-सह-प्रबंधक	67-68
	9.3	सुरक्षा अधिकारी	68
	9.4	सहायक प्रबंधक	68
	9.5	सर्वेक्षक	69
	9.6	उच्चतर प्रबंधन	69
	9.7	अन्य	69
X		निष्कर्ष	
	10.1	निष्कर्षों का सारांश	70
	10.2	सिफारिशें	70-71
	10.3	खर्चों की वसूली	71
	10.4	आभार	71

अनुबंधों की सूची

अनुबंध संख्या		
1	13 नवंबर, 1989 को हुई घातक दुर्घटना के कारण मारे गए व्यक्तियों की सूची	71
2	श्री के०सी० शर्मा की नियुक्ति की अधिसूचना	71
3	श्री पी०सी० होता की नियुक्ति की अधिसूचना	72
4	श्री पी०सी० होता द्वारा दी गई अंडरटेकिंग	72
5	श्री पी० सी० होता द्वारा पक्षकारों को जारी की गयी नोटिस	72
6	प्रबंधन के गवाहों की सूची	72
7	यूनियन के गवाहों की सूची	73
8	न्यायालय के गवाहों की सूची	73
9	प्रबंधन के प्रदर्शों की सूची	73-74
10	यूनियन के प्रदर्शों की सूची	75
11	महावीर खान का वर्णन	75
12	कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 का मूलपाठ	75
13	दुर्घटना स्थल के फोटोचित्र	77
14	उन पक्षकारों और उनके प्रतिनिधियों के नाम जिन्होंने गवाहों की जांच और उनसे जिरह की	77

प्रयुक्त शब्द संक्षेपों की सूची

ए.एम.पी. —खान के परित्याग की योजना

सी.डी.एस —केन्द्रीय डिस्पैचर पद्धति

सी.एम.पी.डी.आई —केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान।

सी.एम.आर —कोयला खान विनियम

सी.डब्ल्यू. —न्यायालय के गवाह

डी.जी.एम.एस —खान सुरक्षा महानिदेशक

प्रयुक्त शब्द संकेतों की सूची

एम. डब्ल्यू. – प्रबंधकों के गवाह

यू. डब्ल्यू. – यूनियन के गवाह

ई.सी. एल. – मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमि.

प्रद. – प्रदर्श

अध्याय- I

1.1 भूमिका

1.2 श्री के.सी. शर्मा का न्यायालय

1.3 श्री पी.सी. होता का न्यायालय

1.4 न्यायालय की कार्यविधि

1.5 न्यायालय की सुनवाई

अध्याय–1

1.1.1 पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स, लि. (कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी) के महावीर खान के भूमिगत कार्यस्थलों में 13 नवंबर, 1989 को सुबह तड़के पानी भर जाने के कारण एक घातक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 6 खनिकों की मृत्यु हो गई जिनके नाम अनुबंध I में दिये हैं। 65 खनिक अंदर ही फंस गये थे क्योंकि उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। करीब 75 घंटों के बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। बोर होल ड्रिल करके और स्थानीय रूप से निर्मित चरखी द्वारा संचालित इस्पात कैपसूल को नीचे भेजकर उनको बचाया गया। बाद में हाथ से संचालित इस चरखी के स्थान पर डीजल से संचालित क्रेन का प्रयोग किया गया। बचाव पद्धति, जिसका प्रयोग भारत में पहली बार किया गया था और इतने बड़े पैमाने पर विश्व में इसका कहीं प्रयोग नहीं किया गया था, जो प्रचार माध्यमों ने खूब सराहा।

1.1.2 खान अधिनियम, 1952 के खण्ड 24 के उप खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने 16 अप्रैल, 1990 को एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा दुर्घटना के कारणों और संगत परिस्थितियों की औपचारिक जांच करने के लिये श्रम मंत्रालय के सेवा निवृत्त अपर सचिव श्री के.सी. शर्मा को इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किया गया। इसी अधिसूचना में जांच न्यायालय के निर्धारकों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया था :—

1. श्री बी. एन. तिवारी, महासचिव, कोलियरी मजदूर सभा, आसनसोल, जिला बर्दवान पश्चिम बंगाल।

2. प्रो. ए.के. घोष, प्रोफेसर, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद।

श्रम मंत्रालय की संगत अधिसूचना अनुबंध II पर दी गई है।

1.2.1 श्री के. सी. शर्मा के जांच न्यायालय की पहली बैठक 24 मई, 1990 को हुई और जिसमें यह निदेश दिया गया कि समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करवाये जायें ताकि संबंधित पक्ष अपना लिखित बयान भेज सकें। जांच न्यायालय ने यह भी निर्णय किया कि वह सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सी एम पी डी आई), आसनसोल के परिसर में 10 जुलाई, 1990 से सुनवाई प्रारंभ करेगा।

1.2.2 जांच न्यायाधीश ने 10–11 जून, 1990 को निर्धारकों, प्रबंधकों के प्रतिनिधियों तथा खान सुरक्षा महानिदेशक (डी जी एम एस) के साथ घटना स्थल का दौरा किया। तत्पश्चात् 2 जुलाई, 1990 से न्यायालय ने सी एम पी डी आई, आसनसोल में औपचारिक सुनवाई प्रारंभ की। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 7 के अन्तर्गत जब्त किये गये महावीर खान की दुर्घटना से संबंधित सभी कागजात प्रस्तुत किये जिन्हें जांच न्यायालय ने अपने कब्जे में कर लिया। तथापि जांच न्यायालय को 7 जुलाई, 1990 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें उच्च न्यायालय ने जांच न्यायालय के एक पक्ष कोल माइंस आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत दायर रिट याचिका की सुनवाई तक जांच न्यायालय की कार्यवाही पर स्थगन दिया था। अत: जांच न्यायालय ने 7 जुलाई, 1990 के बाद अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी।

1.3.1 16 अप्रैल, 1990 की पूर्व अधिसूचना में 3 जनवरी 1991 को आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने श्री के.सी. शर्मा के स्थान पर श्री पी.सी. होता, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय को जांच के लिये नियुक्त किया। इस संबंध में 3 जनवरी, 1991 को जारी की गई अधिसूचना अनुबंध III पर दी गई है।

1.3.2 चूंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने श्री के.सी. शर्मा की जांच पर स्थगन दिया था अत: अपनी नियुक्ति के बाद श्री पी.सी. होता ने उच्च न्यायालय को एक अण्डरटेकिंग दी कि वे पूर्व में श्री के.सी. शर्मा द्वारा की गई जांच प्रक्रिया से बंधे नहीं रहेंगे बल्कि वे अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेंगे। श्री पी.सी. होता द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को दी गई अंडरटेकिंग की एक प्रति अनुबंध VI पर संलग्न है।

1.3.3 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि श्री पी.सी. होता कानून के अनुसार नये सिरे से उपर्युक्त जांच शुरू करेंगे। इन परिस्थितियों में कोल माइंस आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका रद्द कर दी गई और जांच न्यायालय की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश वापस ले लिया गया।

1.3.4 तदनुसार 21 मार्च, 1991 को पक्षों को नोटिस जारी करके सुनवाई के लिए 8 अप्रैल, 1991 को सी एम पी डी आई, आसनसोल में उपस्थित होने के लिये कहा गया। पक्षों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे इस संबंध में उनके द्वारा दिये गये लिखित बयान को प्रमाणित करने के लिये गवाहों की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत करें। पक्षों को जारी किये गये नोटिस की एक प्रति अनुबंध V पर दी गई है।

1.3.5 मैंने जांच न्यायाधीश के रूप में 7 अप्रैल, 1991 को प्रो. ए.के. घोष, निर्धारक तथा मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई सी एल) तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के कुछ अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

1.4.1 जांच न्यायालय ने 8 अप्रैल, 1991 को सी एम पी डी आई, आसनसोल में सुनवाई की। निर्धारक एवं पक्षकार उपस्थित थे। पक्षों को सुनने तथा निर्धारकों के साथ विचार-विमर्श करके मैंने निम्नलिखित आदेश दिया :—

(क) कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में जांच नए सिरे से प्रारंभ की जाएगी लेकिन पक्षों द्वारा श्री के.सी. शर्मा के जांच न्यायालय में प्रस्तुत किए गए लिखित नोट, शपथ तथा गवाहों की सूची इस जांच न्यायालय के लिए भी वैध मानी जाएगी ;

(ख) पक्षों को अधिक से अधिक 30 अप्रैल, 1991 तक पूरक नोट, शपथ तथा गवाहों की अतिरिक्त सूची, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाएगा।

(ग) यदि पक्ष अभिसाक्ष्य आदि की प्रति चाहेंगे तो वह उन्हें तुरंत दी जाएगी ;

(घ) जांच न्यायालय सांविधिक है और अतः अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पक्षों को, यदि वे ऐसा चाहें, किसी वकील या किसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों जिनसे मामले को प्रस्तुत करने में सहायता मिले, के माध्यम अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे पक्षों को इसके लिए जांच न्यायालय से लिखित अनुरोध करना चाहिए और जांच न्यायालय सामान्य तौर पर इसकी अनुमति दे देगा।

1.5.1 नौवीं लोक सभा के आगामी चुनाव और पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनाव तथा इन चुनावों में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए मैंने सी एम पी डी आई, आसनसोल में पक्षों की अगली सुनवाई की तारीख 15 से 22 जुलाई, 1991 के लिए निर्धारित की।

1.5.2 15 जुलाई, 1991 को जब सुनवाई शुरू हुई तो श्री के. पाल, खान सुरक्षा महानिदेशक से उनके द्वारा खान अधिनियम, 1952 की धारा 23 के अंतर्गत की गई दुर्घटना की जांच के दौरान खान अधिनियम, 1952 की धारा 7(2) के अंतर्गत जब्त किए गए कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तदनुसार श्री के पाल ने न्यायालय को जब्त किए गए कागजातों की सूची प्रदान की और मैंने पाया कि यह सूची उस सूची के समान है जो कि पिछले जांच न्यायाधीश श्री के.सी. शर्मा द्वारा अपने कब्जे में लिए गए उक्त कागजातों की सूची है।

1.5.3 15 से 22 जुलाई, 1991 के दौरान आसनसोल में प्रबंधतंत्र के 16 गवाहों के साथ जिरह की गई। इस अवधि के दौरान संघों के प्रतिनिधियों को उन कागजातों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की गई जो कि खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जब्त किए गए थे तथा जिन्हें जांच न्यायालय ने अपने कब्जे में रखा था। इन निरीक्षणों के दौरान जांच न्यायालय के सचिव मौजूद थे।

1.5.4 20 से 26 सितंबर, 1991 को आसनसोल में हुई जांच न्यायालय की अगली सुनवाई के दौरान 6 गवाहों (प्रबंधतंत्र तथा संघ के तीन-तीन गवाह) से जिरह की गई। इस अवधि के दौरान प्रबंधतंत्र के दो गवाहों से भी जिरह की गई।

1.5.5 जांच न्यायालय की अंतिम सुनवाई आसनसोल में 24 से 26 अक्तूबर, 1991 के दौरान हुई, इस सुनवाई में जांच न्यायालय द्वारा बुलाए गए संघ के तीन गवाह तथा एक गवाह (श्री एस.के. सेनगुप्ता, सहायक प्रबंधक, महावीर खान) के साथ जिरह की गई। तथापि न्यायालय के एकमात्र गवाह अर्थात् श्री एस.के. सेनगुप्ता के सामने भी कोई जिरह नहीं की गई। घातक दुर्घटना के लिए उत्तरदायी घटनाओं के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए जांच न्यायालय ने निर्धारकों तथा कुछ गवाहों के साथ 26 अक्तूबर, 1991 को एक बार फिर दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

1.5.6 24 से 26 अक्तूबर, 1991 के दौरान पक्षों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि वे केवल लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे। तदनुसार मैंने जांच न्यायालय के सचिव को 12 और 13 नवम्बर, 1991 को आसनसोल में रहने तथा लिखित तर्क स्वीकार करने के निदेश दिया।

1.5.7 12 और 13 नवंबर, 1991 को जांच न्यायालय के सचिव ने आसनसोल का दौरा किया तथा प्रबंधतंत्र और संघों से लिखित तर्क स्वीकार किए।

1.5.8 जुलाई और अक्तूबर, 1991 के दौरान आसनसोल में जांच न्यायालय की सुनवाई के दौरान बयानों को सामान्यलिपि में लिखकर मैंने साक्ष्यों को व्यक्तिगत रूप से रिकार्ड किया। चूंकि कुछ गवाह अंग्रेजी में निपुण नहीं थे अतः उनसे उस भाषा में प्रश्न पूछे गए जिसे वे जानते थे (अर्थात् हिन्दी और बंगाली)। तथापि मैंने उनके बयानों का खुले न्यायालय में अंग्रेजी में अनुवाद किया और सामान्य लिपि में उन्हें रिकार्ड किया। जैसे ही बयान समाप्त हुए पक्षों को गवाहों के बयानों की फोटोकापी देने के प्रयास किए गए।

गवाहों के बयानों की प्रतियां निरन्तर रूप से पक्षों को भेजी गई ताकि वे अपने आप को जिरह के लिए तैयार कर सकें। जांच न्यायालय की इस तत्परता की प्रबंधतंत्र तथा संघ दोनों ने सराहना की।

1.5.9 12 और 13 नवम्बर, 1991 को लिखित तर्क प्राप्त हो जाने के पश्चात मैं और निर्धारक 20 से 23 नवंबर, 1991 तथा 25 और 26 दिसंबर, 1991 को जांच न्यायालय की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बयानों, तर्कों तथा अन्य संगत मामलों पर विचार करने के लिए दिल्ली में मिले।

1.5.10 जांच न्यायालय की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय के सचिव को प्रस्तुत कर दी गई थी।

1.5.11 इस रिपोर्ट में प्रबंधतंत्र द्वारा पेश किए गए गवाहों को प्रबंधतंत्र के गवाह (एम डब्ल्यू), संघ द्वारा पेश किए गए गवाहों को संघ के गवाह (यू डब्ल्यू) और जांच न्यायालय द्वारा बुलाए गए गवाहों को न्यायालय के गवाह (सी डब्ल्यू) के रूप में रिकार्ड किया गया है। प्रबंधतंत्र संघ तथा न्यायालय के गवाहों की सूची क्रमशः अनुबन्ध VI, VII और VIII पर दी गई है।

1.5.12 वे प्लान तथा कागजात जिन्हें प्रबंधतंत्र ने प्रदर्शित करने का अनुरोध किया था उन्हें प्रबंधतंत्र प्रदर्शन (एक्स एम) तथा जिन्हें कर्मचारी संघों द्वारा प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया था संघ प्रदर्शन (एक्स डब्ल्यू) कहा गया है। क्रमशः अनुबंध IX तथा X पर प्रबंधतंत्र तथा कर्मचारी संघों के प्रदर्शन की सूची दी गई है।

अध्याय—2

2.1 महावीर खान

2.2 प्रबंधतंत्र

2.3 भू-विज्ञान

2.4 पूर्व का उत्खनन

2.5 अभिलाल

2.1.1 महाबीर खान पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान जिले के रानीगंज कोयला क्षेत्र में स्थित है। यह आसनसोल स्टेशन से 18 कि.मी. पूर्व तथा कलकत्ता से लगभग 182 कि.मी. उत्तर पश्चिम में स्थित है। महाबीर खान की भौगोलिक स्थिति, भूतल की विशेषता, स्वामित्व आदि का संक्षिप्त विवरण अनुबंध – XI पर दिया गया है।

2.2.1 महाबीर खान 1975 में मै. कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के स्वामित्व में है। प्रशासनिक सुविधा के लिए मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को दो डिवीजनों में विभाजित किया गया है, अर्थात ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीजन- प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक क्रियात्मक निदेशक होता है। क्रियात्मक निदेशक (फंक्शनल डायरेक्टर) को खान अधिनियम, 1952 की धारा 76 के अन्तर्गत नामित स्वामी" के रूप में अधिसूचित किया जाता है। निगमित स्तर पर एक आंतरिक सुरक्षा संगठन (आई एस ओ) काम कर रहा है। ईस्टर्न डिवीजन को 63 चालू खानों के साथ 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। महाबीर खान कुनुस्टोरिया क्षेत्र में स्थित है जिसमें महाबीर खान सहित ग्यारह चालू खानें शामिल हैं। दुर्घटना के समय मोहम्मद कलीम (एस डब्ल्यू 17) महाबीर खान का एजेंट व प्रबंधक था। वह जून, 1987 में प्रबंधक था और बाद में एजेंट व प्रबंधक नियुक्त किया गया था। अतः 13 नवम्बर, 1989 के मनहूस दिन तक उसे उपर्युक्त खान में दो साल से अधिक का अनुभव प्राप्त था। मोहम्मद कलीम (एस. डब्ल्यू. 17) को कोयला खान का प्रबंध करने में सक्षमता के लिए प्रबंधक का प्रथम श्रेणी प्रमाणपत्र प्राप्त था। उसने कोयला खानों में प्रशिक्षु के रूप में काम आरंभ किया था और नवम्बर, 1989 तक उसे लगभग 28 वर्ष का अनुभव प्राप्त था।

2.2.2 दुर्घटना के समय श्री एस.के.सेनगुप्ता (सी डब्ल्यू 1) और श्री के. दत्ता (एस डब्ल्यू 19) महाबीर खान के सहायक प्रबंधक थे और दोनों के पास क्षमता का द्वितीय श्रेणी प्रबंधक प्रमाण-पत्र था। श्री पी. एल. बनर्जी (एस डब्ल्यू 16) महाबीर खान के सुरक्षा अधिकारी थे और वे मोहम्मद कलीम, एजेंट एवं प्रबंधक (एस डब्ल्यू 17) के प्रति उत्तर-दायी थे। श्री पी. एल. बनर्जी के पास कोयला खानों में दक्षता का प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र था।

2.2.3 श्री पी. एल. ठाकुर (एस डब्ल्यू 16) एक सर्वेक्षक थे। उनके पास सर्वेक्षक सक्षमता प्रमाणपत्र है। कोयला खान नियमावली, 1957 (सी एम आर 1957) के विनियम 49 में उनके कर्तव्य दिए गए हैं। संक्षेप में खान अधिनियम और विनियमों के अंतर्गत उनके अपेक्षित कर्तव्य सही सर्वेक्षण और लेवलिंग करना और ऐसी योजना एवं सेक्शन्स तैयार करना और उनका पता लगाना जैसा भी प्रबन्ध निदेश दे। यह उल्लेख करना संगत होगा कि सर्वेक्षक के वैधानिक कर्तव्य है कि जब खान का कार्य उसकी सीमा बाउंड्री या पानी भरे स्थल से लगभग 75 मीटर दूर रह जाए तो वह संपूर्ण तथ्यों को रिकार्ड करें। एक अन्य सर्वेक्षक तथा कुछ सहायक जिनके पास कोयला खान उत्खनन का औप-चारिक सक्षमता प्रमाण पत्र नहीं था बल्कि केवल अनुभव मात्र था, श्री ठाकुर (एस डब्ल्यू 15) की सहायता कर रहे थे।

2.2.4 खान में 13 ओवरमैन तथा 32 सिरदार थे। उनके पास इस प्रकार की नियुक्ति के लिए अपेक्षित वैधानिक प्रमाणपत्र था। श्री शिवदास चटर्जी, ओवरमैन (एस डब्ल्यू 9) कर्मकारों के निरीक्षक के रूप में नियुक्त थे।

2.3.1 रानीगंज कोयला क्षेत्र की कोयला सीम लोअर गोंडवाना पद्धति की दामुदा श्रेणी की रानीगंज स्टेज से संबंधित थी। सतह का सामान्य झुकाव दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर 2° से 35° के बीच था। कई स्थानों पर निचले गोंडवाना क्षेत्र में डोलाराइट डाइक के रूप में आग्नेय चट्टानें हैं। यहां पर 1.2 मीटर की 10 कोयला सीम है, जो कि रानीगंज स्टेज से संबद्ध मोटाई से ऊपर हैं। कोयला सीमों का नाम अधिकांशतः उन गांवों के नाम पर है जिनसे होकर वे गुजरती हैं, यहां तक कि एक ही सीम का नाम विभिन्न कोयला क्षेत्र के विभिन्न भागों में अलग अलग पाया जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में घटते क्रम में सीमों का सामान्य क्रम आर-एक्स से आर-आई है।

2.3.2 महाबीर खान के क्षेत्र में आर – 9 के बराबर सीयरसोल सीम नामक उच्चतम सीम है जिसकी मोटाई लगभग 6 मीटर है। इस क्षेत्र के लगभग बीच वाले भाग में यह सीम स्थित है। खान क्षेत्र के दक्षिणी भाग में नेगा सीम नामक एक दूसरी सीम है, आर–8 के बराबर में स्थित इस सीम की मोटाई लगभग 8 मीटर है। सीयर सोल और नेगा सीम के बीच की दूरी 51 मीटर है। दमोदर नदी के किनारे खान आहते के साथ दक्षिण की ओर आगे बढ़ने पर आर– 7 के बराबर नारायणकुरी सीम नामक तीसरी सीम स्थित है। नारायण सीम की मोटाई लगभग 3.3 मीटर है। नेगा और नारायणकुरी सीम के बीच की दूरी लगभग 24 मीटर है। नारायणकुरी सीम से 30 मीटर नीचे आर- 6 के बराबर 3 मीटर मोटी बोगरा सीम है। इन सभी सीमों का क्रम इस प्रकार है :--

सीयर सोल सीम	6 मीटर मोटी
बीच की दूरी	50 मीटर
नेगा सीम	8 मीटर मोटी
बीच की दूरी	24 मीटर
नारायणकुरी सीम	3.25 मीटर मोटी,
बीच की दूरी	80 मीटर
बोगरा सीम	3 मीटर

2.3.3 इन कोयला सीमों की उत्तरपूर्वी दिशा में सामान्य गहराई 25 में 1 है। कोयला सीमों के बीच के भाग में कोयला चट्टानों का समूह है। इस क्षेत्र में उत्तर की तरफ एक 60 मीटर ऊंचे फाल्ट को छोड़कर अपेक्षाकृत कोई अन्य भू-वैज्ञानिक गड़बड़िया नहीं है। 1 मीटर से 6 मीटर तक के कई अन्य छोटे फाल्ट भी हैं। इस क्षेत्र में कुछ डाइक्स [illegible] हैं। दक्षिण क्षेत्र जो उठा हुआ भाग है में एक बहुत बड़ा डाइक है। इस डाइक को किसी भी स्थान में पार नहीं किया गया है और इसकी वास्तविक चौड़ाई भी अभी तक अज्ञात है। इसके अलावा एक मीटर से कम मोटाई वाले कई छोटे डाइक है। भारतीय कोयला क्षेत्रों में अन्य कोयला सीमों की तुलना में नारायणकुरी सीम का कठोर कोयला क्षेत्र समझा जाता है।

2.4.1 महाबीर खान और उसके समीप के क्षेत्र, भारत में कोयला खनन के प्रथम केन्द्रों में से एक हैं। 13 नवम्बर, 1989 को हुई घातक दुर्घटना का कारण इन पुराने और परित्यक्त कार्यस्थलों में पानी भर जाना है। अतः संक्षेप में इस क्षेत्र के पूर्व कोयला खान के इतिहास की समीक्षा करना लाभदायक होगा। जब कुछ ब्रिटिश उद्यमियों ने रानीगंज में कोयला खान का कार्य शुरू किया था तभी पता चला कि रिकार्ड के अनुसार भारत में पहली बार कोयला खनन का कार्य 1774 में हुआ था। 1815 में इगारा गांव के नजदीक रानीगज सीम में गड्ढे खोदे गए जो अभी महाबीर खान के अहाते के भीतर स्थित है। 1843 में इस कोल-फील्ड में खनन कार्य बंगाल कोल कंपनी नामक संयुक्त पूंजी कंपनी द्वारा किया जाता रहा था। 1855 में रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने के बाद इस क्षेत्र में कोयला खनन का कार्य तेजी से विकसित हुआ लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी भारत में कोयला खनन का कार्य वैज्ञानिक रीति से नही किया जाता था और कार्य योजनाओं का विवरण भी नहीं रखा जाता था। 1860 के आसपास ज्योलोजीकल सर्वे आफ इंडिया के अधीक्षक श्री थामस ओल्डहाम ने खान योजना की स्थिति पर असंतोष

व्यक्त करते हुए निम्नलिखित विवरण दिया :—

"पिछले एक या दो साल से मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि भूमिगत कार्यों की एक भी बस्ता में सर्वेक्षण नहीं किया गया या योजना नहीं बनाई गई। जहां तक कार्यस्थलों के विस्तार का प्रश्न है किसी वृद्ध व्यक्ति की स्मरण शक्ति से ही कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है .... मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह पद्धति कुछ मामलों में बदल गई है और कम से कम एक मामले में योजनाओं का विवरण रखा जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि अन्य मामलों में भी ऐसा ही किया जाएगा ......"

2.4.2 खनन का तरीका चौड़ी गलियों में खनन करते हुए आगे बढ़ना और बीच में छोटे छोटे खंभे छोड़ते जाना है और चूंकि कोयले को भूमिगत कार्यस्थलों से मनुष्य द्वारा निकालना पड़ता है, अतः एक सैक्टर में केवल छोटे क्षेत्र में काम किया जा सकता है जो कि समय के साथ परित्यक्त हो जाती है और जो कि खनन जोखिम का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है।

2.4.3 पूर्व की कोयला खनन के ये ऐतिहासिक साक्ष्य महावीर खान और उसके आस पास के क्षेत्र की संपत्ति में आज भी देखे जा सकते हैं।

2.5.1 पुनर्गठित महावीर खान का नजदीक की तीन लघु खानों को मिलाकर बनाया गया था जिसे इस खान की तीन इकाइयां कहा जाता है। यहां पर सीयरसोल सीम सबसे ऊंची कोयला सीम है तथा 80 वर्ष पूर्व इसमें निजी कोयला कंपनी द्वारा काम किया जा रहा था। सीम में कार्य समाप्त हो गया था, उसे परित्यक्त छोड़ दिया गया और वर्तमान में यह पानी से भरी हुई है।

2.5.2 सीयरसोल सीम के 51 मीटर नीचे नेगा सीम स्थित है जो कि 7.5 मीटर से 8.7 मीटर मोटी है। इस सीम में महावीर खान की सभी तीन इकाइयों की तुलना में सबसे अधिक काम हुआ है। महावीर इकाई में मुख्य पूर्व रेलवे लाइन की उत्तर दिशा में सं. ए और बी पिटों के माध्यम से नेगा सीम में खनन हुआ। ए और बी पिट के ऊंचाई वाले भाग की ओर अर्थात पूर्व रेलवे लाइन की दोनों तरफ नेगा सीम में खनन तत्कालीन बंगाल कोल कं. लि. से संबंधित रानीगंज कोलियरी द्वारा किया जाता रहा जिसके कारण ए और बी पिट के नेगा सीम कार्यक्षेत्र में कोयले का एक बैरियर बनाया गया। योजना के अनुसार बैरियर 60 मीटर है। रानीगंज कोलियरी के नेगा सीम के कार्य क्षेत्रों के बारे में विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में आगे दिया जाएगा।

2.5.3 नेगा सीम के 24 मीटर नीचे नरायनकुरी सीम स्थित है जो 1.8 से 3.3 मी. मोटा है। महावीर इकाई में नरायनकुरी की मोटाई 3.25 मीटर है और यह पिट ए और बी के माध्यम से काम करती है। इसे रानीगंज कोलियरी के नेगा सीम के पानी भरे क्षेत्र के नीचे विकसित किया जा रहा है।

2.5.4 पूर्व की मै. बंगाल कोल कंपनी का रानीगंज कोलियरी द्वारा बनाई गई नेगा सीम के लगभग 120 हेक्टेयर क्षेत्र में जो कि पूर्वी रेलवे लाइन के दोनों ओर फैला है, में बहुत अधिक पुराना कार्यक्षेत्र है। कार्य की कोई विश्वस्त योजना जिसमें "एबन्डनमेंट" माइन प्लान" (ए एम पी) नामक वह योजना भी शामिल है जिसे किसी कोल सीम को परित्यक्त करने से एकदम पहले तैयार करना आवश्यक होता है, ई. इस्टर्न कोलफील्ड्स के पास उपलब्ध नहीं है। महावीर खान के कार्यालय में उपलब्ध योजना की प्रमाणिकता संदेहास्पद थी क्योंकि इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। यह योजना मुख्य रेलवे लाइन के दोनों तरफ के छोटे दलों पर बहुत आवश्यक अवरोध से कार्य को होता दर्शाता है। रेलवे लाइन की उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित कार्यस्थलों को दो मीटर चौड़ी गलि के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

अध्याय — III

3.1 कोयला खानों में जलप्लावन के खतरे के विरुद्ध सांविधिक प्रबंध।

3.2 भारत

3.3 विकसित देश

3.1.1 दुर्घटना जल भर जाने के कारण हुई थी अतः भारत और विदेशों की भूमिगत कोयला खानों में जलप्लावन के खतरे से संबंधित सांविधिक उपबन्धों की समीक्षा की गई।

3.2.1 कोयला खान विनियम, 1957 का विनियम 127 का उपबन्ध अभियोजन चलाये जाने से संबंधित है तथा भूमिगत कोयला खान में उसी खान या समीप की खान के कार्यस्थलों से जल या अन्य तरल पदार्थों का अंदर आना रोकने के उपबन्ध बनाता है। विनियमन खान अधिनियम, 1952 की धारा 57के खण्ड/खण्डों के अन्तर्गत बनाये गये हैं। कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियम 127 का संपूर्ण पाठ अनुबंध-XII पर दिया गया है।

3.2.2 यह देखा जा सकता है कि विनियम कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127(3) में जो अप्रयुक्त या परित्यक्त कार्यस्थलों जिनकी जांच नहीं की गई थी और उनमें पानी तथा अन्य तरल पदार्थ नहीं पाये गये, के 60 मीटर के अंदर खनन कार्य करने के लिये खानों के मुख्य निरीक्षक जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक (डी जी एम एस) भी कहा जाता है कि अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था है। चूंकि नारायणकुरी सीम जलप्लावित नेगा सीम के 24 मीटर नीचे स्थित है अतः कोयला खान विनियम, 1957 का विनियम 127 नारायणकुरी सीम में खनन कार्यों पर भी लागू होता है।

3.2.3 कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था, का एक रोचक इतिहास है। न तो खान अधिनियम, 1901 और न ही उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई सामान्य नियमावली, 1908 में भूमिगत कोयला खानों के जल से भरे कार्यस्थलों की ओर बढ़ते समय रखी जाने वाली किसी सावधानी का निर्धारण किया गया है। यहां तक कि खान अधिनियम, 1901 के स्थान पर खान अधिनियम, 1923 को प्रतिस्थापित किया गया तब भी इन सावधानियों की व्यवस्था नहीं की गई। 1936 में खान अधिनियम, 1923 में एक संशोधन करके खानों में पानी भरने का इकट्ठा होने और उसके कारण उत्पन्न होने वाले खतरे के विरुद्ध विनियम बनाने के लिये केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार खान अधिनियम 1923 के अन्तर्गत बनाये गये भारतीय कोयला खान विनियम, 1926 (आई सी एम आर 1926) में 1936 के बाद पहली बार जलप्लावित या अप्रयुक्त कार्यस्थलों के 100 फीट (30 मीटर) के क्षेत्र में खनन करते समय बरती जाने वाली सावधानी का निर्धारण किया गया है। सावधानियों में गली की चौड़ाई और ऊंचाई को 8 फीट (2.4 मीटर) तक सीमित रखना तथा कार्यस्थल पर केन्द्रीय बोरहोल और दोनों तरफ पर्याप्त फ्लैंक बोरहोल्स और जहां आवश्यक हो अधिक से अधिक 15 फीट (4.5 मीटर) के अन्तराल पर कार्यस्थल के ऊपर और नीचे बोरहोल्स की व्यवस्था करना। यह भी निर्धारित किया गया है कि खनन करते हुए आगे बढ़ने में इन बोरहोल्स को पर्याप्त दूरी पर रखा जाना चाहिये और यह दूरी किसी भी हालत में 10 फीट (3 मीटर) से कम नहीं होना चाहिए। 1951 में मध्य प्रदेश की एक कोयला खान में जलप्लावन के कारण हुए विनाश जिसमें 63 खनकों की मृत्यु

हो गई थी तथा कोयला खान (अस्थायी) विनियम, 1955 के फलस्वरूप जलप्लावित स्थलों के निकट काम करने के प्रतिबंधों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। संशोधित विनियमों में दूरी के बारे में सांविधिक प्रतिबंध जिसके लिये खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमति अपेक्षित है 100 फीट (30 मीटर) से बढ़ाकर 150 फीट (45 मीटर) कर दी गई है। कोयला खान विनियम, 1957 द्वारा आई.सी.एम.आर, 1926 और कोयला खान (अस्थायी) विनियमन, 1955 को समाप्त कर दिया गया है। भूमिगत पानी के जमाव के खतरे को रोकने के लिये कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 में प्रावधान किये गये हैं। तथापि सांविधिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र को 45 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर कर दिया गया। दिसम्बर, 1975 की चासनाला खान दुर्घटना, जिसमें 375 खनिकों की मृत्यु हो गई थी, के बाद कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम, 127 में व्यापक संशोधन किये गये थे। इनमें से कुछ संशोधन इस प्रकार हैं।

(क) जलप्लावित कार्यस्थलों के 60 मीटर के अंदर कार्य अनुमति के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक को प्रस्तुत आवेदन के साथ योजनाओं और उन खण्डों की प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दिखाया गया हो— सभी अनुपयुक्त और परित्यक्त कार्यस्थलों के समीप के कार्यस्थलों से संबंधित इसकी रूपरेखा अनुमति में चिह्नित प्रस्तावित कार्यस्थल की रूपरेखा, बाधा और पद्धति, फाल्ट, डाइक्स और अन्य भू-वैज्ञानिक गड़बड़ियां और प्रबंधन के पास उपलब्ध अन्य सूचनायें तथा खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा अपेक्षित किसी अन्य बात के बारे में सूचना।

(ख) जब खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा अनुमति प्राप्त हो जाती है तो अनुमति में निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत ही प्लान और पद्धति होनी चाहिये और इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिये बशर्ते कि किसी ऐसे अंतर के निर्माण के लिये खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा पुनः अनुमति न दी गई हो।

(ग) यह भी आवश्यक है कि ऐसे कार्यस्थलों की गहरी लंबाई और चौड़ाई, बनाये गये बोर होल, प्रत्येक बोर होल की लंबाई का रिकार्ड इस उद्देश्य के लिये रखी गई एक जिल्दबंद किताब में रखा जाये और इसमें दर्ज की गई प्रविष्टियों पर प्रतिदिन इस उद्देश्य के लिये नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और प्रबंधक द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाए।

(घ) किसी भूमिगत कोयला खान के कार्य क्षेत्र में किसी भी स्थल पर जब ज्यादा पानी के रिसाव की घटना हो तो तत्काल काम बंद करने के प्रावधानों में जलप्लावित क्षेत्र के 60 मीटर के भीतर के कार्यक्षेत्र भी शामिल हैं।

(ङ) तथापि कोयला खान विनियम, 1957 का विनियम 127 को अधिक लचीला भी बनाया गया है क्योंकि इसमें खान सुरक्षा महानिदेशक को ये शक्तियां दी गई हैं कि यदि वे उचित समझें तो गैलरी के आकार के प्रतिबन्धों में ढील दे सकते हैं और एडवांस बोरहोल बनाने की शर्तों में छूट प्रदान कर सकते हैं।

3.2.3 1983 में जलप्लावन के कारण हुरिलाडीह दुर्घटना जिसमें 19 खनिकों की मृत्यु हुई और जलप्लावित क्षेत्रों के समीप कार्य करने से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए विनियम 127 को पुनः 1990 में संशोधित किया गया था। इसमें अनुपयुक्त और परित्यक्त कार्यस्थल के बीच अंतर समाप्त करने के लिये विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। यहाँ जलप्लावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये होल ड्रिल करने तथा उनकी जांच तथा बाकी कार्यक्षेत्रों ... में भी बताया गया है।

3.3.1 इस स्थिति में यहाँ जलप्लावित क्षेत्रों के समीप कार्य करने से संबंधित विकसित देशों के भूमिगत कोयला खानों के सांविधिक प्रावधानों की समीक्षा करना संगत होगा। प्रायः, सभी देश जलप्लावित क्षेत्रों के समीप कार्य करते समय कुछ सांविधिक प्रतिबंध लगाते हैं। जलप्लावित क्षेत्रों और कार्यस्थलों के बीच सुरक्षा पिलर/बैरियर छोड़ने के रूप में ये प्रतिबंध लगाये जाते हैं। सुरक्षा पिलर के भीतर कुछ प्रतिबंधों के अधीन ही एक निश्चित सीमा में काम करने की अनुमति दी जाती है। प्रायः इन प्रतिबंधों की प्रकृति में गली की चौड़ाई और ऊंचाई सीमित करना तथा एडवांस बोरहोल के कवर के अन्तर्गत कार्यक्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाना शामिल है।

3.3.2 संयुक्त राष्ट्र फेडरल कानून में यह विनिर्दिष्ट है कि यदि पुराने भूमिगत कार्यक्षेत्रों का कोई विश्वसनीय प्लान उपलब्ध नहीं है तो जलप्लावन के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ऐसे कार्यस्थलों के 60 मीटर के भीतर एडवांस बोरहोलों का प्रावधान किया जाना होता है।

इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र का कानून कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 127 की ही तरह का है।

3.3.3 फ्रांस की कोयला खानों के विनियमन में पानी भर जाने के खतरों के विरुद्ध कार्यक्षेत्रों की सुरक्षा अपेक्षित होती है। इसमें यह भी अपेक्षित है कि पानी भर जाने की संभावना वाले क्षेत्रों, गलियों या आगे बढ़ाये जाने वाले क्षेत्रों के पहले करीब 3 मीटर लंबा अग्रवर्ती बोरहोल बनाया जाये।

3.3.4 ब्रिटन के कोयला खान विनियमों में यह अपेक्षित है कि जब किसी खान के किसी अनुपयुक्त कार्यक्षेत्र के 45 मीटर भीतर कोई कार्य किया जा रहा है तो प्रबंधक आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों का प्रबंध करता है इसमें निरीक्षकों तथा कर्मकारों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में पूर्व सूचना देना शामिल है, इसके अलावा इसमें ऐसे कार्यक्षेत्रों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया योजना भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी या किसी अन्य द्रव पदार्थ का अंदर की तरफ बहाव न हो।

3.3.5 भूमिगत पानी के खतरों से संबंधित विभिन्न देशों के उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों की समीक्षा से यह पता चलता है कि हमारे सांविधिक सुरक्षा उपाय संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटन जैसे विकसित देशों के बराबर हैं।

अध्याय-4

आप्लावन के कारण दुर्घटनाएं

4.1 भारत में आप्लावन के कारण दुर्घटनाओं का सामान्य विश्लेषण

4.2 भारत में आप्लावन के कारण प्रमुख दुर्घटनाएं।

4.1.1 हमारे देश की कोयला खानों में दुर्घटनाओं में एक तिहाई व्यक्तियों की मृत्यु आप्लावन के कारण होती है। आप्लावन के कारण प्रमुख विपदाएं 10 दिसम्बर, 1954 को न्यूटन चिकली कोलियरी (मध्य प्रदेश), 20 फरवरी, 1958 को सैन्ट्रल भोवरा कोलियरी (बिहार), 05 जनवरी, 1960 को दमुआ कोलियरी (मध्य प्रदेश), 18 नवम्बर, 1975 को सिलेवरा कोलियरी (मध्य प्रदेश), 27 दिसम्बर, 1975 को चासनाला कोलियरी (बिहार) तथा 14 सितम्बर, 1983 को हुरीलाडीह कोलियरी (बिहार) में हुई जिनमें क्रमशः 63, 23, 16, 10, 375 तथा 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

4.2.1 दिसम्बर, 1954 में न्यूटन चिकली कोलियरी (मध्य प्रदेश) में दुर्घटना इस प्रकार हुई क्योंकि डिवलपमेंट गैलरी किसी पुरानी गैलरी तथा ऊपरी सीम की परित्यक्त जलप्लावित वर्किंग से जुड़ गई।

दो सीमा के बीच पृथक्करण जैसे अपथ्रोफाल्ट (ऊपर की ओर फैंकने की खराबी) के कारण उस क्षेत्र में ऊपरी सीम के बराबर के स्तर के निचली सीम को लाया गया। यह दुर्घटना मुख्यतः गलत खान योजना और भारतीय कोल खान विनियमन 1926 के विनियमन 74, जिसे कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियमन 127 के द्वारा निरसित कर दिया गया था, का अनुपालन न किए जाने के कारण हुई। फरवरी, 1958 में सेन्ट्रल भोवरा कोलियरी (बिहार) में आप्लावन के कारण दुर्घटना उस समय हुई जबकि भूमिगत प्रचालन खान सीमा को पार कर गया तथा यह समीपवर्ती कोलियरी के जलाप्लावित प्रचालन में जा मिला। यह दुर्घटना मुख्यतः बिना उचित सर्वेक्षण तथा उचित योजनाओं के समीपवर्ती कोलियरी में अनधिकार प्रवेश तथा जलाप्लावित क्षेत्रों के 60 मी. के अन्दर बढ़ते हुए प्रचालन के सम्बन्ध में कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियमन 127(3) और (5) के उल्लंघन के कारण हुई। जनवरी, 1960 में दमुआ कोलियरी (मध्य प्रदेश) में दुर्घटना उस समय हुई जबकि प्रचालन अपथ्रोफाल्ट के कारण जलाप्लावित क्षेत्र की ओर बढ़ गया। खराबी वाले क्षेत्र में दो प्रचालनों के बीच 1.8 मी. का अवरोध से दुर्घटना को बढ़ावा मिला।

4.2.2 भारतीय खनन इतिहास में सबसे अधिक घातक दुर्घटना दिसम्बर, 1975 में चासनाला (बिहार) में हुई जिसमें आप्लावन के कारण 325 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। चासनाला में पूर्व प्रचालन ने लगभग वर्ष 1949 में संचालन क्रास-आऊट निकालने समय पुराने प्रचालनों से असावधानी पूर्वक जुड़ने के कारण दिसम्बर, 1975 में दुर्घटना होने से लगभग 26 वर्ष पहले काम करना बन्द कर दिया था।

4.2.3 चासनाला में हुई दुर्घटना के कुछ प्वाइंट वही हैं जो अब हुई दुर्घटना के हैं। दोनों मामलों में ऊपरी पुराने जलाप्लावित प्रचालनों से आप्लावन हुआ तथा तत्काल इसके बाद धसकन हो गई। चासनाला कोलियरी के मामले में, सीम के साथ-साथ चलने वाली मुख्य इन्कलाई की लम्बाई प्लान में इसकी वास्तविक लम्बाई से बहुत कम दिखाई गई थी। महावीर खान के मामले में कलेपाकर पुरानी तथा परित्यक्त शाफ्ट को प्लान में निचली सीम तक बढ़ा हुआ नहीं दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों मामलों में सम्बन्धित प्रबंधकों ने खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा प्रचालन के लिए अनुमोदित न किए गए क्षेत्र में काम किया तथा उन्होंने कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियमन 127 का उल्लंघन किया। सितम्बर, 1983 में हुरीलाडीह कोलियरी (बिहार) में दुर्घटना उस समय हुई जबकि दो अलग अलग समतल रेखाओं में मोटी सीम के विकसित होने से बनी कोयले की पतली सतह अचानक ढह गई। ऊपरी समतल रेखा जो [illegible] का एक भाग थी के प्रचालन से पानी निचली समतल रेखा की ओर बह गया जिससे 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना मुख्यतः गलत योजना तथा कोयला खान विनियमन 1957 के विनियमन 127 के उल्लंघन के कारण हुई।

4.2.4 इन दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण से पता चलेगा कि ये दुर्घटनाएं मुख्यतः गलत खान योजनाओं तथा कोल खान विनियमन 1957 के विनियमन 127 के उल्लंघन आदि के कारण हुईं। दूसरे शब्दों में, ये दुर्घटनाएं ऐसी आपराधिक लापरवाही के कारण हुईं जिनसे बचा जा सकता था।

अध्याय—5

5.1 दुर्घटना

5.2 गुमशुदा व्यक्तियों की पड़ताल करना

5.3 बचाव कार्य

5.1.1 इस स्थिति में यह संगत होगा कि उन घटनाओं के क्रम की पुनरीक्षा की जाए जिनके कारण दुर्घटना हुई। ज्ञात है कि 12 नवम्बर, 1989 को तीसरी पारी में कार्य सामान्य की तरह प्रारम्भ हुआ। नारायण कुडी सीम में तीन प्रचालन भाग अर्थात् "बी" पिट डीपिलरिंग भाग, 21 क्रास कट और 42 क्रास कट डिवेलपमेंट भाग थे। इन सभी में कोयला के [illegible] भूमिगत प्रचालनों में 221 [illegible] नियोजित थे।

5.1.2 समस्त प्रचालन का ओवरमैन प्रभारी श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू-1) था। 42 क्रास कट डेवलपमेंट भाग, जहां दुर्घटना हुई, का सरदार तथा शाटफायरर क्रमशः श्री दौलत पाण्डे (एम डब्ल्यू-13) तथा श्री चन्द्रधारी बराय (एम डब्ल्यू-14) था।

5.1.3 पारी की शुरुआत में, 42 क्रास-कट भाग के 40 डिप फेस में बारह शाट छेद ड्रिल किए गए। इन शाट छेदों की लम्बाई लगभग 1.2 मी. थी। कोयला कटिंग मशीन खराब होने के कारण फेस पर कोई अन्डरकट नहीं थी।

5.1.4 शॉट फायरर श्री चन्द्रधारी बराई (एम डब्ल्यू-14) के साथ श्री बांगी राजभर (यू डब्ल्यू-5) श्री राम अवतार खुसिया, श्री टहुला मांझी और श्री प्यारे चन्द्र शाह हैल्पर थे इस भाग के अन्य फेसों में शाट फायरिंग पूरी करने के बाद, वे लगभग प्रातः 4.00 बजे 40 डिप फेस पर पहुंचे। श्री चन्द्रधारी बराय (एम डब्ल्यू-14) ने साक्ष्य दिया कि उसने फेस में ड्रिल किए गए बारह शॉट होल में से छह को चार्ज किया। इनमें से चार शॉट होल फ्लोर स्तर के थे और शेष दो गैलरी के लगभग मध्य में "कट होल" थे। तथापि श्री बांगी राजभर (यू डब्ल्यू-5) के अनुसार सभी बारह शाट होल को फेस में एक ही समय में चार्ज किया गया। पी. डिटोनेटरों तथा तात्कालिक विद्युत अग्रिक विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया। इसके बाद श्री चन्द्रधारी बराय (एम डब्ल्यू-14) द्वारा छह शॉट होल विस्फोटित किए गए। धुआं तथा भाप हट जाने के बाद वे शेष शॉट होल को चार्ज करने के लिए फेस तक वापिस गए जबकि श्री बांगी राजभर (यू. डब्ल्यू-5) का कहना है कि वे किए शेष छह शॉट होल को जोड़ने गए। जब श्री बांगी राजभर (यू. डब्ल्यू-5) तड़के हुए कोयले के नीचे से शॉट फायरिंग केबल बाहर निकाल रहा था। तो श्री चन्द्रधारी बराय (एम डब्ल्यू-14) को सामने वाले फेस तथा अपने पीछे से ब्रेक होने की आवाज सुनाई दी। इसके तत्काल बाद उन्होंने फेस के दाहिनी तरफ से गंदा पानी फुहार की तरह बहता देखा, श्री बांगी राजभर (यू डब्ल्यू-5) को अपना काम छोड़ना पड़ा। श्री चन्द्रधारी बराय (एम डब्ल्यू-14) ने श्री बांगी राजभर (यू डब्ल्यू-5) को बाहर निकाला, अपने साथियों तथा औजारों को इकट्ठा किया और पानी के अकस्मात अन्तर्वाह की चेतावनी देता हुआ फेस से बाहर दौड़ा। रास्ते में, श्री चन्द्रधारी बराय (एम डब्ल्यू-14) को भाग के हालेज के निकट श्री दौलत पाण्डे (एम डब्ल्यू-13) मिला तथा उसने उसको पानी के अचानक अन्तर्वाह के बारे में बताया। श्री दौलत पाण्डे (एम डब्ल्यू-13) ने उसको उस भाग के सभी व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए कहा तथा उसने पानी के अन्तर्वाह के बारे में 21 क्रास कट भाग के कर्मकारों को सूचना दिया। श्री दौलत पाण्डे ने 40 डिप फेस पानी के अचानक अन्तर्वाह के बारे में लगभग प्रातः 4.30 बजे सी डी एम टेलीफोन पर श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू-1) को बताया। श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू-1) ने पिट टॉप पर हाजिरी केबिन से 21 डेवलपमेंट भाग [illegible] पर सी डी एम टेलीफोन पर तत्काल सम्पर्क किया परन्तु वहां से कोई उत्तर नहीं था। दुर्घटना की सूचना प्रबंधक एवं प्रबन्धक श्री. [illegible] (एम डब्ल्यू-17) को भेज दी गई। फिर उसने सी.डी.एम. टेलीफोन पर सुरक्षा अधिकारी श्री पी एन बनर्जी को दुर्घटना की सूचना दी। इसके पश्चात् उसने हाजिरी केबिन से "बी" पिट डीपिलरिंग भाग के सरदार श्री रामचन्द्र महतो से टेलीफोन पर सम्पर्क किया। उसने श्री रामचन्द्र महतो को "बी" पिट भाग से सभी व्यक्तियों को बाहर निकालने तथा भूमिगत सभी व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए अन्य भागों को सूचित करने के अनुदेश दिए। उसने सी डी एम आपरेटर को भी निदेश दिए कि वह सी डी एम में उपलब्ध माइक्रोफोन सुविधा से भूमिगत सभी व्यक्तियों को चेतावनी दे तथा उन्हें बाहर जाने के निदेश दे। श्री दौलत पाण्डे (एम डब्ल्यू-13) और श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू-1) ने 21 क्रास कट सेक्शन की ओर जाने की कोशिश की परन्तु पानी वहां

भी पहुंच गया। चूंकि ये कर्मचारी के बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते थे वे पिट सतह की ओर दौड़े जहां वे श्री पी.एल. बनर्जी (एम डब्ल्यू-16) से मिले। श्री पी.एल. बनर्जी (एम डब्ल्यू-16) के साथ श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू-1) तथा श्री बौदन पाण्डे (एम डब्ल्यू-13) सैक्शन की ओर वापिस आये। तथापि, 8 लेवल के निकट उन्होंने देखा कि पानी उत्स्रावन की ओर से बह रहा है। फिर श्री पी.एल. बनर्जी (एम डब्ल्यू-16) दो पिट की ओर गए और श्री बौदन पाण्डे (एम डब्ल्यू-13) तथा श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू-1) सं. "ए" पिट की ओर आये। इस आशंका से कि स्थिति बदतर न हो जाए वे तत्काल बाहर आ गए। पिट के बाहर वे मो. कालिम, अभिकर्ता एवं प्रबन्धक (एम. डब्ल्यू-17) से मिले। श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू-1) दोबारा सं. "ए" पिट के मध्य से श्री बौदन पाण्डे (एम डब्ल्यू-13) आक्रामक तथा मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) के साथ भूमि के नीचे गए। परन्तु उन्होंने देखा कि पिट की सतह से ही पानी लगभग सीने तक पहुंच गया है। यह महसूस करते हुए कि पिटों के माध्यम से कर्मकारों को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है, वे लगभग प्रातः 5.30 बजे बाहर वापिस आ गए।

5.2.1 चूंकि कुछ कर्मकारों की शिफ्ट के मध्य में नारायणकुरी सीम से नेगा सीम आने की संभावना थी, श्री पी. एल. बैनर्जी (एम डब्ल्यू-16) अन्यों के साथ नेगा सीम के समीपस्थ यूनिट के निमज्जन ड्रोन से नीचे गए। तथापि उन्होंने वहां नेगा सीम के केवल दो पम्प खलासियों को पाया जो बाहर ले जाये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

5.2.2 हाजिरी रजिस्टर की तत्काल जांच करने से पता लगा कि खान के नीचे 221 कर्मकार गए थे, जिनमें से 150 कर्मकार बाहर आ चुके थे और शेष 71 कर्मकार के बारे में यह अनुमान था कि वे भूमि के नीचे फंस गए। फंसे हुए खनिकों में से अधिकतम 21 क्रास कट भाग के थे और शेष 42 क्रास कट भाग के थे। सौभाग्य से सी.डी. एस टेलीफोन के द्वारा फंसे हुए खनिकों के दो ग्रुपों से शीघ्र सम्पर्क हो गया। फंसे हुए खनिकों ने बताया कि वे पानी के बहाव के कारण, जिससे उनका पहुंच रास्ता बन्द हो गया है, पिट की सतह पर पहुंचने में असमर्थ हैं।

फंसे हुए खनिकों की गिनती करने तथा शीघ्र ही बाहर आ जाने वाले खनिकों की गिनती से पता चला कि पैंसठ खनिक भूमि के नीचे फंस गए थे। अतः छह खनिकों के लापता होने की आशंका थी। बाद में, पैंसठ फंसे हुए खनिकों को सी डी एस टेलीफोन से निर्देश दिए गए कि वे उत्स्रावन की ओर जाएं क्योंकि बरमाछिद्र के माध्यम से बाहर से उनके साथ सीधे सम्पर्क करने के प्रयास किए जाएंगे। यह बताना संगत होगा कि आप्लावन की स्थिति में भी सी डी एस टेलीफोन की कारगरता से प्रारम्भिक अवस्थाओं में बचाव कार्य में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

5.3.1 13 नवम्बर को लगभग प्रातः 10.00 बजे, खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा मैसर्स ई.सी.एल. के वरिष्ठ अधिकारी महाबीर खान पर पहुंचे। यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि दुर्घटना नारायणकुरी सीम के पुरानी तथा जलाप्लावित शाफ्ट सं. 34 से जुड़ने कारण हुई थी तथा उत्स्रावन की ओर वर्किंग्स पानी रहित रहेंगी जहां फंसे हुए खनिज आश्रय ले सकेंगे। यह भी पता चला कि नेगा सीम के शल्क वृष्यांश (आउट क्रोप) के पीछे नारायणकुरी सीम में उत्स्रावन की ओर पहले ड्रिल किए गए कुछ अन्वेषणात्मक छेदों से वास्तव में वर्किंग्स में बाधा आ गयी थी। इस प्रकार यह महसूस किया गया कि बरमाछिद्र के माध्यम से फंसे हुए खनिकों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता था। फंसे हुए खनिकों के वातावरण के बारे में मोटे तौर पर अनुमान था कि उनके लिए लगभग दो सप्ताह तक सामान्य वातावरण अच्छा रहेगा। अतः यह महसूस किया गया कि फंसे हुए खनिकों को आसन्न खतरा नहीं था।

5.3.2 आपात स्थिति के लिए एक ड्रिलिंग रिग लाया गया तथा सर्वाधिक दल द्वारा शीघ्र ही तैयार किए गए मौजूदा बरमा छिद्र सं. 3 का व्यास 14 नवम्बर को प्रातः 2.30 बजे तक चौड़ा करके 20 सें.मी. कर दिया गया। सी डी एस टेलीफोन से फंसे हुए खनिकों को सं. 3 बरमा छिद्र के नीचे एकत्र होने के निदेश दिए गए। पूर्ण सम्पर्क तथा बरमा छिद्र के माध्यम से स्थापित की गई संचार व्यवस्था और इसके चारों ओर फंसे हुए खनिकों के सुरक्षित होने से खनिकों के सुरक्षित बचाव की चिन्ता जो पहले बनी हुई थी वह कम हो गयी।

5.3.3 फंसे हुए खनिकों के बचाव के लिए एक बड़े व्यास का बरमा छिद्र ड्रिल करने के लिए उत्स्रावन की ओर बाहर तत्काल एक उपयुक्त स्थान का चयन किया गया। 14 नवम्बर को प्रातः 9.30 बजे प्रचालन कार्य आरम्भ किया गया तथा 15 नवम्बर को लगभग दोपहर के 3.30 बजे 52 सें.मी. व्यास का बरमा छिद्र पूरा कर दिया गया। जर्मनी डिजाइन पर आधारित कब्जेदार दरवाजों सहित एक स्टील कैप्सूल स्वदेशी रूप से तैयार की गई। एक अस्थाई तिपाई का निर्माण किया गया और घिरनी स्थापित की गई तथा घिरनी प्रचालित (कैप्सूल) के माध्यम से मैसर्स ई.सी. एल. के अतिरिक्त मुख्य खनन इंजीनियर, श्री जी.एस. गिल, जो बचाव कार्य में प्रशिक्षित थे, को 16 नवम्बर को लगभग प्रातः 2.20 बजे भूमिगत वर्किंग्स पर उतारा गया चूंकि हस्तचालित घिरनी से फंसे हुए खनिकों को बाहर लाने में समय लग रहा था, कुछ खनिकों को बचाने के बाद इसे क्रेन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। फंसे हुए पहले खनिक को 16 नवम्बर को प्रातः 2.40 बजे तथा अन्तिम खनिक को उसी दिन प्रातः 8.40 बजे बाहर लाया गया। बचाव की इस प्रणाली का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर ऐसी बचाव प्रणाली का प्रयोग विश्व में नहीं किया गया था। इस बचाव क्रिया का संचार माध्यम से काफी प्रचार हुआ।

5.3.4 इसके बाद, छः लापता व्यक्तियों की तलाश शुरू की गई। तलाशी दलों को कैप्सूल के माध्यम से भेजा गया तथा 18 नवम्बर को प्रातः तक दिन और रात तलाश जारी रही। इसके पश्चात्, बरमा छिद्र के माध्यम से तलाशी दलों को भेजना रोक दिया गया क्योंकि बरमा छिद्र के अरेखांकित भाग से फिसलन के संकेत मिले। तदोपरान्त, पिटों को पानी रहित कर दिया जाने पर, छह लापता खनिकों की तलाश जारी रखी गई। दुर्भाग्यवश इन छह खनिकों को जीवित नहीं बचाया जा सका। एक के बाद एक उनकी लाश पाई गई। अन्तिम लाश 23 दिसम्बर, 1989 को काफी प्रयासों के बाद मिली।

अध्याय-VI

6.1 दुर्घटना स्थल का प्रथम निरीक्षण

6.2 सतही निरीक्षण

6.3 द्वितीय निरीक्षण

6.4 टिप्पणियां

6.1.1 7 अप्रैल, 1991 को मैं दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए महाबीर खान गया। निरीक्षण के दौरान प्रो. ए.के. घोष, मूल्यांकनकर्ता (असेसर), श्री के. पाल, खान सुरक्षा महानिदेशक, श्री टी.के. देव, निदेशक (तकनीकी), मैसर्स ई.सी.एल. तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय और मैसर्स ई सी.एल. के अन्य अधिकारी भी मेरे साथ थे। श्री बी.एन. तिवारी मूल्यांकनकर्ता उपस्थित नहीं हो सके। हम ए पिट के रास्ते से नारायणकुरी सीम तक नीचे गए तथा दिल्ली से हावड़ा तक ईस्टर्न रेलवे लाइन के नीचे ... रेल गेट। रास्ते में मैंने पानी के अन्तर्वाह से हुए विनाश को देखा जिससे हॉलेज पथ के कंक्रीट तथा पैकिंग सामग्री हट कर ... लेवल ... हो गई थी। मुझे वह स्थान भी दिखाया गया जहां से ... में से कुछ लाशें मिली थीं। 33 लेवल पर मैंने भूमिगत टेलीफोन पद्धति (अर्थात् सी.डी. एस. पद्धति) का रिसीवर देखा जिसका प्रयोग फंसे हुए खनिकों द्वारा बाहर आपरेटर से सम्पर्क करने के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट

में मैंने पहले बताया है कि सी.बी.एम. पद्धति के कारगर रूप से कार्य किया तथा इसमें सफलता पूर्वक बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

6.1.2 33 पूर्वी लेवल ढुलाई सड़क के साथ चलते हुए, मैंने सवानन रोक (स्टापिंग) पर पानी द्वारा छोड़े गए निशान देखे। इससे मुझे मंजिला में हुए पानी के बहाव के अधिकतम स्तर का काफी अंदाजा हो गया। 40 डिप आफ 28 लेवल के जंक्शन के चारों ओर, मैंने फर्श पर पड़े पत्थर के दो बड़े ब्लाक देखे। मैंने पानी के प्रवाह से मुड़ी हुई तथा टेढ़ी हुई ढुलाई पटरियों को भी देखा। 40 डिप के प्रवेश मार्ग के साथ-साथ चलते हुए, मुझे स्पष्टतः महसूस हुआ कि 40 डिप पर गैलरी अपनी सामान्य उत्तर पूर्वी दिशा से अकस्मात विचलित हो कर लगभग दक्षिण की ओर हो गई जिससे 40 डिप पुरानी शाफ्ट नं. 34 से जुड़ गई। ठीक उसी स्थान को गोलाश्म (बाउल्डर्स) तथा कंकरों से आच्छादित कर दिया गया जहां 40 डिप आफ 28 लेवल से पुरानी तथा परित्यक्त शाफ्ट सं. 34 का कार्य बन्द कर दिया था। 40 डिप ऑफ 28 लेवल के प्रवेश द्वार के पार चलते हुए मैंने उस गैलरी में फलेंक बरमा छिद्र का केवल एक निशान देखा। दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद में 29 लेवल के साथ-साथ समीपस्थ 39 डिप पर गया तथा 27 लेवल ऑफ 39 डिप पर की फलक (फेस) का निरीक्षण किया जहां से वर्ष 1988 में एक लम्बा बरमा छिद्र ड्रिल किया गया था। मैंने 27 लेवल पर गैलरी में ड्रिल किए गए फलेंक बरमा छिद्र देखे। मैंने 27 लेवल ऑफ 39 डिप पर पिल्लर की सतहों पर रिसाव जल के निशान भी देखे। फलेंक बरमा छिद्रों के नीचे थे। निशान सुस्पष्ट थे। मुझे दुर्घटना स्थल पर जाने तथा निरीक्षण करने में तीन घण्टे लगे।

6.2 8 अप्रैल, 1991 को मैं खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा ई.सी.एल. के कुछ अधिकारियों के साथ सतह पर परित्यक्त शाफ्ट सं. 33 और 34 का निरीक्षण करने गया। शाफ्टों के चारों ओर वन्य-पेड़ थे। निरीक्षण के दौरान, कुछ ग्रामीण लोगों ने मुझे बताया कि 13 नवम्बर 1989, को दुर्घटना से पहले सतह पर शाफ्ट सं. 33 और 34 दिखाई नहीं देती थी क्योंकि वे मिट्टी से ढकी हुई थी और इन पर वनस्पति उगाई गई थी। बाद में मैंने उस बरमा छिद्र के स्थल का निरीक्षण किया जहां से कैप्सूल द्वारा फंसे हुए खनिकों को निकाला गया था। रास्ते में मैंने सड़क पर पड़े गड्ढे (पोटहोल) को देखा जो शायद दुर्घटना के तत्काल बाद हो गया था।

6.3 7 अप्रैल, 1991 को किए गए प्रथम दौरे का उद्देश्य मुख्यतः दुर्घटना स्थल की दशाओं का प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन करना तथा 26 अक्तूबर, 1991 को किए गए दूसरे दौरे का उद्देश्य उन घटनाओं का पुनः प्रदर्शन करना था जिनके कारण दुर्घटना हुई। 26 अक्तूबर, 1991 को चन्द्रधारी यादव (एम डब्ल्यू 14) तथा भोला राजभर (यू. डब्ल्यू-5) ने उन घटनाओं के क्रम के बारे में पुनः बताया जिनके कारण 13 नवम्बर, 1989 की उस अभागी सुबह को 40 डिप फेस पर विस्फोट के बाद दुर्घटना हुई।

6.4.1 दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के आधार पर मेरी टिप्पणी निम्नानुसार है :—

(1) 40 डिप गैलरी ऑफ 28 लेवल के प्रवेश द्वार पर केवल एक फलेंक बरमा छिद्र के सिवाय, रिब साइडों के साथ किसी फलेंक बरमा छिद्र होने का कोई सबूत नहीं था। न्यायालय रिकार्ड के योजनार्थ द्वितीय निरीक्षण के दिन 40 डिप गैलरी तथा 27 के लेवल के फोटोग्राफ तैयार किए गये जो अनुबंध-III पर हैं।

(2) यद्यपि यह स्वीकार किया जा सकता था कि ऐसा सीम से पानी के अन्तर्वाह के कारण गैलरी की साइडों पर कुछ निक्षेपण था, लेकिन 40 डिप गैलरी के साथ किसी फलेंक बरमा छिद्र होने का ऐसा कोई संकेत प्रमाण नहीं था जिससे विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर फलेंकों बरमा छिद्रों की ड्रिलिंग के बारे में न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों पर अधिक संदेह होता हो।

(3) 40 डिप गैलरी के साथ दुर्घटना स्थल के निकट तथा 27 लेवल पर गैलरी की चौड़ाई को अनियमित रूप से मापा गया जिससे पता चला कि दुर्घटना से पहले गैलरी की चौड़ाई प्रारम्भ में लगभग 1.2 मी. थी।

(4) 28 लेवल तथा 40 डिप गैलरी के जंक्शन की सतह पर खाली स्थान था जहां से पत्थर का एक बड़ा ब्लाक खींचकर निकाला गया था और इसे 40 डिप गैलरी के उत्पलवन की ओर लगभग आधा किलकर खिसका गया था।

(5) 28 लेवल तथा 27 लेवल गैलरियों, जिनकी 27 लेवल तथा डिप के बीच कोयले की हल्की परत शामिल है, के साथ दुर्घटना स्थल पर, भू-खिसकन का ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था जिससे घातक दुर्घटना हो।

6.4.2 दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के आधार पर, मुझे प्रबंधकों के कुछ साक्षियों द्वारा दिए गए इस तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला है कि 8 नवम्बर, 1989 के बाद से 40 डिप गैलरी को चालित करते समय मध्य तथा फलेंक बरमा छिद्रों को कोयला खान वि. 1957 के विनियम 127 में दी गई शर्तों के अनुसार सुव्यवस्थित तरीके से ड्रिल किया जा रहा था। यह तर्क दिया जा सकता था कि मध्य बरमा छिद्रों का कोई सबूत नहीं होगा, क्योंकि कोयला निकालते समय वे नष्ट हो जाते थे परन्तु यदि 40 डिप ऑफ 28 लेवल पर फलेंक बरमा छिद्रों की व्यवस्था की जाती तो दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करते समय वे दिखाई देते। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 1988 में 27 लेवल पर फलेंक बरमा छिद्र किए गए थे। जब मैंने दुर्घटना स्थल के समीपस्थ क्षेत्र का निरीक्षण किया और 27 लेवल तक गया तो वे फलेंक बरमा छिद्र स्पष्टतः दिखाई दे रहे थे।

अध्याय-VII

7.1 न्यायालय के समक्ष मुद्दे

7.2 शाफ्ट संख्या 34 का विस्तार

7.3 पानी का असामान्य रिसाव

7.4 अग्रशोधक लम्बा बरमा छिद्र

7.5 प्रकटता (अधिकता) की अनुमति

7.6 पार्श्वीय बरमा छिद्र

7.7 दुर्घटना से संबंधित अन्य मामले

7.1.1 जैसाकि पहले बताया गया है कि दुर्घटना उस समय हुई जबकि विकसित 40 डिप फेस ऑफ 28 लेवल पुरानी तथा जलाप्लावित शाफ्ट सं. 34 से जुड़ गया। रिकार्ड किए गए साक्ष्यों तथा प्रस्तुत किए गए लिखित तर्कों के आधार पर जांच न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे थे :—

(1) क्या पुरानी तथा परित्यक्त शाफ्ट सं० 34 के नारायणकुड़ी सीम तक विस्तार की जानकारी महावीर खान के अभिकर्ता एवं प्रबंधक तथा उनके अधीन कार्यरत अन्य कर्मचारियों को थी और क्या शाफ्ट की गहराई का पता लगाने के लिये उन्होंने कर्तव्यपरायणता बरती।

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को पानी के असामान्य रिसाव की पूर्व चेतावनी दी गई थी जिससे पता चले कि वर्किंग जलाप्लावित। शाफ्ट संख्या 34 के नजदीक जा रही है।

(3) क्या उन कर्मचारियों का लम्बे बरमा छिद्रों की व्यवस्था करके समाधान हो गया था कि शाफ्ट सं. 39 का नारायणकुरी सीमा तक विस्तार नहीं हुआ है।

(4) क्या उक्त कर्मचारियों को 40 डिप गैलरी ऑफ 28 लेवल प्रचालित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय की प्रचालन अनुमति थी।

(5) क्या 40 डिप गैलरी ऑफ 28 लेवल को सड़क तथा पर्याप्त बरमा छिद्रों के उपयुक्त कवर से विकसित कर दिया गया था।

(6) और दुर्घटना से संबंधित अन्य मामले।

7.1.2 इन कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए इन मामलों का विश्लेषण बाद के पैराग्राफों में किया गया है जिनके कारण यह दुर्घटना हुई।

7.2.1 मो. कालिम, अभिकर्ता एवं प्रबंधक एम डब्ल्यू-17 (तथा तथा अन्यों का यह तर्क था कि उन्हें भरसक प्रयासों के बावजूद यह जानकारी नहीं थी कि शाफ्ट सं. 34 नेगा सीम से आगे बढ़ गई है। इसके दूसरी ओर कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों का आरोप था कि शाफ्ट सं. 34 के नेगा सीम से आगे बढ़ जाने का पता लगाने के लिए अभिकर्ता एवं प्रबंधक तथा अन्यों ने पर्याप्त प्रयास नहीं किए।

7.2.2 अभिकर्ता एवं प्रबंधक, मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा अन्य निम्नलिखित आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शाफ्ट सं. 34 नेगा सीम से आगे नहीं पहुंची थी :—

(1) श्री पी.एन. बैनर्जी, सुरक्षा अधिकारी (एम डब्ल्यू-16) ने बताया कि महावीर खान में लगभग एक सौ पुरानी शाफ्टें हैं और उनमें से कुछ शाफ्ट मलबे से भरी पड़ी हैं। शाफ्ट सं. 34 भी ऐसी भरी हुई एक शाफ्ट थी और यह सतह पर नजर नहीं आती थी। बहुत सी पुरानी शाफ्टों को खान के प्लान में दर्शाया गया था। सांविधिक प्लान एग्जीबिट एम-II में शाफ्ट सं. 34 को भी मलबे से भरा हुआ दर्शाया गया था। इसकी गहराई नहीं दी गई थी।

(2) पुरानी प्लानों में दर्शाई गई गहराई वाली सभी शाफ्टों से पता चला कि ये केवल नेगा सीम तक पहुंच गई थीं। कोई भी शाफ्ट ऐसी नहीं थी जो नीचे की नारायणकुरी सीम तक पहुंची हो।

(3) पुरानी शाफ्टों को पुराने प्लान अनुरेखित करके सांविधिक योजना एग्जीबिट एम-II में अंकित किया गया था। वर्ष 1976 में, महावीर खान के तत्कालीन सर्वेक्षक द्वारा एक जांच सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में उपलब्ध पुरानी शाफ्टों की गहराई मापी गई तथा उनकी अवस्थिति का भी सत्यापन किया गया। तथापि, एक भी पुरानी शाफ्ट ऐसी नहीं पाई गई जो नेगा सीम से आगे पहुंची हो। शाफ्ट सं. 34 सतह पर नजर नहीं आता था और सतही क्षेत्र पर एक निजी वनस्पति बगीचा था। चूंकि यह सतह पर नजर नहीं आती थी इसकी गहराई नहीं मापी जा सकी।

(4) वर्ष 1961 में नारायणकुरी सीम जलाप्लावित नेगा सीम के नीचे विकसित की गई थी और यह विकास भी कई पुरानी शाफ्टों के नीचे किया गया था। परन्तु इनमें से कोई भी शाफ्ट नारायणकुरी सीम तक बढ़ी हुई नहीं पाई गई।

(5) श्री पी.एन. ठाकुर (एम डब्ल्यू-15) तथा मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) के अनुसार कोई ऐसा दस्तावेज रिकार्ड उपलब्ध नहीं था जिससे पता चले कि शाफ्ट सं. 34 नारायणकुरी सीम तक बढ़ गई है। महावीर खान के पूर्व अभिकर्ता श्री के.के. दास (एम डब्ल्यू-18) के अनुसार आसपास के क्षेत्र को वर्ष 1926 की कैडेस्टर्ल प्लान तथा 1950 की रिवेन्यू प्लान में भी पुरानी शाफ्ट सं. 34 को नहीं दर्शाया गया।

(6) वर्ष 1925 की मैसर्स बंगाल कोल कम्पनी की रानीगंज कोलियरी और 2 रानीगंज सीम की परित्यक्त खान प्लान (ए.एम.पी.) (दस्तावेज एम/2ए) में शाफ्ट सं. 34 को समीपस्थ खान की सतह पर दर्शाया गया। ए.एम.पी. में शाफ्ट की गहराई 86 फुट (25.9 मी.) रिकार्ड की गई जिससे पता चला कि यह केवल नेगा सीम तक बढ़ी हुई है।

(7) मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) ने निरीक्षण से सतह पर शाफ्ट सं. 34 का पता लगाने का प्रयास किया परन्तु वह पता नहीं लगा सका क्योंकि शाफ्ट पूर्णतः भरी हुई थी और सतही भूमि का प्रयोग वनस्पति उगाने के लिए किया जाता था।

(8) वर्ष 1989 में, मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) को शाफ्ट सं. 34 की अनुमानित स्थिति की ओर नारायणकुरी सीम में 27 श्रृंखला 30 डिप से ड्रिल किया हुआ लगभग 40 मी. लम्बे बरमा छिद्र का पता चला तथापि, यह लम्बा बरमा छिद्र न तो शाफ्ट को छू रहा था और न ही बरमा छिद्र से पानी का कोई रिसाव था जिससे पता चलता कि शाफ्ट सं. 34 नारायणकुरी सीम तक बढ़ी हुई है।

7.2.3 तथापि, कर्मचारी यूनियनों का तर्क था कि मो. कालिम तथा अन्य खान अधिकारी स्थायी सतही विशेषताओं के सन्दर्भ में करके सतह पर शाफ्ट सं. 34 का पता लगा सकते थे। यूनियन के तर्क के अनुसार चूंकि मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) और अन्य अधिकारियों ने शाफ्ट सं. 34 के विस्तार का पता लगाने के लिए न तो ऐसा कोई सर्वेक्षण किया और न ही कोई विशेष प्रयास किए इसलिए वे कर्तव्य परायणता निभाने में असफल रहे जिससे दुर्घटना हुई।

7.2.4 जांच न्यायाधीश के रूप में मैंने दोनों पक्षकारों के उक्त तर्कों पर विचार किया। न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पता चले कि शाफ्ट सं. 34 सतह पर दिखाई देती थी। सतह पर शाफ्ट सं. 34 के मेरे निरीक्षण के दौरान मैं उस क्षेत्र में वन्य वनस्पति देखी जिसके बीच में कहीं कहीं वनस्पति बगीचे थे। मेरे निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीण लोगों ने भी मुझे बताया कि घातक दुर्घटना होने से पहले शाफ्ट सं. 34 सतह पर दिखाई नहीं देती थी।

7.2.5 अगला प्रश्न है कि क्या मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा अन्यों द्वारा उचित प्रयास किए जाने से सतह पर शाफ्ट सं. 34 का पता लगाया जा सकता था। यह माना गया है कि पुरानी योजनाओं से अनुरेखण तथा पुनः अनुरेखण के कारण और सर्वेक्षण की अयथार्थता के कारण प्लान में दर्शाई गई शाफ्ट सं. 34 की स्थिति में गलती होने की संभावना है। चूंकि महावीर खान का सतही क्षेत्र विस्तृत था और उस में कृषि योग्य तथा बंजर भूमि थी, जिसकी कोई प्रमुख सतही विशेषता नहीं थी, इसलिए मिट्टी की असमान परत के नीचे दबी हुई केवल 3 मी. व्यास की शाफ्ट का पता लगाना बहुत आसान न रहा हो। समस्या तभी समझी जा सकती है जब यह देखा जाए कि महावीर खान के छह वर्ग कि. मी. सतही क्षेत्र पर 36 से अधिक भरी हुई शाफ्टें हैं। अतः मेरा विचार है कि सतह पर भरी हुई शाफ्ट सं. 34 का पता लगाना अभिकर्ता एवं प्रबंधक, मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा अन्यों के लिए वास्तव में संभव नहीं था।

7.2.6 मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा अन्य व्यक्तियों ने शाफ्ट सं. 34 की गहराई के संबंध में ए एम पी (दस्तावेज एम/2ए) पर अधिक निर्भर किया परन्तु ए एम पी (दस्तावेज एम/2ए) समीपस्थ 1 व 2 पिट वर्किंग्स का था और न कि शाफ्ट सं. 34 से की गई वर्किंग का ए एम पी (दस्तावेज एम/2ए) में, शाफ्ट सं. 34 को केवल समीपस्थ खान की सतही विशेषता के रूप में दिखाया गया था। दूसरे ए एम पी (दस्तावेज

एम/2ए) में यह रिकार्ड किया गया था कि "पुरानी पिट सं. 34 गहराई 86 फुट करीब करीब स्थिति पुरानी योजना में दी गई। इस प्रकार, ऐसी ए एम पी (दस्तावेज एम/2ए) के आधार पर मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) को पुरानी शाफ्ट सं. 34 तथा इसके केवल नेगा सीम तक विस्तार को अनुमानित स्थिति स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। कोयला खानों में लगभग 28 वर्ष के अनुभव से मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) को इसकी जानकारी अवश्य थी कि गलत प्लान के कारण कोयला खानों में आप्लावन के कारण पहले कई दुर्घटना हुई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उसे तथा सुरक्षा अधिकारी, श्री पी एल बैनर्जी, (एम डब्ल्यू-16) को ए एम पी (दस्तावेज एम/2ए) के आधार पर शाफ्ट सं. 34 के नेगा सीम से आगे न बढ़ने के बारे में आश्वस्त नहीं होना चाहिए था।

7.2.7 जलप्लावित नेगा सीम के नीचे नारायणकुरी सीम को विकसित करने की अनुमति देते समय, खान सुरक्षा महानिदेशक ने पूर्व बरमा छिद्रों की व्यवस्था शामिल की थी यद्यपि प्रासंगिक अनुमति के लिए आवेदन करते समय तत्कालीन अभिकर्ता ने ऐसे बरमा छिद्रों के बारे में छूट की मांग की थी। स्पष्टतः खान सुरक्षा महानिदेशक को नारायणकुरी सीम में पुरानी वर्किंग्स की संभावना की आशंका थी और ए एम पी (दस्तावेज एम/2ए) पर विश्वास नहीं था यह एक और कारण था कि मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा श्री पी. एल बैनर्जी को बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए था क्योंकि 40 डिप ऑफ 28 लेवल ऐसा स्थान था जहां पुरानी शॉफ्ट सं. 34 के होने की संभावना थी। यह सच है कि योजना (दस्तावेज एम/XI) में दी गई पुरानी शॉफ्ट सं. 34 की ओर 27 लेवल फेस से एक लम्बा बरमा छिद्र ड्रिल किया गया यद्यपि बरमा छिद्र ने इसे अन्तर्रोधित नहीं किया। परन्तु यह निर्णायक साक्ष्य नहीं हो सकता था कि शॉफ्ट सं. 34 नारायणकुरी सीम तक बढ़ी हुई नहीं थी। इस बात की काफी संभावना है कि लम्बा बरमा छिद्र केवल 3 मी. व्यास की शॉफ्ट को अन्तर्रोधित न कर सके जैसा कि इस मामले में हुआ। मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा श्री पी. एल बैनर्जी (एम डब्ल्यू 16) को इतना अनुभव अवश्य था कि उनको इस बात की जानकारी थी।

7.2.8 दुर्घटना स्थल की योजना (दस्तावेज एम/12) से पता चलता है कि शॉफ्ट सं. 34 को वर्किंग प्लान (दस्तावेज एम/11) पर दी गई स्थिति 6.5. मी. दक्षिण पश्चिम में शिफ्ट हो गई। इस प्रकार अभिकर्ता एवं प्रबंधक मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा श्री पी एल बैनर्जी, सुरक्षा अधिकारी (एम डब्ल्यू-16) ने एकल लम्बे बरमा छिद्र द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों पर निर्भर रह कर गलती की कि शॉफ्ट सं. 34 नारायणकुरी सीम तक बढ़ी नहीं है।

7.2.9 अब एक प्रश्न उठता है कि कब और कैसे से शॉफ्ट सतह पर दिखाई दी। 13 नवम्बर, 1989 की प्रातः को दुर्घटना होने के शीघ्र बाद भरी हुई शॉफ्ट सं. 34 सतह पर दिखाई दी। थोड़ी देर बाद शॉफ्ट सं. 34 के निकट सतह पर धसकन तथा गड्ढे हो गए। इस बात की काफी संभावना है कि जब पानी नेगा सीम से निकल कर नारायणकुरी सीम की ओर बहने लगा तो पलस्तर जिससे शॉफ्ट भरी हुई थी, खुल गया और सतह पर शॉफ्ट सं. 34 दिखाई देने लगी।

7.3.1 अब मुझे यह विश्लेषण करने दें कि क्या घातक दुर्घटना से एक दम पहले 40 डिप ऑफ 28 लेवल पर पानी का कोई असामान्य रिसाव था। यह माना गया है कि सीम की ओर पानी का असामान्य रिसाव यह सुस्पष्ट चेतावनी है कि वर्किंग्स किसी जलाप्लावित क्षेत्र की ओर जा रही है। कर्मचारी यूनियनों ने बताया कि वर्किंग्स के पुरानी शॉफ्ट सं. 34 के निकट होने के समय पानी का रिसाव अधिक था, परन्तु अभिकर्ता एवं प्रबंधक मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) तथा अन्य अधिकारियों का कहना था कि पानी का रिसाव सामान्य था। को. खान वि. 1957 के विनियमन 127 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वर्किंग्स में किसी स्थान पर सीम की ओर पानी के असामान्य रिसाव का पता चलता है या यदि ऐसा कोई आशंका या संदेह है तो ऐसी वर्किंग्स को तत्काल बन्द कर दिया जाएगा और ऐसे रिसाव की सूचना तत्काल खान सुरक्षा महानिदेशक को दी जाएगी। तथा ऐसी वर्किंग्स का और विस्तार खान सुरक्षा महानिदेशक की लिखित पूर्व अनुमति तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा।

7.3.2 नारायणकुरी सीम की वर्किंग्स सामान्यतः शुष्क है। 1 दिसम्बर, 1988 में पुरानी शॉफ्ट सं. 33 और 34 के निकट विकास कार्य करते समय पूर्व अभिकर्ता श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ने 26, 27 तथा 28 लेवल्स ऑफ 39 डिप की फलकों (फेसिस) में पानी के असामान्य रिसाव की ओर ध्यान दिया। सर्वेक्षक, श्री पी. एन. ठक्कर (एम डब्ल्यू-15) ने पानी के इस असामान्य रिसाव की और वर्किंग्स के पुरानी शॉफ्ट सं. 34 की ओर जाने के बारे में अपनी सांविधिक सर्वेक्षण डायरी में लिखा। को. खा. वि. 1957 के विनियमन 19 के अधीन अपेक्षानुसार डायरी पर प्रबंधक मो. कालिम (एम डब्ल्यू-17) द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए गए। पूर्व अभिकर्ता श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ने भी उन फलकों में पानी के असामान्य रिसाव को देखा तथा इसे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पुस्तक (दस्तावेज डब्ल्यू-15) में लिखा। इस क्षेत्र में वर्किंग्स बन्द कर दी गई तथा खान सुरक्षा महानिदेशक को सूचित कर दिया गया। इसके पश्चात् पूर्व अभिकर्ता, श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू/18) ने 19 जनवरी, 1988 को खान सुरक्षा महानिदेशक को लिखे अपने पत्र (दस्तावेज एम/5) में बताया कि उक्त रिसाव को ध्यान में रखते हुए उससे पहले खान सु. महा. द्वारा अनुमोदित की गई। (दस्तावेज एम/5) शॉफ्ट सं. 33 और 34 के निकट विकास परियोजनाओं में परिवर्तन का पता लगाया तथापि श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (दस्तावेज डब्ल्यू/5) में लिखा कि 13 जनवरी, को देखा गया रिसाव 28 जनवरी, 1988 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कम हो गया था। परन्तु उसकी टिप्पणी सरसरे अनुमान पर आधारित थी न कि वास्तविक माप पर। श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू/18) ने अपने बयान में यह भी कहा कि 27 लेवल पर छत में दरार से पानी का रिसाव हो रहा था। यदि यह ऐसा था तो उसने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (दस्तावेज डब्ल्यू-5) में यह भी रिकार्ड किया होता। उसने ऐसा नहीं किया इसके विपरीत उसने लिखा कि छत और दीवारें (साइड) अच्छी थीं। इसके अतिरिक्त, श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) का वर्किंग्स योजना (दस्तावेज एम/11) में दी शॉफ्ट सं. 34 की स्थिति की ओर 27 लेवल ऑफ 39 डिप से ड्रिल किए गए एक लम्बे बरमा छिद्र का पता लगा। तथापि, शॉफ्ट सं. 34 बरमा छिद्र से जुड़ी नहीं था जैसा कि पहले बताया गया है। फिर भी श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ध्यान पूर्वक आगे बढ़ा और उस क्षेत्र में और विकास कार्य नहीं किया तथा पुरानी शॉफ्ट सं. 34 से लगभग 100 मी. दूर संशोधित परियोजना में कार्य करने के लिए जनवरी, 1988 में खा. सु. महा. की फिर से अनुमति ली। प्रश्न यह है कि श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ने जनवरी, 1988 के बाद 27 लेवल पर वर्किंग्स पर और कार्य क्यों नहीं किया। स्पष्ट था कि 27 लेवल पर पानी का रिसाव इतना अधिक था कि उसने नई परियोजना की वर्किंग्स के लिए खा. सु. महा. की अनुमति ली। श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ने अपने बयान में बताया था कि वह 27 लेवल पर एक लम्बा बरमा छिद्र करके पानी के रिसाव का मूल्यांकन करने के लिए अधिक समय चाहता था। अतः श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) की कार्य प्रणाली में सावधानी पश्चात् पूर्व अभिकर्ता, श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू 18) ने 19 जनवरी, 1988 को खान सुरक्षा महानिदेशक को लिखे अपने पत्र (दस्तावेज एम 5) में बताया कि उक्त रिसाव के स्थान को ध्यान में रखते हुए उससे पहले खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा अनुमोदित की गई (दस्तावेज एम/5) से शॉफ्ट सं. 33 और 34 के निकट विकास परियोजनाओं में परिवर्तन का पता लगाया। तथापि श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (दस्तावेज डब्ल्यू/5) में लिखा कि 13 जनवरी, को देखा गया रिसाव 28 जनवरी, 1988 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय कम हो गया था। परन्तु उसकी टिप्पणी सरसरे अनुमान पर आधारित थी न कि वास्तविक माप पर। श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू-18) ने अपने बयान में यह भी कहा कि 27 लेवल पर छत में दरार से पानी का रिसाव हो रहा

था। यदि यह ऐसा था तो उसने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट (दस्तावेज डब्ल्यू 5) में यह भी रिकार्ड किया होता। उसने ऐसा नहीं किया इसके विपरीत उसने लिखा कि छत और दीवारें (साईड्स) अच्छी थीं। इसके अतिरिक्त श्री के के दास (एम डब्ल्यू 18) को वर्किंग योजना (दस्तावेज एम/11) में दी शॉफ्ट सं. 34 की स्थिति की ओर 27 लेवल ऑफ 39 डिप से ड्रिल किए गए एक लंबे बरमा छिद्र का पता लगा। यथापि, शॉफ्ट सं. 34 लम्बे बरमा छिद्र से जुड़ी नहीं थी जैसा कि पहले बताया गया है। फिर भी, श्री के के दास (एम डब्ल्यू 18) ध्यानपूर्वक आगे बढ़ा और उस क्षेत्र में और विकास कार्य नहीं किया तथा पुरानी शॉफ्ट सं. 34 से लगभग 100 मी. दूर संशोधित परियोजना में कार्य करने के लिए जनवरी, 88 में खान सुरक्षा महानिदेशक की फिर से अनुमति ली। प्रश्न यह है कि श्री के के दास (एम डब्ल्यू 18) ने जनवरी, 1988 के बाद 27 लेवल पर वर्किंग पर और कार्य क्यों नहीं किया। स्पष्ट था कि 27 लेवल पर पानी का रिसाव इतना अधिक था कि उसने नई परियोजना की वर्किंग के लिए खा. सु. महा. की अनुमति ली। श्री के के दास (एम डब्ल्यू. 18) ने अपने बयान में बताया था कि-वह 27 लेवल पर एक लम्बा बरमा छिद्र करके पानी के रिसाव का अवलोकन करने के लिए अधिक समय चाहता था। अतः श्री के के दास (एम डब्ल्यू 18) की कार्यप्रणाली में सावधानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जब श्री के.के. दास (एम डब्ल्यू 18) ने सावधान रहने संबंधी इस प्रकार का संकेत दे दिया तो मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) जो श्री के के दास के अधीन महावीर खान का प्रबंधक था और जिसे इस संबंध में सभी विकास कार्यों की जानकारी थी, को खान सु० महा. की अनुमति के बिना नवम्बर 8, 1989 को 40 डिप गैलरी ऑफ 28 लेवल (जो 39 डिप आफ 27 लेवल के बहुत नजदीक थी तथा शाफ्ट सं. 34 के भी नजदीक थी) में कार्य आरम्भ नहीं करना चाहिए था। यह बताना महत्वपूर्ण है कि घातक दुर्घटना 40 डिप गैलरी ऑफ 28 लेवल में कार्य शुरू करने के पांच दिन के बाद हो गई।

7.3.3 इस बात का साक्ष्य विद्यमान है कि 40 डिप फेस ऑफ 28 लेवल को लगभग दो वर्ष बाद 8 नवम्बर, 1989 को दोबारा आरम्भ किया गया। श्री चंदन पाण्डे (एम डब्ल्यू 13) श्री रामशंकर सरकार (एम डब्ल्यू 12) श्री शिवदास चैटर्जी (एम डब्ल्यू 9) श्री मिहिर कुमार चटर्जी (एम डब्ल्यू 10) तथा श्री चन्द्रशेखर बराय (एम डब्ल्यू 14) सहित प्रबंधतन्त्र के अधिकतम साक्षियों ने बताया कि 12 नवम्बर, 1989 को 40 डिप वर्किंग्स से पानी का कोई रिसाव नहीं था। तथापि, श्री गणेश राम (एम.डब्ल्यू 5) ने बताया कि वे कभी-कभी 42 क्रासकट की फलको से रिसने वाले पानी से पानी की बोतलें भरा करते थे। दुर्घटना के दिन तीसरी पारी में 40 डिप के लोडर, श्री नूर मोहम्मद (एम डब्ल्यू 4) ने कहा कि 40 डिप फेस पर कुछ रिसाव के अलावा यह भाग शुष्क था। इसके विपरीत यूनियनों द्वारा पेश किए गए श्री राम चन्द्र महतो (यू डब्ल्यू 4) और श्री मंगी राजभार (यू. डब्ल्यू 5) जैसे साक्षियों ने बताया कि 12 नवम्बर, 1989 की तीसरी पारी में 40 डिप की छत तथा फलक फेस से पानी का रिसाव काफी था। 40 डिप फेस पर सुरक्षित खनन के लिए तत्परवर्ती कोयला धूल को नियंत्रित रखने के लिए पानी छिड़कने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि यह व्यवस्था इस भाग की अन्य फलकों फेस में की गई थी।

7.3.4 प्रश्न यह है कि क्या घातक दुर्घटना से तत्काल पूर्व 40 डिप फेस ऑफ 28 लेवल पर पानी का रिसाव असामान्य था। यदि यह असामान्य था, तो अभिकर्ता एवं प्रबंधक मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) और उनके अधीन अन्य अधिकारियों को अप्रत्याशित वर्किंग्स के होने की पूर्व चेतावनी लेना चाहिए था और यथावश्यक पूर्व सावधानी बरतना चाहिए था। यद्यपि प्रबंधतन्त्र के अधिकतम साक्षियों (अर्थात् एम डब्ल्यू एस) ने बताया कि पानी का कोई असामान्य रिसाव नहीं था, लेकिन कामगार यूनियन के सभी साक्षियों (अर्थात् यू डब्ल्यू एस) ने घातक दुर्घटना से तत्काल पूर्व 40 डिप फेस पर पानी के असामान्य रिसाव के बारे में बताया। तथापि, कामगार यूनियन के साक्षियों द्वारा पानी के रिसाव की मात्रा अलग-अलग बताई गई। श्री रामचन्द्र महतो (यू डब्ल्यू 4) ने पानी के अधिक रिसाव के बारे में बताया जिससे सामान्य वर्किंग पर प्रभाव पड़ा। श्री मंगी राजभार (यू डब्ल्यू 5) जो अब सेवा निवृत्त हो गए हैं का बयान था कि दुर्घटना से पहले 40 डिप फेस पर पानी का रिसाव असामान्य था जो फुहारे की तरह लगता था। मुझे लगा कि श्री मंगी राजभार (यू डब्ल्यू 5) अपक्षपाती तथा विश्वसनीय साक्षी है। मैं उसके व्यवहार तथा सीधे सादे और सरल उत्तरों से प्रभावित हुआ। घातक दुर्घटना से पहले 40 डिप फेस पर पानी के असामान्य रिसाव के बारे में उसके कथन पर मेरा विश्वास है और मेरा विचार है कि मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) और उनके अधीन अन्य अधिकारियों को नारायणकुरी सीम जो अन्यथा शुष्क थी में जलाप्लावित क्षेत्र में वर्किंग जाने की पर्याप्त जानकारी थी। स्वाभाविक है कि वर्किंग्स के इतने अधिक निकट जलाप्लावित शाफ्ट के होने से 40 डिप फेस पर पानी का असामान्य रिसाव हुआ।

7.3.5 पूर्व अभिकर्ता, श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू 18) और मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) ने बताया कि 26, 27 तथा 28 लेवल की छत, जहां से वर्ष 1988 में पानी का रिसाव हुआ, खराब थी और इसके लिए ठोस टेक (सपोर्ट) की आवश्यकता थी। तथापि दुर्घटना के पश्चात् इन वर्किंग्स के मेरे निरीक्षण के दौरान न तो छत में दरार और न छत खराब थी तथा न ही ठोस टेक लगी हुई थी। यह छत उस भाग की अन्य वर्किंग्स की तरह सामान्य प्रतीत होती थी। उस क्षेत्र की योजना (दस्तावेज एम 11) में भी भौगोलिक बाधा के होने का पता नहीं चलता था। मैंने भी 27 लेवल ऑफ 39 डिप विशेषकर जहां 1988 में विकसित फ्लैंक बरमा छिद्र ड्रिल किए गए थे, की दीवार पर रह गए पानी के रिसाव के निशान देखे थे अतः वर्ष 1988 में 27 लेवल पर पानी का असामान्य रिसाव किसी भौगोलिक बाधा के कारण नहीं था बल्कि यह इसलिए था कि वर्किंग्स जलाप्लावित शाफ्ट सं. 34 के अधिक निकट क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी।

7.3.6 जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि जनवरी, 1988 में पानी के असामान्य रिसाव के कारण 40 डिप की वर्किंग को बन्द कर दिया गया था और इस रिसाव को सांविधिक पुस्तक में रिकार्ड किया गया था तथा खान सुरक्षा महानिदेशक को भी सूचित कर दिया गया था। अतः को. खा. वि. 1957 के विनियम 127 (5) की अपेक्षानुसार खा. सु. महा. की लिखित अनुमति के बिना मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) को भी 8 नवम्बर, 1989 को 40 डिप फेस आफ 28 लेवल को दोबारा शुरू करने का अधिकार नहीं था इस पर श्री पी एन बनर्जी, सुरक्षा अधिकारी (एम डब्ल्यू 16) द्वारा भी आपत्ति नहीं की गई जो जिसका प्रमुख कर्तव्य खान में सुरक्षा सुनिश्चित करना था। श्री के दत्ता (एम डब्ल्यू 15) सहायक प्रबंधक ने भी यह जानते हुए भी विरोध नहीं किया कि 40 डिप आफ 28 लेवल ऐसा क्षेत्र है जहां पानी का अत्यधिक रिसाव है जहां कि वर्ष 1988 में काम बन्द कर दिया गया था और इस क्षेत्र में काम शुरू किया जाना खा. सु. महा. की वर्किंग अनुमति के अधीन नहीं आता।

7.4.1 अब पुरानी शाफ्ट सं. 34 का पता लगाने के लिए वर्ष 1988 का में ड्रिल किए गए लम्बे बरमा छिद्र के बारे में साक्ष्य का विश्लेषण इस प्रकार है। जनवरी 1988 में 26-27 तथा 28 लेवल फलकों (फेसिस) पर पानी का रिसाव हुआ और सर्वेक्षक श्री पी एन जकर (एम डब्ल्यू 16) ने इसे तत्कालीन प्रबंधक मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) और पूर्व अभिकर्ता श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू 18) को बताया कि वर्किंग्स शाफ्ट सं. 34 की ओर जा रही है। इस प्रकार पुरानी शाफ्ट सं. 34 की अनुमानित स्थिति की ओर 27 लेवल आफ 39 डिप से एक लम्बा बरमा छिद्र ड्रिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया। इस लम्बे बरमा छिद्र को ड्रिल करने का उद्देश्य था कि शाफ्ट सं. 34 का पता लगाया जाए ताकि खा. सु. महा. की लिखित अनुमति

(दस्तावेज एम/6) की शर्तों का अनुपालन भी किया जाए। श्री पी.एल. ठक्कर निरीक्षक (एम डब्ल्यू 15) ने बरमा छिद्र की दिशा बताई जिससे कि यह नारायणकुरी सीम में शाफ्ट नं. 34 को अन्तर्रोधन कर सके। उसने 27 लेवल ऑफ 39 डिप फेस की स्थिति के अनुरूप खान वर्किंग प्लान (दस्तावेज एम/11) पर दर्शाई गई शाफ्ट नं. 34 की स्थिति पर आधारित बरमा छिद्र की दिशा तथा लम्बाई का अनुमान लगाया। सर्वेक्षक द्वारा अंकित दिशा के आधार पर ड्रिलर श्री रमेश मांझी (एम डब्ल्यू 8) ने 27 लेवल के फेस के लगभग मध्य में 133 फुट (40मी.) लम्बा छिद्र ड्रिल किया। ड्रिलिंग कार्य श्री पी एल बैनर्जी (एम डब्ल्यू 16) की देख रेख में किया गया। श्री पी एल ठक्कर (एम डब्ल्यू 15) ने लम्बे बरमा छिद्र की लम्बाई आदि तथा इसकी दिशा का सत्यापन किया मैंने दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान उक्त लम्बा बरमा छिद्र को देखा इस प्रकार मेरा समाधान हो गया है कि लम्बे बरमा छिद्र को शाफ्ट सं. 34 का पता लगाने के लिए वास्तव में वर्ष 1989 में ड्रिल किया गया।

7.4.2 मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) ने खान वर्किंग प्लान (दस्तावेज एम/11) में दर्शाई गई शाफ्ट सं. 33 और 34 की स्थिति में गलती की संभावना को स्वीकार किया। तथा श्री पी एल बैनर्जी (एम डब्ल्यू 16) ने बताया कि इस लम्बे बरमा छिद्र के सम्भाव्य विचलन को रोकना सम्भव नहीं था और उनके पास यह ज्ञात करने के लिए ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं था कि क्या लम्बा बरमा छिद्र वास्तव में अपने स्थान से हट गया है। श्री पी एल ठक्कर (एम डब्ल्यू 15) ने बताया कि यदि ड्रिलर पर्याप्त सावधानी न बरते तो बरमा छिद्र के विचलित होने की पूरी संभावना थी। इस प्रकार लम्बे बरमा छिद्र के विचलित होने तथा पुरानी शाफ्ट नं. 34 को अन्तर्रोधन न करने की सम्भावना थी। मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) और श्री पी एल बैनर्जी (एम डब्ल्यू 16) के पूर्णतः विश्वस्त होने का कोई आधार नहीं था कि 133 फुट (40 मी.) का लम्बा बरमा छिद्र पुरानी शाफ्ट नं. 34 को पार गया है।

7.4.3 तदोपरान्त, प्रबंधतंत्र द्वारा दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण किया गया तथा एक प्लान (दस्तावेज एम/12) तैयार की गई इसमें बताया गया कि शाफ्ट सं. 34 की वास्तव में खान वर्किंग प्लान (दस्तावेज सं. एम/11) में दर्शाई गई स्थिति से 6.5 मी. दूर थी। अतः लम्बा बरमा छिद्र नारायणकुरी सीम में पुरानी शाफ्ट सं. 34 को अन्तर्रोधन करने में असफल रहा। इस प्रकार, वर्ष 1988 में 27 लेवल पर केवल एक लम्बा बरमा छिद्र ड्रिल करने से सुनिश्चितता की गलत भावना पैदा हो गई कि कि शाफ्ट सं. 34 नारायणकुरी सीम तक नहीं पहुंची है।

7.5.1 28 लेवल पर 40 डिप पर कार्य करने के लिए अभिकर्ता-एवं-प्रबंधक मो. कासिम (एम डब्ल्यू 17) द्वारा खा. सु. महा. की वर्किंग अनुमति प्राप्त किए जाने के बारे में विश्लेषण इस प्रकार है। कर्मचारी यूनियनों द्वारा लिखित आरोप लगाया गया कि खा. सु. महा. की बिना किसी वर्किंग अनुमति के 40 डिप आफ 28 लेवल को 8 नवम्बर 1988 से विकसित किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रबंधतंत्र का तर्क था कि उनके पास खा. सु. महा. की वैध अनुमति है और इसलिए 40 डिप आफ 28 लेवल के चालन की अनुमति है।

7.5.2 को. खा. वि. 1957 के विनियमन 127 में अपेक्षा की गई है कि विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन खा. सु. महा. की बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी वर्किंग विस्तार या किसी जलाप्लावित वर्किंग के 60 मी. के अन्दर नहीं किया जाएगा। विनियमन में यह भी अपेक्षा की गई है कि ऐसी किसी वर्किंग के विस्तार की अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्लान संलग्न किए जाएं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित वर्किंग की रूप रेखा, स्थल तथा विधि दी गई हो। यदि वर्किंग के विस्तार के लिए खा. सु. महा. द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो इसका विस्तार पूर्णतः अनुमोदित योजना, विधि और इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया जाएगा। वर्किंग अनुमति में दी गई शर्तों में अभिकर्ता एवं प्रबंधक द्वारा कोई परिवर्तन किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक ऐसे परिवर्तन को बाकायदा खा. सु. महा. द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।

7.5.3 दिसम्बर, 1983 में प्रबंधतंत्र ने मुख्य रेलवे लाइन के दक्षिण में नारायणकुरी सीमा क्षेत्र को विकसित करने की अनुमति के लिए आवेदन किया आवेदन पत्र (दस्तावेज एम 4) के साथ प्रस्तुत की गई योजना में पुरानी शाफ्ट सं. 33 तथा 34 के नीचे विकास की परियोजना दर्शाई गई। इस विकास के लिए खा. सु. महा. के 12 मार्च, 198 के पत्र सं. एस-3/173 (सी डी, एम बी) II-बी 84/1062 (दस्तावेज एम 5) के तहत वर्किंग अनुमति प्रदान की गई थी, इसमें वह क्षेत्र शामिल किया गया था जहां 13 नवम्बर, 1989 को दुर्घटना हुई। वर्किंग अनुमति में अपेक्षा की गई थी कि पुरानी शाफ्ट बनाए गए स्तम्भ के ऊपर हो। इस अनुमति के अनुसार ठोस स्तम्भों में शाफ्ट को रोकते हुए शाफ्ट सं. 33 तथा 34 की स्थिति में पड़े 26 लेवल तथा 31 लेवल के बीच के क्षेत्र को विकसित किया जा सकता था। इस प्रकार, वर्ष 1984 में वर्किंग अनुमति प्रदान करते समय, खान सुरक्षा महानिदेशक ने भी सुरक्षा पूर्वोपायों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया था।

7.5.4 तथापि, पूर्व अभिकर्ता, श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू 18) ने 19 जनवरी, 1988 के अपने पत्र सं. ई सी एल : एस-पी डी-ई-सी 88/198 में पुरानी शाफ्ट सं. 34 के निकट 26 लेवल आफ 38 डिप तथा 27 लेवल आफ 39 डिप की दरारों (क्रिप) में पानी के असामान्य रिसाव को ध्यान में रखते हुए खा. सु. महा. से विकास परियोजनाओं में परिवर्तन की अनुमति मांगी।

7.5.5 योजना के प्रोजेक्शन की तुलना 1983 (प्रदर्श-एम/4) के लिए अनुमति के अनुप्रयोग के साथ 1988 (प्रदर्श-एम/7) से करने पर पता चलता है कि संशोधित प्रोजेक्शन (प्रदर्श-एम/7) में 26 और 31 स्तरों के बीच किए जा रहे कार्य को पुराने शाफ्ट सं-33 एवं 34 की ओर आगे नहीं किया जाना चाहिए था। पुराने शाफ्टों को 32 स्तर से क्रास-कट के बाद बाईपास किया जाना था। 41 क्रास कट नामक अगले क्रास कट को शाफ्ट सं.-33 से 45 मीटर की दूरी पर और शाफ्ट सं-34 से 100 मीटर की दूरी पर हटाया जाना था 41 क्रास कट के गहराई वाले भाग का आगे विकास करने का प्रस्ताव नहीं था।

7.5.5 खान सुरक्षा महा. के दिनांक 2 मार्च, 1988 (प्रदर्श-एम/8) के अपने पत्र सं.-एस-3/22.03/062/II ए/88/623 में नए प्रोजेक्शन (प्रदर्श-एम/7) के अनुसार नारायणकुरी सीम का विकास करने के लिए संशोधित अनुमति दी थी। तथापि, खान सुरक्षा महा. के पूर्व अनुमति सं.-1062 दिनांक 12 मार्च, 1984 (प्रदर्श-एम/5) में निर्धारित शर्तों को बदला नहीं गया था।

7.5.6. पूर्व एजेंट, श्री के. के. दास (एम. डब्ल्यू-18), प्रबंधक, मु. कासिम (एम. डब्ल्यू. 17), सुरक्षा अधिकारी श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू. 16) का यह विचार था कि 1984 की अनुमति (प्रदर्श-एम 15) द्वारा मंजूर की गयी विकास का प्रोजेक्शन तब भी वैध था जब उन्होंने विशेष कारणों से प्रोजेक्शन (प्रदर्श-एम/7) में संशोधन के लिए इच्छा व्यक्त की थी और तदनुसार उनको 1988 (प्रदर्श एम 8) की अनुमति मिली थी। दूसरे शब्दों में, 1988 की अनुमति 1984 का अनुमति का अतिक्रमण नहीं करती थी और इसलिए नवम्बर 8, 1989 से 28 स्तर पर 40 डिप का विकास अनुमति प्राप्त क्षेत्र में किया गया था। मेरे विचार से खान सुरक्षा महा. के लिए "1984 की अनुमति" से तात्पर्य करते हुए यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं था कि "1984 की अनुमति" रद्द की गयी थी। इस प्रकार का स्पष्टीकरण स्वतः स्पष्ट था, क्योंकि पूर्व एजेंट श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू 18) ने स्वयं शाफ्ट सं.-34 के समीप 26 [illegible] 27 [illegible] के पास [illegible]

रिसने की घटना को देखते हुए संशोधन का अनुरोध किया था । इसके अलावा, प्रबंधन का यह कथन कदापि मानने योग्य नहीं है, क्योंकि यथोक्त विनियमन 127 (5) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि ज्यादा पानी रिसने के कारण किसी विशेष क्षेत्र में एक बार कार्य रोक दिया जाता है तो उस क्षेत्र में दुबारा कार्य तब तक नहीं शुरू किया जाएगा, जब तक खान सुरक्षा महानिदेशालय से लिखित रूप में नयी अनुमति प्राप्त न हो जाए । इस मामले में, खान सुरक्षा महानिदेशालय ने कोई नयी अनुमति नहीं दी थी । अतः 28 स्तर के 40 डिप के पास 8 नवंबर 1989 से खनन कार्य शुरू करना, जिसको जनवरी, 1988 में ज्यादा पानी रिसने के कारण बंद कर दिया गया था, बिल्कुल गलत था । मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) श्री पी. एन. बनर्जी (एम. डब्ल्यू 16) और श्री के. दत्त (एम. डब्ल्यू. 18) वरिष्ठ और उत्तरदायी अधिकारी हैं और इनके पास प्रबंधक कुशलता का प्रमाणपत्र है । इन अधिकारियों को विनियम के इस पहलू को महसूस करना चाहिए था ।

7.5.5 प्रबंधन का यह कहना है कि जब पानी जमाव क्षेत्र एक ही सीम में स्थित होता है, तब यह आवश्यक होता है कि एक बीच का बोरहोल और अनेक अगल बगल बोरहोल ड्रिल किया जाए, लेकिन यदि प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के ठीक ऊपर पानी जमाव स्थल विद्यमान है तो 3 मीटर लंबे अगल बगल बोरहोल बनाना अनावश्यक होता है और आगे किसी भूवैज्ञानिक खतरे की संभावना का पता लगाने के लिए केवल एक बीच का बोरहोल बनाना अपेक्षित होता है । लेकिन इस दलील में ज्यादा दम नहीं है, जैसा कि आगे के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा ।

7.5.6 नेगा और नारायणकुरी सीम के बीच का अंतर केवल 24 मीटर है और एक अज्ञात गहराई का पुराना शाफ्ट है, जो शायद नारायणकुरी सीम तक बढ़ गया हो । नारायणकुरी सीम तक एक पुराने शाफ्ट या ऊपर वाले सीम के पिलरों के माध्यम से नारायणकुरी सीम में पुराने कार्यक्षेत्रों के होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः यह माना नहीं जा सकता, जैसा कि प्रबंधन का कथन है, कि पानी जमाव क्षेत्र केवल ऊपर वाले सीम में स्थित था और इस प्रकार आगे अगल बगल छेद करना आवश्यक नहीं था । खान सु. महानिदेशालय की अनुमति (प्रदर्श एम/5) में इन सभी संभावनाओं का ध्यान रखा जाना था, क्योंकि खान सुरक्षा महा. ने सेन्ट्रल बोरहोल के साथ उचित संख्या में अगल बगल भी बोरहोल बनाने का आदेश दिया था ।

7.5.7 इसका यदि विस्तृत रूप से वर्णन किया जाए तो इस प्रकार है :— सतग्राम खान के नारायणकुरी सीम के लिये खान सुरक्षा महा. की 1984 और 1988 में दी गयी कार्य अनुमति पूर्णतया विनियमन 127(6) (क) के अनुसार थी, जिसके द्वारा यह अपेक्षित था कि जब पानीजमाव क्षेत्रों की ओर कार्य बढ़ाया जाये तो कार्यस्थल के मध्य भाग के समीप कम से कम एक बोरहोल बनाया जाये और दोनों ओर उचित संख्या में फ्लैंक बोरहोल बनाये जायें, और जहां आवश्यक हो कार्य स्थल के ऊपर और नीचे भी बोरहोल बनाये जायें जिनकी एक दूसरे से दूरी 5 मीटर से ज्यादा न हो । ऐसे सभी बोरहोल बनाए जाए और कार्यस्थल के पहले उचित दूरी से इस पर ध्यान रखा जाये और किसी भी मामले में यह दूरी 3 मीटर से कम न हो । इन प्रावधानों का पालन विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिये प्राधिकृत खान अधिकारी द्वारा, जिसके पास प्रबंधक या ओवर मैन का प्रमाणपत्र हो, किया जाना अपेक्षित है । संगत विनियमन के अन्तर्गत, कार्यस्थलों की ऊंचाई और चौड़ाई तथा बोरहोल की संख्या उनकी लंबाई और दिशा का रिकार्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित है और इस रजिस्टर पर प्रतिदिन इस उद्देश्य के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना होता है । इन रिकार्डों का पालन मो. कलीम एजेंट-सह प्रबंधक (एम. डब्ल्यू-17) और उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया ।

7.6.1 अब मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित साक्ष्यों का विश्लेषण करना है कि क्या 8 नवम्बर 1989 से शुरू किए गए चालीसवें डिप के मुहाने पर किये जा रहे कार्य में सेन्ट्रल और फ्लैंक बोरहोल्स की उचित सुरक्षा थी मोहम्मद कलीम (एम. डब्ल्यू 17) ने यह कहा है कि खान सुरक्षा महानिदेशक की कार्य अनुमति तथा कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127 की अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करने के क्रम में उन्होंने ड्रिलिंग मशीन जनशक्ति और पर्यवेक्षण जैसी आवश्यक अन्य संरचनाओं की व्यवस्था की थी । एडवांस बोरहोल को सामान्य कोयला ड्रिलों से ड्रिल किया गया था । इस प्रक्रम में मुहाने पर एक सेन्ट्रल बोरहोल और मुहाने से 45° पर दो फ्लैंक बोरहोल शामिल थे । फ्लैंक होल की लंबाई 3 मीटर से 3.6 मीटर तक थी और इसके दोनों रिबों में ड्रिल किया गया था । होल ड्रिल करने के उद्देश्य से 1.8 मीटर 3.6 मीटर और 5.4 मीटर की लम्बाई वाले स्टील ड्रिलों के तीन सेटों सहित एक कोयला ड्रिल का प्रावधान किया गया था ।

7.6.2 इस बात के प्रमाण हैं कि जून 1989 तक एडवांस ड्रिलिंग गैंग की सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध करवाई गई थी । ड्रिलिंग गैंग के ये कर्मकार, जिनको ड्रिलर कहा जाता है के नाम श्री कुलदीप दास (यू डब्ल्यू 1) भारी दुसाद और बिंदु बावरी थे । यह ड्रिलिंग गैंग प्रथम पारी के आरम्भिक घंटों में डिप में पहुंच जाया करता था और बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित सभी मुहानों से बोरहोल ड्रिलिंग का कार्य उसी दिन समाप्त कर दिया करता था । तथापि जून 1989 में मोहम्मद कलीम (एम. डब्ल्यू 17) एजेंट सह प्रबंधक द्वारा ड्रिलिंग गैंग को भंग कर दिया गया और ड्रिलरों को अन्य कार्यों में लगा दिया गया था । श्री कुलदीप दास (यू डब्ल्यू 1) के अनुसार चूंकि जून 1989 में ड्रिलिंग गैंग को भंग कर दिया गया था इसीलिए कोई एडवांस बोरहोल ड्रिल नहीं किया गया था । मो. कलीम (एम. डब्ल्यू 17) और श्री पी. एन. बनर्जी (एम. डब्ल्यू-16) ने यह कहा है कि जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिये एडवांस ड्रिलिंग गैंग को भंग कर दिया गया था । तथापि एडवांस बोरहोल के ड्रिलिंग का कार्य प्रथम पारी के सामान्य मजदूरों द्वारा किया जा रहा था और ऐसी एडवांस सेन्ट्रल बोरहोल और फ्लैंक बोरहोल का प्रावधान 40 डिप फेस में किया था, जब 8 नवम्बर 1989 से इसको प्रारम्भ किया गया था । उसके बाद प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के अनुसार इन सभी बोरहोल को नियमित रूप से ड्रिल किया जाता था और 12 नवम्बर 1989 को पहली पारी में एडवांस सेन्ट्रल बोरहोल को 3.6 मीटर से 5.4 मीटर तक बढ़ाया गया था 3.0 मीटर से 3.6 मीटर की लम्बाई वाले दो बोरहोल को 40 डिप फेस के रिब में ड्रिल किया गया था । इन एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग श्री मिहिर कुमार चटर्जी (एम. डब्ल्यू-10) और श्री सी. डी. सिंह (एम डब्ल्यू 11), ओवरमैन के पर्यवेक्षण में की गयी थी । उन्होंने सभी एडवांस बोरहोल की लम्बाई को सही पाया था । दूसरी पारी में, श्री शिवदास चटर्जी (एम. डब्ल्यू 9) ओवरमैन ने एडवांस बोरहोल की जांच की और उन्हें पता चला कि इसकी लम्बाई 3.6 मीटर थी । उन्होंने एडवांस फ्लैंक बोर होल की भी जांच की और इसे सही पाया तीसरी पाली में श्री दुखन पाण्डेय, सरदार (एम. डब्ल्यू 13) ने भी 40 डिप फेस के सेन्ट्रल बोरहोल की जांच की और उन्हें पता चला कि इसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक थी । शाट फायरर श्री चंद्रधारी बरई (एम. डब्ल्यू 14) ने यह कहा कि दुर्घटना के दिन 40 डिप के फेस में शाट चार्ज करने के पूर्व, उन्होंने अपनी 1.8 मीटर लंबी छड़ी से सभी सेन्ट्रल और फ्लैंक बोरहोल की जांच की थी और उन्होंने आगे कहा कि ये होल उस समय 1.8 मीटर से ज्यादा लम्बे थे । तथापि श्री धनी राजभर (यू. डब्ल्यू. 5), जिन्होंने दुर्घटना के ठीक पहले 40 डिप के शाट-होलों को चार्ज किया था, ने यह कहा कि फेस में की गई एडवांस और फ्लैंक बोरहोल नहीं था । उन्होंने दावा किया कि वे शाट होल और एडवांस बोरहोल में अंतर समझते हैं ।

गनेश राम (एम. डब्ल्यू 5) और श्री राम चंद्र महतो (यू. डब्ल्यू 4) जैसे अन्य गवाहों ने भी फेस में कोई एडवांस होल नहीं देखा।

7.6.3 यहां एक उल्लेखनीय बात यह है कि वैसे सभी व्यक्तियों जिन्होंने यह कहा है कि एडवांस बोरहोल ड्रिल किये गये थे, वे इन होलों को ड्रिल करने वाले एक भी ड्रिलर का नाम तक नहीं बताया। केवल एक गवाह श्री सी. डी. सिंह (एम. डब्ल्यू-11) ने माधुरी पासवान नामक एक ड्रिलर का नाम बताया। लेकिन वे भी उस ड्रिलर के पदनाम के बारे में निश्चित नहीं थे। प्रारंभ में उन्होंने कहा कि यह ड्रिलर एक सामान्य मजदूर है लेकिन बाद में उसका पदनाम ड्रिलर के रूप में बताया। चूंकि एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग नियमित रूप से होती है, जैसा कि एजेंट-सह प्रबंधक मो. कलीम (एम. डब्ल्यू-17) और उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों का कहना है अतः यह असंभव है कि एजेंट-सह प्रबंधक से नीचे के कर्मचारियों में से किसी को भी, जो 28-स्तर के 40 डिप के एडवांस बोरहोल के पर्यवेक्षण से संबद्ध है, इस एडवांस बोरहोल ड्रिल करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम याद न हो। दूसरी बात यह है कि एक सामान्य कोयला ड्रिल से 5.4 मीटर के एक एडवांस बोरहोल को ड्रिल करने से क्रमिक रूप से ड्रिल रॉड में परिवर्तन होता है। ड्रिल होल को मध्य में ड्रिल किया जाना तथा फेस से 45° पर ड्रिल किया जाना अपेक्षित होता है। अतः इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि एडवांस बोरहोल को ड्रिल करने में उतनी कुशलता चाहिये जितनी की फेस के शाट होल्स को ड्रिल करने के लिये अपेक्षित होती है। यह असंभव है कि यह कार्य नैमित्तिक आधार पर इस काम पर लगाये गये सामान्य मजदूरों से हो सकता है, जैसा कि मो. कलीम, एजेंट-सह प्रबंधक (एम डब्ल्यू 17) और अन्य अधिकारियों का दावा है।

इसके अलावा इस न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में प्रस्तुत किसी भी पर्यवेक्षी अधिकारी ने कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियम 127 (6) के अन्तर्गत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एडवांस होल के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया गया। मो. कलीम (एम. डब्ल्यू 17) ने यह कहा कि उन्हें याद है कि उन्होंने इस उद्देश्य के लिये दो ओवर मैनों को प्राधिकृत किया था, पर वे श्री मुखर्जी को छोड़कर किसी और का नाम नहीं बता सके। तथापि, कोई ऐसे व्यक्ति (अर्थात् श्री मुखर्जी) को प्रबंधक द्वारा गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। श्री मिहिर चटर्जी, ओवरमैन (एम. डब्ल्यू 10) ने एडवांस बोरहोल के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व केवल उस हद तक स्वीकार किया कि उनको आमतौर पर मो. कलीम (एम. डब्ल्यू 17) एजेंट सह प्रबंधक द्वारा एडवांस बोरहोल के कार्य का पर्यवेक्षण करने को कहा जाता था, पर कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियम 127 के अन्तर्गत अपेक्षित तरीके से ऐसे बोरहोल के निरीक्षण के लिये उनको प्राधिकृत नहीं किया गया था। मो० कलीम (एम० डब्ल्यू०17) ने यह स्वीकार किया कि 28 स्तर के बगल वाले 40 डिप या महावीर खान के अन्य कार्य मुहानों पर एडवांस बोरहोल का अनिवार्य रिकार्ड नहीं रखा गया।

7.6.4. एडवांस सेन्ट्रल बोरहोल को 5.4 मीटर लंबा ड्रिल करने और फ्लैंक बोरहोल को 3.0 मीटर से 3.6 मीटर लंबा ड्रिल करने की मानिटरिंग की पद्धति और प्रक्रिया तथा फेस से 45° का स्थान एजेंट-सह प्रबंधक मो. कलीम (एम. डब्ल्यू 17) द्वारा साफ शब्दों में नहीं बताया गया था। साक्ष्यों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जब कभी भी पर्यवेक्षी टास्क फेस पर आता था, तभी वे एडवांस बोरहोल की नाप-जोख करते थे। इसका रिकार्ड रखने और इसको मानिटर करने की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी।

7.6.5 दुर्घटना के बाद 40 डिप फेस के मेरे निरीक्षण के दौरान मैंने फ्लैंक बोर होल गैलरी के शुरू में एक को छोड़कर, के किसी प्रमाण को नहीं देखा। ये फ्लैंक बोरहोल यदि ड्रिल किए जाते हैं तो उन्हें खेमे में छोड़ दिया जाता है। इस मुद्दे पर न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू 16) और श्री के. दत्ता (एम. डब्ल्यू 19) ने यह कहा कि जब पानी का सोता फूटा तो फ्लैंक बोरहोल पानी में डूब गये और पानी के कारण इनका निशान मिट गया। तथापि, 40 डिप की चौड़ाई किसी के अन्य गैलरी की तरह ही है, अर्थात करीब 4.2 से 4.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। किनारे और छत सामान्यतः उसी तरह उबड़ खाबड़ दिखायी देती है, जैसा कि कोई गैलरी ब्लास्टिंग के बाद विकसित की जाती है। अतः श्री पी. एल. बनर्जी (एम० डब्ल्यू-16) तथा प्रबंधतंत्र और इंडियन माइन मैनेजर्स एसोसियेशन का यह कथन, कि फ्लैंक बोर होल का नामोनिशान पानी के प्रवाह से मिट गया, विश्वास करने योग्य नहीं है। इसी तरह, अन्दर आने वाले पानी के प्रवाह के कारण कीचड़ और कोयला चूर्ण से फ्लैंक बोर होल के बंद हो जाने की संभावना का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दुर्घटना स्थल पर मेरे द्वारा किये निरीक्षण संबंधी विश्लेषण से इस बात की पुष्टि नहीं होती।

7.6.6 दुर्घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान किए गये विश्लेषण के आधार पर, जिससे साफ पता चलता है कि फ्लैंक बोर होल नहीं किये गये थे, श्री मंगो राजभर जैसे प्रत्यक्षदर्शी गवाह (यू डब्ल्यू. 5), बोरहोल के न्यूनतम अनिवार्य रिकार्ड प्रस्तुत करने में खान प्रबंधन की असफलता और ऐसे किसी भी एक गवाह को पेश नहीं किया जाना जिसने वास्तव में एडवांस बोरहोल ड्रिल किया हो, मेरा यह विचार है कि दुर्घटना की तारीख 12 नवम्बर 1989 को 40 डीप फेस में कोई एडवांस सेन्ट्रल और फ्लैंक बोरहोल ड्रिल नहीं किया गया था. यह कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियम 127(6) का पूर्ण रूप से जानबूझकर किया गया उल्लंघन था।

7.6.7 दुर्घटना स्थल पर अपने निरीक्षण के दौरान मैंने देखा कि 40 डिप गैलरी किसी की किसी अन्य गैलरी से भिन्न नहीं है। फ्लैंक होल की व्यवस्था वाले समीप के अन्य गैलरियों सहित किसी अन्य गैलरी की चौड़ाई, ऊंचाई और रूपरेखा है। 40 डिप गैलरी की किनारों में, गैलरी के आरंभ एक फ्लैंक बोरहोल को छोड़कर कोई अन्य फ्लैंक बोरहोल होने का कोई प्रमाण नहीं है।

7.6.8 मेरे विचार में श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू.-16) श्री सी. डी. सिंह (एम डब्ल्यू-11) श्री मिहिर कुमार चटर्जी (एम. डब्ल्यू 10), श्री चंद्रधारी बराई (एम. डब्ल्यू 14) और श्री के. दत्ता का यह कथन कि 4.2 मीटर की सामान्य चौड़ाई के मुकाबले 40 डिप गैलरी चौड़ाई केवल 3 मीटर थी, असत्य थी। यह कथन संभवतः इस बात को न्यायोचित ठहराने के उद्देश्य से दिया गया था कि 40 डिप में बनाये गये फ्लैंक बोरहोल अन्दर आने वाले पानी के कारण सपाट हो गये थे जिससे अन्ततः इसकी चौड़ाई 4.2 मीटर हो गई।

7.7.1 दुर्घटना स्थल का प्लान 40 डिप गैलरी में तीव्र घुमाव प्रदर्शित करता है, जो शाफ्ट सं. 34 से तनेक्शन के समीप है। श्री के. दत्ता (एम डब्ल्यू 19), श्री मिहिर कुमार चटर्जी (एम डब्ल्यू 10) श्री सी. डी. सिंह (एम. डब्ल्यू 11), श्री दूवनु पांडेय (एम डब्ल्यू 13) और श्री चन्द्रधारी बराई (एम. डब्ल्यू 14) जैसे प्रबंधन की तरफ गवाहों ने यह बयान दिया है कि दुर्घटना के दिन फेस के पीछे 40 डिप गैलरी की मध्य रेखा ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर से 3.6 मीटर की थी। तथापि सर्वेयर श्री पी. एल. ठक्कर ने यह दावा किया कि 8 नवम्बर 1989 से पुनः शुरू होने के बाद उन्होंने 40 डिप गैलरी के मध्य रेखा की मापजोख जारी नहीं की थी। उन्होंने यह भी बयान दिया कि 8 नवंबर और दुर्घटना वाले दिन 13 नवंबर के बीच उन्होंने कभी भी 40 डिप गैलरी का दौरा नहीं किया। यह हो सकता है कि उनके सहायकों ने मध्य रेखा को आगे बढ़ाया हो, पर इस बारे में भी वे आश्वस्त नहीं थे। गैलरी के ऐसे तीव्र घुमाव के कारणों के बारे में किसी भी गवाह या किसी भी पक्षकार ने कुछ भी नहीं कहा। यह हो सकता है कि प्लान में शाफ्ट सं. 34 का संभावित स्थल का ध्यान रखते हुए इस गैलरी को जानबूझकर घुमाया गया हो ताकि इसके नीचे ड्राईव किया जा सके और यह निश्चित हो सके कि बनने वाला पिलर शाफ्ट के समीप हो। 40 डिप गैलरी के ढाल के पास पुराने शाफ्ट सं. 31

से एक इनसैट की उपस्थिति एवं अन्य संभावना हो सकती है। जब गैलरी का कार्य आगे बढ़ रहा था इनसैट के साथ लगा बैरियर छोटा हो गया और अंततः यह नाकाम हो गया। पुराने और परित्यक्त शाफट से संबंध के परिणामस्वरूप एक तीव्र दक्षिणवर्ती घुमाव बन गया। अपने निरीक्षण के दौरान चालीस डिप गैलरी की पूरी लम्बाई के आकार प्रकार में मैंने अधिक अन्तर अनुभव नहीं किया। अतः मुझे यह सम्भव नहीं लगता है कि पहले यह एक शाफट इन्सैट या शाफट संख्या 34 में एक गैलरी विद्यमान थी। इसके अलावा सभी प्रत्यक्षवर्ती गवाहों के इस बयान के अनुसार कि एक मध्य रेखा का प्रावधान था, और इसके विपरीत इसका कोई साक्ष्य विद्यमान न होने के गैलरी में घुमाव होने की तीसरी सम्भावना से मैं इन्कार करता हूं। इस प्रकार से यह महसूस करता हूं कि यह सम्भव है कि गैलरी में जानबूझकर परिवर्तन किया गया था।

7.7.2 जैसे कि पहले भी कहा गया है, पुराने शाफट संख्या 34 के समीप के 40 डिप फेस को उस क्षेत्र में ज्यादा पानी रिसने के कारण जनवरी 1988 से बन्द कर दिया गया था। उस समय 28 स्तर से इस फेस की दूरी ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 फीट की थी (3 से 3.6 मी)। बाद में 28 स्तर के समीप के 40 डिप के जंक्शन पर अनंत समय तक समान परिवहन करने के लिये रिटेन परखी स्थापित कर दी गयी। मो. कलीम (एम डब्ल्यू.-17) ने यह बयान दिया है कि चालीस डिप गैलरी को नवम्बर, 1989 में फिर से शुरू किया गया जबकि श्री के. दत्त (एम डब्ल्यू 19) ने यह बयान दिया है कि इसको नवम्बर 1989 के प्रथम सप्ताह में पुनः शुरू किया गया। श्री मिहीर कुमार चटर्जी (एम. डब्ल्यू 10), श्री शिवदास चटर्जी (एम डब्ल्यू 9) और श्री सी. डी. सिंह (एम डब्ल्यू 11) जैसे अन्य गवाहों ने यह बयान दिया है कि 40 डिप में इसको 8 नवम्बर 1989 से पुनः शुरू किया गया। अतः मेरा मानना है कि 28 स्तर के समीप 40 डिप फेस जो पुराने शाफट संख्या 34 से जुड़ गया था और जिसके कारण यह घातक दुर्घटना हुई, को दुर्घटना के ठीक 5 दिन पहले 8 नवम्बर 1989 से पुनः शुरू किया गया।

7.7.3 अलगा मुद्दा यह है कि क्या शाफट संख्या 34 से 40 डिप गैलरी के जुड़ जाने के अन्य कारण और परिस्थितियां थीं। श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू 16) ने यह दावा किया है कि शाफट संख्या 34 और गैलरी के बीच 3 मीटर से भी ज्यादा के एक कोयला बैरियर के अचानक टूट जाने के कारण यह सम्बन्ध (कनैक्शन) स्थापित हुआ।

7.7.4 दुर्घटना के पहले, 40 डिप फेस की लम्बाई का आकलन श्री राम शंकर सरकार (एम डब्ल्यू 12) श्री शिव दास चटर्जी (एम डब्ल्यू 9), श्री सी. डी. सिंह (एम डब्ल्यू 11) और श्री मिहीर कुमार चटर्जी (एम. डब्ल्यू 10) जैसे अन्य गवाहों द्वारा किया गया जो कि करीब 40 से 45 फीट के बीच था, (12 से 17मी.)

7.7.5 40 डिप गैलरी की लम्बाई और दुर्घटना स्थल के प्लान प्रदर्श एम 12) से निर्धारित पुराने शाफट संख्या 34 के बारे में उपरोक्त गवाहों के आकलन के आधार पर श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू - 16 ने यह बयान दिया है कि दुर्घटना होने के ठीक पहले शाफट संख्या 34 और 40 डिप फेस के बीच का बैरियर 3 मीटर से ज्यादा का था। लेकिन मैंने यह स्वीकार नहीं किया है क्योंकि विभिन्न गवाहों द्वारा बतायी गयी 40 डिप फेस की लम्बाई केवल नेत्रवानुमान पर आधारित थी। और वास्तव में इसकी कोई नाप जो नहीं की गई थी।

अध्याय-VIII

8.1 साक्ष्यों का विश्लेषण
शाफट सं. 34 का एक्सटेंशन
8.2 पानी का असामान्य रिसाव
8.3 40 डिप का पुनः शुरू किया जाना
8.4 एडवांस बोर होल
8.5 स्तरों का खिसकना (मुवमेंट)
8.6 फ्लोर पत्थर का ढीला होना
8.7 दुर्घटना का कारण

8.1 यह सर्वविदित था कि नारायणकुरी सीम के 24 मीटर ऊपर पुराने रानीगंज कोलियरी के नेगा सीम के कार्यस्थलों में पानी भरा था इसमें अनेक पुराने शाफट भी थे, जिनमें से कुछ की गहराई अभी तक अज्ञात है। ऐसा है एक पुराना शाफट संख्या 34 था, जो मलबे से भरा हुआ था और जिसकी गहराई भी ज्ञात नहीं थी। खान प्रबंधन ने यह बयान दिया है, कि उन्होंने उपलब्ध पुराने प्लान और दस्तावेज का अध्ययन किया, लेकिन इससे भी पुराने शाफट की गहराई का पता नहीं चला। तथापि समीर के कार्यस्थल के एक ए.एम.पी. ने शाफट संख्या 34 की गहराई 86 फीट होने का संकेत दिया, जो कि उस क्षेत्र नेगा सीम की गहराई के बराबर है। खान सुरक्षा महा. ने 1934 में विकास की अनुमति (प्रदर्श-एम/5) देते हुये बहुत ही सतर्क थे और उन्होंने नारायणकुरी सीम तक पुराने शाफट के बढ़ जाने की आशंका का ध्यान रखते हुए फ्लैंक और सेन्ट्रल एडवांस होल का प्रावधान करने की शर्तें को इसमें शामिल कर दिया 1988 में जब पुराने शाफट सं.-34 के समीप विकास कार्य हो रहा था तब खान प्रबंधन ने भी ज्यादा पानी के रिसाव की बात देखी थी। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, उन्होंने विकास कार्य रोक दिया और कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127 (5) के अन्तर्गत अपेक्षित शर्तों के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित किया चूंकि शाफट सं.-34 का वास्तविक स्थल संदेहास्पद था अतः प्रबंधन ने उपलब्ध, दस्तावेजों और सूचना प्राप्त करने के अन्य स्त्रोतों के माध्यम से जानकारी लेनी चाही, ताकि शाफट सं. 34 की गहराई निश्चित की जा सके। तथापि, उनको इसकी गहराई के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं मिली। उन्होंने प्रत्यक्ष निरीक्षण करके भी शाफट सं. -34 के स्थान को निश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि शाफट सं. 34 मलबे से भर गया था। बाद में, खान प्रबंधन ने 39 डिप के समीप 27 स्तर से एक लंबा बोरहोल करके शाफट का स्थान निश्चित करने का प्रयास किया। लेकिन न बोरहोल का संपर्क पुराने शाफट से हुआ और न इससे पानी का रिसाव हुआ। खान प्रबंधन ने यह स्वीकार किया कि पुराने प्लान में पता लगाने, प्लान के छोटे हो जाने की संभावना और सर्वेक्षण और नक्शा बनाने में हुयी चूक के कारण वर्किंग प्लान (प्रदर्श-एम/II) में दर्शायी गयी शाफट सं. 34 की स्थिति में गलती की संभावना थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शायद लंबे बोरहोल की दिशा में परिवर्तन हो गया था। स्पष्टतः करीब 40 मीटर लंबे एक बोरहोल द्वारा केवल 3 मीटर व्यास के एक पुराने शाफट के स्थान का पता लगाने का तरीका बहुत पुराना था।

8.2 1988 में खान प्रबंधक ने कार्य स्थगित करने और संभावित पुराने शाफट सं.-34 के आसपास द्वारा विकास कार्य की दिशा में परिवर्तन करने का सही निर्णय लिया। 26, 27 और 28 स्तरों पर पानी के असामान्य रिसाव के कारण प्रोजेक्शन में परिवर्तन का आवेदन किया गया। इस क्षेत्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर संशोधित प्रोजेक्शन प्लान की मंजूरी खान सुरक्षा महा. द्वारा मार्च, 1988 में दी गयी (प्रदर्श एम/8)

8.3 नवंबर 1989 में संशोधित प्रोजेक्शन 1988 (प्रदर्श-एम 8) के अनुसार जब विकास कार्य हो रहा था तब 42 क्रास कट भाग में एक डाइक संपर्क में आया। बदले में एक नया कार्य क्षेत्र ढूंढने के उद्देश्य मो. कलीम (एम डब्ल्यू. 17) ने सर्वेक्षण कार्यालय में प्लान का अवलोकन किया और 28 स्तर के समीप 40 डिप फेस को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है। इस फेस में किया जा रहा कार्य 1988 से बंद कर दिया गया था। प्रबंधन के इस कथन कि इस क्षेत्र में केवल वायु संचार में सुधार करने के लिये 8 नवंबर 1989 से 40 डिप फेस को पुनः शुरू किया गया था, को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वायु संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए अन्य उपाय भी मौजूद थे। 40 डिप के पास कार्य शुरू करके मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने कोयला खान नियमावली 1957 के विनियमन 127 (5) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया, जिसके द्वारा अपेक्षित था कि कार्य शुरू करने के पूर्व खान सुरक्षा महा. से अनुमति ली जाए दूसरे शब्दों में, ज्यादा पानी रिसाव के कारण जनवरी, 1989 में शाफट

सं. 34 के पास जब कार्य एक बार बंद कर दिया गया था, तब कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127(5) के अन्तर्गत ऐसे कार्यों को अपने आप पुनः शुरू करने के लिए मो. कलीम प्राधिकृत नहीं थे। इस प्रकार मैं समझता हूं कि मो. कलीम ने खान सुरक्षा महा. की अनुमति के बिना और कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127(3) का उल्लंघन करते हुए 40 डिप, जो पानी जमाव क्षेत्र के 60 मीटर के भीतर स्थित है, का विकास कार्य 8 नवंबर, 1989 से शुरु कर दिया।

8.4 अनेक गवाहों ने यह बयान दिया है कि जून 1989 से एक नियमित कार्यदल द्वारा उचित तरीके से एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग बंद कर दी गयी थी बाद में, एडवांस बोरहोल को कथित रूप से सामान्य मजदूरों द्वारा ड्रिल करवाया जाता था। ऐसी ड्रिलिंग के लिये कथित रूप से काम पर लगाये गये ये सामान्य मजदूर नियमित नहीं थे बल्कि उनको नैमित्तिक आधार पर काम में लगाया गया था। ये कर्मकार अपेक्षाकृत अकुशल कर्मकार थे जबकि नियमित ड्रिलर कुशल कर्मकार होते हैं। 40 डिप के दीवारों में किसी फ्लैंक बोरहोल का भी निशान नहीं है। यह संकेत देने के लिये भी कोई रिकार्ड नहीं है कि ऐसे बोरहोल ड्रिल किये गये थे। एडवांस बोरहोल को ड्रिल करने वाले कर्मकारों को प्रबंधन द्वारा गवाह के रूप में पेश किया गया। एजेंट सह-प्रबंधक द्वारा ऐसे एडवांस बोरहोल के ड्रिलिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये किसी सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की गयी थी। एडवांस बोरहोल के प्रावधानों से संबंधित ब्यूसतम सांविधिक रिकार्ड रखने सहित किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के न होने से, ऐसे बोरहोल की ड्रिलिंग के लिये नियमित कर्मकारों और ड्रिलिंग के पर्यवेक्षण के लिये सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति न करने से, ऐसे बोरहोल की लंबाई और दिशा मापने की पद्धति और मेरे निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर फ्लैंक बोरहोल के न होने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 40 डिप फेस में सेन्ट्रल बोरहोल भी ड्रिल नहीं किया गया था।

8.5 कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं, क्योंकि सुरक्षा अधिकारी श्री पी.एल. बनर्जी (एम.डब्ल्यू. 16) ने बताया है कि एक बड़े भू-स्तर के खिसकने के कारण 40 डिप फेस और शाफ्ट सं.-34 के बीच का कोयला बैरियर टूट गया। इंडियन माइन्स मैनेजर्स एसोसिएशन का भी यही तर्क है। श्री चंद्रधारी बराई (एम. डब्ल्यू. 14), जब वे 40 डिप फेस में दूसरी बार शाट फायर कर रहे थे तब उन्होंने फेस के आगे और पीछे छत की चट्टान टूटने की आवाज सुनी। 40 डिप और 28 स्तर के जंक्शन से भूतल पत्थरों के बड़े टुकड़ों का खिसकना और सतह पर पोटहोल बन जाना भूस्तर खिसकने का साक्ष्य बताया गया है। यदि चट्टान टूटने की आवाज हुई होती तो वह न केवल श्री चन्द्रधारी बराई (एम. डब्ल्यू. 14) को सुनाई देती बल्कि 28 लेवल के आसपास उपस्थित अन्य कर्मकारों को भी सुनाई देती। लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अन्य कर्मकारों में किसी चीज की टूटने की आवाज सुनी। मेरे विचार से 27 स्तर और 40 डिप के बीच एक मीटर से भी कम मोटे कोयला रिब और छत पर किसी भी दृष्टव्य प्रमाण के न होने सहित 50 डिप के करीब बड़े भू-स्तर मूवमेंट के बारे में किसी सबूत के न होने के कारण इस प्रकार की घटना के होने की संभावना को नकारता है। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि ऊपर स्थित नेगा सीम में पुराने और परित्यक्त स्टूक के टूटने के कारण हुये भूस्तर मूवमेंट से 40 डिप गैलरी और शाफ्ट सं.-34 के बीच का कोयला यदि बैरियर टूट गया। यदि ऐसा कोई भूस्तर मूवमेंट हुआ रहता तो इससे कहीं-कहीं पॉटहोल होने की बजाए भूमि का बहुत बड़ा भाग नीचे खिसक गया होता। पॉटहोल का बनना पुराने कार्यस्थल से पानी निकालने के बाद आमतौर पर देखी जाती है।

8.6 यह कहना उचित नहीं होगा कि 40 डिप की सतह और 20 स्तर जंक्शन से बड़े पत्थरों की चट्टानों के खिसकने का और इन चट्टानों के करीब आधा पिलर की दूरी पर चले जाने का कारण भूस्तरीय मूवमेंट था, जिसके कारण यह घातक दुर्घटना हुयी। यह संभव हो सकता है कि मूलतः हलका होने के कारण फ्लोर स्टोन ढीला हो गया हो। जब अचानक पानी अंदर पाया तो शायद पत्थरों का ढीला खंड अपनी वास्तविक स्थिति से करीब आधे पिलर की दूरी पर चला गया। किसी भी स्थिति में 40 डिप और 28 स्तर के जंक्शन की सतह पर पत्थर ढीला होने की घटना का इस घातक दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है।

8.7 साक्ष्य के आधार पर मैं यह समझता हूं कि उस पर स्थित परित्यक्त और पानी से भरे नेगा सीम से जुड़े नारायणकुरी सीम में एडवांस 40 डिप गैलरी और पानी से भरे शाफ्ट सं. -34 के बीच सीधे संपर्क के कारण यह घातक दुर्घटना हुई। नारायणकुरी सीम में पानी से भरे शाफ्ट सं.-34 की ओर बढ़े 28 स्तर के समीप 40 डिप गैलरी में सेन्ट्रल और फ्लैंक बोरहोल न होने के कारण यह दुर्घटना हुई। ऐसे दो रहोल का होना कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127(6) के अन्तर्गत अनिवार्य है तथा खान सुरक्षा महा. की कार्य अनुमति द्वारा अपेक्षित है। इसके अलावा 28 स्तर के समीप 40 डिप गैलरी को खान सुरक्षा महा. द्वारा कार्य करने के लिये गैर मंजूरी कृत क्षेत्र में पानी से भरे शाफ्ट सं. 34 की ओर बढ़ाया गया था। अतः गैर मंजूरी कृत क्षेत्र जहां ज्यादा पानी रिसने के कारण जनवरी, 1988 में खनन कार्य बंद कर दिया गया था, की गैलरी में कार्य शुरू करने के पांच दिनों के भीतर यह घातक दुर्घटना थी। यह गैर मंजूरीकृत क्षेत्र खान सुरक्षा महा. द्वारा खनन कार्य के लिये मंजूर क्षेत्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। इस प्रकार यह घातक दुर्घटना अभियोज्य मानवीय लापरवाही के कारण थी।

अध्याय IX

9.1 दायित्व का विश्लेषण

9.2 एजेंट व प्रबंधक

9.3 सुरक्षा अधिकारी

9.4 सहायक प्रबंधक

9.5 सर्वेक्षक

9.6 उच्च प्रबंधक

9.7 अन्य

9.1 दुर्घटना के कारणों का पता लग जाने के पश्चात् इसके लिए जिम्मेदार कौन था इसका पता लगाना होगा। दुर्घटना के कारणों से यह स्पष्ट है कि यह अभियोज्य मानवीय लापरवाही के कारण से हुई। निम्नलिखित पैराग्राफों में मैंने उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए साक्ष्यों का विश्लेषण किया है:—

9.2.1 मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) जून, 1987 से खान प्रबंधक और जुलाई, 1988 से एजेंट-सह-प्रबंधक हैं। अतः वे दिसम्बर, 1987 से 13 नवम्बर, 1989 तक की खान की घटनाओं से पूर्णतः परिचित हैं। खान के पुराने शाफ्ट सं. 33 और 34 के समीप 26, 27 और 28 स्तर के पास के कार्यस्थलों में दिसम्बर, 1987 में ज्यादा पानी की रिसाव की घटना देखी गयी और पूर्व एजेंट श्री के. के. दास (एम डब्ल्यू 18) द्वारा जनवरी, 1988 में उस क्षेत्र में कार्य स्थगित कर दिया गया था। तब उन्होंने ज्यादा पानी रिसाव को देखते हुए विकास की दिशा में परिवर्तन करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक के पास आवेदन दिया। जनवरी, 1988 में खान सुरक्षा महा. को दिए गए संशोधित आवेदन सहित शाफ्ट सं. 34 को 100 मी. की दूरी से बाइपास करने की प्रोजेक्शन योजना (प्रवर्ण—एम/7) के बारे में मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) को प्रबंधक की हैसियत से जानकारी थी। संशोधित प्रोजेक्शन को मंजूर करते हुए अनुमति पत्र (प्रवर्ण एम/8) की प्रति खान सुरक्षा महा. द्वारा प्रबंधक मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) को मार्च, 1988 को भेजी गयी। 1988 में, शाफ्ट सं. 34 की संभावित स्थिति की ओर 27 स्तर से एक लंबा बोरहोल ड्रिल किया गया। चूंकि लंबे बोरहोल का संपर्क शाफ्ट सं. 34 से नहीं हुआ और बोरहोल से पानी का भी रिसाव नहीं हुआ, अतः मो. कलीम (एम.डब्ल्यू. 17) ने यह अनुमान लगाया कि

पुराना शाफ्ट केवल नेगा सीम तक ही था। स्पष्टत: इन अपूर्ण मान्यों के आधार पर मो. कलीम (एम डब्ल्यू 17) जैसे एक अनुभवी प्रबंधक के लिए यह समझना उचित नहीं था कि पुराने शाफ्ट सं. 34 का विस्तार केवल नेगा सीम तक ही था।

9.2.3 नवंबर 1989 में जब खान सुरक्षा महा. द्वारा मंजूर नियमित क्षेत्रों के कार्यस्थल में बहुत सारे डाइक मिले तो मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने सर्वेक्षण कार्यालय से संपर्क करके, और सर्वेक्षक से प्लान के बारे में विचार-विमर्श करके 28 स्तर फेस के समीप 40 डिप में कार्य पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खान सुरक्षा से संबंधित खान सुरक्षा महा. के पूर्व के सभी अनुमति पत्रों और अन्य पत्राचारों का अध्ययन किया। इस प्रकार मो. कलीम इस बात से पूर्ण रूप से अवगत थे कि ज्यादा पानी रिसाव के कारण जनवरी, 1988 में शाफ्ट सं. 34 के समीप कार्य बंद कर दिया गया था। उन्हें कोयला खान नियमावली 1957 के विनियमन 127(5) के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी थी, जिसके द्वारा यह अपेक्षित था कि ज्यादा पानी के रिसाव के कारण जिन कार्य स्थलों को बंद कर दिया गया है उनको खान सुरक्षा महा. की लिखित पूर्व अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। चूंकि ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी अतः नवंबर 1989 से उनके द्वारा स्वयं ही 40 डिप को पुनः शुरू कर दिए जाने की घटना कोयला खान नियमावली 1957 के विनियमन 127(5) का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है।

9.2.2 मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने यह भी स्वीकार किया है कि खान सुरक्षा महा. के अनुमति पत्र (प्रदर्श एम 18) और कोयला खान नियमावली 1957 के अन्तर्गत अपेक्षित एडवांस सेन्ट्रल और फ्लैंक बोरहोल तथा कार्य का प्लान का रिकार्ड नहीं रखा गया। उन्होंने एडवांस होल के ड्रिलिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये किसी सक्षम अधिकारी को भी प्राधिकृत नहीं किया। यह कोयला खान नियमावली 1957 के विनियमन 127(6) (ख) का स्पष्ट उल्लंघन था। एडवांस बोरहोल को ड्रिल करने के लिये उन्होंने नियमित ड्रिलिंग गैंग का भी प्रावधान नहीं किया और इसके स्थान पर इस कार्य के लिये सामान्य मजदूरों जैसे अकुशल कर्मकारों को नैमित्तिक आधार पर कार्य में लगाया। यह दुःखद बात है कि मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17), जिनके पास वर्षों का अनुभव है, इस स्पष्ट खतरे को पहचान नहीं सके। यह खतरा अचानक नहीं आया बल्कि पर्याप्त पूर्वसूचनाओं के लक्षण के बाद ही आया। मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने या तो आत्म विश्वास के कारण या इस गलत धारणा के कारण, कि शाफ्ट सं. 34 नेगा सीम के आगे नहीं गई है, खतरे को भांपने में असमर्थ रहे जिसके परिणामस्वरूप यह घातक दुर्घटना हुयी। अतः मैं उन्हें 13 नवंबर 1989 को महावीर खान में घटित दुर्घटना का प्रमुख दोषी व्यक्ति मानता हूं। लेकिन दुर्घटना के मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) को प्रमुख दोषी मानते हुये भी साक्ष्य देने में उनकी दृढ़ता तथा जिस रीति से उन्होंने सच्चाई से बयान दिया है, प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि वे खान-कार्यों का संचालन कर रहे थे और उन्हें कोयला उत्पादन की उस सीमा के बारे में निर्देश नहीं दिया गया जिसके बाद सुरक्षा विनियमनों का उल्लंघन हो सकता है। जांच के दौरान उचित व्यवहार के लिये मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं।

9.3.1 क्रमानुक्रम में श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू. 16) खान में मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) के बाद अधीनस्थ अधिकारी है। उन्होंने महावीर खान में जून 1988 से सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया। 1983 से उन्होंने उक्त खान के सहायक प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। इस प्रकार वे 1983 से लगातार खान में कार्य करते आ रहे थे। उनकी ड्यूटी में पानी भरने की घटना सहित सभी संभावित खतरों के स्रोत के बारे में प्रबंधक (अर्थात् मो. कलीम) को जानकारी देना शामिल है। उनको खान के विभिन्न भागों का अवलोकन करके प्रबंधक को इस बात की रिपोर्ट देनी होती है कि खान अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमनों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

9.3.2 श्री पी. एल. बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुराने प्लान का अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि शाफ्ट सं.—34 में मलवा भरा है। कार्यक्षेत्रों का प्लान बनाने के लिये उन्होंने खान कार्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्लानों का उपयोग किया। सतह पर शॉफ्ट सं.—34 उनको नजर नहीं आई। जनवरी 1988 में उन्होंने 27 स्तर के पास ज्यादा पानी का रिसाव देखा था और इसके लिये एक लंबा बोर होल ड्रिल करवाने का इंतजाम किया था। उनके बयान के अनुसार लंबे बोरहोल को घुमाव की संभावना के बारे में भी उनको जानकारी थी। उन्होंने खान सुरक्षा महा. की 1984 की अनुमति (प्रदर्शन एम. 15) और 1988 की अनुमति (प्रदर्शन एम 18) का अध्ययन किया था और अनुमति के शर्तों से वाकिफ थे 18 नवंबर, 1989 से 40 डिप फेस को पुनः शुरू किये जाने के बारे में भी उनको जानकारी थी। उन्होंने यह भी बताया कि 40 डिप फेस से पानी का रिसाव नहीं हो रहा था और 8 नवंबर 1989 से कार्य शुरू किये जाने के बाद फ्लैंक और सेन्ट्रल बोर होल के दायरे में फेस को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने बयान दिया कि प्रत्येक कार्यक्षेत्र फेस में एडवांस बोरहोल को आगे बढ़ाने के पहले इन बोरहोलों की ड्रिलिंग सुनिश्चित करने के लिये उनके पास कोई पद्धति नहीं थी। उन्होंने कार्यक्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान ऐसे बोरहोलों की मानिटरिंग सुनिश्चित की तथापि उनके बयान के अनुसार वर्किंग फेसों के निरीक्षणों की कोई निर्धारित समय सूची नहीं थी। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि गैर मंजूरी कृत कार्य क्षेत्र में ज्यादा पानी के रिसाव के बावजूद एडवांस बोर होल तैयार किये बिना 40 डिप फेस को आगे बढ़ाये जाने के कारण यह घातक दुर्घटना हुयी। इन उल्लंघनों के बारे में भी पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू. 16) को जानकारी थी। इस प्रकार उन्होंने कोयला खान नियमावली 1957 के विनियमन 41 ए और बी (iii) के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, क्योंकि पानी भर जाने के एक संभावित स्रोत के रूप में शाफ्ट सं. 34 के बारे में उन्होंने एजेंट-सह प्रबंधक (एम. डब्ल्यू. 17) को सूचना नहीं दी। अपने निरीक्षणों के दौरान न तो उन्होंने सेन्ट्रल और फ्लैंक बोरहोल ड्रिल किये जाने पर ध्यान नहीं दिया बल्कि कोयला खान नि. 1957 के विनियमन 41 ए(1) (एफ) के साथ पठित कोयला खान नि. 1957 के विनियमन 127(6) का उल्लंघन करते हुये बिना बोरहोल बनाये 40 डिप फेस को आगे बढ़ाने की जानबूझकर अनुमति दी। अतः यह स्पष्ट है कि श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू. 16) ने कोयला खान विनियमन 1957 के विनियमन 41 ए (1) (जी.) के साथ पठित विनियमन 127 का उल्लंघन करते हुए 40 डिप फेस के एडवांस बोरहोल की सुरक्षात्मक ड्रिलिंग पद्धति को सुनिश्चित करने के लिये भी कोई उपाय नहीं किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संभावित खतरों को जानते हुए श्री पी. एल. बनर्जी (एम. डब्ल्यू. 16) ने कोयला खान नियमावली 1957 के विनियमन 41 ए (1) (जी.) के अन्तर्गत अपेक्षित सुरक्षा उपायों के पालन करने के लिए उचित कदम नहीं उठाया। अतः इस दुर्घटना के लिये वे भी उत्तरदायी है।

9.4.1 महावीर खान में दो सहायक प्रबंधक थे। एक का नाम श्री के. दस (एम. डब्ल्यू. 19) और दूसरे का नाम श्री एस. के. सेनगुप्ता (सी. डब्ल्यू. 1) है। श्री के. दस ने सहायक प्रबंधक के रूप में महावीर खान में 1979 से कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने 7 नवंबर और 12 नवंबर, 1989 के बीच 40 डिप का दो बार निरीक्षण किया और 12 नवंबर 1989 की दूसरी पारी में भी इसका निरीक्षण किया। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ज्यादा पानी रिसाव के कारण 40 डिप फेस में जनवरी 1988 से काम बंद कर दिया गया था। उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि उपस्थित नेगा सीम में पूर्णतः पानी भरा है। उन्होंने बयान दिया कि 40 डिप फेस उचित लम्बाई के एडवांस सेन्ट्रल और फ्लैंक बोरहोल का प्रावधान किया था लेकिन इतना साफ बयान देने के बावजूद भी न तो उन्होंने इस उद्देश्य के लिये रखे जा रहे किसी रिकार्ड से इस बयान को साबित किया न ही ऐसा स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किया जो यह कह सके कि ऐसे बोरहोल नियमित रूप से बनाये जाते थे। उन्होंने यह भी साबित नहीं किया कि गैलरी आगे बढ़ाये जाते से पहले पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा ऐसे बोरहोल की उचित जांच होती थी।

9.4.2 अतः इस क्षेत्र के सहायक प्रबंधक के रूप में वे यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि को. खा. नि. 1957 के विनियमन 127(6) के साथ पठित को. खा. नि. 1957 के विनियमन पर की अपेक्षाओं के अनुसार 40 डिप फेस में एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग हो रही थी। इस प्रकार से उन्होंने भी कानून का जानबूझकर उल्लंघन किया जिसके कारण दुर्घटना हुयी और इस दुर्घटना के लिये वे भी उत्तरदायी हैं।

9.4.3 दूसरे सहायक प्रबंधक श्री एस. के. सेनगुप्ता (सी. डब्ल्यू. 1) ने खान में अक्तूबर 1989 से ही कार्यभार ग्रहण किया। वे कुछ दिनों के अवकाश पर थे इसके बाद उनको किसी अन्य विकास कार्य का जिम्मा दिया गया और उन्होंने दुर्घटना स्थल के 42 क्रास-कट क्षेत्र का पर्यवेक्षण का कार्य नहीं किया। इस प्रकार इस घातक दुर्घटना के लिये वे उत्तरदायी नहीं है।

9.5.1 श्री पी. एल. ठक्कर (एम. डब्ल्यू 15) 1957 में महाबीर खान के सर्वेयर थे। उन्होंने जनवरी 1988 में 27 स्तर के ज्यादा पानी के रिसाव की घटना देखी। उन्होंने इस बात को अपनी सांविधिक सर्वेक्षक डायरी में रिकार्ड किया तथा यह भी सूचना दर्ज की कि पानी से भरे शाफ्ट सं. 34 का कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है। इस डायरी को प्रबंधक मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया। उनका यह कहना थी कि वे प्रबंधक को इस बात की सूचना दें कि हो रहा कार्य पानी से भरे शाफ्ट सं. 34 के पास पहुंच रहा था। उन्होंने इस मामले में भी ऐसा ही किया। पूर्व एजेंट श्री के. के. दास (एम. डब्ल्यू. 18) ने यह बयान दिया कि उन्हें इस बात का स्मरण है कि श्री पी. एल. ठक्कर (एम. डब्ल्यू. 15) ने उन्हें एक रिपोर्ट दी थी कि 27 स्तर का कार्य क्षेत्र परित्यक्त शाफ्ट सं.—34 की ओर बढ़ रहा था। मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने यह भी स्वीकार किया कि श्री पी. एल. ठक्कर (एम. डब्ल्यू. 15) को डायरी द्वारा पानी भर जाने के खतरे की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया गया था। इस प्रकार श्री पी. एल. ठक्कर (एम. डब्ल्यू. 15) ने को. खा. नि. 1957 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अपनी ड्यूटी का उचित ढंग से पालन किया।

9.5.2 इस स्थिति में, मैं दुर्घटना के लिये श्री पी. एल. ठक्कर (एम. डब्ल्यू. 15) को उत्तरदायी नहीं मानता हूं।

9.6.1 जिरह के दौरान मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने यह बयान दिया कि पर्यवेक्षकों से विचार कर के ही वे कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करते रहे थे। यह एक संयुक्त निर्णय था और यह महाप्रबंधक द्वारा जो कि उनका वरिष्ठ अधिकारी था, आरोपित स्वेच्छाचारी निर्णय नहीं था। इसके अलावा कार्य के दौरान यदि कोई समस्या थी तो वे उत्पादन लक्ष्य पर विचार-विमर्श करने और इसमें संशोधन करने के लिये स्वतंत्र थे। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया कि उत्पादन लक्ष्य में कमी होने की संभावना के कारण उन्होंने अनधिकृत प्रोडेक्शन में स्थित खान में बेरोक-टोक खनन कार्य किया। कार्य अनुमति के लिए खान सुरक्षा महा. को प्रस्तुत आवेदन के संबंध में उन्होंने बयान दिया कि महाप्रबंधक की औपचारिक अनुमति अपेक्षित नहीं है फिर भी उन्होंने ऐसे मामलों पर महाप्रबंधक से विचार किया। उन्होंने बयान दिया कि खान सुरक्षा विनियमनों के प्रवर्तन के लिये एजेंट सह प्रबंधक के रूप में उनके पास पर्याप्त शक्तियां थीं। उनके ठीक ऊपर वरिष्ठ अधिकारी कुनस्तोरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक थे। महाप्रबंधक को क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, जो उनका स्टाफ कर्मचारी है, द्वारा सुरक्षा मामलों पर सलाह दी गयी थी। मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने पानी भर जाने के संभावित खतरे के बारे में क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और महाप्रबंधक से विचार-विमर्श किया था। मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने यह बयान दिया है कि इन अधिकारियों ने उनको सदैव खान सुरक्षा महा. की "अनुमति" का पालन करने की सलाह दी थी। इस प्रकार मो. कलीम (एम. डब्ल्यू. 17) ने यह स्वीकार किया कि 8 नवंबर, 1989 से 28 स्तर के पास 40 डिप में उनके आदेश से कार्य शुरू किया गया और इससे उनके वरिष्ठ अधिकारियों का कुछ लेना-देना नहीं था। इसके अलावा ऐसा कोई गवाह नहीं है जिसने 8 नवंबर 1989 से 40 डिप की गैलरी में कार्य शुरू होने के बारे में महाप्रबंधक को जानकारी के संबंध में जांच न्यायालय के समक्ष बयान दिया हो। इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि महाप्रबंधक को इस बात की जानकारी थी कि सुरक्षा विनियमनों का उल्लंघन किया जा रहा था और गैलरी को बढ़ाते समय एडवांस सेन्ट्रल बोर और फ्लैंक बोर होल नहीं बनाये गये थे। महाप्रबंधक ग्यारह खानों के प्रभारी हैं। जिनमें से एक महाबीर खान है। उनके लिये यह संभव नहीं था कि वे को. खा. नि. 1957 के विनियमन 127 के अनुसार एडवांस बोरहोल बनाने के लिए खान सुरक्षा महा. की अनुमति में निहित शर्तों के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करें। तदनुसार, मैं कुनुस्तोरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक को इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी नहीं मानता हूं।

9.7.1 ओवर मैन और रिसदार जैसे पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा भी चूकें हुयी हैं। इन चूकों का विश्लेषण इस प्रकार है :—

9.7.2 श्री निहिर कुमार चटर्जी (एम डब्ल्यू 10) ओवरमैन जो सामान्य पारी कहे जाने वाली प्रथम पारी में स्थायी रूप से तैनात थे। उन्होंने बयान दिया है कि चूंकि उनका कार्य विविध प्रकृति का है और उनको एडवांस बोरहोल के पर्यवेक्षण के लिये औपचारिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि एजेंट-सह प्रबंधक मो. कलीम (एम. डब्ल्यू 17) आमतौर पर उनसे ऐसे बोरहोल के ड्रिलिंग आदि का पर्यवेक्षण करने को कहा करते थे। श्री सी.डी. सिंह (एम. डब्ल्यू 4) 42 क्रासकट क्षेत्र के शिफ्ट ओवरमैन थे और 12 नवंबर, 1989 की पहली पारी में वे ड्यूटी पर थे। श्री शिवदास चटर्जी ओवरमैन (एम डब्ल्यू 9) और श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू 1) अन्य दो ओवर मैन थे जिनको 12 नवंबर 1989 को क्रमशः दूसरी और तीसरी पारी में ड्यूटी पर लगाया गया था।

9.7.3 श्री निहिर कुमार चटर्जी (एम. डब्ल्यू. 10) और श्री सी.डी. सिंह (एम. डब्ल्यू 4) ने 12 नवंबर, 1989 को पहली पारी में 40 डिप फेस में 5.4 मीटर लंबे एडवांस सेन्ट्रल बोरहोल और दो फ्लैंक बोर होल की निश्चित ड्रिलिंग करने का दावा किया है। श्री शिवदास चटर्जी (एम डब्ल्यू 9) ने उसी दिन की दूसरी पारी में उन एडवांस बोर होलों की नापजोख करने का दावा किया है। इन सभी ओवर मैनों ने यह दावा किया है कि 40 डिप फेस में ज्यादा पानी का रिसाव नहीं था।

9.7.4. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 12 नवंबर, 1989 को 28 स्तर के समीप 40 डिप फेस में कोई एडवांस बोरहोल नहीं था और उसी दिन फेस से ज्यादा पानी का रिसाव हो रहा था। अतः एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग और ज्यादा पानी न रिसने के संबंध में इन ओवर मैनों के बयान पर मैं विश्वास नहीं करता हूं।

9.7.5. श्री फौजदार सिंह (एम डब्ल्यू 1) ही अकेले 12 नवंबर, 1989 की तीसरी पारी में जब दुर्घटना हुयी थी, ओवर मैन को ड्यूटी पर थे और उनके चार्ज में अधिक दूरी पर स्थित तीन क्षेत्र थे। अतः दुर्घटना होने के पूर्व 40 डिप फेस का निरीक्षण करने का अवसर उन्हें नहीं मिला।

9.7.6. श्री राम शंकर सरकार (एम डब्ल्यू 12) और दूदन पाण्डेय (एम डब्ल्यू 13) 12 नवंबर, 1989 की दूसरी और तीसरी पारी में 42 क्रासकट क्षेत्र में ड्यूटी पर थे। मैं उनके बयान पर भी विश्वास नहीं करता कि 40 डिप फेस में एडवांस बोरहोल थे और फेस में से ज्यादा पानी का रिसाव नहीं हो रहा था।

9.7.7. श्री चंद्र धारी बराई (एम डब्ल्यू. 14) 12 नवंबर, 1989 की तीसरी पारी में 40 डिप फेस के शाट फायरर की ड्यूटी पर थे। मैं उनके इस बयान पर भी विश्वास नहीं करता कि उन्होंने दुर्घटना वाले दिन 13 नवंबर, 1989 को शाट फायर करने के पहले 40 डिप फेस के एडवांस और फ्लैंक बोरहोल की जांच कर ली थी।

9.7.8. खान सुरक्षा का प्रथम उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है । खान के सहायक कर्मचारियों से यह अपेक्षा होती है कि वे उनके आदेशों का पालन करें । मैंने पहले भी कहा है कि इस बात की जानकारी एजेंट सह-प्रबंधक (एम.डब्ल्यू. 17) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को थी कि 40 डिप फेस में एडवांस बोरहोल ड्रिल नहीं किये गये है और इससे ज्यादा पानी रिस रहा है । यदि एजेंट सह-प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ कर्मचारी सतर्क रहते और खान सुरक्षा के अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतर्क रहते तो उन्होंने एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग करवा ली होती और ज्यादा पानी के रिसाव की ओर ध्यान दिया होता ।

उनके द्वारा स्थिति को हाथ से निकलने देने के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे ओवरमैनों, सिरदारों तथा सोट फाइररों को गलत संकेत मिले। अतः उनकी गल्तियों के बावजूद भी मैं सर्वश्री मिहिर कुमार चटर्जी (एम डब्ल्यू 10), सी. डी. सिंह (एम.डब्ल्यू 11), शिबदास चटर्जी (एम डब्ल्यू 9) , राम शंकर सरकार (एम डब्ल्यू 12), दोदन पाण्डे (एम डब्ल्यू 13) चन्द्रधारी बराई (एम डब्ल्यू-14) को घातक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं ।

9.7.9 पानी भर जाने के कारण हुई अधिकांश दुर्घटनाओं तथा आपदा के कारणों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि खान में कार्यरत उच्चाधिकारी मूल रुप से जिम्मेदार होते है, परन्तु सामान्य कर्मकार तथा उनके पर्यवेक्षकों जैसे सोटफाइररों, सिरदारों तथा ओवरमैन के लिए सुरक्षा पैरामीटर की जानकारी अपेक्षित है । सामान्यतः पानी भर जाने के कारण हुयी किसी दुर्घटना पहले कुछ अपसामान्य संकेत तथा लक्षणों जैसे बहुत अधिक पानी की सीपेज इत्यादि होती है । यह जरूरी है कि भूमिगत कोयला-खानों में काम करने वाले प्रथम स्तर के पर्यवेक्षक तथा कर्मकार ऐसे सूचक लक्षणो/कारण की पहचान कर उन्हें प्रबन्धन के उच्च स्तर की जानकारी में लाएं। यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षकों तथा कर्मकारों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और सुरक्षा संबंधी ज्ञान उन्हें दिया जाना चाहिए ।

9.7.10 कमकारों के निरीक्षकों के संस्थान तथा सुरक्षा समिति को इस आशय से कानूनी समर्थन दिया गया है कि कमकारों की सुरक्षा में संस्थानों के क्रियाकलाप दुर्घटनाओं तथा गम्भीर संकट की घटनाओं को कम करने में महत्वपूण भूमिका निभाएंगे । इस मामले में कमकारों क निरीक्षक तथा सुरक्षा समिति उनसे अपेक्षित उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे । कमकारों के निरीक्षक ने अस्वीकृत क्षेत्र में 40 डिप को पुनः प्रारम्भ करने के कारणों के बारे में पूछताछ नहीं की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि 40 डिप फेस बोरहोलों खुदायी भी पहले से कर ली जाए । इसक विपरीत उसने मेरे सामने पानी के अपसामान्य सीपेज न होने तथा 12 नवम्बर, 1989 को 40 डिप फेस पर बोर होलों को पहले से ही खुदायी के बारे में गलत बयान दिया ।

9.7.11 लगभग सभी पयवेक्षक स्टाफ और अनेक कमकारों को इस बात की जानकारी थी कि उपरिशायी नेगासीम में काफी पानी जमा था। फिर भी खान में पानी भर जाने के खतरे का मामला सुरक्षा समिति जिसकी बैठक महीने में लगभग एक बार होती है के सामने विचार के लिए नहीं आया ।

9.7.12 यह सही है कि खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबन्धन की है। परन्तु यह भी सही है कि इसे बिना कर्मकारों के तथा ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग के प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इस मामले में यह प्रतीत होता है कि एडवान्स बोर होल को व्यवस्था तथा फेस पर पानी की असामान्य सीपेज की जानकारी कुछ कर्मकारों द्वारा स्थानीय ट्रेय यूनियन नेताओं के ध्यान में लायी गयी थी । दुर्भाग्य से ऐसी सूचना होने पर उनके द्वारा भी कोई अनुकूल कारवाई नहीं की गई।

अध्याय-10

10.1 निष्कर्षों का सा

10.2 सिफारिशें

10.3 खर्चों की वसूली

10.4 आभार

10.1.1 13 नवम्बर, 1989 को महाबीर खान की नारायणकूरी सीम में घटित घातक दुघटना का कारण पुराने पड़े हुए उपरिसायी तथा साफ्ट सं. 34 के कार्यों से जलाक्रांत नेगा सीम से पानी का तेज बहाव था । परित्यक्त तथा जलाक्रांत साफ्ट सं. 34 जिसे 28 लेवल के पास 40 डिप गैलरी को बढ़ाते हुए नाराणकु सीम तक जोड़ा गया था के कारण दुर्घटना हुयी और इससे 6 बहुमूल्य जाने गयी ।

10.1.2 यह दुर्घटना, जलाक्रांत साफ्ट सं. 34 की ओर जाने वाली 40 डिप गैलरी में पर्याप्त संख्यां में मध्य तथा फलैंक बोर होल्स उपलब्ध न कराये जाने क कारण हुयी । यदि ऐसे विकसित बोरहोल्स कवर उपलब्ध कराये गये होते तो अधिकारीगण जलाक्रांत साफ्ट के खतरे के बारे में सावधान हो जाते और इस प्रकार से घातक दुघटना को टाला जा सकता था । ऐसे विकसित बोरहोल्स कोयला खान नियमावली 1957 के 127 विनियम के अन्तर्गत आवश्यक है । खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी कार्य सम्बन्धी अनुमति में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि ऐसे बोरहोल्स उपलब्ध कराये जाने चाहिएं थे । इसके अतिरिक्त 28 लेवल के पास तक 40 डिप गैलरी को खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा कार्य कर के लिए स्वीकृत परिवर्धन प्रक्षेपण से दूर लगभग 100 मी. अनाधिकृत क्षेत्र में बढ़ा दिया गया था । यह घातक दुर्घटना 28 लेवल के पास 40 डिप गैलरी जहां पानी की अपसामान्य सीपेज के कारण जनवरी, 1988 में खनन कार्य रोक दिया गया था, में कार्य प्रारम्भ किं जाने के मात्र 5 दिन के भीतर ही हो गयी । मेरे विचार से यह घातक दुर्घटना सर्व श्री मों. कलीम , एजेंट तथा प्रबन्धक तथा पी. एल. बनर्जी सुरक्षा अधिकारी तथा महाबीर खान के सहायक प्रबन्धक श्री के. दत्ता की गम्भीर लापरवाही के कारण घटी है । इन तीनों अधिकारियों ने कोयला खान नियमावली 1957 के विनियम 127 ले प्रावधानों तथा साथ ही साथ खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी की गयी कार्यानुमति में निर्धारित शर्तों का उल्लघंन किया है ।

10.2.1. हमारे देश की भूमिगत कोयला खानों में बाढ़ के कारण अन्य घोर विपदाओं की तरह यह घातक दुर्घटना कोयला खान विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुपालन में मनुष्य द्वारा की गयी चूक के कारण हुयी । जबकि संगत कोयला खान विनियमों का अनुपालन ही ऐसे घातक और घोर विपदाओं को रोक सकता है, चिन्ता की बात यह है कि समय-समय पर इसकी पुनरावृत्ति होती है । मेरे विचार में कर्मकारों को तथा प्रथम पंक्ति के पर्यवेक्षक कर्मचारियों जैसे शॉट फाइर्स, सिरदारों तथा ओवर मैनों को इस बारे में कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अवगत कराना बाढ़ संबंधी खतरे के संकेतों के बारे में पहले से सचेत रहने के लिए उपयुक्त रूप से उन्हें प्रशिक्षित करना जिससे कि समय पर दोष निवारक उपाय किए जा सकें । मैंने यह भी पाया कि कर्मकारों के निरीक्षण के स्थान तथा सुरक्षा समिति जो कि काफी हद तक सुरक्षा चेतना जगा सकती है को सुदृढ़ करने की पर्याप्त गुंजाइश है ।

10.2.2. चूंकि जलाक्रांत वर्किंग्स आने वाले समय में कोयला खनन में सम्भावित जोखिम के स्रोत बने रहेंगे । इन जोखिमों का अधिक यथार्थ रूप से पता लगाने के लिए किसी प्रणाली की खोज अविरल रूप से की जानी चाहिए । *****बाढ़ के सम्भावित जोखिमों के निर्धारण के लिए मानवोचित निर्णय पर भरोसा करने में अनेक कठिनाइयां है जैसा कि कोयला खानों में अनेक दुर्घटनाओं तथा घोर संकटों की प्रचुर मात्रा से ज्ञात होत है । अतः भारत के कोयला उद्योग को जलाक्रांत कार्यप्रणाली की पहचान तथा रूप रेखा बनाने के लिए अधिक विकसित तकनीक अपनानी चाहिए जिससे कि बाढ़ के समय मानव द्वारा की गयी चूक से दुर्घटनाएं तथा भारी संकट उत्पन्न न हों । संक्षेप में, मैं निम्नलिखित सिफारिशें करता हूं :—

(i) शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में वृद्धि के द्वारा जोखिमों का पता लगाने की आवश्यकता को देखते हुए प्रथम पंक्ति के पर्यवेक्षकों तथा कर्मकारों के अभिज्ञान का विकास करना ;

(ii) सुरक्षा समिति तथा कर्मकारों के निरीक्षक संस्थानों को सक्रिय करना जिससे कि वे भूमिगत कोयला खानों की सुरक्षा आवश्यकताओं को तर्क संगत बना सके ;

(iii) भूमिगत कोयला खान कर्मचारियों के मन में सुरक्षा कानूनों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता को बैठाना ;

(iv) जलाक्रांत कार्यों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए ड्रीलिंग एडवान्स बोरहोल्स के लिए अर्धसंरचना व्यवस्था ;

(v) भूमिगत संचित जलाशयों का पता लगाने तथा रूप रेखा बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिये नयी तकनीकियों का विकास ।

(vi) संकट के समय खान में फंसे हुए खनिकों के लिए केन्द्रीयकृत स्थान पर बर्डे डायमीटर आकार की बोरिंग सुविधाओं की व्यवस्था ।

10.3. रिपोर्ट के अन्तिम भाग का संबंध न्यायालय के खर्चों की वसूली से है । खान अधिनियम, 1952 की धारा 63 के अन्तर्गत बनायी गयी खान नियमावली , 1955 के नियम 22 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी जांच न्यायालय को यह पता चलता है कि दुर्घटना प्रबन्धन की असावधानी अथवा लापरवाही के कारण हुयी है तो न्यायालय इस पर आयव्ययों की वसूली मालिक एजेंन्ट अथवा मैनेजर से वसूल करने के निर्देश जारी कर सकता है, रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह दुर्घटना एजेंट तथा मैनेजर की लापरवाही और अन्य अधिकारियों द्वारा कोयला खान विनियमावली, 1957 के विनियम 12.7 का अनुपालन न किए जाने के कारण हुयी । लेकिन क्योंकि खर्चो की वसूली के आदेश करने के बारे में जांच न्यायालय का अपना विवेकाधिकार है और क्योंकि न्यायालय के खर्चो को न्यूनतम रखा गया है तथा चूकचर्ता अधिकारी केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के हैं । मैं आदेश देता हूं कि जांच न्यायालय की लागत की वसूली किसी भी पक्ष अथवा कर्मचारी से नहीं की जायेगी ।

10.4. रिपोर्ट को समाप्त करने से पूर्व मैं निर्धारणकर्ता श्री बी. एन. तिवाड़ी और प्रो. ए.के. घोष की सहायता के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं । वे न्यायालय की लगभग सभी बैठकों में उपस्थित रहे । अनेक व्यवस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने कोर्ट के सामने साक्ष्य तथा दलीलों पर विचार-विमर्श तथा उनका मूल्यांकन करने में अपना बहुमूल्य समय दिया । मैं, इस्टर्न कोलफील्ड लि., उनके एडवोकेट श्री बी. जोशी तथा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों जो कि इस कार्यवाही में पक्षकार थे का भी आभारी हूं । मैं रिपोर्ट के इस भाग में उनके नामों का भी उल्लेख करना चाहता था किन्तु स्थानाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया तथापि कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों जिन्होंने इस कोर्ट के समक्ष शहादत के बारे में तथा जिरह में भाग लिया है कि एक सूची अनुलग्नक XIV पर है। मैं, श्री एस.सी. चटर्जी, क्षेत्रीय निदेशक सेन्ट्रल माइन प्लानिंग तथा डिजायन इन्स्टिट्यूट, आसनसोल और उनके अधिकारियों जिन्होंने आसनसोल में इस न्यायालय को कार्य करने के लिए अधसंरचना सहायता उपलब्ध करायी, के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं

ह०

(पी.सी. होता)

महाबीर कोर्ट आफ इन्क्वारी

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली-110001

ह./- ह./-

(बी.एन.तिवाड़ी) (प्रो.ए.के.घोष)

निर्धारणकर्ता निर्धारणकर्ता

अनुलग्नक-I

महाबीर माइन में 13 नवम्बर, 1989 को घटित घातक दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्तियों की सूची ।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	आयु
1.	सीताराम दुसाद	टिम्बर मजदूर	52
2.	पन्ना लाल तिवारी	,, ,,	54
3.	आमन्दी तुरी	लोडर	45
4.	बिशु हाजम	विस्फोटक ले जाने वाले	51
5.	अंगु नुनिया	लाइन मजदूर	54
6.	झारी बिसरा	लोडर	54

अनुलग्नक-II

जांच न्यायालय

की नियक्ति संबंधी

अधिसूचना

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल, 1990

का. आ. 327(ई):—13 नवम्बर, 1989 को पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में स्थित मैसर्स ईस्ट्रन कोलफील्ड लि० की महाबीर कोलियरी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई व्यक्तियों की जाने गयी थी;

और केन्द्रीय सरकार का विचार है कि दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की तात्कालिक जांच की जाये ;

अतः केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के. सी. शर्मा, अवकाश प्राप्त अपर सचिव श्रम मंत्रालय को इस बारे में जांच करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करती है और उस जांच के लिए निर्धारकों के रूप में नियुक्त करती है।

(1) श्री बी. एन. तिवाड़ी,
महासचिव
कोलयरी मजदूर सभा (एटक),
जी. टी. रोड, आसनसोल,
जिला बर्दवाई (पश्चिम बंगाल)

(2) प्रो. ए. के. घोष,
प्रोफेसर आफ माईनिंग इंजीनियरिंग,
इंडियन स्कूल आफ माईन्स,
धनबाद —826004 (बिहार)

[फा. सं. एन 11015/1/90 आई एस एच-II]

ह०/—

आर. टी. पाण्डे, उप सचिव

अनुलग्नक–III

श्री पी. सी. होता की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II—खण्ड 3 (ii)]

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी 1991

का. आ. 3(ई):—भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 327(ई) दिनांक 16 अप्रैल, 1990 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी. सी. होता, अपर सचिव, भारत सरकार श्रम मंत्रालय को श्री के. सी. शर्मा के स्थान पर महावीर कोलियरी में हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करती है।

[फा. सं. एन-11015/1/90-आई एस एच–II]

ह./-

आर. टी. पाण्डेय, उप सचिव

अनुलग्नक–IV

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को श्री पी. सी. होता द्वारा दी गई अंडरटेकिंग।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायालय आवेश सं. 7650(डब्ल्यू) 1990 में श्री पी. सी. होता, महावीर कोलयरी दुर्घटना जांच न्यायालय का लिखित वक्तव्य—कोल माईन्स आफिसर्स आफ इंडिया बनाम महावीर कोलयरी दुर्घटना जांच न्यायालय

मुझे, 13-11-1989 को महावीर कोलयरी में हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए श्री के. सी. शर्मा के स्थान पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय अधिसूचना सं. एन–11015/1/90 आई. एस० एच–II, दिनांक 3-1-1991 (प्रति संलग्न) के अनुसार जांच न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है।

मेरा कथन है कि उक्त जांच के संचालन के लिए श्री के. सी शर्मा द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूं। मुझे यह भी कहना है कि संबंधित पक्षकारों से विचार विमर्श करके उक्त जांच संचालन के लिए मैं अपनी प्रक्रिया अपनाऊंगा।

पी. सी. होता

महावीर कोलयरी दुर्घटना जांच न्यायाल

अनुलग्नक —V

कोर्ट आफ इन्क्वारी द्वारा पक्षकारों के लिए जारी की गयी सूचना

सूचना

महावीर कोलयरी में हुए दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खान अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 3(ई) दिनांक 3-1-1991 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को श्री के. सी. शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया है तथा खान नियमावली, 1955 के नियम 21 के अधीन अपेक्षित जांच न्यायालय की प्रक्रिया अपनाने के लिए न्यायालय की प्रथम बैठक सी. एम. पी. श्री. आई. (समिति कक्ष), आसनसोल में दिनांक 8-4-1991 को पूर्वाह्न 10 बजे होगी। अतः आप से अनुरोध है कि उक्त तिथि को दिए गये समय पर न्यायालय में उपस्थित होने की कृपा करें।

2. आपसे अनुरोध है कि आपके संगठन की ओर से पहले से ही दायर किए गये लिखित ब्यानों में किए गये अनुरोधों को प्रमाणित करने के लिए जिरह किए जाने वाले प्रस्तावित गवाहों की क्रमवार पूरी सूची जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि न्यायालय के सामने कौन से गवाह ब्यान देंगे, प्रस्तुत करें।

ह./-

(पी. सी. होता)

महावीर कोलयरी कोर्ट आफ इन्क्वारी

सेवा में

सभी पक्षकारों को प्रेषित

अनुलग्नक–VI

प्रबन्धन के गवाहों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	गवाह की संख्या
1	2	3	4
1.	सर्वश्री फौजदार सिंह	ओवर मैन	एम डब्ल्यू —1
2.	रामचन्दर महतो	माईनिंग सिरदार	एम डब्ल्यू—2
3.	शालिगराम सिंह	पिट क्लर्क	" —3
4.	नूर मोहम्मद	लोडर	" —4
5.	गणेश राय	यू. जी. लोडर	" —5
6.	जयदेव मोंडल	माईनिंग सिरदार	"—6
7.	भूलन मोंडल	शॉट फाइरर	"—7
8.	रमेश माझी	फिटर बोरिंग आपरेटर	—8
9	शिवदास चटर्जी	ओवर मैन	" —9
10.	मिहीर कुमार चटर्जी	ओवर मैन	"—10
11.	सी. डी. सिंह	ओवर मैन	"—11

1	2	3	4
12.	रामशंकर सरकार	माईनिंग सिरदार	एम डब्ल्यू—12
13.	वोदन पाण्डे	माईनिंग सिरदार	"—13
14.	चन्द्र धारी बराई	शाटर फाईरर	" —14
15.	पी. एल. ठक्कर	सर्वेयर	"—15
16.	पी. एल. बनर्जी	सुरक्षा अधिकारी	"—16
17.	मोहम्मद कलीम	प्रबन्धक एजेन्ट	"—17
18.	के. के. दास	एजेन्ट	"—18
19.	के दत्ता	सहायक प्रबन्धक	"—19

अनुलग्नक VII

कर्मचारी यूनियन के गवाहों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	गवाह संख्या
1.	कुबदीपा दास	ड्रिलर	यू. डब्ल्यू-1
2.	मुन्ना तुरी	यू.जी. लोडर	"—2
3.	छदी हरिजन		"—3
4.	रामचन्द्र महतो	लोडर	"—4
5.	भागी राजभार	ड्रेसर ड्रीलर	"—5
6.	राम सुधार चौबे	ओवर मैन	"—6

अनुलग्नक VIII

कोर्ट गवाहों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	गवाह संख्या
1.	श्री सन्त कुमार सेनगुप्ता	सहायक प्रबन्धक	सी. डब्ल्यू—1

अनुलग्नक

प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची

(दस्तावेज-एम)

क्रम संख्या	दस्तावेज संख्या	दस्तावेजों का ब्यौरा
1.	एम/1	श्री स्वपन घटक का हैंड प्लान (42-एल-धारा) (कब्जे में किए गये प्रलेखों का सी 5)
2.	एम 2 (ब)	दि बंगाल कोल कं. लि. रानीगंज कोलियरी रानीगंज सीम का प्लान जिसे ए.एम.पी.नं. 1121 से निकाला गया (ट्रेसिंग नं. 1746, 25-7-25)

क्रम सं.	दस्तावेज संख्या	दस्तावेजों का ब्यौरा
3.	एम/2 (ख)	दि बंगाल कोल कं. लि., रानीगंज कोलियरी, रानीगंज सीम का प्लान जिसे ए.एम.पी. नं. 1121 से निकाला गया (ट्रेसिंग नं. 1743, 25.7.25) ए० एम० पी०नं० 1211 के फार्म नं. 1, से (दो पृष्ठ)
4.	एम/3	महाबीर कोलियरी के एजेन्ट से खान सुरक्षा महानिदेशक को लिखे गये पत्र संख्या इ.सी.एल./एम.बी (पी)/4009 दिनांक 16 17/12/83 के पत्र की फोटो प्रति
5.	एम/4	विकास अनुमति प्लान, प्लान सं. ई.सी.एल./एम.बी./एम.यू/20, दिनांक 16-12-1983
6.	एम/5	पत्र सं. एस 3/173 (बी.डी.) (एम.बी.)II-बी/84/1061 दिनांक 12-3-1984 की फोटो प्रति
7.	एम/6	महाबीर कोलियरी के एजेन्ट द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक को भेजे गये पत्र सं. ई.सी.एल./एस.बी.आई. विका 88/198 दिनांक 19-1-88 की फोटो प्रति
8.	एम/7	सी.एम.आर. 105, 126 तथा 127 के अधीन नेगा सीम की जलाक्रांत कार्यों के नीचे/एन/के सीम में प्रस्तावित विकास कार्यों का परिवर्तित प्रक्षेपण दर्शाने वाला महाबीर कोलियरी (आर) का इ सी एल प्लान सं. ई. सी.एल./एम.बी./62, दिनांक 16-1-88
9.	एम/8	खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा एजेन्ट महाबीर कोलियरी को लिखे दिनांक 22-3-88 के पत्र सं. एस. 3/22-03-062/11ए/88 की फोटो प्रति
10.	एम/9	प्लान सं. इ.सी.एल./एम.बी./20 दिनांक 16-12-83 के प्रक्षेपणों पर अध्यारोपित प्लान सं. इ.सी.एल./एम.बी./62/62 दि. 16-1-88 के प्रक्षेपण दर्शाने वाला इ.सी.एल. प्लान का भाग
11.	एम/10	खान सुरक्षा महानिदेशक से प्राप्त दिनांक 2-8-83 के पत्र सं. एस-3/173 (बी डी) (एम बी) 11-बी/83/4472 की फोटो प्रति
12.	एम/11	अनुरेखण कागज पर सं. 13 दिनांक 14-5-75 से 24-4-88 तक नारायनकुरी सीम की कार्य योजना (जब्त किए गये प्रलेखों का सी 4) (केवल अनुरेखण)
13.	एम/12	दुर्घटना के पश्चात महाबीर कोलियरी की इ सी एल नारायणकुरी सीम से प्राप्त दुर्घटना स्थल का नक्सा
14.	एम/12(क)	दिखाये गये स्थल "क" से स्थल "ख" से पत्थर के बड़े टुकड़े को हटाने की स्थिति दर्शाने वाला नक्शा ।

अनुलग्नक

कर्मकारों की यूनियन के दस्तावेजों की सूची (दस्तावेज—डब्ल्यू)

क्रम सं.	दस्तावेजों का ब्यौरा	दस्तावेज की संख्या
1.	श्री स्वपन घटक का हाथ का नक्शा	डब्ल्यू/1
2.	इ.सी.एल. पत्र सं. जी.एम./के.एम.टी. 17/540/88 दिनांक 25-7-88 (जब्त किए गये प्रलेखों का बी-1)	डब्ल्यू/2
3.	इ.सी.एल. पत्र सं. ई.सी.एल./एम.बी. (आर.) 98 सुरक्षा/297 दिनांक 22-2-89 (जब्त किए गये प्रलेखों का बी. 2)	डब्ल्यू/3
4.	इ.सी.एल.पत्र सं. इ.सी.एल./एन.बी. (आर.) '88 सुरक्षा/318 दिनांक 28/30-1-88	डब्ल्यू/4
5.	भूतपूर्व एजेंन्ट श्री के.के. दास की अनुदेश पुस्तिका के पृष्ठ सं. 1 से 3 (1-11-88 से 10-13-88 तक) जब्त कागजों का ए-6	डब्ल्यू/5
6.	इ.सी.एल.पत्र सं. इ.सी.एल./सुरक्षा आर एन यू. 1683 दिनांक 14-1-88 (जब्त प्रलेखों का बी-8)	डब्ल्यू/6
7.	जांच न्यायालय को दिए गये इ.सी.एल. के मुख्य शपनों के साथ संलग्न प्लेट सं. 4	डब्ल्यू/7
8.	खान अधिनियम की धारा 7(2) के अन्तर्गत खान सुरक्षा द्वारा जब्त किए गये रजिस्टर, अभिलेख पत्र तथा नक्शों की सूची	डब्ल्यू/8
9.	पत्र सं. एम 11.591 (बी) 87 14040 एफ. दिनांक 30-11-1961	डब्ल्यू/9
10.	एन.के.सीम में पानी के खतरे संबंधी नक्शा (जब्त किए गये प्रलेखों का सी. 1)	डब्ल्यू/10

अनुलग्नक XI

महाबीर खान का संक्षिप्त वर्णन

महाबीर खान जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह खान लगभग 23°36' से 23°38' अक्षांश उत्तर तथा 87°05' से 87° 07' देशांतर पूर्व के बीच स्थित है। इस खान का कुल सतही क्षेत्र लगभग 612 हेक्टेयर है।

इस खदान का कार्यालय पूर्वी रेलवे के रानीगंज रेलवे स्टेशन के लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा ग्रांड ट्रंक रोड के लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रानीगंज रेलवे स्टेशन को जी.टी. रोड से जोड़ने वाले एप्रोच मार्ग से निकलती हुई एक पक्की सड़क इस खदान के कार्यालय को जाती है।

महाबीर खदान मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की है जिसका गठन देश की गैर कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लगभग दो वर्ष पश्चात् 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में किया गया था। राष्ट्रीयकरण के समय आस-पास कार्यरत निजी स्वामित्व वाली तीन खानों तथा एक बन्द पड़ी खदान को मिलाकर महाबीर खदान का गठन किया गया था। तीन कार्यरत खानें महाबीर काजोरा सिलेक्टेड तथा सीयरसोल खानें थीं। बन्द पड़ी रानीगंज खान तत्समय को मैसर्स बंगाल कोल कंपनी की थी।

महाबीर खदान की मुख्य विशेषतायें यह हैं उसकी भू-संपत्ति पर पुराना इगरा तथा नया इगरा गांव और रानीगंज कस्बे का कुछ भाग है हावड़ा से दिल्ली जाने वाला मुख्य पूर्वी रेल मार्ग उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व को जाता है तथा महाबीर खदान की भू-संपत्ति को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। महाबीर खदान तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हमारे देश में कोयला खनन के लिए प्रथम केन्द्र के रूप में मान्यता दी गयी थी।

कोयला खान विनियमावली, 1957 के विनियम 127 का पाठ :

127. भूमिगत जल-प्लाम से खतरा :—

(1) किसी खान अथवा अन्य पास वाली खान के कार्यों से पानी अथवा अन्यतरल पदार्थ के हमले को रोक-थाम के लिए प्रत्येक खान में समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(2) जहां निम्नलिखित में से किसी में कार्य किया जा रहा हो—

(2) जहां निम्नलिखित में से किसी में कार्य किया जा रहा हो–

(1) किसी सीम अथवा भाग अन्य सीम के नीचे अथवा भाग, में या

(2) सीम के किसी स्थान अथवा भाग में जो कि किसी नीची सीम अथवा भाग में किसी दूसरे स्थान की अपेक्षा किसी नीचे सीम पर है अथवा

(3) सीम के किसी ऐसे स्थान में जहां से कोई त्रुटि उपरी सीम के द्वारा जाती है, जिसमें पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ का संचय शामिल है अथवा हो सकता है,

कार्यस्थलों में पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ के आने को रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए जायेंगे।

3. कोई भी कार्य जो कि किसी ऐसे अप्रचलित अथवा परित्यक्त कार्य के 60 मीटर की दूरी के अन्दर किए गये हों (वह ऐसे कार्य नहीं होंगे जिनका निरीक्षण किया गया हो और पानी अथवा अन्य किसी तरल पदार्थों के संचयन से मुक्त पाया गया हो), चाहे वह उसी खान अथवा किसी पास वाली खान में आगे नहीं बढ़ाये जायेंगे जब तक कि मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्ण अनुमति न हो और ऐसी शर्तों पर जो मुख्य निरीक्षक इस प्रकार की अनुमति में निर्दिष्ट करे।

परिभाषा:– इस उपविनियम के प्रयोजनार्थ उपयुक्त कार्य स्थलों के बीच की दूरी का अर्थ होगा उसी सीम के कार्य स्थलों अथवा किन्हीं दो सीम या भागों के बीच कम से कम दूरी चाहे वह समतल सीधे (ऊर्ध्वाकार) अथवा झुके रूप से, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी दिशा में मापी गयी हो।

2 (* *)

उपर्युक्त विनियमों के उप-विनियम (4), (5) और (6) को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"3(4)(क) उप-विनियम (3) में उल्लिखित किसी कार्य को बढ़ाने संबंधी अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्लान तथा भाग की दो प्रतियां जिसमें निम्न बातें दर्शाई गयी हों:–

(1) उस कार्य के बारे में ऐसे सभी कार्यस्थल जो प्रयोग में न लाए जा रहे हों अथवा परित्यक्त कार्य स्थल तथा उपरी सतह से ऐसे सभी अप्रचलित और परित्यक्त कार्य स्थलों की गहरायी की रूप रेखा।

(2) प्रस्तावित उस कार्य की रूप रेखा सहित तथा कार्यविधि जिसके लिए अनुमति मांगी गयी है।

(3) उप-विनियम की धारा (i) अथवा (ii) में विनिर्दिष्ट कार्य से सम्बन्धित त्रुटियों, नहरों (पतनालों) तथा अन्य भौगोलिक बाधाएं, और

(4) ऐसी अन्य कोई सूचना जो प्रबन्धन के पास उपलब्ध हो तथा अन्य ब्यौरे या सूचना जिसकी मुख्य-निरीक्षक को अविश्यकता हो।

(ख) उप विनियम (5) में उल्लिखित किसी वर्किंग के विस्तार केलिए आगे जब कभी अनुमति प्रदान की जाती है, तो उसका विस्तार तथा प्लान स्वीकृत विधि के अन्तर्गत तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा ऐसी अनुमति से हट कर कुछ भी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिए भी मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो।

5. जब कभी पानी का रिसाव जो सामान्यता सीम में अथवा किसी कार्य स्थल पर दिखायी नहीं देती, अथवा जहां ऐसा संदेह या शक हो तो ऐसा कार्य तुरन्त रोक दिया जायेगा और ऐसे रिसाव आदि के बारे में मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को शीघ्र सूचना दी जायेगी। ऐसे कार्य मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्वानुमति के बिना कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और यदि अनुमति मिल जाती है तो उसमें मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के तहत ही वह कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।

(6) (क) उप-विनियम (3) अथवा उप-विनियम (5) में उल्लिखित किसी कार्य-स्थल की ऊंचाई 2-4 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा कार्यस्थल के मध्य भाग के आस-पास कम से कम एक बोरहोल तथा प्रत्येक सिरे पर पर्याप्त बोर-होल्स और कार्यस्थलों के ऊपर तथा नीचे जहां भी आवश्यक हो वहां ज्यादा से ज्यादा पांच मीटर की दूरी पर बोर होल्स किए जायेंगे। ऐसे सभी बोर होल को चालू स्थिति में रखा जायेगा, और ये बोरहोल्स कार्य के पहले पर्याप्त दूरी पर और यह दूरी किसी भी स्थिति में तीन मीटर से कम नहीं होगी और उन्हें निरन्तर चालू स्थिति में रखा जाएगा ये पूर्वोपाय/सावधानियां किसी अधिकारी, जिसके पास मैनेजर अथवा ओवर मैन का प्रमाण-पत्र विशेष तौर इस प्रयोजनार्थ हो की सीधी निगरानी में किए जायेंगे।

(ख) धारा (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जिल्द-बन्द पृष्ठों वाली पुस्तिका में, जिसमें ऐसे कार्य स्थल को वास्तविक ऊंचाई तथा चौड़ाई चालू बोर होलो की संख्या प्रत्येक बोर होल की सम्बाई, प्रत्येक बोर होल का स्थान तथा दिशा जिस ओर वह चलाया जा रहा था दर्शाने वाला अभिलेख रखा जायेगा तथा उसमें की गयी प्रविष्टियों को ऐसा सक्षम व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा और उस पर हर रोज प्रबन्धक प्रति हस्ताक्षर करेगा। प्रत्येक ऐसे कार्य के उपयुक्त विवरण दर्शाने वाला प्लान तथा भाग तैयार किया जाऐगा और रखा जायेगा तथा और उन्हें हर 15 दिन में कम से कम एक बार अद्यतन किया जायेगा।

(7) जब तक मुख्य निरीक्षक द्वारा उप-विनियम (8) के अन्तर्गत लिखित में सुस्पष्ट छूट प्रदान नहीं की जाती है तब तक उप-विनियम (6) के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा, अर्थात उप-विनियम (3) अथवा उप-विनियम (5) में उल्लिखित किसी कार्य का विस्तार करने चाहे ऐसे कार्यों को बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी हो अथवा नहीं उप-नियम (6) के समस्त अथवा किसी प्रावधान का अनुपालन अपेक्षित है।

(8) यदि मुख्य निरीक्षक इस बात से सन्तुष्ट है कि किसी खान अथवा उसके किसी भाग में परिस्थितियां उप-विनियम में विनिर्दिष्ट सभी अथवा कोई प्रावधान इस प्रकार का है कि उसका अनुपालन अनावश्यक अथवा अव्यावहारिक है तो वह लिखित में आदेश निकाल कर उप-विनियम (6) की लिखित सभी अथवा किन्हीं शर्तों तथा अपेक्षाओं में ढील दे सकता है परिवर्तित कर सकता है अथवा समाप्त कर सकता है और यदि वह समझे कि किसी खान अथवा उसके किसी भाग में परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके बारे में अपेक्षित अतिरिक्त पूर्वोपाय किए जाने हैं, तो वह, उपविनियम (6) में विनिर्दिष्ट उन पूर्वोपायों के अतिरिक्त लिखित में एक आदेश द्वारा ऐसे अतिरिक्त अपेक्षित पूर्वोपाय कर सकता है।

अनुलग्नक—XIII

दुर्घटना स्थल का चित्र

दुर्घटना स्थल की ओर गैलरी प्रवेश द्वारा से दिखाया गया 40 डिप गैलरी का वाहिनी रिव साइड का चित्र ।

चित्र (क) कनैक्शन स्थल से लगभग 20 फट दूर

चित्र (ख) आगे 20 फीट दूर दुर्घटना स्थल का चित्र

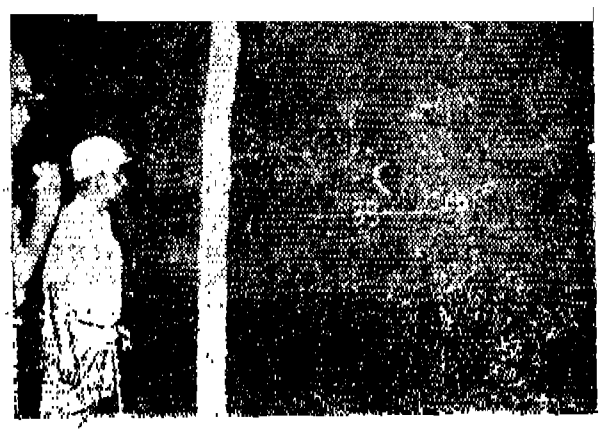

चित्र (ग) आगे 20 फीट

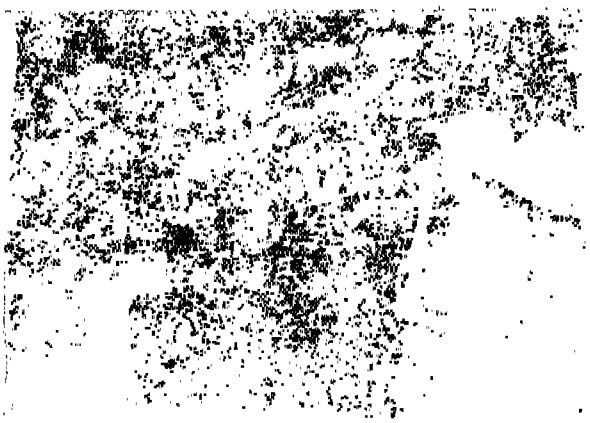

चित्र (घ) गैलरी का अन्तिम छोर

चित्र (ङ) : गैलरी का अन्तिम छोर

अनुलग्नक— 14

संगठन तथा प्रतिनिधियों की सूची जिन्होंने गवाहों से जिरह की।

क्रम संख्या	नाम	संगठन का नाम जिसका प्रतिनिधित्व किया
1.	श्री ए. मैती, सचिव	सी. एम. एस. (एटक)
	श्री सुनील सेन, संगठन सचिव	सी. एम. एस. (एटक)
2.	श्री जे. पी. गोस्वामी, सचिव	सी. एम. एस. आई (सीटू)
3.	श्री बी. एन. शर्मा	कोल मजदूर यूनियन (इंटक)
	श्री एल. एन. भट्टाचार्या सचिव (सुरक्षा)	आई एन एम डब्ल्यू एफ (इंटक)
	श्री एस. एस. चौधरी, सचिव	सी० एम० यू (इंटक)
4.	श्री शक्ति पाडा चटर्जी, संयुक्त सचिव,	सी०एम०सी० (एच०एम०एस०)
	श्री जयंत पोद्दार, महासचिव	सी०एम०सी० (एच०एम०एस०)
5.	श्री एच०एस० मुखर्जी, उपाध्यक्ष	के. एम. सी.

1	2	3
	श्री राकेश कुमार, मुख्य संगठन सचिव	के एम सी
6.	श्री डी. एम. दास, महासचिव,	आई एन एन ई डब्ल्यू ए
7.	श्री के प्रसाद, महासचिव,	ए आई एम एस
8.	श्री जे के बनर्जी, महासचिव	आई एन एम ओ एम एस ए
9.	श्री बी जोशी, एडवोकेट	ई सी एल
10.	श्री डी. डी. मुखर्जी, श्री जे. बनर्जी, उपाध्यक्ष	सी एम ओ ए सी एम ओ ए
11.	श्री ए. के. मजूमदार	आई एम एम ए

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th August, 1992

S.O. 69.—In pursuance of section 27 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby publishes, as Annexure to this notification, the following report submitted to it under sub-section (4) of section 24 of the said Act by the Court of Inquiry appointed to hold an inquiry into the causes of and circumstances attending the accident which occurred on the 13th November, 1989 in the Mahabir Colliery M/s Eastern Coalfields Limited (A Subsidiary of Coal India Limited) in the district of Burdwan, State of West Bengal).

"Report of the Court of Inquiry on the accident which occurred on the 13th November, 1989 at Mahabir Colliery in Burdwan District, State of West Bengal.

[File No. N-11015/2/92-ISH-II]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

REPORT UNDER SECTION 24 OF THE MINES ACT 1952 ON THE FATAL ACCIDENT DUE TO INUNDATION AT THE MAHABIR MINE OF MESSRS EASTERN COALFIELDS LIMITED ON NOVEMBER 13, 1989

[VOLUME I—Main Report with Annexures—VOLUME II—Oral Depositions VOLUME III—Exhibits]

On January 3, 1991 the Ministry of Labour issued a Notification under Section 24 of the Mines Act 1952 appointing me to inquire into the causes of and the circumstances attending the fatal accident on November 13, 1989 resulting in loss of six lives at Mahabir Mine near Asansol. Shri B. N. Tewari, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, Asansol and Prof. A. K. Ghose, Professor of Mining Engineering, Indian School of Mines, Dhanbad, were appointed Assessors to the Court of Inquiry.

2. I commenced the Court of Inquiry on April 7, 1991 with a visit of the site of the accident. On the following day I heard the parties at Asansol and laid down the procedure of the Court, inter alia, permitting the parties to be represented through lawyers.

3. I did not fix any date for hearing in May and June, 1991 as the representatives of the Employees Unions were busy in the General Elections to the Parliament and the elections to the West Bengal Legislative Assembly. Only after the elections were over, the work of examination and cross-examination of witnesses could commence. Between July—October, 1991 I examined all the witnesses at Asansol and also made another visit of the Mahabir Mine with the Assessors and some witnesses to reconstruct the sequence of events leading to the accident.

4. I was appointed as the Court of Inquiry in addition to my duties as Additional Secretary in the Ministry of Labour. In spite of it, the hearing could be completed during July—October, 1991. The written arguments were submitted by the parties in November, 1991 and thereafter I had meetings wih the Assessors to analyse the evidence and the arguments.

5. Broadly speaking, the fatal accident at the Mahabir Mines occurred when an advaning gallery at a depth of 55m. got connected with an old, abandoned and waterlodged shaft. There was heavy inrush of water through the shaft from the waterlogged workings of the overlying seam connected to it. Six miners lost their lives. 65 miners working at different places in the same seam were trapped as their exists were cut off. These miners managed to take shelter on the rise side of the workings, which was free from water. They were rescued within about 75 hours of the accident by a locally fabricated steel capsule which was lowered with a winch through a large-diameter borehole drilled for the purpose. The unique rescue operation, which was tried in India for the first time and had never been tried elsewhere in the world on such a large scale, attracted considerable media attention.

6. I have held that the cause of the fatal accident was the failure to provide central and flank boreholes in a gallery advancing towards an old, abandoned and waterlogged shaft. Had such advance boreholes been provided, the officials of the mine would have been forewarned of the waterlogged shaft ahead and the fatal accident averted. Such advance boreholes are mandatory under Regulation 127 of the Coal Mines Regulation, 1957. The working permission granted by the Directorate General of Mines Safety also clearly laid down that such boreholes were to be provided. Moreover, the gallery was advanced in an area not approved for working by the Directorate General of Mines Safety but was about 100 m. away from the approved area. Incidentally the fatal accident occurred within only five days of commencement of workings in the gallery in the unapproved area where mining had been stopped in January, 1988 due to unusual seepage of water. Thus the accident was due to culpable negligence attributable to the Agent-cum-Manager of the Mahabir Mine and some senior officials working under him.

7. It would be relevant to assess whether the present accident has points of similarity with some of the major disasters due to inundation in coal mines of our country and whether any further amendment of the Coal Mines Regulations 1957 at this stage would be required to prevent accidents and disasters due to inundation. It is found on review that some major disasters due to inundation in underground coal mines in India have been as follows :

(i) Newton Chickil Colliery, (Madhya Pradesh) on December 10, 1954 with 63 deaths;

(ii) Central Bhowrah Colliery (Bihar) on February 20 1958 with 23 deaths;

(iii) Damua Colliery (Madhya Pradesh) on January 5 1960 with 16 deaths;

(iv) Silewara Colliery (Madhya Pradesh) on November 18, 1975 with 10 deaths;

(v) Chasnalla Coliery (Bihar) on December 27, 1975 with 375 deaths; and

(vi) Hurriladih Colliery (Bihar) on September 14, 198[illegible] with 19 deaths.

The Reports of the Courts of Inquiry appointed for the purpose indicate that most of these disasters took place due to avoidable human failure and culpable negligence. In pursuance of the recommendations of some of those Courts of Inquiry, Gvernment of India have amended the Coal Mine

Regulations from time to time. But unfortunately, accidents and disasters due to inundation in under-ground coal mines continued to occur mostly due to culpable negligence and disregard of the statutory Regulations. Therefore, I do no think any further amendment of the Coal Mines Regulation, 1957 at this stage can by itself prevent such tragic occurrences and Regulation 127 ibid contains all the necessary measures to guard against dangers of inundation from underground water. But unfortunately even in the most tragic disaster at Chasnalla (December 27, 1975), provisions of Regulation 127 said were not compiled with due to culpable negligence. The tragic story of this fatal accident is also no different.

8. While concluding, I must say that my efforts and efforts of others, who have cooperated with me in conducting the inquiry, would be amply rewarded if the relevant provisions of the Coal Mines Regulations are followed scrupulously by the management of the Coal Mines and their workforce and necessary awareness is created for the purpose.

9. I may place on record my sincere thanks to the Assessors, who in spite of numerous engagements, spread their valuable time for the inquiry. My thanks are also due to the parties for their willing cooperation.

December 31, 1991.

(P. C. HOTA),
Mahabir Court of Inquiry

Sharm Shakti Bhawan
Rafi Marg, New Delhi-110001

CONTENTS

CHAPTER		SUBJECT	PAGE
I		COURT OF INQUIRY	
	1.1	Introduction	81
	1.2	Court of Inquiry of Shri K. C. Sharma	81
	1.3	Court of Inquiry of Shri P.C. Hota	81—82
	1.4	Procedure of the Court	82
	1.5	Hearing of the Court	82
II		GENERAL INFORMATION	
	2.1	Mahabir mine	82
	2.2	Management	82—83
	2.3	Geology	83
	2.4	Early mining	83
	2.5	Workings	83
III		REVIEW STATUTE	
	3.1	Statutory provisions against danger of inundation in coal mines	84
	3.2	India	84
	3.3	Developed countries	84—85
IV		INUNDATION DISASTER	
	4.1	General analysis of disaster due to inundation in India	85
	4.2	Prominent disasters due to inundation in India	85
V		ACCIDENT	
	5.1	The accident	85—86
	5.2	Checking the missing persons	86
	5.3	The rescue	86
VI		INSPECTION	
	6.1	First inspection of the site of accident	86
	6.2	Surface inspection	87
	6.3	The second inspection	87
	6.4	Observations	87

CHAPTER		SUBJECT	PAGE
VII		ISSUES	
	7.1	Issues before the Court	87
	7.2	Extension of Shaft No. 34	87-88
	7.3	Unusual seepage of water	88-89
	7.4	Advance long borehole	89-90
	7.5	Permission for working	90-91
	7.6	Advance boreholes	91-92
	7.7	Other issues connected with the accident	92
VIII		CAUSE	
	8.1	Analysis of evidence—extension of Shaft No. 34	92
	8.2	Unusual seepage of water	92
	8.3	Restarting of 40 dip	92-93
	8.4	Advance boreholes	93
	8.5	Strata movement	93
	8.6	Loosening of stone	93
	8.7	Cause of the accident	93
IX		RESPONSIBILITY	
	9.1	Analysis of responsibility	93
	9.2	Agent-cum-Manager	93-94
	9.3	Safety Officer	94
	9.4	Assistant Manager	94
	9.5	Surveyor	94
	9.6	Higher Management	94
	9.7	Others	94-95
X		CONCLUSION	
	10.1	Summary of findings	95
	10.2	Recommendations	95-96
	10.3	Recovery of expenses	96
	10.4	Acknowledgement	96

LIST OF ANNEXURES

ANNEXURE NO.	SUBJECT	PAGE
I	List of persons who lost their lives due to the fatal accident on November, 13, 1989	96
II	Notification of the appointment of Shri K.C. Sharma	97
III	Notification of appointment of Shri P.C. Hota	97
IV	Undertaking of Shri P.C. Hota	97
V	Notice issued by Shri P.C. Hota to the parties	97
VI	List of Management Witnesses	97-98
VII	List of Union Witnesses	98

ANNEXURE NO.	SUBJECT	PAGE
VIII	List of Court Witnesses	98
IX	List of Management Exhibits	99
X	List of Union Exhibitis	99-100
XI	Description of Mahabir mine	100
XII	Text of Regulation 127 of CMR 1957	100
XIII	Photographs of site of accident	101
XIV	Name of the parties and their representatives who examined and cross-examined the witnesses	102

LIST OF ABBREVIATION USED

AMP	—	Abandonment Mine Plan
CDS	—	Central Despatcher System
CMPDI	—	Central Mine Planning and Design Institute
CMR	—	Coal Mines Regulation
CW	—	Court Witness
DGMS	—	Director General of Mines Safety
MW	—	Management Witness
UW	—	Union Witness
ECL	—	Messers Eastern Coalfields Limited
Exh	—	Exhibit

CHAPTER I

1.1 INTRODUCTION

1.2 COURT OF SHRI K. C. SHARMA

1.3 COURT OF SHRI P. C. HOTA

1.4 PROCEDURE OF THE COURT

1.5 HEARING OF THE COURT

1.1.1 In the early hours of November 13, 1989 a fatal accident due to inundation took place in the underground workings of the Mahabir mine of M/s. Eastern Coalfields Limited (A Subsidiary of Coal India Ltd.) in the district of Burdwan, West Bengal. In this accident, six miners lost their lives. Their names are at Annexure—I. 65 miners were also trapped as their exists were cut off. They were rescued after almost seventy-five hours. The method of rescue was by drilling of borehole and lowering a winch-operated steel capsule fabricated locally. Later, the manually operated winch was replaced by a diesel operated crane. This method of rescue which was tried for the first time in India and had not been tried elsewhere in the world on such a large scale received considerable media attention.

1.1.2 In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Mines Act, 1952, Government of India in the Ministry of Labour issued a notification on April 16, 1990 appointing Shri K. C. Sharma, retired Additional Secretary in the Ministry of Labour, for holding a formal inquiry into the causes of and circumstances attending the accident. In the same notification, the following were appointed as assessors to the Court of Inquiry :

1. Shri B. N. Tewary, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha, Asansol, District Burdwan West Bengal.

2. Prof. A. K. Ghose, Professor of Mining Engineering Indian School of Mines, Dhanbad, Bihar.

The relevant notification of the Ministry of Labour is at Annexure-II.

1.2.1 The Court of Inquiry of Shri K. C. Sharma held its first meeting on May 24, 1990 and directed to issue notices in newspapers calling upon the interested parties to file their written statements. The Court of Inquiry also decided that it would commence hearing from July 10, 1990 in the premises of the Central Mine Planning and Design Institute (CMPDI), Asansol.

1.2.2 The Court of Inquiry visited the site of accident on June 10-11, 1990 along with the Assessors, representatives of the management and the Director-General of Mines Safety (DGMS). Thereafter the hearing of the Court was formally started from July, 1990 at the CMPDI, Asansol. The DGMS produced all the documents seized under Section 7 of the Mines Act, 1952 in connection with the accident from the Mahabir mine and these documents were taken possession by the Court of Inquiry. On July 7, 1990, however, the Court of Inquiry received an order of the Hon'ble High Court of Calcutta granting stay of the proceeding pending hearing of the writ petition filed under Article 226 of the Constituion of India by the Coal Mines Officers' Association, a party in the Court of Inquiry. Thus the Court of Inquiry stayed its proceeding from July 7, 1990 onwards.

1.3.1 In partial modification of the earlier Notification of April 16, 1990, on January 3, 1991. Government of India in the Ministry of Labour appointed Shri P. C. Hota, Additional Secretary, Ministry of Labour to hold the inquiry in place of Shri K. C. Sharma. The Notification issued in this regard on January 3, 1991 is at Annexure-III.

1.3.2 As the Calcutta High Court had stayed the inquiry of Shri K. C. Sharma, Shri P. C. Hota on his appointment

gave an undertaking to the High Court that he would not be bound by the procedure of the earlier inquiry of Shri K. C. Sharma and that he would devise his own procedure. A copy of the 'undertaking' of Shri P. C. Hota to the Calcutta High Court is at Annexure IV.

1.3.3 The Calcutta High Court directed that Shri P. C. Hota will start the said inquiry de novo in accordance with the law. In the circumstances, the Writ Petition filed by the Coal Mines Officers' Association was dismissed and the order of stay of the proceedings of the Court of Inquiry was vacated.

1.3.4 Accordingly, on March 21, 1991 notice was issued to parties to attend the hearing before the Court of Inquiry at the CMPDI Asansol, on April 8, 1991. The parties were also requested to submit a complete list of witnesses to substantiate the written statements filed by them in this behalf. A copy of the notice issued to the parties is at Annexure V.

1.3.5 On April 7, 1991, as the Court of Inquiry, I visited the site of accident with Prof. A. K. Ghose, the Assessor and some officials of M/s. Eastern Coalfields Ltd. (ECL) and the DGMS.

1.4.1 On April 8, 1991, the Court of Inquiry met at the CMPDI, Asansol. The Assessors and the parties were present. After hearing the parties and in consultation with the Assessors, I passed the following order :—

(a) in accordance with the order of the Hon'ble Calcutta High Court, the inquiry will start 'de novo' but the written notes, memoranda and list of witnesses already submitted by the parties to the Court of Inquiry of Shri K. C. Sharma shall be considered as valid for this Court of Inquiry also ;

(b) the parties would get another opportunity to file supplementary notes, memoranda and additional list of witnesses, if any, latest by April 30, 1991 ;

(c) if the parties desire copies of depositions etc. they would be supplied the same expeditiously ;

(d) The Court of Inquiry is statutory and therefore to enable parties to represent their case effectively, they would be allowed if they so desire to be represented by a lawyer or to make use of the services of any such person/persons who may be of help in presenting the case. Such parties may make a request in writing in this behalf and the Court of Inquiry shall ordinarily accord such permission.

1.5.1 In view of the ensuing General Election to the Ninth Lok Sabha and election to the West Bengal Assembly and pre-occupation of representatives of Employees' Unions in this regard, I fixed the next date for hearing of the parties at the CMPDI, Asansol from July 15 to 22, 1991.

1.5.2 On July 15, 1991 when the hearing commenced, Shri K. Paul, Director-General of Mines Safety (DGMS) was asked to present the documents etc. seized under Section 7(2) of the Mines Act, 1952 during his inquiry into the accident under Section 23 of the Mines Act, 1952. Accordingly, Shri K. Paul, submitted the list of seized documents to the Court and I found that these were the same as the documents contained in the list of seized documents taken possession of by the earlier Court of Inquiry of Shri K. C. Sharma.

1.5.3 Between July 15—22, 1991, at Asansol, as many as 16 witnesses of the Management were examined and cross-examined. During this period, inspection by the representatives of the Unions of documents seized by the DGMS and kept in the custody of the Court of Inquiry was permitted. The Secretary of the Court of Inquiry was present during such inspection.

1.5.4 During the next hearing of the Court of Inquiry at Asansol between September 20—26, 1991, six witnesses (three witnesses of the management and three witnesses of the Union) were examined and cross-examined. Two witnesses of the Management were also cross-examined during this period.

1.5.5 The last hearing of the Court of Inquiry at Asansol was from October 24 to 26, 1991, when three witnesses of the Union and one witness summoned by the Court of Inquiry (Shri S. K. Sengupta, Assistant Manager of Mahabir mine) were examined and cross-examined. There was, however, no cross-examination in case of the sole Court witness viz. Shri S. K. Sengupta. On October 26, 1991, the Court along with the Assessors and some witnesses made another visit of the site of accident to reconstruct the sequence of events leading to the fatal accident and other related matters.

1.5.6 During October 24—26, 1991, it was also decided in consultation with the parties that they would submit only written arguments. Accordingly, I directed the Secretary of the Court of Inquiry to be at Asansol on November 12 and 13, 1991 and receive the written arguments.

1.5.7 On November 12 and 13, 1991, the Secretary of the Court of Inquiry visited Asansol and received the written arguments from the Management and the Unions.

1.5.8 During the hearings of the Court of Inquiry at Asansol between July and October, 1991 I recorded the evidence personally by writing down the depositions in long hand. Since some witnesses were not proficient in English, they were asked questions in languages they knew (i.e. Hindi and Bengali). Their depositions were, however, translated into English by me in the open Court and were recorded by me in long hand. Effort was made to supply the photocopies of depositions of witnesses to the parties as soon as the deposition were over.

Invariably, copies of depositions of witnesses in examination-in-chief were supplied to the parties to enable them to prepare themselves for cross-examination. This promptness on the part of the Court of Inquiry was appreciated both by the management and the Unions.

1.5.9 After receipt of the written arguments on November 12 and 13, 1991, myself and the Assessors met at Delhi during November 20—23, 1991 and December, 25-26 1991 to consider the depositions, arguments and other relevant matters for finalizing the Report of the Court of Inquiry.

1.5.10 The Report of the Court of Inquiry was submitted to the Secretary, Ministry of Labour, Government of India on December 31, 1991.

1.5.11 In this Report the witnesses produced by the management have been recorded as Management Witness (MW), those produced by the Union as Union Witness (UW) and the witness called by the Court as Court witness (CW). The list of management, union and court witnesses are at Annexures VI, VII and VIII respectively.

1.5.12 The plans and documents which the Management requested to be made exhibits are called Management Exhibits (Exh. M) and the plans and documents requested to be made exhibits by the Employees' Union are called Union Exhibits (Exh. W). Annexures IX and X give the list of Management's and Employees' Union's exhibits respectively.

CHAPTER II

2.1 MAHABIR MINE

2.2 MANAGEMENT

2.3 GEOLOGY

2.4 EARLY MINING

2.5 WORKINGS

2.1.1 Mahabir mine is situated in the Raniganj Coalfield in the district of Burdwan, West Bengal. It is about 18 km east of the Asansol Railway Station and about 182 km north-west of Calcutta. A brief description of the geographical location, surface features, ownership etc. of the Mahabir mine is at Annexure—XI.

2.2.1 Since 1975, the Mahabir mine is owned by M/s. ECL, a Subsidiary of M/s. Coal India Ltd. For administrative convenience, the M/s. ECL is divided into two divisions, viz., Eastern and Western Division—each division being headed by a functional Director. The functional Directors

are notified as 'Nominated Owner' under Section 76 of the Mines Act, 1952. At the Corporate level there is an internal Safety Organisation (ISO). The Eastern Division is divided into six areas with 63 workingg mines. Mahabir mine is in the Kunustoria Area, which has eleven working mines including the Mahabir mine. At the time of the fatal accident, Md. Kalim (MW-17) was the Agent-cum-Manager of the Mahabir mine. He was the Manager from June, 1987 and later appointed as Agent-cum-Manager. Hence on the fateful day of November 13, 1989, he had more than two years of experience as Manager in the said mine. Md. Kalim (MW-17) holds a Manager's first class certificate of competency to manage a coal mine. He started his career as an apprentice in the coal mines and by November, 1989 had about 28 years of experience.

2.2.2 At the time of the accident, Shri S. K. Sengupta (CWI) and Shri K. Dutta (MW-19) were Assistant Managers of Mahabir mine and both of them held second class manager's certificate of competency. Shri P. L. Banerjee (MW-16) was the Safety Officer of the Mahabir mine and he was reporting to Md. Kalim, Agent-cum-Manager (MW-17). Shri P. L. Banerjee (MW-16) held a first Class Manager's Certificate of Competency for Coal Mines.

2.2.3 Shri P. L. Thacker (MW-15) was the Surveyor. He holds a Surveyor's Certificate of Competency. His duties are as contained in Regulation 49 of Coal Mines Regulations, 1957 (CMR 1957). In short, his duties were to make accurate surveys and levellings and prepare such plans and sections and tracing thereof as the Manager may direct or as may be required by the Mines Act and the Regulations. It is relevant to mention that the statutory duty of the Surveyor is to record full facts when the workings of the mine have approached to about 75 m. from the mine boundary or from disused or waterlogged workings. Shri Thacker (MW-15) was assisted by another qualified surveyor and a few assistants who did not have any formal certificate of competency in coal mining but had only experience.

2.2.4 The mine had 13 overmen and 32 sirdars. They held statutory certificates required for such appointments. Shri Shibdas Chatterjee, Overman, (MW-9) was appointed as the Workmen's Inspector.

2.3.1 The coal seams of Raniganj Coalfield belong to the Raniganj stage of the Damuda series of Lower Gondwana System. The general inclination of the strata is towards south and south-east varying from 2 to 35 .At places, igneous intrusion in the form of dolerite dykes traverse the Lower Gondwanas. There are ten coal seams of 1.2 m. and above in thickness associated with Raniganj stage. The coal seams are mostly named after the village in which they occur and the same seam is even found to have different names in different parts of the coalfields. The generalised sequence of the seams in descending order in Raniganj Coalfields is from R-X to R-I.

2.3.2 In the property of the Mahabir mine, the topmost seam is called Searsole seam corresponding to R-IX and is about 6 m thick. The seam outcrops almost in the central of the part of the property. On the southern part of the property is the outcrop of the second seam called the Nega seam which is about 8.0 m. in thickness corresponding to R-VIII. The parting between the Searsole and the Nega seams is 51 m. Further on the south side, along the mine boundary almost on the bank of the river Damodar is the outcrop of the third seam called the Narainkuri seam corresponding to R-VII. The Narainkuri seam is about 3.3 m. in thickness. The parting between the Nega and the Narainkuri seam is 24 m. Lying 80 m. below the Narainkuri seam is 3 m. thick Bogra seam corresponding to R-VI. The sequence of the seams is as follows :—

Searsole seam	— 6 m. thick
Parting	— 50 m.
Nega seam	— 8 m. thick
Parting	— 24 m
Narainkuri seam	— 3.25 m
Parting	— 80 m.
Bogra seam	— 3 m

2.3.3 The coal seams have a gentle dip of 1 in 25 in north-easterly direction. The parting between the coal seams consists of coal bearing rock formation. The property is relatively free from geological disturbances except for a major upthrow fault of 60 m. on the northern side. There are also a few small faults having a throw of 1 m. to 6 m. The property is traversed by a few dykes. On the south side, which is also the rise, there is a major dyke. This dyke had not been crossed at any place, and the width is not exactly known. In addition, there are a few small dykes having a thickness of less than a metre. Narainkuri seam is considered as a hard coal when compared to other coal seams in Indian Coalfields.

2.4.1 The Mahabir mine and the adjoining area was the very first centre of coal mining in India. The fatal accident on November 13, 1989, took place due to inundation from very old and abandoned workings. Therefore, it would be interesting to briefly review the history of early coal mining in this area. The first recorded coal mining in India dates back to 1774 when some British enterpreneurs started coal mining around Raniganj. Around 1815, pits were sunk in the Raniganj seam near Egara village presently within the boundary of the Mahabir mine. Since 1843, the coalfield was systematically exploited by a newly-formed joint stock company called the Bengal Coal Company. With extension of the railway line upto Raniganj in 1855, coal mining of this area got a big boost. But even by the middle of the 19th century, coal mining in India was not very scientific and plans of workings were mostly not maintained. Around 1860, Mr. Thomas Oldham, Superintendent of Geological Survey of India, left his "Minutes" on the unsatisfactory state of affairs of the mine plans as follows :

> "Upto last year or two I am unable further to state that in no single instance was survey of underground workings made or plans kept. The memory of the 'old men' was only source from which information could be obtained as to the extent of the workings .....
>
> I am glad to say that this system or want of system, has been changed in some cases and plans are now kept, certainly in one case, and I hope also in others .....".

2.4.2 The method of mining was essentially driving wide galleries and leaving small pillars, and as coal had to be hauled manually from underground workings, only a small area could be worked from a shaft, which in course of time became abandoned and could constitute a potential source of mining hazard.

2.4.3 These historical evidence of early coal mining could still be seen in the property of Mahabir mine and the surrounding area.

2.5.1 The reconstituted Mahabir mine is formed by amalgamating three small adjoining mines since called the three units of the mine Here Searsole seam is the tompost coal seam. It had been worked by a private coal company about 80 years ago. The seam had been exhausted, abandoned and presently lying waterlogged.

2.5.2 Lying 51 m. below the Searsole seam is the Nega seam which is 7.5 m. to 8.7 m in thickness. It has been extensively worked in all the three units of the Mahabir mine. In the Mahabir unit, Nega seam had been worked on the northern side of the main Eastern Railway line through No. A and B Pits. Towards the rise side of A & B Pits on both side of main Eastern Railway line, the Nega seam had been worked by Raniganj Colliery belonging to the erstwhile M/s. Bengal Coal Company Limited, leaving a barrier of coal with the Nega seam working seam workings of A and B Pits. As per plan, the barrier is 60 m. More details about the workings of the Nega seam of Raniganj Colliery will appear in the later part of this report.

2.5.3 Lying 24 m. below the Nega seam is the Narainkuri seam which is about 1.8 to 3.3 m. in thickness. In the Mahabir unit, the Narainkuri seam is 3.25 m. in thickness and is worked through A and B Pits. It is being developed beneath the waterlogged workings of the Nega seam of the Raniganj Colliery.

2.5.4 There are extensive old workings in the Nega seam in an area of about 120 hectares on both sides of the main

Eastern Railway line, made by the Raniganj Colliery of the erstwhile M/s. Bengal Coal Company. No reliable plan of the workings, including the plan which is required to be prepared immediately before abandoning a coal seam also called the 'Abandonment Mine Plan' (AMP), was available with M/s. ECL. A plan which was available at the office of the Mahabir mine was of doubtful authenticity. It did not bear any signature. This plan indicated extensive workings standing on small stooks on both side of the main railway line. The two sets of workings on the north and south side of the railway line was inter-connected by four galleries.

CHAPTER III

3.1 STATUTORY PROVISIONS AGAINST DANGER OF INUNDATION IN COAL MINES

3.2 INDIA

3.3 DEVELOPED COUNTRES

3.1.1 The accident took place due to inundation and hence a review is made of the statutory provisions relating to danger of inundation in underground coal mines of India and abroad.

3.2.1 The provision of Regulation 127 of CMR 1957 relates to the precautions to be taken and provisions to be made in an underground coal mine to prevent inrush of water or other liquid matter from the workings of the same mine or adjoining mine. The Regulations have been framed under clause(s) of Section 57 of the Mines Act, 1952. The full text of Regulation 127 of CMR 1957 is at Annexure XII.

3.2.2 It may be seen that Regulation 127(3) of CMR 1957 requires a working permission from the Chief Inspector of Mines who has been also designated as the Director-General of Mines Safety (DGMS) for working within 60 m of dis-used or abandoned workings which have not been examined and found free from accumulation of water or other liquid matter. Since the Narainkuri seam is 24 m below the waterlogged Nega seam, provisions of Regulation 127 of CMR 1957 were also to govern mining operations in the Narainkuri seam.

3.2.3 Regulation 127 of CMR 1957 which had been amended several times has an interesting history. Neither the Mines Act, 1901 nor the General Rules, 1908 framed under the aforesaid Act laid down any precautions to be taken while approaching waterlogged workings in underground coal mines. Even when the Mines Act, 1901 was replaced by the Mines Act, 1923, such precautions were not provided for. It was only in 1936 by an amendment of the Mines Act, 1923 the Central Government was empowered to frame regulations to porvide against inrush of water or accumulation of water in the mines and dangers arising therefrom. Thus the Indian Coal Mines Regulation, 1926 (ICMR 1926) framed under the Mines Act, 1923 laid down for the first time after 1936 the percautions to be taken while approaching within 100 feet (30 m.) of waterlogged or dis-used workings. The precautions included restriction of width and height of the gallery to 8 feet (2.4 m.) and previsions of a Central borehole at the working face and sufficient flank boreholes on each side, and where necessary boreholes above and below the workings at an interval not more than 15 feet (4.5 m.). It was also laid down that such boreholes are to be maintained at a sufficient distance in advance of the workings and such distance shall in no case be less than 10 feet (3 m.) Following a disaster due to inundation in a coal mine in Madhya Pradesh in 1954 (Newton Chickli Colliery) where 63 miners lost their lives and following the enactment of Coal Mines (Temporary) Regulations, 1955, the restrictions of working near waterlogged workings were made more stringent. The revised Regulations included increasing the distance of Statutory restricted area requiring working permission of the DGMS from 100 feet (30 m.) to 150 feet (45 m.). The CMR, 1957 repealed ICMR 1926 and Coal Mines (Temporary) Regulation, 1955. The provisions against danger from underground inundation was contained in Regulation 127 of CMR 1957. The statutory restricted area was however increased from 45 m. to 60 m. Following the Chasnalla mine disaster in December, 1975 in which 375 miners lost their lives, there were major amendments in Regulation 127 of CMR 1957. Some of these amendments were :

(a) In the application to the DGMS seeking working permission within 60 m. of waterlogged workings, it is mandatory to furnish copies of plans and sections showing inter alia, outlines of all disused or abandoned workings in relation to the working approaching them; the outlines, the layout and the method of the proposed working for which the permission was sought; faults, dykes and other geological disturbances, and such other informations that is available with the management and any other information required by the DGMS.

(b) Once the permission is granted by the DGMS the workings shall be extended strictly in accordance with the plan and the method approved under the conditions specified in such permission and there shall be no variation therefrom unless such variation is again approved by the DGMS.

(c) It is also necessary to maintain record showing the exact height and width of such workings, the number of boreholes driven, the length of each borewhole, the places at which and the direction in which each borehole was driven in a bound-paged book kept for the purpose and the entries therein are required to be signed by a competent person appointed for the purpose and counter-signed by the manager every day.

(d) The provision of immediate stoppage of work when unusual seepage of water is noticed at any place in any working in an underground coalmine was extended to the workings which are also within 60 m. of the waterlogged workings.

(e) however Regulation 127 of the CMR 1957 was also made more flexible as it vested the DGMS with powers to grant relaxation from restrictions in the size of the gallery and exemptions from advance boreholes if deemed fit.

3.2.3 Following the Hurriladih disaster due to inundation in 1983 when 19 miners lost their lives and in the light of experience gained while working near waterlogged workings, Regulation 127 was again amended in 1990. It was made more specific to eliminate ambiguity between dis-used and abandoned workings. It also laid down the precautions to be taken while drilling holes for probing into water bodies.

3.3.1 At this stage, it would be relevant to review the statutory provisions in underground coal mines in some advanced countries regarding working near waterlogged areas Almost all countries impose certain statutory restrictions while working near water logged workings. The restiction is in the fom of leaving safety pillar/barrier between the waterbody and the workings. Workings are permitted to a certain limit within the safety pillar subject to certain restrictions. These are usually in the form of restricting the width and height of the galleries as well as advancing the workings under cover of advance boreholes.

3.3.2 The U.S. Federal law specifies that if there is no reliable plan of an old underground working, advance boreholes have to be provided within 60 m. of such workings to avert accidents and disasters due to inundation. In this respect, the U.S. law is almost similar to Regulation 127 of CMR 1957.

3.3.3 The French Regulaitons for coal mines require protection of the workings against risks of inrush of water. It also requires that galleries or workings driven in a region where an inrush of water is feared should be preceded by divergent boreholes of at least 3 m. in length.

3.3.4 The Coal Mines Regulations of the United Kingdom require that when any workings in a mine would be within 45 m. of any disused workings, the Manager shall take necessary precautionery measures. This includes giving advance notice in this respect to the Inspectorate as well as workers' representaives, along with a scheme which shall lay down the procedure to be followed in such workings de-

signed to ensure that inrush of water or other liquid matter does not occur.

3.3.5 The above global review of the statutory provisions regarding the danger from underground water indicates that our statutory safety precautions are at par with advanced countries such as USA, France and the United Kingdom.

CHAPTER—IV

DISASTERS DUE TO INUNDATION

4.1 GENERAL ANALYSIS OF DISASTERS DUE TO INUNDATION IN INDIA

4.2 PROMINENT DISASTERS DUE TO INUNDATION IN INDIA

4.y.1 About one third of the deaths in disasters in coal mines of our country is accounted for by inundation. The prominent disasters due to inundations are those of Newton Chickli colliery (Madhya Pradesh) on December 10 1954 with 63 deaths; Central Bhowrah colliery (Bihar) on February 20, 1958 with 23 deaths; Damua colliery (Madhya Pradesh) on January 5, 1960 with 16 deaths; Silewara colliery (Madhya Pradesh) on November 18, 1975 with 10 deaths; Chasnalla colliery (Bihar) on December 27, 1975 with 375 deaths and Hurriladih colliery (Bihar) on September 14, 1983 with 19 deaths.

4.2.1 The disaster at Newton Chickli Colliery (Madhya Pradesh) in December, 1954 occurred when a development gallery got connected to an old and abandoned waterlogged workings of overlying seam. The underlying seam had been brought to the same level as that of the upper seam in that area due to an upthrow fault equal to the parting between the two seams. The disaster occurred primarily due to inaccurate mine plan, as well as non-compliance of Regulation 74 of the ICMR 1926, which was repealed by Regulation of 127 CMR 1957. The disaster due to inundation at the Central Bhowrah colliery (Bihar) in February, 1958 occurred when the underground workings crossed the mine boundary and got connected to the waterlogged workings of the adjoining colliery. The disaster occurred primarily due to encroachment in the adjoining property without proper survey and proper plans, as well as violation of Regulation 127(3) and (5) CMR 1957 in respect of extending workings within 60 m. of waterlogged areas. The disaster at Damua colliery (Madhya Pradesh) in January, 1960 occurred when the workings were advanced towards the waterlogged area across an up-throw fault. The barrier of 1.8 m. between the two workings in faulted area gave away causing the disaster.

4.2.2 The most tragic disaster in the history of mining in India was that of Chasnalla (Bihar) in December, 1975, when 375 persons lost their lives due to inundation. The old workings at Chasnalla had been abandoned around 1949—about 26 years before December, 1975 when the disaster occurred due to an inadvertant connection with the old workings while driving a ventilaton cross-out.

4.2.3 The disaster at Chasnalla has some points of similarity with that of the present accident. In both the cases, inundation occurred from overlying old waterlogged workings and subsidence followed closely thereafter. In the case of the Chasnalla colliery, the length of the main incine driven along the seam was shown in the plan to be much shorter than its actual length. In the case of Mahabir mine the offending old and abandoned shaft was not shown in the plan to have extended to the underlying seam. Again, in both the cases the respective managements worked in areas not approved for working by the DGMS and in violation of Regulation 127 of CMR 1957. The disaster at Hurriladih colliery (Bihar) in September, 1983 occurred when a thin parting of coal formed as a result of developing a thick seam in two different horizons collapsed suddenly. Water from the workings of the upper horizon which formed a part of the sump flowed to the lower horizon, killing 19 persons. The disaster occurred primarily due to inaccurate plan and contravention of Regulation 127 of CMR 1957.

4.2.4 An analysis of the causes of these disasters would indicate that these disasters had occurred mainly because of inaccurate mine plans, and contravention of Regulation 127 of the CMR 1957 etc. In other words, these disasters took place mostly due to avoidable human failure tantamount to culpable negligence.

CHAPTER-V

5.1 THE ACCIDENT

5.2 CHECKING THE MISSING PERSONS

5.3 THE RESCUE

5.1.1 At this stage, it would be relevant to review the sequence of events leading to the accident. Apparently, the work in the third shift of November 12, 1989 started normally. There were three working districts in the Narainkuri seam, namely, 'B' Pit depillaring district 31 cross-cut and 42 crosscut development districts. In all about 221 workers were employed in the workings underground before the accident.

5.1.2 Shri Fouzdar Singh (MW 1) was the Overman in charge of the entire workings. Shri Dodan Pandey (MW 13) was the Sirdar and Shri Chandradhari Barai (MW 14) was the shotfirer respectively of the 42 cross-cut development district, where the accident occurred.

5.1.3 In the beginning of the shift, twelve shot holes were drilled in 40 dip face of 42 cross-cut district. These shot holes were about 1.2 m. in length. There was no under-cut at the face as the coal cutting machine was out of order.

5.1.4 Shri Bhangi Rajbhar (UW 5), Shri Ramawtar Khurasia, Shri Tatua Majhi and Shri Pyar Chand Shaw were helpers attached to the shot-firer Shri Chandradhari Barai (MW 14). After completing shot firing in other faces of the district, they reached 40 dip face at about 4.00 a.m. Shri Chandradhari Barai (MW 14) deposed that he charged six out of the twelve shot holes drilled in the face. Four of these shot holes were at the floor level, whereas the remaining two were the "cut holes" almost in the centre of the gallery. However, according to Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) all the twelve shot holes were charged at a time in the face. P_3 explosives and instantaneous electric detonators were used. Thereupon the six short holes were fired by Shri Chandradhari Barai (MW 14). After clearance of smoke and fumes they went back to the face to charge the remaining six shot holes, where as according to Shri Bhangi Rajbhar (I) VW 5) they went to connect the remaining six charged shot holes. When Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) was pulling out the shot firing cable beneath the broken coal, Shri Chandradhari Barai (MW 14) heard cracking sound from the face ahead and the area behind him. Immediately, they saw muddy water gushing out like a spray from the right (south) side of the face, Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) was knocked off his feet. Shri Chandradhari Barai (MW 14), pulled out Shri Bhangi Rajbhar (UW 5), collected his assistants and tools and rushed out of the face shoutings warnings regarding the sudden in rush of water. On the way, Shri Chandradhari Barai (MW 14) met Shri Dodan Pandey (MW 13) near the haulage of the district and the informed him about the sudden inrush of water. Shri Dodan Pandey (MW 13) asked him to evacuate all the persons of the district and he took the task of informing the workers of 21 crosscut district about the inrush of water. Shri Dodan Pandey (MW 13) in turn informed Shri Fouzdar Singh, (MW 1) at about 4.30 a.m. over the CDS telephone about the sudden inrush of water from the 40 dip face. Shri Fouzdar Singh (MW 1) immedaitely used the CDS telephone at 21 level off 6 dip to contact the attendance cabin at the pit top but there was no response. Information about the accident was sent to the Agent-cum-Manager Md. Kalim (MW 17). Then he contacted Shri P. L. Banerjee, (MW 16), Safety Officer over the CDS telephone and informed him about the accident. Thereafter, he again rang up the attendance cabin and got Shri Ram Chandra Mahato, Sirdar of the 'B' Pit depillaring district. He instructed Shri Ram

Chandra Mahato to evacuate all persons from the 'B' pit district and to inform the other districts over the telephone to evacuate all persons from underground. He also instructed the CDS operator to announce over the microphone facility available with the CDS to warn all persons underground and direct them to evacuate to the surface. Shri Dodan Pandey (MW 13) and Shri Fouzdar Singh (MW 1) tried to go towards 21 crosscut section, but soon water also reached there. Since they could do nothing more to rescue the workers, they rushed towards the pit bottom, where they met Shri P. L. Banerjee (MW 16). With Shri P. L. Banerjee (MW 16), Shri Fouzdar Singh (MW 1) and Shri Dodan Pandey (MW 13) came back towards the section. However, near 8 level, they found water rushing from the rise side. Shri P. L. Banerjee (MW 16) then went towards 'B' pit, whereas Shri Dodan Pandey (MW 13) and Shri Fouzdar Singh (MW 1) came to No. 'A' pit. Fearing the worst, they immediately got upto the surface. At the pit top, they met Md. Kalim, Agent-cum-Manager (MW 17). Shri Fouzdar Singh (MW 1) again went underground through No. 'A' Pit alongwith Shri Dodan Pandey (MW 13), the onsetter and Md. Kalim (MW 17). But they found that water has risen almost chest high in the pit bottom itself. Realising that there was no further scope of rescuing the workers through the pits, they came back to the surface by about 5.30 a.m.

5.2.1 As there was a possibility that some workers might have come from the Narainkuri seam to the Nega seam through the drift, Shri P. L. Banerjee (MW 16) along with others went down through the sinking bucket of the adjoining unit to the Nega seam. They however could not find any one except the two pump khalasis of Nega seam waiting to be hoisted up.

5.2.2 A quick check of the attendance register revealed that out of the 221 workers who had gone down the mine, 150 workers had come out, and thus the remaining 71 workers were presumed to be trapped underground. Most of the trapped miners were from the 21 cross-cut district, and the remaining from the 42 cross-cut district. Fortunately, contact with the two groups of trapped miners could be established soon over the CDS telephone. The trapped miners informed that they were unable to reach the pit bottom due to the rising water, which had cut off their approach route. Counting of the trapped miners and the reconciliation of figures of miners who could quickly come out to the surface, revealed that there were sixtyfive miners who had been trapped underground. Hence six miners were feared to be missing. Later, the sixtyfive trapped miners were guided over the CDS telephone to go towards the rise side as attempts would be made from the surface to establish direct contact with them through a borehole. It would be relevant to mention that the effective functioning of the CDS telephone even under conditions of submergence contributed vitally to the rescue operation in the initial stages.

5.3.1 Around 10 a.m. of November 13, the Senior Officials of the DGMS and M/s. ECL Ltd. reached the Mahabir mine. It soon became clear that the accident had taken place due to a connection in the Narainkuri seam with the old and waterlogged Shaft No. 34 and the workings on the rise side would remain free from water where the trapped miners could take shelter. It also transpired that in the past a few exploratory holes drilled in the rise side of the Narainkuri seam beyond the outcrop of the Nega seam, had in fact punctured the workings. Thus it was felt that communication could be established with the trapped miners through a borehole. A rough estimate of the entrapped air indicated that it would be good enough to permit normal breathing for about two weeks. It was therefore felt that the trapped miners were not in imminent danger.

5.3.2 A drilling rig was brought on emergency basis and existing Borehole No. 3 which had been quickly located by a search party was reamed to 20 cm. diameter by 2.30 a.m. of November 14. Through the CDS telephone, the trapped miners were directed to assemble below the No. 3 Borehole. With clear supply and communication line established through the borehole and with all the trapped miners safely around it, the initial anxiety regarding safe rescue of the miners was reduced.

5.3.3 A suitable site was immediately selected on the surface towards the rise side for drilling a large diameter borehole to rescue the trapped miners. The operation was started around 9.30 a.m. on November 14 and a borehole of 52 cm. diameter was completed around 3.30 p.m. of November 15. A steel capsule with hinged doors based on a German design was fabricated locally. A temporary tripod was erected and winch was installed and through the winch-operated capsule, Shri G. S. Gill, Additional Chief Mining Engineer of M/s. ECL, who was trained in rescue operations, was lowered to the underground workings around 2.20 a.m. on November 16. As the manually operated winch was taking time for hoisting of the trapped miners, this was replaced by a crane after some miners had been rescued. The first trapped miner was brought out by 2.40 a.m. on November 16 and the last one was rescued by 8.40 a.m. of the same day. This unique method of rescue was tried for the first time in India. Never before in the world, such a method of rescue had been tried on such a large scale. The rescue operation received considerable media attention.

5.4.4 Thereafter, search operation was started for the six missing persons. Search parties were sent through the capsule and search continued throughout the day and night till the early hours of November 18. Sending of the search parties through the Borehole was stopped thereafter because the unlined portion of the borehole gave indications of caving in. Subsequently when the pits were de-watered, search for the six missing miners continued. Unfortunately, these six miners could not be rescued alive. Their dead bodies were recovered one after another. The last body was rescued on December 23, 1989 after considerable efforts.

CHAPTER-VI

6.1 First Inspection of the Site of Accident

6.2 Surface Inspection

6.3 The Second Inspection

6.4 Observations

6.1.1 On April 7, 1991 I went to the Mahabir mine to inspect the site of accident, Prof. A. K. Ghose, Assessor, Shri K. Paul, DGMS, Shri T. K. Dev, Director (Technical), M/s. ECL and other officers of DGMS and M/s. ECL also accompanied me during the inspection. Shri B. N. Tewary, Assessor, could not be present. We went down through No. 'A' Pit to the Narainkuri seam and walked beneath the Eastern Railway line from Delhi to Howrah. Enroute I saw the devastation caused by inrush of water which had scoured the ballast and packing materials of the haulage track and deposited it on the adjoining level galleries. The location from which some of the six dead bodies were recovered was also shown to me. At 33 level, I saw the receiver of the underground telephone system (i.e., CDS system) which was used by the trapped miners for communicating with the operator on the surface. Earlier in this Report I have mentioned that the CDS system functioned effectively and played a crucial role in the successful rescue operations.

6.1.2 While proceeding along the 33 east level haulage road, I saw marks left by water on the ventilation stoppings. It gave me a fair idea of the maximum level to which water had risen in the workings. Around junction of 40 dip off 28 level, I saw two big blocks of stone lying on the floor. I also saw haulage rails which had been bent and twisted by the force of water. While proceeding along with drivage of 40 dip, I got the distinct impression that the gallery at 40 dip, had abruptly deviated from its normal north easterly bearing to almost due south connecting 40 dip with old Shaft No. 34. The exact spot where 40 dip off 28 level had punctured the old and abandoned Shaft No. 34 was covered with boulders and rubbles. While proceeding along the drivage of 40 dip off 28 level, I could not see any trace of flank boreholes except one in that gallery. After visiting the site of accident I went along 29 level to adjoining 39 dip and inspected the face at 27 level off 39 dip from where a long borehole had been drilled in 1988. I saw the flank boreholes drilled in the gallery at 27 level. I also saw the marks left by the seepage water along the sides of the pillar at 27 level off 39 dip. These marks were prominent below the flank boreholes. My journey to the site of accident and inspection lasted for about three hours.

6.2 On April 8, 1991 I along with some officers of the DGMS and the ECL, went to inspect the abandoned Shaft Nos. 33 & 34 at the surface. The surrounding area of the shafts was full of wild growth. During the inspection some villagers told me that before the accident on November 13, 1989, Shaft Nos. 33 & 34 were not visible on the surface as they were covered with soil and vegetables had been grown on it. Later I inspected the site of the borehole through which the trapped miners were rescued by a capsule. On the way, I saw a pothole which perhaps occurred shortly after the accident.

6.3 Whereas the first visit on April 7, 1991 was primarily for making a first-hand appraisal of the conditions prevailing at the site of accident, the second visit on October 26, 1991 was for the purpose of a re-enactment of the events leading to the accident. On October 26, 1991, Chandradhari Barai (MW 14) and Bhangi Rajbhar (UW 5) re-enacted the sequence of events leading to the accident after firing the first round of shots at 40 dip face on the fateful morning of November 13, 1989.

6.4.1 Based on inspections of the site, my observations are as follows :—

1. Except at the entry of 40 dip gallery off 28th level where there was only one flank borehole, there was no evidence whatsoever of any flank boreholes along the rib sides. For the purposes of court records, a mosaic of photographs of 40 dip gallery and the 27th level on the date of second inspection was prepared and is at Annexure-XIII.

2. Even if some scouring of the sides of the gallery due to the in rush of water from Nega seam could be conceded, there was no tell-tale evidence whatsoever of the presence of any flank boreholes along 40 dip gallery which casts serious doubts on the depositions made before the Court regarding drilling of flank boreholes at specified intervals.

3. Random measurements were made of the gallery width, both near the site of accident, along the 40 dip gallery and at 27 level which established that the gallery, as originally driven before the accident was about 4.2 m.

4. The floor of the junction off 28 level and 40 dip gallery showed a void from which a large block of stone had been wrenched off and which moved nearly half a pillar to the rise up the 40 dip gallery.

5. At the accident site, along the 28 level and 27 level galleries including the thin rib of coal between 27 level and 40 dip, there was no visible evidence of any ground movement to which the fatal accident could be attributed.

6.4.2 On the basis of the site inspection I have found no evidence to support the contention made by some witnesses of the management that both central and flank boreholes were being systematically drilled while driving 40 dip gallery from November 8, 1989 onwards as per the stipulations contained in Regulation 127 of CMR 1957. It could be argued that there would be no evidence of central boreholes as these were blasted while extracting coal but if flank boreholes would have been provided at 40 dip off 28 level there would have become visible when the site of the accident was inspected. For example, flank boreholes had been given at 27 level in 1988. When I inspected the adjoining area of the site of the accident and went to the 27 level, I could clearly see those flank boreholes.

CHAPTER-VII

7.1 Issues before the Court.

7.2 Extension of Chaft No. 34

7.3 Unusual seepage of water

7.4 Advance long borehole

7.5 Permission for working

7.6 Advance boreholes

7.7 Other issues connected with the accident.

7.1.1 As stated earlier, the accident took place when a connection was established between the advancing 40 dip face off 28 level and the old and waterlogged Shaft No. 34. On the basis of evidence recorded and written arguments advanced, the following issues were before this Court of Inquiry.

1. Whether the extension of old and abandoned Shaft No. 34 upto the Narainkuri seam was known to the Agent-cum-Manager, Mahabir mine & other officials working under him and whether they exercised due to diligence to find the depth of the shaft;

2. whether the above officials had prior warning such as unusual seepage of water to indicate that the workings were approaching towards waterlogged Shaft No. 34;

3. whether the above officials satisfied themselves by providing long boreholes that Shaft No. 34 had not extended upto the Narainkuri seam;

4. whether the above officials had any working permission of the Directorate General Mines Safety to drive the 40 dip gallery off 28 level;

5. whether the 40 dip gallery off 28 level was advanced with adequate cover of central and flank boreholes;

6. and other issues connected with the accident.

7.1.2 These issues are analyzed in the subsequent paragraphs to come to the findings regarding the causes of and circumstances attending the fatal accident.

7.2.1 Md. Kalim, Agent-cum-Manager (MW 17) and others contended that inspite of their best efforts they were not aware that Shaft No. 34 had extended beyond the Nega seam. The representatives of the employees' Union on the other hand alleged that the Agent-cum-Manager & others did not make adequate efforts to find if Shaft No. 34 had extended beyond the Nega seam.

7.2.2 The Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW 17) and others came to the conclusion that Shaft No. 34 had not gone beyond the Nega seam, on the following basis :

(1) According to Shri P. L. Banerjee, Safety Officer (MW 16) there are about one hundred old shafts in the Mahabir mine and some of the shafts are filled with debris. Shaft No. 34 was one such filled up shaft and was not traceable on the surface. Many of these old shafts were shown in the plan of the mine. In the statutory plan (Exh. M/11) Shaft No. 34 was, also shown as filled with debris. Its depth was not indicated.

(2) All the shafts the depths of which were shown in the old plans indicated that these had gone upto the Nega seam only. No shaft had been shown to have gone upto the underlying Naralnkuri seam.

(3) The old shafts were plotted in the statutory plan (Exh. M/11) by tracing from the old plan. In 1976, a check survey was conducted by the then Surveyor of the Mahabir mine. In the above survey the depth of the available old shafts was measured and their locations were also verified. However of the old shafts was found to have gone beyond the Nega seam. Shaft No. 34 was not traceable at the surface, and the area on the surface was a private vegetable garden. Obviously, as

it could not be located at the surface, its depth could not be measured.

(4) Narainkuri seam had been developed beneath the waterlogged Nega seam since 1961 and this development had been also made beneath a number of old shafts. But none of these shafts was found to have extended upto the Narainkuri seam.

(5) According to Shri P. L. Thacker (MW 15) and Md. Kalim (MW 17) there were no documents/records available to indicate that Shaft No. 34 had extended upto the Narainkuri seam. According to the former Agent of Mahabir mine, Shri K. K. Das (MW 18) the Cadastral Plan of 1926 as well as the Revenue Plan of 1950 of the surrounding area did not also show old Shaft No. 34.

(6) The Abandonment Mine Plan (AMP) of the Raniganj seam, 1 & 2 pit, Raniganj Colliery of M/s. Bengal Coal Company of 1925 (Exh. M/2A) showed Shaft No. 34 as a surface feature of the adjoining mine. The depth of the shaft was recorded in the AMP as 86 feet (25.8 m) which indicated that it had extended upto the Nega seam only.

(7) Md. Kalim (MW 17) tried to locate shaft No. 34 at the surface by visual inspection but he failed to do so as the shaft was completely filled up and the surface land was used for growing vegetable.

(8) In 1989, Md. Kalim (MW 17) got a long borehole of about 40 m. length drilled from 27 level off 39 dip in the Narainkuri seam towards the expected position of shaft No. 34. However, the long borehole neither touched the shaft nor there was any water percolation from the borehole to indicate that Shaft No. 34 was sunk upto the Narainkuri seam.

7.2.3 The Employees' Union however, contended that the Md. Kalim (MW 17) and other mine officials could have located Shaft No. 34 at the surface by conducting a survey with reference to fixed surface features. According to the Union since the Md. Kalim (MW 17) and other officials did not either conduct any such survey or make any other special efforts, to locate the extent of shaft No. 34 they failed to exercise due diligence resulting in the accident.

7.2.4 As the Court of Inquiry I considered the above arguments of both parties. No evidence was brought before the Court to indicate that Shaft No. 34 was visible on the surface. During my inspection of Shaft No. 34 at the surface, I saw wild growth around the area with some patches of vegetable garden. The villagers who were present during my inspection also informed me that Shaft No. 34 was not visible at the surface before the occurrence of the fatal accident.

7.2.5 The next question is whether the Shaft No. 34 could have been located at the surface by Md. Kalim (MW 17) and others with reasonable efforts. It has been admitted that there is possibility of error in the position of Shaft No. 34 indicated on the plan due to tracing and retracing from old plans as well as due to inaccuracy of survey. Since the surface area of the Mahabir mine was large and consisted of cultivable land and barren land without many prominent surface features, it might not have been very easy to locate a shaft of only 3 m. diameter hidden under an unknown cover of soil. The problem can be appreciated when one observes that there are over 36 filled shafts scattered over six square Km. surface area of the Mahabir mine. Thus, I hold that it was not reasonably possible for the Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW 17) and others to locate the filled up Shaft No. 34 at the surface.

7.2.6 Md. Kalim (MW 17) and others had relied largely on the AMP (Exhibit M/2A) in respect of depth of Shaft No. 34. But the AMP (Exh. M/2A), was of the adjoining 1 and 2 pit workings and not of workings made from Shaft No. 34. In the AMP (Exh. M/2A), Shaft No. 34 was merely shown as a surface feature of the adjoining mine. Secondly, it was recorded in the AMP (Exh. M/2A) as follows : 'Old Pit No. 34, depth 86 feet. Approximate position taken from old plan'. Thus such an AMP (Exh. M/2A) should not have made the Md. Kalim (MW 17) presume the supposed location of old Shaft No. 34 and its extension upto the Nega seam only. With about 25 years of experience in coal mines, Md. Kalim (MW 17) was knowledgeable enough to understand that in the past a number of disasters due to inundation had occurred in coal mines because of inaccurate plans. In this context, he and the Safety Officer, Shri P. L. Banerjee (MW 16) should not have become complacent that Shaft No. 34 did not extend beyond the Nega seam only because the AMP (Exh. M/2A) indicated so.

7.2.7 While granting permission for developing the Narainkuri seam below the waterlogged Nega seam, the DGMS included provision of advance boreholes though while applying for the working permission the then Agent had sought exemption from such boreholes. Obviously the DGMS apprehended possibility of old workings in the Narainkuri seam and had not relied on the AMP (Exh. M/2A). This was yet another reason why Md. Kalim (MW 17) and Shri P. L. Banerjee (MW 16) should have proceeded very cautionsly because 40 dip off 28 level was the area where the old Shaft No. 34 was likely to be located. It is a fact that a long borehole was drilled from 27 level face towards the position of old Shaft No. 34 indicated in the plan (Exh. M/11) though the borehole did not intercept it. But it could not be the conclusive evidence that Shaft No. 34 had not extended upto the Narainkuir seam. It is quite likely that a long borehole may fail to intercept a shaft of only 3 m. diameter as in this case. Md. Kalim (MW 17) and Shri P.L. Banerjee (MW 16) were also experienced enough to know it.

7.2.8 The plan of the site of the accident (Exh. M/12) indicates that the Shaft No. 34 had shifted by 6.5 m south west of its position shown on the working plan (Exh. M/11). Thus the Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW 17) and Shri P. L. Banerjee, Safety Officer (MW 16) had erred in relying on the data provided by a single long borehole that Shaft No. 34 had not extended upto the Narainkuri seam.

7.2.9 A question now arises as to when and how did these shafts get exposed on the surface. Soon after the occurrence of the accident on the morning of November 13, 1989 filled Shaft No. 34 got exposed to the surface. It was a little later that subsidence and potholes developed at the surface near Shaft No. 34. It is quite possible that when water flowed from the Nega seam to the underlying Narainkuri seam, the debris column that filled the shaft got washed down, exposing Shaft No. 34 to the surface.

7.3.1 Let me now analyze whether there was any unusual seepage of water at 40 dip off 28 level immediately before the fatal accident. It is accepted that seepage of water not normal to the seam is a positive warning that the workings are approaching a waterlogged area. The Employees' Unions deposed that there was heavy seepage of water while working near the old Shaft No. 34, but the Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW 17) and other officials deposed that the seepage of water was not unusual. Regulation 127 of CMR 1957 lays down, inter alia, that whenever seepage of water which is not normal to the seam is noticed at any place in any workings, or if there be any such suspicion or doubt, such working shall immediately be stopped and the DGMS shall forthwith be informed of such seepage and such workings shall not be extended further except with prior permission in writing of the DGMS and subject to such conditions as he may specify therein.

7.3.2 The workings of the Narainkuri seam is normally dry. In December, 1988 while developing near old Shaft Nos. 33 and 34 the former Agent Shri K. K. Das (MW 18) observed unusual seepage of water from the faces at 26, 27 and 28 level off 39 dip. The Surveyor Shri P. L. Thacker (MW 15) recorded in his statutory surveyor's diary about this

unusual seepage of water as well as the fact that the workings were nearing old shaft No. 34. As required under Regulation 49 of CMR 1957, the daily was counter signed by the Manager Md. Kalim (MW 17). The former Agent Shri K. K. Das (MW 18) also observed the unusual seepage of water in those faces and recorded the same in his inspection report book (Exhibit W/5). The workings in this area was stopped and the DGMS was informed. Thereafter the former Agent, Shri K. K. Das (MW 18), vide his letter of January 19, 1988 (Exhibit M/5) addressed to the DGMS stated that in light of above seepage, he sought change in the projections of development near Shaft Nos. 33 and 34 from those earlier approved by the DGMS (Exh. M/5). Shri K. K. Das (MW 18) however recorded in his inspection report (Exhibit W/5) that the seepage observed by him on January 13, got reduced when he submitted his report on January 28, 1988. But his observation was based on eye estimation and not on actual measurement. In his deposition, Shri K. K. Das (MW 18) also stated that water was percolating through the cracks in the roof at 27 level. If it was so, he would have also recorded in his inspection report (Exh. W/5). He had not done so. On the contrary he had recorded that the roof and sides were good. Further, Shri K. K. Das (MW 18) got a long borehole drilled from 27 level off 39 dip towards the position of Shaft No. 34 indicated in the working plan (Exh. M/11), Shaft No. 34, was, however, not connected by the long borehole as stated earlier. Nevertheless, Shri K. K. Das (MW 18) proceeded cautiously and did not go ahead with further development in that area and sought fresh permission of DGMS in January, 1988 to work in a revised projection about 100 m. away from old Shaft No. 34. The question is why Shri K. K. Das (MW 18) did not go ahead with the workings at 27 level after January, 1988. It was obvious that the seepage of water at 27 level was so heavy that he sought permission of the DGMS for working a new projection. In his deposition, Shri K. K. Das (MW 18) had stated that he wanted a longer period to observe the seepage of water at 27 level by driving a long borehole. Hence caution was the keynote in the approach of Shri K. K. Das (MW 18). When such was the note of caution sounded by Shri K. K. Das (MW 18), Md. Kalim (MW 17) who was a Manager of the Mahabir Mine under Shri K. K. Das (MW 18) and was aware of all developments in this regard should not have started work in the 40 dip gallery off 28 level (which was very close to 39 dip off 27 level and still closer to shaft No. 34) on November 8, 1989 without any permission from the DGMS. It is significant to note that the fatal accident occurred only after five days of the commencement of work at 40 dip gallery off 28 level.

7.3.3 There is evidence that 40 dip face off 28 level was re-started on November 8, 1989 after a lapse of almost two years. Most of the witnesses of the management, including Shri Dodan Pandey (MW 13), Shri Ram Shankar Sarkar (MW 12), Shri Shivdas Chatterjee (MW 9), Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW 10) and Shri Chandradhari Barai (MW 14) stated that there was no seepage of water from 40 dip working on November 12, 1989. However Shri Ganesh Roy (MW 5) stated that they sometimes used to fill their water bottles with the water seeping from faces of 42 cross-cut. Shri Nur Mohammed (MW 4), a loader of 40 dip on third shift of the day of the accident deposed that the district was dry except some seepage at 40 dip face. On the contrary, witnesses produced by the Unions like Shri Ram Chander Mahato (UW 4) and Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) reported heavy seepage of water from the roof and face of 40 dip on the third shift of November 12, 1989. There was also no water spraying arrangement provided at 40 dip face, though it was provided in other faces of the district, to suppress air-borne coal dust for safe mining.

7.3.4 The question is whether the seepage of water at 40 dip face off 28 level immediately before the fatal accident was unusual. If it was unusual, the Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW 17) and the officials under him would have been forewarned of waterlogged workings ahead and should have taken necessary precautions. Whereas most of the witness of the management (i.e. MWs) deposed that there was no unusual seepage of water, all the witnesses of the employees' Union (i.e. UWs) deposed regarding unusual seepage of water at 40 dip face immediately before the fatal accident. There was, however variation in the quantity of seepage of water among the witnesses of the Employees' Union. Shri Ramachandra Mahato (UW 4) deposed regarding heavy seepage of water which affected normal working. Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) who has since retired from service, deposed that the seepage of water at 40 dip face prior to the accident was unusual to the extent that it appeared like a mild drizzle. Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) Appeared to me to be a non-partition and truthful witness. His demeanour and simple and straightforward answers impassed me. I believe him regarding unusual seepage of water at 40 dip face prior to the fatal accident and hold that Md. Kalim (MW 17) and officials working under him had enough warning of the workings approaching a waterlogged area in an otherwise dry Narainkuri seam. Naturally, existence of a waterlogged shaft in such close proximity of the workings did cause unusual seepage of water at 40 dip face.

7.3.5 The former Agent Shri K. K. Das (MW 18) as well as Md. Kalim (MW 17) deposed that the roof of 26, 27 and 28 levels from where seepage of water was observed in 1988 was bad and needed heavy support. However my inspection of these workings after the accident indicated neither presence of cracks and bad roof conditions nor presence of heavy supports. The roof appeared to be normal like any other workings of the district. The plan (Exh. M/11) of the area also did not indicate presence of geological disturbances. I had also observed the marks of seepage of water left in the wall of 27 level off 39 dip particularly where advance flank boreholes had been drilled in 1988. Therefore the unusual seepage of water at 27 level in 1988 was not due to presence of any geological disturbances but because the workings were advancing to an area in close proximity of the waterlogged Shaft No. 34.

7.3.6 As already indicated, the workings of 40 dip had been stopped for unusual seepage of water in January 1988 and this seepage was recorded in the statutory book and the DGMS had also been informed. Therefore Md. Kalim (MW 17) was also not within his right to restart 40 dip face off 28 level on November 8, 1989 without written permission of the DGMS as required under Regulation 127(5) of CMR 1957. This was also not objected to by Shri P. L. Banerjee, Safety Officer (MW 16) whose primary duty was to ensure safety in the mine. The Assistant Manager, Shri K. Dutta (MW 19) also did not protest even though he knew that 40 dip off 28 level was known to be an area of heavy seepage of water where work had been stopped in January, 1988 and commencement of work in this area was not covered by the working permission of DGMS.

7.4.1 Let me now analyze the evidence regarding the long borehole drilled in 1988 to locate the old Shaft No. 34. In January, 1988, seepage of water was observed in 26, 27 and 28 level faces and the Surveyor Shri P. L. Thacker (MW 16) brought this to the notice of the Md. Kalim (MW 17), who was then the Manager, as well as the former Agent Shri K. K. Das (MW 18) that the workings were approaching Shaft No. 34. A long borehole was thus proposed to be drilled from 27 level off 39 dip towards the expected position of old Shaft No. 34. The purpose of the long borehole was to locate Shaft No. 34 and also to comply with the stipulations contained in the working permission of the DGMS (Exh. M/5). Shri P. L. Thacker, Surveyor (MW 15) gave direction of the borehole so as to intercept the Shaft No. 34 in the Narainkuri seam. He made the calculation of the direction and the length of the borehole based on the position of Shaft No. 34 marked on the mine working plan (Exh. M/11) with reference to position of 27 level off 39 dip face. He also gave the bearing of the long borehole at the site. On the basis of the direction marked by the Surveyor, the Driller Shri Ramesh Majhi (MW 8) drilled a long hole of 133 feet (40 m) at almost the centre of the face of 27 level. The drilling operation was done under the supervision of Shri P. L. Banerjee (MW 16). Shri P. L. Thacker (MW 15) measured the length of the long borehole and verified its direction. I saw the above long borehole during the inspection of the site of the accident. I am thus satisfied that the long borehole was in fact drilled in 1988 to locate Shaft No. 34.

7.4.2 Md. Kalim (MW 17) admitted the possibility of error in the location of Shaft No. 33 and 34 in the mine

working plan (Exh. M/11), Shri P. L. Banerjee (MW 16) however stated that it was not possible to take any measure to prevent the likely deviation of the long borehole and there was no instrument available with them to examine whether long borehole has actually deviated. Shri P. L. Thacker (MW 15) stated that there was every chance of the borehole deviating if the drillers did not take adequate care. Thus there was possibility of the long borhole deviating and failing to intersect the old Shaft No. 34. Md. Kalim (MW 17) and Shri P. L. Banerjee (MW 16) had no reasons to be absolutely sure that the long borehole of 133 feet (40 m.) had crossed the old Shaft No. 34.

7.4.3 Subsequently, a survey of the site of accident was conducted by the management and a plan was prepared (Exhibit M/12). It indicated that the actual location of Shaft No. 34 was 6.5 m. away from that show in the mine working plan (Exhibit No. M/11). The long borehole therefore failed to intersect old Shaft No. 34 in the Narainkuri seam. Thus the drilling of only one long borehole at 27 level in 1988 developed a false sense of security that Shaft No. 34 had not extended upto the Narainkuri seam.

7.5.1 Let me analyze whether the Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW 17) had working permission of the DGMS to work 40 dip at 28 level. It was alleged by the Employees' Unions in the written arguments that 40 dip off 28 level was being developed from November 8, 1989 without any working permission of the DGMS. On the other hand the management argued that they had a valid permission from the DGMS and therefore drivage of 40 dip off 28 level was permitted.

7.5.2 Regulation 127 of CMR 1957 requires that no workings shall be extended within 60 m. of any waterlogged working without prior permission in writing from the DGMS subject to the conditions specified. The Regulation also requires that every application for permission to extend any such workings should be accompanied by plans showing, inter alia, the outlines, the layout and the method of proposed working. Once the permission is granted by the DGMS to extend the working, it shall be extended strictly in accordance with the plan, the method approved and the conditions specified therein. There is no scope for the Agent-cum-Manager to vary the stipulations in the working permission unless such variation is again approved by the DGMS.

7.5.3 In December, 1983, the management applied for permission to develop an area in Narainkuri seam on the south side of the main railway line (Exh. M|5). The plan submitted with the application (Exh. M/4) showed projections of development beneath old Shaft Nos. 33 and 34. Working permission for this development was granted vide DGMS letter No. S-3|173 (BD)|(MB)|II-B|84|1062 dated March 12, 1984 (Exh. M|5). It included the area where the accident took place on November 13, 1989. The working permission required that old shaft should overlie the pillars formed. According to this permission the area between 26 level and 31 level could be developed beyond the location of Shaft Nos. 33 and 34, leaving the shaft in solid pillars. Thus while granting the working permission in 1984, DGMS had also taken care of safety precautions adequately.

7.5.4 However, in his letter No. ECL : MB : DEV : 88 :| 198 dated January 19, 1988 (Exh. M|6), the former Agent Shri K. K. Das (MW 18) sought change in projections of development from the DGMS in the light of unusual seepage of water in the faces of 26 level off 38 dip and 27 level off 39 dip in proximity of the old Shaft No. 34.

7.5.5 A comparison of the projections in the plan accompanying the application for the permission in 1983 (Exh. M.4) with that of 1988 (Exh. M. 7) would indicate that in the received projection (Exh. M|7), the workings between 26 and 31 level were not to be advanced any further towards old Shaft Nos. 33 & 34. The old shafts were to be bypassed following a cross-cut from 32 level. The next cross-cut known as 41 cross-cut was to be driven 45 m. away from Shaft No. 33 and 100 m. away from Shaft No. 34. No development was proposed on the dip side of 41 cross-cut.

7.5.5 The DGMS in his letter No. S3/22 03/062/IIA| 88/623 dated March 2, 1988 (Ex. M/8) granted modified permission to develop Narainkuri seam according to the new projections (Exh. M/7). However, the terms and conditions stipulated in the earlier DGMS permission letter No. 1062 dated March 12, 1984 (Exh. M/5) remain unaltered.

7.5.6 The former Agent Shri K. K. Das (MW 18), the Manager, Md. Kalim (MW 17), the Safety Officer Shri P. L. Banerjee (MW 16) were of the opinion that the projections for development granted by the permission of 1984 (Exh. M/5) remained valid even when they had sought modification of the projections (Exh. M/7) for specific reason and were granted accordingly the permission of 1988 (Exh. M/8). In other words, the modified permission of 1988 did not supersede the permission of 1984 and therefore the development of 40 dip at 28 level from November 8, 1989 was done in a permitted area. In my opinion it was not necessary for the DGMS to state categorically in the "1988 permission" that the "1984 permission" stood cancelled. Such a cancellation was implicit as the former Agent, Shri K. K. Das (MW 18) had himself sought modification in the "permission" in light of heavy seepage of water at 26, 27 and 28 levels in close proximity of Shaft No. 34. Further such a line of argument for the management is not at all tenable as Regulation 127 (5) ibid clearly stipulates that once a working is stopped in a particular area for unusual seepage of water, the working shall not be restarted in that area without a fresh permission in writing from the DGMS. In this case, the DGMS had given no such fresh permission. Hence resumption of mining from November 8, 1989 at 40 dip at 28 level, where it had been stopped in January 1988, due to unusual seepage of water, was totally unwarranted. Md. Kalim, (MW 17), Shri P. L. Banerjee, (MW 16) and Shri K. Dutta, (MW 19) being senior and responsible officials and holding Managers' certificate of competency should have realized this aspect of the Regulation.

7.5.5 The management have argued that whenever the waterlogged workings are situated in the same seam, it might be necessary to drill one central borehole as well as a number of flank boreholes but if the waterlogged workings are situated vertically above the proposed workings, flank boreholes of 3 m. in length is unnecessary and only a central advance borehole may be required to explore the possibility of existence of geological disturbance ahead. But this line of argument is not sound as the subsequent analysis would indicate.

7.5.6 The parting between the Nega and the Narainkuri seam is only 24 m. and there are old shaft of unknown depth which might have extended upto Narainkuri seam. The possibility of an old shaft extending upto Narainkuri seam or existence of old workings in the Narainkuri seam through drifts from overlying seam, could not be rule out. Therefore it could not be assumed, as the management have argued, that the waterlogged workings were only in the overlying seam and thus no advance flank hole was necessary. The permission of DGMS (Exh. M 5) was to take care of all these possibilities, as the DGMS had prescribed sufficient number of flank boreholes along with central boreholes.

7.5.7 To elaborate: the working permission of the DGMS both in 1984 and in 1988 for the Narainkuri seam of the Mahabir Mine was in total conformity with Regulation 127(6)(a) which requires that when the workings are advanced towards waterlogged areas, there shall be maintained at least one borehole near the centre of the working face and sufficient flank boreholes on each side, and where necessary boreholes above and below the workings at intervals not more than 5 m. All such bore holes shall be maintained and shall be constantly maintained at sufficient distance in advance of the workings and such distance shall in no case be less than 3 m. These stipulations are required to be carried out under the direct supervision of an official of the mine having a manager's or overman's certificate, specially authorised for the purpose. Under the relevant Regulations, a record of the height and width of the workings as well

as the number of boreholes, their length and direction is required to be maintained in a register and the register is to be signed by the official authorised for the purpose and counter-signed by the manager everyday. These records were not maintained by Md. Kalim, Agent-cum-Manager (MW 17) and the officials under him.

7.6.1 Now let me analyse the evidence regarding the most important issue whether the working at 40 m. face started from November 8, 1989. had adequate protection of advance central and flank boreholes. Md. Kalim (MW 17) deposed that in order to ensure compliance of all the conditions of the working permission of the DGMS as well as the requirements of Regulation 127, of CMR 1957 he had provided necessary infrastructure like drilling machine, manpower and supervision. The advance boreholes were drilled by means of ordinary coal drill. The pattern consisted of a central borehole in the face and two flank boreholes in the jobs at forty five degrees to the face. The length of the flank hole was 3 to 3.6 m. and these were drilled on both the ribs. For the purpose of drilling the holes, a coal drill with three sets of drill steel of 1.8 m., 3.6 m. and 5.4 m. length was provided.

7.6.2 There is evidence that upto June, 1989 a regular advance drilling gang was provided. These workers, in the drilling gang who were designated drillers, were Shri Kuldip Das, (UW 1), Barho Dusad and Bindu Bouri. The drilling gang use to reach the district in the early hours of the first shift and complete drilling of the advance boreholes in all the faces proposed to be advanced on that day. However, in June, 1989, the drilling gang was disbanded by the Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW 17) and the drillers were deployed elsewhere. According to Kuldip Das (UW-1) since the disbandment of the drilling gang in June, 1989, no advance boreholes were drilled. Md. Kalim (MW 17) and Shri P. L. Banerjee (MW 16) stated that for better utilisation of manpower the advance drilling gang was disbanded. However drilling of the advance boreholes was continued by the general mazdoor of the first shift and such advance central and flank boreholes were provided in 40 dip face when it was started on November 8, 1989. Thereafter, according to the witnesses produced by the management, these boreholes were regularly drilled and on the first shift of November 12, 1989. the advance central borehole was extended from 3.6 m to 5.4 m and two flank boreholes of 3.0 m. to 3.6 m. in length was drilled in the ribs of 40 dip face. These advance boreholes were drilled under the supervision of Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW-10) and Shri C. D. Singh (MW 11). Overman. They found the length of the advance boreholes to be in order. In the second shift, Shri Shivdas Chatterjee (MW 9), Overman checked the advance boreholes and found it to be about 3.6 m in length. He also checked the advance flank boreholes and found them to be in order. In the third shift Shri Dodan Pandey, Sirdar (MW 13) also checked the central borehole in 40 dip face and found it to be more than 3 m. The shot-firer Shri Chandradhari Barai (MW 14) deposed that before charging the shots in the face of 40 dip on the fateful day, he had also checked the central and flank boreholes with his stemming rod which was 1.8 m. in length and thus he concluded that these holes were more than 1.8 m. However, Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) who also charged the shot-holes of 40 dip immediately prior to the accident categorically stated that there was no advance and flank boreholes in the face. He claimed to have known the difference between shot holes and advance boreholes. Other witnesses such as Ganesh Roy (MW 5) and Ram Chandra Mahato (UW 4) also denied having seen any advance holes in the face.

7.6.3 An interesting point is that none of the persons who stated that advance boreholes were drilled, could name even a single driller who drilled those holes. Only one witness, Shri C. D. Singh (MW 11), could recollect the name of a driller called Shri Madhuri Paswan. But he too was also not sure of his designation. Initially he stated the driller to be a general mazdoor but later recollected his designation to be a driller. Since drilling of advance boreholes was a regular affair as claimed by the Agent-cum-Manager Md. Kalim (MW 17) and other officials under him it is highly unlikely that none of the officials from Agent-cum-Manager downwards, who claimed to be connected with the supervision of advance boreholes at 40 dip on 28 level, could remember the name of even a single person who drilled those advance boreholes. Secondly, drilling of an advance borehole of 5.4 m. by an ordinary coal drill involves change of the drill rods in stages. The drill holes are required to be drilled centrally as well at forty five degrees to the face. Therefore there could be no denial that drilling of advance boreholes required skill, not less than that required for drilling shotholes at the face. It is unlikely that the job could be done by general mazdoors deployed to do the job on a casual basis as claimed by Md. Kalim, Agent-cum-Manager (MW 17) and other officials.

Further, no supervisory officials examined as witness before this Court accepted the responsibility of supervision of the advance holes in terms specified under Regulation 127(6) of CMR, 157. Md. Kalim (MW 17) stated that he could recollect to have authorised two overmen for this purpose but failed to recall their names, except the name of one Shri Mukherjee. However, no such person (i.e. Shri Mukherjee) could be produced by the management as a witness. Shri Mihir Kumar Chatterjee, Overman (MW-10) accepted the responsibility of supervising the advance boreholes only to the extent he was generally asked by the Agent-cum-Manager Md. Kalim (MW 17) to supervise the work of advance boreholes, but he was not normally entrusted with the supervision of such boreholes as required under Regulation 127 of CMR 1957. Md. Kalim (MW 17) also admitted that no mandatory records of the advance boreholes at a 40 dip of 28 level or at any other working face of the Mahabir mine were maintained.

7.6.4 The manner and the system of monitoring the drilling of advance central borehole upto a length of 5.4 m and flank boreholes 3.0 m to 3.6 m long and at forty five degrees to the face was also not clearly spelt out by the Agent-cum-Manager Md. Kalim (MW 17). From the analysis of the evidence, it appears that only when the supervisory staff would go to the face, they would measure the advance boreholes. There was no regular system either for recording or for monitoring the same.

7.6.5 During my inspection of 40 dip face after the accident, I did not see any signs of flank boreholes except one at the start of the gallery. These flank boreholes, if drilled would have been left in the pillars. On this issue, to a question from the Court of Inquiry, Shri P. L. Banerjee, (MW 16) and K. Dutta (MW 19) stated that the flank boreholes were denuded and washed away by the water when the inrush took place. However the width of 40 dip was like any other gallery of the district i.e. about 4.2 to 4.5 m. The side and roof bore the same jagged look normally seen when a gallery is developed by blasting. Hence the argument put forward by Shri P. L. Banerjee (MW 16) as well as the Management and the Indian Mine Managers' Association that the flank boreholes were washed away cannot be relied upon. Similarly, the possibility of the flank boreholes having been sealed by flowing mud and coal dust due to the inrushing water cannot be accepted as the same is not borne out by observations made during my inspection of the site of accident.

7.6.6 On the basis of the observations during inspection of the site of accident which clearly revealed absence of flank boreholes, evidence of eye witnesses like Shri Bhangi Rajbhar (UW 5), failure of the management of the mine to furnish the minimum mandatory records of boreholes, and failure to produce a single witness who had actually drilled the advance boreholes I am of the opinion that no advance central and flank boreholes were drilled in 40 dip face on the fateful day of November 12, 1989. This was a gross and wilful violation of Regulation 127(6) of CMR 1957.

7.6.7 During my inspection of the site of accident I had observed that 40 dip gallery was no different from any other gallery of the district. It had the same width and height and the same appearance like any other gallery, including the adjacent galleries where flank holes were provided. The sides of the 40 dip gallery exhibited no sign of existence of flank holes except one flank borehole at the start of the gallery.

7.6.8 Therefore, in my opinion the deposition of Shri P. L. Banerjee (MW 16), Shri C. D. Singh (MW 11), Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW 10), Shri Chandradhari Barai (MW 14) and Shri K. Dutta (MW 19) that the width of 40 dip gallery was only 3 m. against normal width of 4.2 m. was incorrect. It was possibly made with the motive of justifying the stand that the flank boreholes made along 40 dip gallery had been denuded by the inrushing water, ultimately assuming its final width of 4.2 m.

7.7.1 The plan of the site of accident (Exh. M/12) showed an abrupt deviation of 40 dip gallery, near the connection with Shaft No. 34. The management witnesses like Shri K. Dutta (MW 19), Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW 10), Shri C. D. Singh (MW 11), Shri Dodan Pandey (MW 13), and Shri Chandradhari Barai (MW 14) deposed that the centre line of 40 dip gallery was hardly 3 m. to 3.6 m. behind the face on the day of the accident. However, the Surveyor Shri P. L. Thacker (MW 15) claimed that he had not marked the centre line of 40 dip gallery after it was restarted on November 8, 1989. He even deposed that he had not visited 40 dip face between November 8, and November 13, the day of the accident. It could be that his assistants had extended the centre line, but he was not sure. No explanation was given either by any witness or by any of the parties to account for such abrupt deviation of the gallery. It could be that the gallery was purposely deviated with reference to the presumed location of Shaft No. 34 in the plan to avoid driving beneath it and to make sure the pillar to be formed encloses the shaft. The other possibility could be the presence of an inset from old Shaft No. 34 oblique to 40 dip gallery. While advancing the gallery the barrier with the inset got reduced and ultimately it failed. The resultant connection with the presumed old and abandoned shaft inset took the form of an abrupt southerly deviation. In my inspection, I had not observed any marked difference in shape and size of 40 dip gallery all throughout its length. Therefore it appears unlikely that there was existence of a shaft inset or a gallery from Shaft No. 34. Further, in view of all the eye witnesses deposing that the centre line was provided and there being no evidence to the contrary, I rule out the third possibility of deviation of the gallery because of absence of suitable centre line. Hence I feel that it is likely that the gallery was purposely deviated.

7.7.2 As already mentioned, 40 dip face which was in close proximity of old Shaft No. 34 was stopped in January, 1988 when unusual seepage of water was observed in that area. At that time the face had hardly extended about 10 feet to 12 feet (3 to 3.6 m.) from 28 level. Later the junction of 40 dip off 28 level housed the return pulley of the endless haulage Md. Kalim (MW 17) deposed that 40 dip gallery was restarted in November, 1989, whereas Shri K. Dutta (MW 19) deposed that it was started in the first week of November, 1989. Other witnesses like Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW 10), Shri Shibdas Chatterjee (MW 9) and Shri C. D. Singh (MW 11) deposed that 40 dip face was restarted on November 8, 1989. Therefore, I hold that 40 dip face off 28 level, which got connected with old Shaft No. 34 and caused the fatal accident was restarted on November 8, 1989, barely five days before the accident.

7.7.3 The next point is whether there were other causes and circumstances leading to the connection of 40 dip gallery with Shaft No. 34. Shri P. L. Banerjee (MW 16) claimed that the connection took place due to sudden failure of a coal barrier of more than 3 m. between the advancing gallery and Shaft No. 34.

7.7.4 The length of 40 dip face prior to the occurrence of the accident was estimated by various witnesses like Shri Ram Sankar Sarkar (MW 12), Shri Shibdas Chatterjee (MW 9), Shri C. D. Singh (MW 11) and Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW 10) to be around 40 feet to 45 feet (12 m. to 17 m.).

7.7.5 On the basis of the estimates of the above witnesses about the length of the 40 dip gallery and the position of old Shaft No. 34 determined from the plan of the site of accident (Exhibit M/12), P. L. Banerjee (MW 16) deposed that the barrier between the 40 dip face and Shaft No. 34 was more than 3 m. immediately before the accident occurred. But I have not accepted this as the length of 40 dip face as stated by different witnesses was on the basis of eye estimates only and not on the basis of actual measurement.

CHAPTER VIII

8.1 ANALYSIS OF EVIDENCE— EXTENSION OF SHAFT NO. 34

8.2 UNUSUAL SEEPAGE OF WATER

8.3 RESTARTING OF 40 DIP

8.4 ADVANCE BOREHOLES

8.5 STARTA MOVEMENT

8.6 LOOSENING OF FLOOR STONE

8.7 CAUSE OF THE ACCIDENT

8.1 It was well known that workings of the Nega seam of the old Raniganj Colliery 24 m. above the Narainkuri seam was waterlogged. There were also a number of old shafts in the property, the depths of some of which were not known. One such old shaft was No. 34, which was filled with debris and whose depth was also not known. The management of the mine deposed that they studied the available old plans and records, but could not find the depth of the old shaft. However an AMP of the adjoining workings (Exhibit M/2-A) indicated the depth of Shaft No. 34 as 86 feet which corresponded to the depth of the Nega seam in that area. While granting permission for development in 1984 (Exhibit M/5) the DGMS was very careful and apprehending extension of old shafts upto the Narainkuri seam included the condition of providing flank and central advance holes. In 1988, while developing in the vicinity of old Shaft No. 34, the management of the mine also observed unusual seepage of water. As already mentioned, they stopped the development workings and informed the DGMS as required under Regulation 127 (5) of CMR 1957. Since the existence of old Shaft No. 34 was suspected, the management consulted available plans, documents and other sources of informations so as to ascertain the depth of Shaft No. 34. However, no precise information about its depth was available to them. They also tried to locate the Shaft No. 34 at the surface by visual inspection, but failed to do so as it was filled with debris. Later the management of the mine tried to locate the shaft by providing a long borehole from 27 level off No. 39 dip. Neither the borehole touched the old shaft, nor was there any seepage of water from it. The management of the mine admitted that there was possibility of error in the position of Shaft No. 34 indicated in the working plan (Exh. M/11) because of tracing and retracing from old plan, possibility of shrinkage of the plan as well errors in surveying and plotting. They had also admitted the possibility of deviation in the direction of the long borehole. Obviously, with so many unforeseen parameters, the possibility of proving the existence of an old shaft of hardly 3 m. in diameter by only one long borehole of about 40 m. length is indeed very remote.

8.2 In 1988, the management of the mine rightly decided to suspend the workings and to change the projections of development by passing the suspected old Shaft No. 34. The application for change in projection was made in view of unusual seepage of water at 26, 27 and 28 levels. The revised projection plan about 100 m. away from this area was approved by the DGMS in March, 1988 (Exhibit M/8).

8.3 In November 1989, while developing as per the revised projection of 1988, (Exhibit M/8), the workings touched a dyke in 42 cross-cut section. In order to get a new working area in replacement, Md. Kalim (MW-17) consulted the plan at the survey office, and decided to restart 40 dip face off 28 level. As already mentioned, working in this face had stopped since 1988. The argument of the Management that 40 dip face was restarted from November 8, 1989 to improve ventilation only in the district cannot be accepted as there were other options available to improve ventilation. By starting work at 40 dip, Md. Kalim (MW-17) clearly violated the provision of Regulation 127(5) of CMR 1957 which requires prior written permission of the DGMS. In other words, once the workings around Shaft No. 34 had been stopped in January 1988 due to unusual seepage of

water, Regulation 127 (5) of CMR 1957 does not give any authority to Md. Kalim (MW-17) to restart such workings unilaterally. Thus I hold that from November 8, 1989, Md. Kalim (MW-17) developed 40 dip which was in an area within 60 m. of waterlogged workings without permission of DGMS and in contravention of Regulation 127 (3) of CMR 1957.

8.4 A number of witnesses have deposed that drilling of advance boreholes in a systematic manner by a regular gang was stopped since June, 1989. Subsequently, the advance boreholes were reportedly drilled by general mazdoors. These general mazdoors reportedly used for such drilling were also not regular but were employed on casual basis. These workers were relatively unskilled workers whereas the regular drillers were required to be skilled workers. There were also no marks of any flank boreholes along the sides of 40 dip. There was also no records to indicate that such boreholes were drilled. The workers who had actually drilled the advance borcholes were not produced as witnesses by the management. No competent person was also appointed by the Agent-cum-Manager to supervise the drilling of such advance boreholes. In the absence of any documentary evidence including the minimum statutory record regarding provision of advance boreholes, non-appointment of regular drillers to drill the boreholes and competent person to supervise the drilling such boreholes, absence of a system of measuring the length and direction of such boreholes, as well as absence of flnak boreholes at site during my inspections leads me to conclude that even the central boreholes was also not drilled at 40 dip face.

8.5 Some witnesses, as the Safety Officer P. L. Banerjee (MW-16) have attributed the failure of the coal barrier between 40 dip face and Shaft No. 34 to a major strata movement. This is also the argument of the Indian Mine Managers' Association. The noise of the cracking of the roof rock in the front and behind the face heard by Shri Chandradhari Barai (MW-14) while firing the second round of shots at 40 dip face, the dislodgement of a large piece of floor stone from the junction of 40 dip and 28 level, and the appearance of subsidence and potholes on the surface, have been advanced asa evidence of such strata movement. The sound of cracking of rock, had it been there, would have been audible to not only Shri Chandradhari Barai (MW-14) but also to other workers present in the vicinity of 28 level. There was no evidence that other workers heard such a cracking noice. In my view, the absence of any tell-tale evidence of any major strata movement in an around 40 dip, including no visible effect on the roof and especially on the thin rib of coal less than a metre in thilkness between 27 level and 40 dip, rules out any such eventuality. It is, therefore, tenuous to suggest that any puncturing of the coal barrier between 40 dip gallery and Shaft No. 34 resulted from strata movement due to crushing of aged and left-out stooks in the overlying Nega seam. If such a strata movement would have taken place it would have led to a large subsidence rather than localised potholes which are common occurrences after drainage of water from old workings.

8.6 It is tenuous to suggest that loosening of the big block of stone from the floor of 40 dip and 28 level junction and its shifting by almost a distance of half a pillar was because of a major strata movement causing the fatal accident. It is quite possible that the floor stone could have got loosened due to its inherent weakness. When there was sudden inrush of water, the loose block of stone perhaps got carried upto a distance of about half a pillar from its original position. In any case, the occurrence of the loose block of stone on the floor of the junction of 40 dip and 28 level had absolutely no connection with the fatal accident.

8.7 On the basis of the evidence, I hold that the cause of the fatal accident was due to direct connection between the advancing 40 dip gallery and waterlogged Shaft No. 34 in the Narainkuri seam connected to the overlying abandoned and waterlogged Nega seam. The accident occurred due to the failure to provide, central and flank boreholes in 40 dip gallery off 28 level advancing towards the waterlogged Shaft No. 34 in the Narainkuri seam. Such boreholes are mandatory under Regulation 127(6) of the CMR 1957 as well as required by the working permission of the DGMS. Further 40 dip gallery off 28 level was advanced towards the waterlogged Shaft No. 34 in an area not approved for working by the DGMS. Incidentally, the fatal accident occurred within only five days of commencement of working in the gallery in the unapproved area where mining had been stopped in January, 1988 due to unusual seepage of water. This unapproved area was about 100 m. away from the area approved for mining by the DGMS. Thus the fatal accident was due to culpable human negligence.

CHAPTER IX

9.1 ANALYSIS OF RESPONSIBILITY
9.2 AGENT-CUM-MANAGER
9.3 SAFETY OFFICER
9.4 ASSISTANT OFFICER
9.5 SURVEYOR
9.6 HIGHER MANAGEMENT
9.7 OTHERS

9.1 Once the cause of the accident is established the responsibility for the accident has to be fixed. It is evident from the cause of accident that it had occurred due to culpable human negligence. In the subsequent paragraphs, I have analysed the evidence to fix the responsibility.

9.2.1 Md. Kalim (MW-17) was the Manager of the mine since June, 1987 and Agent-cum-Manager since July, 1988. He was therefore well conversant with the mine from December 1987 till November 13, 1989. In December 1987, while working at 26, 27 and 28 level near old Shaft Nos. 33 and 34 of the mine, unusual seepage of water was noticed and the workings in that area was stopped in January, 1988 by the former Agent Shri K. K. Das (MW-18). He then applied to the DGMS for a change in the projections of development in the light of unusual seepage of water. The projection plan (Exh. M/7), by-passing Shaft No. 34 by a clear margin of 100 m. accompanying the revised application submitted to the DGMS in January 1988, was known to Md. Kalim (MW-17) *in his capacity as Manager*. A copy of the permission letter (Exh. M/8) approving the revised projections was sent by the DGMS to the Manager viz. Md. Kalim (MW-17) in March, 1988. In 1988, a long boreholes was drilled from 27 level towards the expected position of Shaft No. 34. Since the long boreholes did not intercept the old Shaft No. 34 and there was also no percolation of water from the boreholes, Md. Kalim (MW-17) assumed that the old shaft was sunk upto the Nega seam only. Obviously, on the basis of these incomplete investigations, it was not proper for an experienced Manager like Md. Kalim (MW-17) to conclude that the old Shaft No. 34 had gone upto the Nega seam only.

9.2.3 In November, 1989, when the workings of the regular district approved by the DGMS met with a series of dykes, Md. Kalim (MW-17) decided to restart working in the 40 dip off 28 level face, after visiting the survey office, consulting the plan and discussing with the Surveyor. He also admitted to have studied all the previous permission letters and other correspondence from the DGMS relating to mine safety. Thus he was fully aware of the fact that the workings near Shaft No. 34 had been stopped in January 1988 due to unusual seepage of water. He was also aware of the provision of Regulations 127(5) of CMR 1957 which requires that workings which had been stopped due to unusual seepage of water shall not be extended further without previous permission of the DGMS in writing. Since no such permission was obtained his act of restarting 40 dip unilaterally from November, 1989 amounted to wilful and flagrant violation of Regulation 127(5) of CMR 1957.

9.2.2 Md. Kalim (MW-17) also admitted of not maintaining records of the advance central and flank boreholes as well as the plan of the workings required by the permission letter of the DGMS (Exh. M/8) and Regulation 127(6) (b) of CMR 1957. He had also not authorised any competent official to supervise the drilling of advance holes. This was a clear contravention of Regulation 127(6)(b) of CMR 1957. He also did not provide a regular drilling gang for drilling advance boreholes, but employed on casual basis unskilled workers such as General Mazdoors for the job. It is a sad story that Md. Kalim (MW-17) with all these years of experience failed to apprehend an obvious danger which did not appear suddenly but gave enough advance signals. Md. Kalim (MW-17) either due to complacency or

due to an erroneous belief that Shaft No. 34 had not extended beyond the Nega seam failed to visualise the dangers, ultimately leading to the fatal accident. I therefore hold him primarily responsible for the accident which occurred at Mahabir Mine on November 13, 1989. While holding Md. Kalim (MW-17) primarily responsible for the accident, one cannot fail to admire his poise and steadfastness in the witness box and he in his calm and collected manner told the truth. He also deposed that he was directing the operations in the mine and no target of coal production necessitating violations of safety regulations was imposed upon him. A truthful officer as Md. Kalim (MW-17) certainly deserves words of appreciation from me for his conduct during the enquiry.

9.3.1 In the mine, Shri P. L. Banerjee (MW-16) was next in the hierarchy to Md. Kalim (MW-17). He worked as the Safety Officer of Mahabir Mine since June, 1988. Since 1983 he had also worked as Assistant Manager of the same mine. Thus he has been continuously working in the Mahabir Mine since 1983. His duty includes studying and apprising the Manager (i.e. Md. Kalim) of all possible source of danger including inundation. He is also to report to the Manager his observations during his visit to the various parts of the mine, as to whether the provisions of the Mines Act and Regulations framed thereunder are being complied with.

9.3.2 Shri P. L. Banerjee (MW-16) stated that he studied the old plans and found that old shaft No. 34 was filled up with debris. He relied on the various plans available at the mine office to plan out the workings. He could not locate Shaft No. 34 at the surface. He had observed unusual seepage of water at 27 level in January 1988 and had arranged to get a long boreholes drilled. As per his deposition, he was also aware of the possibility of deviation of the long borehole. He had studied the DMS permission of 1984 (Exhibit M/5) and 1988 (Exhibit M/8) and was therefore aware of the conditions of the permission. He was also aware of restarting of 40 dip face in November 8, 1989. He also maintained that there was no seepage of water from 40 dip face and the face was advanced with cover of flank and central boreholes after the work was started from November 8, 1989. But he deposed that there was no method by which he could ensure drilling of advance boreholes in every working face before advancing the same. He only ensured monitoring of such boreholes when he inspected the workings. However, as per his deposition, there was no laid down schedule of his visit and inspection of the working faces. I have already held that the fatal accident occurred because 40 dip face was advanced without cover of advance boreholes in spite of unusual seepage of water in an area not approved for working. These violations were known to Shri P. L. Banerjee (MW-16). Thus he failed to perform his duties under Regulation 41 A(1)(b)(iii) of CMR 1957 to apprise the Agent-cum-Manager Md. Kalim (MW-17) about Shaft No. 34 as a possible source of inundation. He either did not note during his inspection that central and flank boreholes were not being drilled, or wilfully allowed the 40 dip face to be advanced without such boreholes in contravention of Regulation 127(6) of CMR 1957 read with Regulation 41-A (1)(f) ibid. Thus it is evident that Shri P. L. Banerjee (MW-16) also did not take measures to promote safe practices of drilling of advance boreholes at 40 dip face in contravention of Regulation 127 read with Regulation 41-A(1)(g) of CMR 1957. I therefore also hold him responsible for the fatal accident. Thus it is evident that Shri P. L. Banerjee (MW-16) while being fully aware of the possible dangers, did not take necessary measures to promote safety practices as required under Regulation 41-A(1)(g) of CMR 1957. He is therefore also responsible for the fatal accident.

9.4.1 There were two Assistant Managers in the Mahabir Mine. They were Shri K. Dutta (MW-19) and Shri S. K. Sengupta (CW-1). Shri K. Dutta worked as Assistant Manager of the Mahabir Mine since 1979. He inspected 40 dip twice between November 7 and November 12, 1989 and also on the second shift of November 12, 1989. He knew that work in 40 dip face was stopped in January 1988 because of unusual seepage of water. He also knew that the overlying Nega seam was full of water. He deposed that advance central and flank boreholes of adequate length were provided in 40 dip face but beyond making such a bold statement, he could not either support it with any record maintained for the purpose or establish through independent witnesses that such boreholes were being systematically and regularly provided. He also could not establish that there was any system of checking such boreholes by supervisory officials before the gallery was advanced.

9.4.2 Therefore as an Assistant Manager of the district, he had failed to ensure that advanced boreholes were drilled in 40 dip face as required under Regulation 42 of CMR 1957 read with Regulation 127(6) of CMR 1957. Thus he had also wilfully violated the provision of the law resulting in the accident and is responsible for the same.

9.4.3 The second Assistant Manager Shri S. K. Sengupta (CW-1) joined the mine only on October, 1989. He was on leave for a few days thereafterr. He was assigned some other development jobs and did not do the job of supervision of 42 cross-cut district where the accident occurred. Thus he was not responsible for the fatal accident.

9.5.1 Shri P. L. Thacker (MW-15) was Surveyor of Mahabir Mine since 1977. He had observed the unusual seepage of water at 27 level in January, 1988. He had recorded this fact in his statutory Surveyor's Diary as well as recorded the information that the workings were approaching the waterlogged Shaft No. 34. The diary was counter signed by the Manager Md. Kalim (MW17). It was his duty to point out to the Manager that the workings had reached within 75 m. from waterlogged Shaft No. 34. He has done so in this case. The former Agent Shri K. K. Das (MW-18) deposed that he remembered that Shri P. L .Thacker (MW-15) gave him a report that workings of 27 level was approaching the abandoned Shaft No. 34. Md. Kalim (MW-17) also admitted that his attention was drawn to the danger of inundation through the diary maintained by Shri P. L. Thacker (MW-15). Obviously, Shri P. L. Thacker (MW-15) properly performed the duties enjoined upon him by CMR 1957.

9.5.2 In the circumstances, I do not hold Shri P. L. Thacker (MW-15) responsible for this accident.

9.6.1 Md. Kalim (MW-17) deposed in his cross examination that he used to fix the target of production of coal in consultation with his supervisor. It was invariably a joint decision and not an arbitrary decision imposed by the General Manager who was his official superior. Further in course of working, he was free to discuss and revise his target of production, if there was any problem. He denied the allegation that because of a likely shortfall of target of production he worked the mine at random in unauthorised projections. In respect of applicaion to the DGMS for working permission, he deposed that formal permission of the General Manager is not required but normally he discussed such cases with the General Manager. He deposed that for enforcement of mine safety regulations he had sufficient powers as the Agent-cum-Manager. His immediate superior was the General Manager of Kunustoria Area. The General Manager is advised on Safety matters by the Area Safety Officer, who is his staff officer. Md Kalim (MW-17) had discussed the likely danger of inundation from the old and abandoned shaft with the Area Safety Officer and the General Manager. Md. Kalim (MW-17) deposed that they had always advised him to strictly follow the 'permission' of the DGMS. Thus Md. Kalim (MW-17) had admitted that working of 40 dip off 28 level from November 8, 1989 was done under his orders and without the involvement of his superior officers. Moreover, there was no witness who deposed before the Court of Inquiry regarding the knowledge of the General Manager about commencement of work in the gallery at 40 dip from November 8, 1989. There was also no evidence that General Manager had known that safety regulations were being violated and advance Central and flank boreholes were not being given while driving the gallery. The General Manager was in charge of eleven mines of which Mahabir was one. It was obviously not possible for him to supervise the enforcement of the stipulations contained in the permission of the DGMS to give advance boreholes in accordance with Regulation 127 of CMR 1957. Accordingly, I do not hold that General Manager of Kunustoria Area, responsible for the fatal accident.

9.7.1 There had been lapses on the part of the supervisory officials like the overman and the Sirdar. These lapses are analysed below :

9.7.2 Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW-10) was the Overman permanently deployed in the first shift also called the

general shift. He deposed that his job was miscellaneous in nature and though he was not formally entrusted with supervision of advance boreholes, he was generally asked by the Agent-cum-Manager, Md. Kalim (MW-17) to supervise drilling etc. of such boreholes. Shri C. D. Singh (MW-11) was the shift overman of 42 crosscut district and he was on the first shift on November 12, 1989. Shri Shibdas Chatterjee, Overman (MW-9) and Shri Fouzdar Singh (MW-1) were the other two Overmen who were in the second and third shifts respectively on November 12, 1989.

9.7.3 Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW-10) and Shri C. D. Singh (MW-11) claimed to have ensured drilling of advance central boreholes of 5.4 m in length and two flank boreholes at 40 dip face in the first shift of November 12, 1989 Shri Shibdas Chatterjee (MW-9) claimed to have seen and measured those advance boreholes on the second shift of the same day. All those overmen also claimed that there was also no unusual seepage of water from the 40 dip face.

9.7.4 I have already held that there was no advance boreholes at 40 dip face off 28 level on Nobember 12, 1989 and there was also unusual seepage of water from the fact on the same day. Hence I do not believe the deposition of these overmen regarding drilling of advance boreholes and absence of unusual seepage of water.

9.7.5 Shri Fouzdar Singh (MW-1) was the sole overman in the third shift of November 12, 1989. When the fatal accident occurred and had three far-flung district under his charge. As such, he did not get an opportunity to inspect the 40 dip face before the fatal accident occurred.

9.7.6 Shri Ram Sankar Sarkar (MW-12) and Shri Dodan Pandey (MW-13) were the Sirdars of 42 crosscut district on the second and third shift of November 12, 1989. I also do not believe their deposition that there were advance borcholes at 40 dip face, and that the seepage of water from the face was not unusual.

9.7.7 Shri Chandradhari Barai (MW-14) was the Shot firer of 40 dip face. On the third shift of November 12, 1989 I also do not believe his deposition that he had checked the advance and frank boreholes at 40 dip face before firing the shots on the fateful day of November 13, 1989.

9.7.8 The primary responsibility of safety in mines is that of the management. The subordinate officials in the mine are required to carry out their orders. I have already held that the fact that advance borehole were not drilled and there was unusual seepage of water at 40 dip face was known to the Agent-cum-Manager (MW-17) and other senior officials. If the Agent-cum-Manager and the senior officials would have been alert and alive to their responsibilities for safety in the mine, they could have ensured the drilling of advance borchoes and also taken due note of unusual seepage of water. The fact that they allowed things to drift gave the wrong signal to the subordinate officials as Overmen, Sirdars and Shotfirers. Therefore inspite of their lapses, I do not hold S/Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW-10), C. D. Singh (MW-11), Shibdas Chatterjee (MW-9), Ram Sankar Sarkar (MW-12), Dodan Pandey (MW-13) and Chandradhari Barai (MW-14) responsible for the fatal accident.

9.7.9 An analysis of causes of the majority of the accidents and disasters due to inundation would indicate that though the higher officials in a mine are primarily responsible, awareness of safety parameters is required of ordinary workers and their immediate supervisors as Shotfirers, Sirdars and Overmen. Usually an accident due to inundation is preceded by some unusual signs any symptoms as heavy seepage of water etc. It is important that the first level supervisors and workers in an underground coal mine are able to identify such symptoms and bring them to the notice of the higher management. It is essential that such type of training should be given to the supervisor and the workers and an awareness of safety should be installed into them.

9.7.10 The institution of workmen's inspectors and safety committee have been given statutory backing with the hope that the involvement of these instituions in workers safey would go a long way in bringing down the incidence of accidents and disasters. In this case, both the Workmen's Inspector and the Safety Committee believed the hopes cast in them. The Workmen's Inspector did not question the reasons of restarting 40 dip in an unapproved area. He also did not ensure drilling of advance boreholes at 40 dip face. On the contrary, he deposed incorrectly before me regarding absence of unusual seepage of water and drilling of advance boreholes at 40 dip face on November 12, 1989.

9.7.11 The fact that the overlying Nega seam was waterlogged was known to almost all the supervisory staff and many workers. Yet the aspect of danger of inundation did not figure in the discussions of the Safety Committee which met almost once in a month.

9.7.12 It is accepted that safety of the mine is the responsibility of the management. But it may be appreciated that it cannot be achieved without the active cooperation of workers and the representatives of trade unions. In this case it appears that unusual seepage of water at the faces as well as the non-provision of the advance boreholes was brought to the notice of the local trade union leaders by some workers. Unfortunately no positive action was taken even by them on such information.

CHAPTER—X

10.1 SUMMARY OF FINDINGS

10.2 RECOMMENDATIONS

10.3 RECOVERY OF EXPENSES

10.4 ACKNOWLEDGEMENTS

10.1.1 The fatal accident in the Narainkuri seam of the Mahabir Mine on November 13, 1989 occurred due to inrush of water from the overlying old abandoned and waterlogged Nega seam workings through shaft No. 34. The abandoned and waterlogged shaft No. 34 which had extended upto the Narainkuri seam got connected with the advancing 40 dip gallery off 28 level, causing the accident with loss of six precious lives.

10.1.2 The accident occurred because of the failure to provide sufficient number of central and bank boreholes in 40 dip gallery advaning towards the waterlogged shaft No. 34. Had such cover of advance boreholes been provided the officials of the mine would have been forewarned of the danger of the waterlogged shaft ahead and the fatal accident averted. Such advance boreholes are mandatory under Regulation 127 of CMR 1957. The working permission of the DGMS also clearly stipulated that those advance boreholes were to be provided. Further, the 40 dip gallery off 28 level was advanced in an unauthorised area about 100 m. away from development projections approved for working by the DGMS The fatal accident occurred within only days of commencement of workings in 40 dip gallery off 28 level where mining operation had been stopped in January, 1988 due to unusual seepage of water. I am of the opinion that the fatal accident was due to culpable negligence on the part of Sarbasree Md. Kalim, Agent-cum-Manager, and P. L. Banerjee, Safety Officer and K. Dutta, Assistant Manager of the Mahabir mine. These three officials contravened the provisions of Regulation 127 of the CMR 1957, as well as the conditions laid down in the working permission of the D.G.M.S.

10.2.1 This fatal accident like most other disaster due to inundation in underground coal mines of our country took place essentially because of human failure in complying with the relevant provisions of Coal Mines Regulations. Whereas compliance of the relevant Coal Mines Regulations is the answer to prevent such fatal accident and disasters, what is disturbing is their recurrene from time to time. In my view, there is an urgent need to make the workers and the first-line supervisory official like Short-firers. Sirdars and Overman aware of the statutory provisions in this regard vis-a-vis their duties, as well as to train them suitably to be forewarned regarding danger signals regarding inundation so that timely corrective measures could be taken. Here I see a great scope

for strengthening the institutions of Workman's Inspector and Safety Committee which can go a long way in arousing safety consciousness.

10.2.2 Since waterlogged workings will continue to be a source of potential hazard in coal mining in the foreseeable future, the search for methods for more accurate detection of these hazards should be unremitting. The reliance on human judgement to assess potential hazards of inundation has its pitfalls as a number of accidents and disasters in coal mines has amply demonstrated. The coal industry in India must therefore adopt more refined state-of-the are techniques to detect and delineate the waterlogged workings so that human lapses do not cause accidents and disasters due to inundation. In summary, therefore, I recommend:

(i) development of awareness among workers and the first-line supervisors of the need for identifying hazards through intensified programmes of education and training;

(ii) activizing the institutions of Safety committee and Workmen's Inspector so that they become relevant to the safety needs of underground coal mining;

(iii) inculcation in the minds of workers and officials in underground coal mines the need for compliance with the provisions of the safety laws and regulations;

(iv) provision of infrastructure for drilling advance boreholes to detect the presence of waterlogged workings;

(v) development through R&D efforts new techniques for detection and delineation of accumulated waterbodies underground, and

(vi) provision of large diameter boring facilities at a centralized location to access entombed miners in the event of an emergency.

10.3 The last part of the report deals with the recovery of expenses of the Court. Rule 22 of the Mines Rules, 1955, framed under Section 63 of the Mines Act, 1952 stipulates that if the Court of Inquiry finds that the accident is due to carelessness or negligenle on the part of the management, the Court may direct the recovery of its expenses from the Owner, Agent or Manager. The report discloses that the accident had taken place due to the negligence of the Agent-cum-Manager and other officials in not complying with Regulation 127 of the Coal Mines Regulations, 1957. But as the Court of Inquiry has the discretion in the matter of ordering recovery of expenses and as the expenses of the Court have been kept to the minimum and the defaulting officials belong to a Public Sector of the Central Government, I order that there would be no recovery of cost of this Court of Inquiry from any party or fficial.

10.4 Before concluding the Report, I must record my gratitude for the help by the Assessors Shri B. N. Tewary and Prof. A. K. Ghose. They were present in almost all the sittings of the Court. In spite of their numerous engagements, they also spared their valuable time for discussion and assessment of the evidence and arguments before the Court. I am also grateful to the management of the Eastern Coalfields Ltd., their advocate Shri B. Joshi and the representatives of the Employees' Union, who were parties to the proceedings. I would have liked to mention their names in this part of the Report but consideration of space has prevented me from doing so. However, a list of names of representatives of the Employees' Union, who examined and cross-examined the witnesses before this Court, is at Annexure XIV. I also take this opportunity to thank Shri S. C. Chatterjee, Regional Director of the Central Mine Planning & Design Institute, Asansol; and his Officers, who provided the infrastructural support for this Court to function at Asansol.

(P. C. HOTA)
MAHABIR COURT OF INQUIRY

SHRAM SHAKTI BHAWAN
RAFI MARG
NEW DELHI-1100001

(B. N. TEWARY)
ASSESSOR

(PROF. A. K. GHOSE)
ASSESSOR

ANNEXURE—I

List of persons who lost their lives in the fatal accident on November 13, 1989 at Mahabir Mine

Sl. No.	Name	Designation	Age
1	2	3	4
1.	Sitaram Dusad	Timber Mazdoor	52
2.	Panna Lal Tiwari	Timber Mazdoor	54
3.	Anandi Turi	Loader	45
4.	Bishu Hazam	Explosive Carrier	51
5.	Agnu Nunia	Line Mazdoor	54
6.	Jhari Bishra	Loader	54

ANNEXURE—II

NOTIFICATION REGARDING APPOINTMENT OF THE COURT OF INQUIRY

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1990

S. O. 327(E).—Whereas an accident occurred in the Mahabir Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited in District Burdwan of West Bengal State, on the 13th November, 1989 causing loss of lives ;

And whereas the Central Government is of oppinion that formal inquiry into the causes of and the circumstances attending the accident ought to be held ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri K. C. Sharma, retired Additional Secretary, Ministry of Labour to hold such inquiry and also appoints the following persons as assessors in holding the inquiry, namely :—

(1) Shri B. N. Tewary,
General Secretary,
Colliery Mazdoor Sabha (AITUC),
G. T. Road, Asansol,
Distt. Burdwan (West Bengal).

(2) Prof. A. K. Ghosh,
Professor of Mining Engineering,
Indian School of Mines,
Dhanbad—826 004 (Bihar).

[F. No. N-11015/1/90-ISH-II]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

ANNEXURE—III

NOTIFICATION REGARDING APPOINTMENT OF SHRI P. C. HOTA

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 1991

S. O. 3(E).—In partial modificaiion of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 327(E), dated the 16th April, 1990, the Central Government hereby appoints Shri P. C. Hota, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, to hold the inquiry into the causes of and circumstances attending the accident in the Mahabir Colliery, in place of Shri K. C. Sharma, with immediate effect.

[F. No. N-11015/1/90-ISH.-II]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

ANNEXURE—IV

UNDERTAKING OF SHRI P. C. HOTA TO THE HON'BLE CALCUTTA HIGH COURT

Written statement of Shri P. C. Hota, Mahabir Colliery Accident Court of Inquiry, in C. O. No. 7650 (W) of 1990 in Calcutta High Court—Coal Mines Officers Association of India Vs. Mahabir Colliery Accident Court of Inquiry.

That I have been appointed as the Court of Inquiry to inquire into the causes of and circumstances attending the accident which took place in Mahabir Colliery on 13-11-1989, in place of Shri K. C. Sharma, vide Government of India in the Ministry of Labour notification No. N-11015/1/90-ISH-II, dated 3-1-1991 (copy enclosed).

2. I state that I am not bound by the procedure adopted by Shri K. C. Sharma for the conduct of the said inquiry. I further state that I will devise my own procedure for the conduct of the said inquiry in consultation with the parties concerned.

Sd./-

P. C. HOTA,
Mahabir Colliery,
Accident Court of Inquiry.

ANNEXURE—V

NOTICE ISSUED TO THE PARTIES BY THE COURT OF INQUIRY

Dated, the 21st March, 1991.

NOTICE

The undersigned appointed by the Central Government under Section 24 of the Mines Act, 1952, vide Notification No. S. O. 3(E), dated the 3rd January, 1991, to hold the Inquiry into the causes and circumstances attending to the accident in Mahabir Colliery in place of Shri K. C. Sharma, will have a preliminary sitting of the Court on 8-4-1991 at C.M.P.D.I. (Conference Hall) at Asansol from 10 A.M. to devise the procedure of the Court of Inquiry as contemplated under Rule 21 of the Mines Rules, 1955. You are, therefore, requested to attend the Court on the said date at the said time.

2. Further to substantiate the submissions made in the written statements already filed on behalf of your Organisation, you are requested to submit on the said date a complete list of witnesses proposed to be examined by you indicating therein the order in which the witnesses will depose before the Court.

Sd./-

P. C. HOTA,
Mahabir Colliery,
Court of Inquiry

To,

All the Parties.

ANNEXURE—VI

List of Management Witnesses

S. No.	Name	Designation	Witness Number
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Fouzdar Singh	Overman	MW 1
2.	Ram Chander Mahato	Mining Sirdar	MW 2

1	2	3	4
3.	Saligram Singh	Pit Clerk	MW 3
4.	Nur Mahammad	Loader	MW 4
5.	Ganesh Rai	U/G Loader	MW 5
6.	Joydeb Mondal	Mining Sirdar	MW 6
7.	Bhullan Mandal	Shot Firer	MW 7
8.	Ramesh Majhi	Fitter/Boring Machine Operator	MW 8
9.	Shibdas Chatterjee	Overman	MW 9
10.	Mihir Kr. Chatterjee	Overman	MW 10
11.	C.D. Singh	Overman	MW 11
12.	Ram Shankar Sarkar	Mining Sirdar	MW 12
13.	Dodan Pandey	Mining Sirdar	MW 13
14.	Chandradhari Barai	Shot Firer	MW 14
15.	P.L. Thacker	Surveyor	MW 15
16.	P.L. Banerjee	Safety Officer	MW 16
17.	Md. Kalim	Manager/Agent	MW 17
18.	K.K. Das	Agent	MW 18
19.	K. Dutta	Assistant Manager	MW 19

ANNEXURE—VII

List of Employees' Unions witnesses

S. No.	Name	Designation	Witness Number
1	2	3	4
S/Shri			
1.	Kuldip Das	Driller	UW 1
2.	Munshi Turi	UG Loader	UW 2
3.	Chedi Harijan		UW 3
4.	Ram Chandra Mahato	Loader	UW 4
5.	Bhangi Rajbhar	Dresser/Driller	UW 5
6.	Ram Sudhar Choubey	Overman	UW 6

ANNEXURE—VIII

List of Court Witness

S. No.	Name	Designation	Witness Number
1.	Shri Sanat Kr. Sengupta	Assistant Manager	CW 1

ANNEXURE—IX

List of Management Exhibits (Exh. M)

S. No.	Exhibit No.	Details of the Exhibits
1	2	3 4
1	M/1	Hand Plan of Shri Swapan Ghatak (42-L-Section) (C.5 of 'seized documents)
2.	M/2(A)	The Bengal Coal Co. Ltd. Plan of Raneelganj Colliery, Raniganj Seam traced from AMP No. 1121 (Tracing No. 1746 on 25-7-25).
3.	M/2(B)	The Bengal Coal Co. Ltd. Plan of Raneeganj Colliery, Raniganj Seam traced from AMP No. 1121 (Tracing No. 1746 on 25.7.25) from No. 1 of AMP No. 1121 (two pages)
4.	M/3	Photostat copy of letter No. ECL/MB(P)/4009 dt. 16-17/12/83 from the Agent, Mahabir colliery to DGMS
5.	M/4	Plan No. ECL/MB/MU/20 dt. 16-12-1983 Development Permission Plan
6.	M/5	Photostat Copy of letter No. S.3/173/(BD)(MB) II-B/84/1061 dt. 12-3-1984
7.	M/6	Photostat copy of letter No. ECL/MBI DEV: 88/198 dt. 19-1-88 from Agen t Mahabir Colliery to DGMS.
8.	M/7	ECL Plan No. ECL/MB/62 dt. 16-1-88 of Mahabir Colliery (R) showing changed projection of proposed development working in N/K seam below waterlogger working of Nega seam under CMR 105, 126 & 127.
9.	M/8	Photostat copy of letter No. S.3/22-03-062/II-A/88 dt. 22-3-88 from DGMS to Agent Mahabir Colliery
10.	M/9	ECL's Part Plan showing Projections of Plan No. ECL/MB/62/62 dt. 16-1-88 superimposed on Projections of Plan No. ECL/MB/20 dt. 16-12-83.
11.	M/10	Photostat copy of letter No. S.3/173 (BD) (MB)/II-B/83/4472 dt. 2-8-83 from DGMS
12.	M/11	Working Plan of Narainkuri Seam in tracing cloth bearing No. 13 dt. 14-5-75 upto 21-4-88 (C.4 of 'seized documents') tracing only.
13.	M/12	Plan of Accident site from ECL Narainkuri seam of Mahabir Colliery as surveyed after the accident.
14.	M12(A)	Plan showing position of shifting of large piece of stone from position A to position B shown there in

ANNEXURE—X

List of Employees' Unions Exhibits (Exh. W)

S.No.	Details of Exhibit	No. of Exhibit
1	2	3
1.	Hand Plan of Shri Swapan Ghatak (42-L Section) (C.5 of "seized papers")	W/1
2.	ECL letter No. GM/KMT/17/540/88 dt. 25-7-1988 (B.1 of seized documents).	W/2
3.	ECL letter No. ECL/MB(R)/98/Safety/297 dt. 22-2-89 B.2 of seized documents)	W/3
4.	ECL letter No. ECL/MB (R)/88/Safety/318 dt. 28/30/30-1-88 (B.7 of seized documents)	W/4
5.	Pages No. 1 to 3 of Instruction Book of K.K. Das, Ex. Agent (from 1-11-88 to 10-13-88) A.6 of seized papers	W/5

1	2	3
6.	ECL letter No. ECL/Safety/RNU/1683 dt. 14-1-88 (B.8 of seized documents)	W/6
7.	Plate No. 4 attached to ECL's main Memoranda to Court of Inquiry	W/7
8.	List of Registers, records, letters & plans seized by DGMS u/s 7(2) of Mines Act	W/8
9.	Letter No. M 11.154(B)87/40140 F. dt. 30-11-1961	W/9
10.	Water Danger Plan of N.K. seam (C.1 of 'seized documents)	W/10

ANNEXURE-XI

A BRIEF DESCRIPTION OF THE MAHABIR MINE

Mahabir mine is situated in the south eastern part of the Raniganj Coalfield in the district of Burdwan, West Bengal. Geographically, the mine is located approximately between latitude 23 degree 36' to 23 degree 38' north and longitude 87 degree 05' to 87 degree 07' east. The total surface area of the mine is about 612 hectares.

The office of the mine is located about 2 km north west of Raniganj railway station of the Eastern Railway and about 2 km south of the Grand Trunk road. A metalled road, branching out from the feeder road connected the G. T. road to the Raniganj railway station, leads to office of the mine.

Mahabir mine is owned by M/s ECL which was formed as a public sector undertaking in 1975 about two years after the non-coking coal mines of the country were nationalised. On nationalisation, three privately owned small adjoining working mines and a closed mine were amalgamated to form the Mahabir mine. Three working mines were Mahabir, Kajora selected and Searsole mines. The closed mine was the Raniganj mine belonging to the erstwhile M/s Bengal Coal Company.

The important surface features over the property of the Mahabir mine are old Egara and new Egara villages and a part of the Raniganj township. The main Eastern Railway line from Howrah to Delhi runs from north west to south east and divides the property of the Mahabir mine into almost two equal halves. Mahabir mine and its surrounding area was the first recorded centre of coal mining in our country.

ANNEXURE-XII

TEXT OF REGULATION 127 OF THE CMR, 1957

127. Danger from underground inundation :—(1) Proper provision shall be made in every mine to prevent irruption of water or other liquid matter from the workings of the same mine or of an adjoining mine.

(2) Where work is being done in—

(i) any seam or section below another seam or section; or

(ii) any place in seam or section, which is at a lower level than any other place in a lower seam or section; or

(iii) any place in seam approaching a fault passing through an upper seam of section, which contains or many contain an accumulation of water or other liquid matter.

adequate precautions shall be taken against an irruption of water or other liquid matter into the workings.

(3) No working which has approached within a distance of 60 metres of any such disused or abandoned working (not being workings which have been examined and found to be free from accumulation of water, or other liquid matters), whether in the same mine or in an adjoining mine, shall be extended further except with the prior permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein:

Explanation :—For the purpose of this sub-regulation, the distance between the said workings shall mean the shortest distance between the workings of the same seam or between any two seams or section, as the case may be, measured in any direction whether horizontal, vertical or inclined.

2 (X X X X)

Sub-regulations (4), (5) & (6) of the said regulations may be substituted as follows :—

"3(4)(a) Every application for permission to aexend any working referred to in sub-regulation (3) shall be accompanied by two copies of the plan and section showing :—

(i) The outlines of all such disused or abondoned workings in relation to the working approaching them and also the depth of such dismsed or abandoned workings from the surface.

(ii) The outlines, the layout and the method of the proposed working for which permission is sought.

(iii) the faults, dykes and other geological disturbances in relation to working specified in clause (i) or (ii) of the sub-regulation, and

(iv) Any other information that is available with the management and any other particulars or information that may be required by the Chief Inspector.

(b) When permission is granted to extend any working referred to in sub-regulation (5), it shall be extended strictly in accordance with the plan and the method approved under, and the conditions specified, in such permission and there shall be no variation therefrom unless such variation is again approved by the Chief Inspector.

(5) Whenever seepage of water, which is not normal to the seam is noticed at any place in any working, or if there be any such suspicion or doubt, such working shall immediately by stopped and the Chief Inspector and the Regional Inspector shall forthwith be informed of such seepage. Such working shall not be extended further except with the prior permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein.

(6)(a) The height of any working referred to in such regulation (3) or sub-regulation (5) shall not exceed 2.4 metres and there shall be maintained at least one bore hole near the centre of the working face, and sufficient flank bore holes on each side, where necessary, bore holes above and below the workings at intervals of nor more than five metres. All such bore holes shall be maintained and shall be constantly maintained at sufficient distance in advance of the working and such distance shall in no case be less than three metres. These precautions shall be carried out under the direct supervision of an official having Manager's or Overman's Certificate specially authorised for the purpose.

(b) A record showing the exact height and width of such working, the number of bore holes driven, the length of each bore hole, the places at which and the direction in which each bore hole was driven, shall be maintained by the official referred to in clause (a) in a bound paged book kept for the purpose and the entries made therein shall be signed

and dated by such competent person and shall be countersigned by the Manager every day. Also plan and section of such working showing the above particulars shall be prepared and maintained and they shall be brought up-to-date at least once in every fifteen days.

(7) Unless specific relaxation is granted by the Chief Inspector in writing under sub-regulation (8), all the provisions of sub-regulation (6) shall be strictly complied with while extending any working referred to in sub-regulation (3) or sub-regulation (5) whether or not the permission granted to extend such workings requires compliance with all or any of the provisions of sub-regulation (6).

(8) If the Chief Insector is satisfied that the conditions in any mine or part thereof are such as to render compliance with all or any of the provisioes specified in sub-regulation (6), unnecessary or impracticable, he may be, by an order in writing and subject to such conditions as may be specified therein relax, vary or dispense with all or any of the conditions and requirements contained in sub-regulation (6), and, if he is of the opinion that the conditions at any mine or part thereof are such as to require additional precautions to be taken, he may by an order in writing require that such additional precautions besides those specified in sub-regulation (5) shall be taken)".

Photographs of the site of accident ANNEXURE-XIII

Photographic record of the Right rib side of 40 rip gallery as viewed from the gallery entrance towards the site of the accidental connection.

Photograph (a) : Approximately 20 ft. from the site of connection

Photograph (b) : Next 20 ft.

Photographs of the site of accident

Photograph (C) : Next 20 ft.

Photograph (d) : End of Gallery

Photographs of the site of accident

Photograph (e) : End of the Gallery

ANNEXURE-XIV

List of the Organisation and Representatives who Cross Examined the Witnesses

S.No.	Name	Organisation Represented
1	2	3
1.	Sh. A. Maiti, Secretary	CMS (AITUC)
	Sh. Sunil Sen, Organising Secy.	CMS (AITUC)
2.	Sh. G.P. Gowswami, Secretary	CMSI (CITU)
3.	Sh. V.N. Sharma	Coll. Maz. Un (INTUC)
	Sh. L.N. Bhattacharya Secy. (Safety)	INMWFI (INTUC)
	Sh. S.S. Chowdhury, Secy.	CMU (INTUC)
4.	Sh. Saktipada Chatterjee , Jt. Secy.	CMC (HMS)
	Sh. Jayanta Poddar, Genl. Secy.	CMC (HMS)
5.	Sh. H.S. Mukharjee, Vice-President	KMC
	Sh. Rakesh Kumar, Chief Org. Secy.	KMC
	Sh. Keshwa Singh, Asstt. Genl. Secy.	KMC
6.	Sh. D.M. Dass, Genl. Secy.	INMEWA
7.	Sh. K. Prasad , Genl. Secy.	AIMS
8.	Sh. J.K. Banerjee, Genl. Secy.	INMOSSA
9.	Sh. B. Joshi, Advocate	ECL
10.	Sh. D.D. Mukherjee	CMBA
	Sh. J Banerjee, Vice-President	CMBA
11.	Sh. A.K. Mazumdar	IMMA

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1992

का. आ. 70 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु मैगनेसाईट ,लिमिटेड, सेलम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-12-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल--29012/14/92--आई आर (मिस.)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th December, 1992

S.O. 70.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Tamil Nadu Magistrate Limited(Salem and their workmen, which was recieved y by the Central Government on 9-12-92.

[No. L-29012/14/92-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated, this 30th day of November, 1992

Present :

Shri M. B. Vishwanath, B.Sc.,B.L., Presiding Officer.

CENTRAL REF. NO. 42/92

I party

The General Secy., Salem Dist. Magnesite Labour Union, No. 237, Tharamangalam Road, Old Suramangalam Road, Salem-636 005.

Vs

II party

The Chairman-cum-M.D., Tamilnadu Magnesite Ltd., 5/53, Omalur Main Road, Jagir Ammapallayam Salem-636 302.

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by its order No. L-29012/14/92-IR (Misc.) Dt. 16-4-92 under Sec. 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 the point for adjudications per schedule to the reference is :

"Whether the dependents of S/Shri Anamalai/Palani Token No. 1188 and Kaveri/Raman, Token No. 830/12 who were discharged from service on medical grounds by the management of Tamailnadu Magnesite Limited, Salem are entitled for employment with the company as per the provisions of the Settlement dated 17-8-87 arrived at between the management and the union ?"

2. In the claim statement it is contended that the dependant of workman Shri Anamalai Token No. 1188 and the dependant of workman Kaveri Token No. 830/12 who were discharged from service on medical grounds by the Management of Tamilnadu Magnesite Ltd., Salem are entitled for employment in the company as per provisions of the settlement dt. 17-8-87 arrived between the management and the Union.

3. In the counter statement the fact that Anamalai and Kaveri were workmen who were discharged from service on medical grounds is admitted. In the counter statement it is contended that the dependents are not entitled to employment. It is further contended that the wife of the workman Kaveri has been working for a long time as an employee in the II party and so the debendant of the workman Kaveri is not entitled to employment.

4. Since it was felt that the evidence was not necessary, the case was posted for arguments on merits. At the time of the arguments today the General Secretary representing the I party has filed a memo that the dependent of the workman Anamalai s/o Palani, one of the workman in the schedule to the reference, has been provided with a job by the II party and therefore he does not press the reference against Sh. Anamalai, Token No. 1188.

5. Now the point for consideration is whether the dependant of the workman Kaveri is entitled to employment in the II party company.

6. The I party has produced the zerox copy of the settlement relied on by both parties. This settlement, it is clear remained in force from 1-12-86 to 30-11-89. The workman Kaveri was discharged from service on 14-11-89, after he had put in more than 25 years of service. It is admitted that he was discharged on medical grounds viz, multi volvular heart disease. It is obvious that because of the said serious heart trouble the workman Kaveri was permanently disabled and so he was discharged.

7. The provision 5.4 of the memorandum of settlement entered into between the workmen representatives and the management representatives which included the present II party says :

It is agreed that the companies will provide suitable employment to one direct dependant of the employee only who dies in service or becomes permanently disabled and out of job subject to the fulfilment of the following conditions :—

(i) Medical fitness.

(ii) The incumbent must have the qualifications to fulfil the job requirement.

8. The main provision 5.4, as I understand means that the company should provide suitable employment to one direct dependant of the employee when he dies while in service OR when the employee becomes permanent disabled.

9. It is argued by the officer Srinivasan on behalf of the II party that the phrase "Permanent disabled" relates only to employment injury. It is argued that since the workman did not suffer any injury in the course of his employment, his dependant is not entitled to employment. If we accept the argument advanced on behalf of the II party, it would mean reading into the provision 5.4 something which is not there. The requirement of the provision 5.4 is that the employee should have become permanently disabled, whatever may be the reason of permanent disablement. It is admitted that the workman Kaveri was discharged because of the serious heart disease. This means he became permanently disabled and therefore was discharged from service. I reject the argument that "permanently disabled" relates to employment injury.

10. It is argued that the wife of the workman Kaveri has been working in the II party for the last so many years, even before the workman Kaveri was discharged. His wife was recruited along before Kaveri was discharged. It is argued by the Learned officer for the II party that since the wife has been employed and has been working and she is the only dependent, the other dependant of workman Kaveri is not entitled for employment. Because the wife of Kaveri has been working, long before Kaveri was discharged on medical grounds, it is difficult to accept the argument that the other direct dependant of Kaveri is not entitled to employment. The Learned Officer who argued for the II party did not bring to my notice any provision in the settlement Dt. 17-8-87 that only the wife is the direct dependant of a man-employee. Surely, the sons or daughters who are maintained by the man-employee are dependants of that employee. The provision 5.4 does not say that if the wife of the workman is also employed, the other direct dependant is not entitled to employment. The Tribunal should not incorporate into the provision 5.4 a condition which is not there. Surely the workman Kaveri must be having sons or daughters who are direct dependants. One of them is certainly entitled for employment, if the conditions medical fitness and the qualification required for the job are fulfiled.

ORDER

The reference with regard to workman Sh. Anamalai, Palani, Token No. 1188 is rejected.

It is hereby declared that one direct dependant of Sh. Kaveri/Raman Token No. 830/12, who was discharged from service on medical grounds, is entitled for employment with the II party company as per the provisions of settlement Dt. 17-8-87 arrived at between the Management and the Union.

Reference accepted in part as stated herein.
Submit to Government.

(Dictated to Stenographer, typed by him, corrected, signed by me on this 30th day of November, 1992).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1992

का. आ. 71.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, तमिलनाडु (मद्रास) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-33012/5/88-डी III (बी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th December, 1992

S.O. 71.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Tamil Nadu (Madras) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Madras Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 9-12-92.

[No. L-33012/5/88-D III(B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU
MADRAS

Friday, the 23rd Day of October, 1992

PRESENT:

Thiru M. Gopalaswamy, B.Sc., B.L.,

INDUSTRIAL TRIBUNAL

Industrial Dispute No. 30 of 1989

(In the matter of the dispute for adjudication u/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the Management of Madras Port Trust, Madras-1)

Between

Thiru L. Abdul Babu,
No. 61, Noruppu Medu,
Alandur Salai, Saidapet,
Madras-600 015.

AND

The Chairman,
Madras Port Trust, Rajaji Road,
Madras-600 001.

REFERENCE:

Order No. L.33012/5/88-D. III(B). dt. 13-3-89 of the Minister of Labour Govt. of India

This dispute coming on for final hearing on Monday the 6th day of July, 1992 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Tvl. R. Ganeson, S. Shathiamurthi and R. Gowthaman, advocates appearing for workman and of Tvl. A. L. Somayaji R. Arumugham, advocates appearing for the management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following award.

AWARD

This dispute between the workman and the management of Madras Port Trust, Madras-1 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its order No. L.33012/5/88-D.III (B). dated 13-3-1989 of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue:

"Whether the management of Madras Port Trust is justified in dismissing Shri L. Abdul Babu, D. V. Driver from service with effect from 11-6-1987. If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

(2) The petitioner workman alleges as follows :

He was working as a Driver under the Respondent. He received a chargememo allewing that he committed the misconduct of absenting himself from duty without leave from 23-9-86 to 9-10-86. Such unauthorised absence does not attract the charge framed under the standing order 42-D(ii) but it can be a charge only under Standing Order 42-A. The Petitioner has submitted his explanation to charge memo on 23-12-1986. At the domestic enquiry officer himself examined the Petitioner delinquent. He has produced a certificate of posting under which he sent a post card on 23-9-86 requesting grant of leave on medical grounds. He produced medical certificate on 10-2-87 before the enquiry officer relatings the treatment received by him during the period. The enquiry officer's finding that the charges proved is perverse in the absence of evidence. The enquiry officer failed to consider the medical certificate produced by the petitioner and certificate of posting relating to be leave letter. The order of the disciplinary authority in which he approved the findings and imposed the penalty of dismissing from servce is unjust. The appellate authority disposing of appeal passed merely a onspeaking order. Hence it is not valid. The petitioner was not served with any notice of previous punishment which he has suffered. Hence the respondent's act of weighing the past records in inflicting the punishment is bad and illegal. In any event, the order of dismissal from service with effect from 11-6-87 is shockingly disproportionate and liable to be set aside.

(4) The Management States in its counter as follows :

The charge framed against the petitioner for the misconduct of *Unauthorised absence is sustainable in terms of* Clause 43(B)(ii) of the Standing Orders. The Petitioner did not give his explanation to the charge memo as early as on 23-12-86, but he gave it only on 5-1-87 just after the notice regarding the commencement of domestic enquiry was issued. Junior Assistant Dural Singh was examined as Management witness at the domestic enquiry to prove the charge. The Petitioner-workman has been punshed on 15 earlier occassions. The domestic enquiry officer's findings are sound and sustainable. The punishment of dismissal is fair and adequate. Respondent may be given opportunity to 1st in evidence if the domestic enquiry is held to be unfair and vitiated. The claim is liable to be dismissed.

(4) The points for determination are as follows :

(1) Whether the findings of the domestic enquiry officer and the approval of the said findings by the disciplinary authority are perverse and not supported by evidence?

(2) Wnether the punishment of dismissal is just and lawful?

(5) This Tribunal held a preliminary enquiry on the issue relating to the fairness of the domestic enquiry, and passed an order by holding that the domestic enquiry have been held fairly. The charge memo issued to the Petitioner-workman Ex. M. 1v dated 23-10-86 states that the Petitioner has been guilty of the misconduct namely absence without prior permission from 23-9-86 to 14-10-86, punishable under Clause 42(B)(ii). Admittedly the Petitioner has not sent his leave application or letter by Registered Post or Telegram but on the other nand he claims that he sent a post card under certificate of posting requesting grant of leave from 23-10-86 to 14-10-86. The enquiry officer in his findings Ex. M. 12 has mentioned that the Petitioner did produce, even if it be after the conclusion of the domestic enquiry, the postal acknowledgement relating to the Certificate of posting and a medical certificate got from a private doctor referring to his illness. The said medical certificate issued by one Dr. Paulsamy is Ex. M. 5. After the expiry of the period of absence ending with 9-10-86, the Petitioner has admittedly resumed duty on 15-10-86. On that date he has presented a leave application in person in respect of the same period for which he earlier sent a post card by certificate of posting. This belated leave application Ex. M. 6 has been received by the respondent office on 15-10-86. He has also sent Ex. M. 9 letter dated 28-12-86 in addition to Ex. M. 10 and Ex. M. 11 letters, both dated 14-1-87, wherein he pleaded that his nervous system has been affected due to electric shock suffered by him 2 years before, that the said disability or disorder has not cured and as a result thereof from September, 1986 he has suffered nervous problems in his right leg, that he was taking treatment for the same from private doctor and that he has already sent in his leave application praying for leave from 23-9-86 onwards.

(6) At the domestic enquiry, the management witness Dmai Singh gave evidence regarding the Petitioner's absence from 23-9-86. This witness vide Ex. M. 20 proceedings has proved a belated telegram dated 30-10-86 and a leave letter received from the Petitioner on 15-10-86 which is Ex. M. 6. The Petitioner was examined in the domestic enquiry by the domestic enquiry officer himself without the assistance of a presenting officer. In the findings Ex. M. 42 the domestic enquiry officer has not at all examined the value of the

certificate of posting or postal acknowledgement and the private medical certificate produced by the petitioner though belatedly. He should have admitted these two documents as evidence and duly assessed their evidentiary value in examining the truth of the facts relating the petitioner having sent any leave application supported by private medical certificate. Neither the domestic enquiry officer nor the disciplinary authority who has passed Ex. M. 13 order has given any thought and much less weight to these material documents produced by the Petitioner as well as his plea that he has been suffering from the after effects of electrical shock received by him 2 years prior to 1986. The Respondent has not denied anywhere the fact that the petitioner has suffered electrical shock affecting the nervous system. On a consideration of the materials on record I hold that the domestic enquiry officer's findings and also the concurrent findings recorded by the disciplinary authority are pervese and not supported by legal evidence.

(7) Even on the question considering the past record of the Petitioner in the context of punishment, the respondent has failed to issue a notice informing the petitioner about his past acts of misconduct for enabling him the explain past misconduct and quantum of punishment. In my view of the matter, the punishment of dismissal is extremely harsh and disproportionate. Hence the findings are held to be perverse, there is no basis for imposing any punishment on the petitioner. Both these points are accordingly answered in favour of the petitioner. Therefore the Petitioner deserves to be reinstated in service. However on the question of backwages I feel that it will be fit and proper to restrict the back wages to 60 per cent by depriving the petitioner of the remaining 40 per cent in the peculiar circumstances of the case. In the result, an award is passed directing the respondent to reinstate the Petitioner in service, pay 60 per cent of back wages only and allow continuity of service besides other benefits. No costs.

Dated, this 23rd day of October, 1992.

M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

WITNESS EXAMINED

For both side : None.

DOCUMENTS MARKED

For Workman

Ex. W. 1 11-6-87—Charge Memo issued to Petitioner-workman (xerox copy).

Ex. W. 2 30-9-88—Conciliation failure report (xerox copy).

For Management :

Ex. M. 1 31-12-86—Order of Chief Mechanical Engineer for apopintment of Enquiry Officer (xerox copy).

Ex. M. 2 15-1-87—Letter from Thiru M. Mathews to the Management (xerox copy).

Ex. M. 3 27-1-87—Reply by the Management to Ex. M. 2 (xerox copy).

Ex. M. 4 29-1-87—Enquiry notice (xerox copy).

Ex. M. 5 14-10-86—Medical certificate issued by Dr. V. Maluswamy to the Petitioner-workman (xerox copy).

Ex. M. 6—Letter from Petitioner-workman to the management (xerox copy).

Ex. M. 7—Telegram from Petitioner-workman (xerox copy).

Ex. M. 8 10-2-86—Letter from Petitioner-workman to the Management (xerox copy)

Ex. M. 9 28-12-86—Letter from Petitioner-workman to the Management (xerox copy).

Ex. M. 10 14-1-87—Letter from Petitioner-workman to the Management (xerox copy).

Ex. M. 11 14-1-87—Letter from Petitioner-workman to the Management (xerox copy).

Ex. M. 12 18-2-87—Findings of the Enquiry Officer (xerox copy).

Ex. M. 13 26-2-87—Second show-cause notice issued to the Petitioner-workman (xerox copy).

Ex. M. 14 13-3-87—Explanation by the Petitioner workman (xerox copy).

Ex. M. 15 2-4-87—Enquiry notice (xerox copy).

Ex. M. 16—Leave particulars of the Petitioner-workman (xerox copy).

Ex. M. 17 17-6-87—Appeal preferred by the Petitioner-workman (xerox copy).

Ex. M. 18 21-7-87—Order of appellate authority (xerox copy).

Ex. M. 19 23-10-86—Charge memo issued to the Petitioner-workman (xerox copy).

Ex. M. 20—Proceedings of the Enquiry Officer (xerox copy).

Ex. M. 21—Previous record of punishment awarded to the Petitioner-workman (xerox copy).

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1992

का. आ. 72.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30012/38/90-आई आर (विविध)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th December, 1992

S.O. 72.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of India oil Corporation Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 9-12-92

[No. L-30012/38/90-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD.

In the matter of a reference under section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 41 of 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Indian Oil Corporation Ltd., B. K. Pipe Lines, Barauni.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri N. K. Gupta, Advocate.

For the Workmen.—Shri J. D. Lall, Advocate.

STATE.—Bihar. INDUSTRY.—Oil.

Dated, the 26th November, 1992.

AWARD

By Order No. L-30012/38/90-I. R. (Misc.), dated, the 18th/ 19th April, 1991, the Central Government in the Ministry of Labour, has in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Indian Oil Corporation Ltd., B. K. Pipe Lines, Barauni in deducting the fitment benefits granted to Shri S. S. Prasad, Operator 'A' is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present industrial dispute between the management of Indian Oil Corporation Ltd., B. K. Pipelines Barauni and their workmen represented by Indian Oil Corporation Ltd. Pipelines Workers' Union, Barauni, over alleged wrongful deduction of wages of the concerned workman was raised by the President, Indian Oil Corporation Ltd., Pipelines Workers' Union, Barauni, by letter dated 15-5-90. Upon failure of conciliation proceeding, the present industrial dispute was referred to this Tribunal for adjudication by the appropriate Government.

3. The order of reference was received in the office of the Tribunal on 8-5-91. The President of the sponsoring union, Sri C. M. Singh, filed statement of claim dt. 3-7-91 in this case and on that date he gave letter of authority to Shri J. D. Lall, Advocate and S. S. Prasad, the concerned workman, to represent workman in the present proceeding. The employers submitted their written statement in denial of the claim of the sponsoring union on 10-1-92. The President of the union submitted a petition on 10-1-92 and stated that in view of long term settlement out of which the industrial dispute has arisen, the union, in order to maintain industrial peace and good relation with the management, do not press the dispute and prayed for disposal of the dispute as not pressed. Simultaneously on the even date the President of the union withdraw the authority for representation of the case in favour of Shri J. D. Lall, Advocate. But S. S. Prasad, the concerned workman, who was earlier authorised by the President of the union to represent his case before the Tribunal, gave a letter of authority in favour of Shri J. D. Lall on 4-3-92 and submitted a petition on 3-3-92 expressing his desire to continue the industrial dispute.

3. The case of the sponsoring union is that the concerned workman, S. S. Prasad has been working as Operator Grade 'A' in the Indian Oil Corporation Ltd., B. K. Pipelines, Barauni. The management of Indian Oil Corporation Ltd. (Refineries & Pipelines Division) entered into a settlement dated 22-2-89 with the workers' Union whereby pay scales and other benefits were revised upwards with effect from 1-5-86. In terms of the aforesaid setilement, the pay scale of the concerned workman was revised and refixed in terms of Clause 3.1.3, by Office Order dated 20-3-69/18-7-69 the management, however without any notice or show-cause issued another order dated 15-11-89 superseding the earlier Office Order and refixed the pay scale of the concerned workman in the revised pay scale and as a result the basic pay of the concerned workman was reduced resulting in a great financial loss to him. The management stated deducting Rs. 600/- per month from the salary of the concerned workman from February, 1991. The concerned workman is entitled to get his salary as fixed by the earlier order. Refixation of his salary by the management by subsequent order is illegal, arbitrary and in violation of Clause 3.1.3. The management had earlier fixed his salary in terms of clause 3.1.3 of the settlement dated 22-2-89 because one D. N. Tiwary, Operator 'A' who is junior to him, was drawing higher basic salary in the revised pay scale than him and hence the clause 3.1.3 of the settlement dated 22-2-89 was applicable to him in the matter of fixation of his basic pay which was done by order dated 18-7-89. The concerned workman made several representation to the management against refixation of his basic salary, but no action has been taken thereon. In the circumstances, the union has prayed that the management is not justified in deducting fitment benefit granted to the concerned workman by order dated 18-7-89 in terms of settlement dated 22-2-89.

4. In denial of the claim of the sponsoring union, the management has stated in its written statement that the memorandum of long term settlement was arrived at on 22/25-2-89 with all the unions of all units in R&P Division, of Indian Oil Corporation and the settlement came into effect on 1-5-86. The settlement is still binding and subsisting between the parties. Clause 3 of the aforesaid settlement provides revised scale of pay. Immediately before 1-5-86 the concerned workman was Operator 'A' in the scale of pay of Rs. 642-1425 and he was getting basic salary of Rs. 1030/- per month. As per the settlement his basic pay was fixed at Rs. Rs. 1900/- w.e.f. 1-5-86 in the revised pay scale. By Office Order dated 18-7-89 the concerned workman was informed about his fitment in the new scale. His pay was fixed at Rs. 1900/- in the revised scale of pay as against his pre-revised pay of Rs. 1030/- with effect from 1-5-86 as per terms of

settlement. His date of annual increment was however preponed from April, 1986 to July, 1986 by mistake. However on review it was noticed that the settlement signed with the unions did not provide any such preponment. After noticing the mistake, the fitment of the concerned workman was again calculated and fitted and a revised office order dated 15-11-89 was issued. As per revised order his date of increment was correctly taken as 1-4-89 and accordingly on 1-4-89 his basic pay was fixed at Rs.2095|- His immediate junior D. N. Tewari was Operator-B on 1-5-1986. His pay was also fixed in the corresponding revised scale with effect from 1-5-86 as per the conciliation settlement. Since the date of promotion of Tewari as Operator-A was 12-6-86, his pay was fixed in higher grade in the revised scale of pay with effect from 12-6-86. His date of annual increment was 1-7-86. By virtue of Tewari's increment due before date of increment of the concerned workman, the pay of Sri Tewari became higher than that of concerned workman. The fitment of the concerned workman and also of Sri Tewari was done in accordance with Clause 3.1.2 of the long term Conciliation Settlement. As provided under Clause 3.1.8 of the Long Term Settlement anomalies arising out of pay structure were discussed with the unions at All India Level Meeting on 11-2-91 at Bombay. The meeting among others was also attended by the President of the sponsoring union and such anomalies were mutually discussed. In the meeting it was decided that an option should be given to the senior employees postponing the date of their pay fixation on promotion (from the preesnt date) to the date of pay fixation on promotion to the comparable junior employees. It was also clarified that for the purpose of seniority, original date of promotion of the employee would be reckoned with. But for the purpose of pay and consequential benefits, date of revised pay fixed would be taken into consideration. In view of the above decision taken after discussion with the union, administrative instructions by circular dated 28-6-89 was issued wherein the workmen were asked to give their option in this regard before 31-7-91. But the concerned workman did not exercise his option. In the context of facts, the concerned workman should not have made any grievance, more so when the union was a party to the decision communicated by the circular as aforesaid. It is not a case of deduction from fitment benefits granted to the concerned workman, but it is a case of the correct fitment given to the concerned workman to which he is entitled in law.

5. The union filed its statement of claim on 22-7-91 and the management submitted its written statement on 10-1-92. On the same date the President of the Union submitted a petition stating that the industrial dispute be disposed of as no pressed. The petition discloses that in view of long term settlement out of which the aforesaid dispute arose, the union, in order to maintain industrial peace and good relationship with the management, do not press the dispute and that neither the union nor the concerned workman has any grievance against the fitment as per the settlement as finally communicated to him. Earlier the President of the union gave authority to Shri J. D. Lall and the concerned workman to represent the case before this Tribunal by letter of authority dated 3-7-91. The President of the union by letter dated 10-1-92 withdrew the authority for representation given in favour of Shri J. D. Lall, Advocate. But the authority given in favour of the concerned workman was not withdrawn. The concerned workman gave another authority in favour of Shri J. D. Lall Advocate, by petition dated 4-3-92 and submitted a petition on 3-3-92 stating that the compromise petition was not fair and bonafide and that his interest had been sacrificed by the union for own interest. The union had raised the industrial dispute challenging the management. The union also filed written statement assailing the action of the management and supporting his claim. Hence, he prayed that the compromise petition be rejected.

In rejoinder, the management has reiterated the fascicle of facts as appearing in its written statement and contended that when a dispute concerning individual workman is taken up by the union of which he is a member it becomes a matter affecting the workman in general and on that basis a reference is made under Industrial Disputes Act, the individual workman cannot claim to be heard individually. When an individual workman becomes a party to the dispute under the Industrial Disputes Act, he is a party not independently of the union which has espoused his cause. It is well settled that when an industrial dispute is raised by the union in respect of the grievance of individual workman and reference is made by the Government, the dispute is between the management and the union and not between the management and the individual workman concerned. The individual workman has no locus-standi in the matter. It is also well settled that when there is a bonafide settlement between the union and the management and a compromise is filed before the Industrial Tribunal, the Tribunal should pass award in terms of the compromise. The question of giving any consent by the workman to the compromise petition does not arise. The union is competent to file a compromise keeping in view the interest of the workmen in general and also to maintain industrial peace and harmony. The authority in favour of Shri J. D. Lall was filed by the union on 3-7-91 because the union was/is a party to the dispute. The authority was withdrawn by the union on 10-1-92. Hence, Shri Lall has no authority to represent the union. The workman authorised Shri J. D. Lall, Advocate and the authority in his favour was filed on 4-3-92. Since the workman has no locus standi as he is not a party to the reference, he is not competent to authorise any person to represent him. In the circumstances the management has prayed that the petition dated 10-1-92 be accepted and an award be passed in terms of the compromise.

6. Shri K. N. Gupta, learned Advocate for the management has contended that there exists no industrial dispute in the eye of law as the union which raised the dispute has not pressed the same. Shri J. D. Lall, learned Advocate for the concerned workman, has resisted this contention and cited the decision reported in 3 SCLJ 1769 (Bombay Union Journalists Vs. The 'Hindu' Bombay and another) and 1972 Lab. I.C. 1141 (SC) (Binny

Ltd. Vs. Their workmen and another). Both these decisions underline the legal position that when an industrial dispute existed at the time of making order of reference, the dispute does not cease to be the so merely because the union which raised the dispute choses not to pursue it by subsequent withdrawal of support. The withdrawal of such support will not affect the jurisdiction of the Tribunal to adjudicate upon it. This being the legal position, I overrule the contention of Shri Gupta that there exists no industrial dispute in the eye of law.

7. Then again, Shri Gupta has contended that the concerned workman has not right to give authority to Shri J. D. Lall, Advocate, to represent his case as it is not an individual dispute and as a corollary Shri J. D. Lall has no right to represent the concerned workman. In support of this contention Shri Gupta has cited the decision reported in AIR 1961 (SC) 857 (Ram Prasad Biswakarma Vs Chairman, Industrial Tribunal, Patna and others). Their Lordships of Supreme Court held that when an industrial dispute concerning individual workman is taken up by the union of which the workman is a member, as a matter affecting the workmen in general and on that basis a reference is made under Industrial Disputes Act, the individual workman cannot ordinarily claim to be heard independently of the union. The ordinary rule should be that such representation by an officer of the trade union should continue throughout the proceeding in the absence of exceptional circumstance which may justify the Tribunal to permit other representation of the workman concerned. In the present case the President of the union gave authority to Shri J. D. Lall Advocate and the concerned workman to represent the case. Thereafter the President withdrew the authority given in favour of Shri J. D. Lall, but he did not revoke the authority given in favour of the concerned workman. Thereafter the concerned workman gave authority in favour of Shri J. D. Lall, Advocate. In the context of these facts, I think that it is not unjustified to permit the concerned workman to be represented by his Advocate. Here again, I am constrained to state that I do not agree with the contention of Shri Gupta and so I overrule his contention.

8. Admittedly, the management of Indian Oil Corporation (Refineries & Pipelines Division) entered into a Long Term Conciliation Settlement dated 22-2-89 with the Workers' Union including the sponsoring union whereby pay scale and other benefits of workmen were revised upwards with effect from 1-5-86 in accordance with the terms of settlement. The pay scale of the concerned workman was revised and refixed in terms 3.1.3 of the said settlement by Office Order dated 20-3-89 18-4-89. But by subsequent order dated 15-11-89 the management superseded the earlier order and refixed the pay scale of the concerned workman in revised pay scale. The contention of the workman is that he has been adversely affected by this revised order. According to the management the earlier fixation of pay of the concerned workman was a mistake and this was refixed by order dated 15-11-89. It is the further case of the management that certain anomalies in the term of settlement were discussed with the sponsoring union and other union on 11-2-91 and it was decided that option should be given to the senior employees postponing the date of their pay fixation on promotion to the date of pay fixation on promotion to the comparable junior employees. It was also clarified that for the purpose of seniority original date of promotion of the employee would be reckoned with But for the purpose of pay and consequential benefits, date of revised pay fixed would be taken into consideration. Accordingly an option was given to the concerned workman but he did not exercise his option. The management issued administrative instruction dated 28-6-91 for implementing the decision arrived at All India Level Meeting on 11-2-91. In the context of discussion and settlement of anomalies the sponsoring union has presented the petition for not pressing the dispute.

9. It appears that the union presented a statement of claim on 3-7-91 even after administrative instruction for implementation was issued. Shri J. D. Lall has contended that the union was pursuing the dispute even after issuance of administrative instruction for implementation of the decision. Indeed, the union has submitted statement of claim after the necesary circular was issued. But that may be due to various reasons including lack of coordination and mis-conception.

Shri J. D. Lall has contended that the petition of the union praying for disposal of the case as not pressed is malafide. The union has made it abundantly clear in its petition that in view of the Long Term Settlement out of which the present dispute has arisen it does not press the dispute in order to maintain industrial peace and good relationship. In other words, the intention of the union is to maintain the fabric of industrial peace and good relationship in fact. This intention cannot be considered as mala fide. That apart when an industrial dispute is raised by the union or a group of workmen in respect of the grievance of the individual workman and reference is made by the Government, the dispute is between the management and the union and not between the management and the individual workman. As a matter of fact, the individual workman have no locus-standi in the matter. In such a case when there is bona fide settlement between the union and the management and a compromise is filed before the Tribunal, it has to pass a award in terms of the compromise unless it is shown that the settleent is arrived at by fraud, mis-representation or undue influence. This legal proposition was laid down by the Patna High Court in the case reported in 1968 Lab. I. C. 1430 (Eastern Manganese and Minerals Ltd. Vs. Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad and others). In the present case the sponsoring union does not want to proceed with the industrial dispute further in the interest of industrial peace and good relationship. I find no fraud, mis-representation and undue influence as there is no vestige of evidence on record on that score. Accordingly, I accept the petition presented by the sponsoring union and overrule the objection of the concerned workman.

10. Hence, it is ordered that the present industrial dispute be disposed of as not pressed by the sponsoring union.

In the circumstances of the case, I award no cost.

This is my award.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1992

का. आ. 73.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कुन्नन केमिकल्स कम्पनी, मद्रास-600083 के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, तमिलनाडु के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 9-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29011/31/89-आईआर (मी.)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th December, 1992

S.O. 73.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Tamilnadu as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kunnan Chemicals Company, Madras-600083 and their workmen, which was received by the Central Government on the 9-12-1992.

[No. L-29011|31|89-JR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Tuesday, the 27th day of November, 1992.

Present :

THIRU M. GOPALASWAMY, B.Sc., B.L. Industrial Tribunal.

INDUSTRIAL DISPUTE No. 52 OF 1990

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Madras Dock Labour Board, Madras-1.)

Between :

The Workmen represented by :

The General Secretary,

The Madras Harbour Workers Union,

'Bhagat House',

204, Prakasam Salai, Madras-600 108.

And

The Chairman,

Madras Dock Labour Board,

Rajaji Salai, Madras-600 001.

REFERENCE : Order No. L-33011/3/90-IR (Misc.), dated 21-6-1990 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiru M. Shanmugavelu, Advocate appearing for the workmen and of Thiru R. Arumugam, Advocate appearing for the management, upon perusing the reference, claim and counter statements and other connected papers on record and the parties having filed a joint memo and recording the same, this Tribunal passed the following :

AWARD

This dispute between the workmen and the management of Madras Dock Labour Board, Rajaji Salai, Madras-1 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India, in its Order No. L-33011/3/90-IR (Misc.) dated 21-6-1990 of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue :

"Whether the demand of the General Secretary, the Madras Harbour Workers Union, Bhagat House, 204, Prakasam Salai, Madras-600 108 for absorption of 59 casual workers (as per list attached) by the management of Madras Dock Labour Board, Rajaji Salai, Madras is justified. If so, to what relief the workmen concerned are entitled?"

CLEARING AND FORWARDING WORKERS (CASUAL) NAME LIST

DATE OF APPOINTMENT 21-2-1980 (ALL WORKERS)

Serial No.	Name	Card No.	Father name	Designation
1	2	3	4	5
1.	K. Bakthan	1001	Kanniappan	Mazdoor
2.	S. Gowthaman	1002	Seshachalam	Mazdoor
3.	C. Kesavan	1003	Chipamkaram	Mazdoor
4.	M. Narasimman	1004	R. Munusamy	Mazdoor
5.	R. Thambirane	1005	Rathinam	Mazdoor
6.	S. Palani	1006	Subramani	Mazdoor
7.	J. Kalidoss	1007	Jeyaraman	Mazdoor
8.	B. Ramachandran	1008	Balakrishnan	Mazdoor
9.	M. Subramani	1009	Mottai	Mazdoor
10.	C. Ramasamy	1010	Kundumani	Mazdoor
11.	K. Malar	1011	Nannan	Maistry
12.	K. Kapali	1012	Kupusamy	Maistry
13.	K. Sundara Moorthy	1013	Kanniappan	Mazdoor
14.	K. Shanmugam	1014	Kannan	Mazdoor
15.	G. Jeyasankar	1015	Gopal	Maistry
16.	M. Puruosothaman	1016	Murugesan	Maistry
17.	A. Syed Sabir Rahiman	1017	Abdul Mazit	Maistry
18.	K. Arumugam	1018	Kanniappan	Maistry
19.	K. Delli	1019	Kanniappan	Maistry
20.	B.V. Allapichai	1020	Dasha boy	Maistry
21.	M. Neelakandan	1021	Murugon	Maistry
22.	K. Porumal	1022	Kannappan	Mazdoor
23.	A. Mothu	1023	Arumugus	Mazdoor
24.	P. Nagappan	1024	Psriyasamy	Mazdoor
25.	A. Govindaraj	1025	Blusslai	Mazdoor
26.	R. Thiru Neelakandan	1026	Hagevan	Mazdoor
27.	P. Jayaraman	1027	Ponnusamy	Maistry
28.	K. Gopal	1028	Kanniappan	Maistry
29.	T. Alugu	1029	Periyasamy	Mazdoor
30.	M. Natarajan	1030	Rasilamani	Mazdoor
31.	R. Aromugam	1031	Ranthathan	Mazdoor
32.	P. Rajendran	1032	Palayam	Mazdoor
33.	V. Ramalingam	1033	Varadhan	Mazdoor
34.	V. Davadoss	1034	Varadkhan	Mazdoor
35.	A. Ganesan	1035	Alagian	Mazdoor
36.	O. Selvam	1036	Govindasamy	Mazdoor

1	2	3	4	5
37.	O. Krishnan	1037	Gopal	Mazdoor
38.	J. Syed Nasir	1038	Johnay	Mazdoor
39.	K. Kavikumar	1039	Mithiraj	Mazdoor
40.	B. Rajalingam	1040	Subramani	Mazdoor
41.	K. Anthanairaj	1041	A. Kaspar	Mazdoor
42.	Sagadsamy	1042	Duraisamy	Mazdoor
43.	G. Pandian	1043	Jeyaraman	Mazdoor
44.	K. Karunakaran	1044	Krishnan	Mazdoor
45.	C. Balakrishnan	1045	Chinnappan	Mazdoor
46.	P. Subramani	1046	Arumugam	Mazdoor
47.	K. Vadhachalam	1047	Narasimman	Mazdoor
48.	V. Sunderraj	1048	Venkatasan	Mazdoor
49.	S. Annemalai	1049	Sinni Maicker	Maistry
50.	R. Ganasunderam	1050	Kathinam	Maistry
51.	B. Joseph	1051	Khanasingh	Maistry
52.	M. Sundaram	1052	Manickam	Mazdoor
53.	M. Palani	1053	Munasamy	Mazdoor
54.	M. Jayaraman	1054	Malayan	Mazdoor
55.	K. Moorthy	1055	Krishnan	Maistry
56.	V. Sundaram	1056	Veeramuthu	Maistry
57.	R. Anandaraj	1057	Ramadass	Maistry
58.	C. Nelvam	1058	Chinnappa	Maistry
59.	P. Gandhi	1059	Bharathanarathy	Maistry

(2) Parties were served with summons. Both parties were represented by counsel.

(3) Petitioner-Union filed its claim statement on 17-9-90 putting forth the claim of the workmen. In repudiation thereof, the Respondent-Management has filed their counter statement on 11-1-1991.

(4) After several adjournments, when the dispute was called today, both the parties filed a joint memo. It runs as follows :

> "The issue involved in the above Industrial Dispute is for the absorption of 59 casual workers in the Respondent Board. Pending the above Industrial Dispute, the Respondent absorbed 59 casual workers involved in this Industrial Dispute in the Respondent Board as permanent workmen as and when vacancies arose.
>
> In these circumstances the Petitioner and Respondent jointly pray that the above Industrial Dispute may be dismissed as withdrawn by the workmen."

(5) In view of the joint memo, industrial dispute is dismissed as withdrawn.

Dated, this 17th day of November, 1992.

M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1992

का. आ. 74.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. राजमहल क्वार्ट्ज सैण्ड एंड काओलिन कंपनी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29011/4/90—आई आर (Misc.)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th December, 1992

S.O. 74.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M|s. Rajmahal Quartz Sand & Kaolin Co. and their workmen, which was received by the Central Government on 9-12-82.

[No. L-29011|4|90-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

in the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 53 of 1990

PARTIES :

Employers in relation to the management of M|s. Rajamahal Quartz-Sand & Kaoilin Co.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employees : Shri B. B. Pandey, Advocate.

For the Workmen : Shri U.S. Sinha, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Minor Mineral.

Dated, the 25th November, 1992

AWARD

By Order No. L-29011|4|90-I.R. (Misc.), dated, the 2nd March, 1990, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of sub-section (2-A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of Khadan Mazdoor Sangh, Maharajpur, Dist. Sahibganj, for payment of wages during the period from 16-4-89 to 20-4-89 to a section of workers engaged in the new plant of M|s. Rajmahal Quartz Sand & Kaolin Company's Mangalhat Unit is justified. If so, what relief are the workers concerned entitled to?"

2. The order of reference was received in the office of the Tribunal on 9-3-1990. After receipt of the order of reference, notice was issued to the President, Khadan Mazdoor Sangh, P.O. Maharajpur, Distt. Sahebganj, Bihar, for filing written statement on behalf of the concerned workmen. Thereafter several adjournments were given to the union to file written statement. Ultimately, a petition of the President, Khadan Mazdoor Sangh, Maharajpur was received by this Tribunal on 20-11-1992. In that petition the President has stated that the payment of wages during the period 16-4-89 to 20-4-89 has already been paid by the management and prayed that the present industrial dispute be withdrawn In view of the petition, I consider that there exists no dispute between the parties.

3. Accordingly, the present industrial dispute be disposed of as 'withdrawn'.

In the circumstances of the case, I award no cost. This is my award.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1992

का. आ. 75.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमि. की जीलगोरा कोलियरी का भौरा क्षेत्र नं. 11 के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (नं. 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 24012/(12)/86-डी. 4 (बी) आई आर. (कोल-1)]

एच. सी. गौड़, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the, 15th December, 1992

S.O. 75.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Bhowra Area No. XI of M|s BCCL and their workmen which was received by the Central Government on 15-12-92.

(No. L-24012(12)|86-D.IV(B)|IR(Col.1)

HARISH GUAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 288 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Bhowra Area No. IX of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri R. N. Mondal, Assistant Secretary R.C.M.S.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE :—Bihar. INDUSTRY :—Coal.

Dated, Dhanbad, the 4th December, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(12)/86-D.IV(B), dated, the 13th August, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Jealgora Colliery of Bhowra Area No. XI of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jealgora, Distt. Dhanbad in terminating the services of Shri Balagobind Tanti, M.C. Loader is justified ? If so, to what relief the workman is entitled ?"

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. Both the parties appeared before me and filed a Joint etc. Thereafter at the stage of oral evidence, both the parties appeared before me and filed a Joint Compromise Petition under their signature. I heard both the parties on the said petition of compromise and do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both of them. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

B. Ram, Presiding Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD.

Reference No. 288/96.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Jealgora Colliery of Bhowra Area, B.C.C.L.

AND

Their Workmen

JOINT COMPROMISE PETITION OF THE EMPLOYERS AND THE WORKMEN

The above mentioned Employers and the workmen/Sponsoring Union most respecfully beg to submit jointly as follows :—

(1) That the representatives of the Employers and the representatives of the workman/Sponsoring Union have jointly negotiated the above matter referred to this Hon'ble Tribunal with a view to arriving at a mutually acceptable and amicably settlement.

(2) That as a result of such mutual negotiations, the parties have agreed to settle the matter covered by the above reference on the following terms and conditions :—

(a) It was agreed that the Management would refer the workman concerned Sri Bal Gobind Tanti who was retired from service from 1-7-90, to the Apex Medical Board of B.C.C.L. as per the existing procedure for determination of his age on the date of the medical examination.

(b) It was further agreed that if the age as assessed by the Apex Medical Board on the date of assessment and by back calculations, the workman concerned was below 60 years he would be entitled to remain in service for further period, he would be given such benefit and if however, as per such age assessment, the workman concerned was less than 60 years as on 1-7 85 and has already crossed the age of 60 years by the date of assessment of his age by the Apex Medical Board, he would be paid back wages.

(c) It was agreed that since the Apex Medical Board, in accordance with the above decision, assessed the age of the workmen concerned as 61 years as on 15-11-1991, his date of birth would be deemed to have been superannuated from 15-11-90.

(d) It is agreed that in the light of the clause(c) above, the workman concerned would be deemed to have retired from 15-11-90 instead of from 1-7-90 and he would be paid wages for the period from 1-7-90 to 14-11-90 and other benefits for such period.

(e) It is agreed that this is an over-all settlement in full and final settlement of all the claim of the workman concerned and the Sponsoring Union arising out of the above Reference.

(3) That the Employers and the workmen| Sponsoring Union consider and hereby declare that the above terms and conditions are fair, just and reasonable to both the parties.

In view of the above, the Employers and the workmen|sponsoring Union most respectfully pray jointly that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this Joint Compromise Petition and dispose of the above reference accordingly by giving an Award in terms thereof.

R.N. Mondal
Secretary,
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh,
Branch: Bararee Jealgora Colliery.
for and on behalf of workman.

Sd|- Illegible.
Agent,
Jealgora Colliery, BCCL,
for and on behalf of
Employers.

Dated : 30-4-92

Dy. C.P.M.,
Bhowra Area, B.C.C. Ltd.,
for and on behalf of
Sd|- Illegible.
Employers.
Advocate for Employer

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1992

का. आ. 76.--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमि. की ईस्ट कटरास कोलियरी क्षेत्र--4 के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-24012/(61)/86-डी-4 (बी) आई आर (कोल-1)]
एच. सी. गौड़, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th December, 1992

S.O. 76.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of East Katras Colliery Area IV of M|s. B.C.C.L. and their workmen which was received by the Central Government on 15-12-92.

[No.L-24012(61)|86-D-IV(B)|IR(C.I.)]
HARISH GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 66 OF 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of East Katras Colliery Area IV of M|s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 7th December, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(61)|86-D.IV(B) dated, the 14th January, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of East Katras Colliery Area IV of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. in not providing job to one dependent of Late Shri Deoki Bhuia who died while in service is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. This reference is pending since 1991 for filing W.S. by the parties. But inspite of several registered notices sent against the parties nobody appeared on behalf of the workmen. I find that Shri B. Joshi, Advocate has been putting his attendance on behalf of the management. This shows that the workmen concerned is not very much interested in pursuing with the matter. In the circumstances no dispute award is passed.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1992

का. आ. 77.--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमि. की ईस्ट बसुरिया कोलियरी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-200[illegible]/[illegible]/[illegible]-डी-[illegible] (ए) आई आर (कोल-I)]
एच. सी. गौड़, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th December, 1992

S.O. 77.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of East Basuriya Colliery of M/s.

B.C.C.L. and their workmen which was received by the Central Government on 15-12-92.

[No. L-20012(144)|87-D.III(A)|IR(Coal-I)]

HARISH GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 312 OF 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of East Bassuriya Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri D. K. Dey, Secretary, Colliery Karamchari Sangh.

On behalf of the employers : None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 7th December, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order N. L-20012(144)|87-D. III(A), dated, the 21st December, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Bassuria Colliery, Kusunda Area of M|s. Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad in dismissing Shri Bijay Bhuiya Driller from service with effect from 11-6-84 is justified? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. This reference is also pending since March, 1992 for filling W.S. of the parties. I find that till this day no W.S. could be filed. Only on the last date i.e. on 2-12-92 Shri D.K. Dey, Secretary, Dhanbad Colliery Karamchari Sangh filed a petition for passing no dispute award. In the circumstances of the case I find no reason as to why a 'no dispute' award should not be passed when the union itself is praying for passing no dispute award. Hance a 'No Dispute' Award is passed.

B. RAM, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1992

का. आ. 78.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं.-2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/255/86-डी-II(ए)]

वी. के. वेणुगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th December, 1992

S.O. 78.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 15-12-92.

[No. L-12012|255|86-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 189 OF 1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of India and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employers : Shri Basu Deva Patre, Industrial Relations Officer.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Banking.

Dated, Dhanbad, the 7th December, 1992

AWARD

The Govt. o India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-12012|255|86-D.II(A), dated, the 5th May, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of India, Rajrappa Project Branch, Hazaribagh in terminating the services of Shri Upendra Kumar Ram, Subordinate cadre employee with effect from 21-3-85 and not considering him for further employment while recruiting fresh hands under Section 25H of the I.D. Act, is legal and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. This reference is pending since March, 1982 for filling W.S. by the workmen. I find that one Shri Basu Deva Patra has been putting his appearance on behalf of the management. On 31-1-92 Shri Patra appeared and filed a petition for passing no dispute award. As regards the workmen I find that nobody ever appeared on behalf of the workmen. Since the workmen is not taking any step nor filling any W.S. the Tribunal has got no other option but to pass no dispute Award. Accordingly a 'No Dispute' award is passed

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1992

का.आ. 79.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.पी. डब्ल्यू. डी., नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 दिसम्बर, 1992 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल 42012/151/90-आई.आर. (डी.यू.) (पी.टी.)]
के.वी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1992

S.O. 79.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on 16-12-92.

[No. L-42012/151/90-IR(DU)(Pt.)]
K. V B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I.D. No. 19/91

In the matter of dispute between :

Shri Sita Ram S/o Shri Tulsi Ram, as represented by CPWD Mazdoor Union, E-26 (Old Qrtr.), Raja Bazar, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi.

Versus

Executive Engineer (Elect.), Electrical Division-V, CPWD, Sewa Bhavan, R. K. Puram, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Nand Lal for the workman.

Shri Chander Singh, Head Clerk of the Management.

AWARD

The Central Givernment in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42012/151/90-IR(D.U.) dated 18-2-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of CPWD, New Delhi in not regularising the services and not paying the wages from 30-11-88 to 18-3-89 to Shri Sita Ram, Lift Operator is justified ? If not, to what relief the workmen is entitled to ?"

2. The case were fixed today for further proceedings which the representative for the workman made statement that the matter has been settled and no dispute award may be passed. Head Clerk of the management was also present. In view of this statement. No dispute exist between the Parties I, therefore, pass a no dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

2nd December, 1992.

GANPAT SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1992

का.आ. 80.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.पी.डब्ल्यू.डी. नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 दिसम्बर, 1992 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/150/90-आई.आर. (डी.यू.) (पीटी)]
के.वी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1992

S.O. 80.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on 16-12-1992.

[No. L-42012/150/90-IR(DU) (Pt.)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 18/91

In the matter of dispute between :

Shri Avtar Singh, Lift Operator, as represented by CPWD Mazdoor Union, E-26 (Old Qrtr), Raja Bazar, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi.

Versus

Executive Engineer (Elect), Electrical Division III, CPWD, I.P. Bhawan, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Nand Lal for the workman.

None of the management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42012|150|90-IR(LU) dated 18-2-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of CPWD New Delhi in not regularising the services and not paying the wages to Shri Avtar Singh, Lift Operator from 15-1-1989 to 18-3-1989 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The case was fixed or 51-98 and has been taken up today at the request of the representative for the workman who has stated that the matter has been settled and no dispute award may be passed. In view of fhe statement of the workman representative no dispute exist between the parties. I, therefore, pass a no dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

2nd December, 1992.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1992

का.आ. 81.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सा.पी.डब्ल्यू.डी. नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/136/90-आई.आर. डी.यू. (पीटी)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1992

S.O. 81.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D Nirman Bhawan and their workmen, which was received by the Central Government on 16-12-92.

[No. L-42012/136/90-IR(DU)(Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

3128 GI/92—11

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI

I.D. No. 17|91

In the matter of dispute between :

Shri Madav Nand s|o Shri Khema Nand as represented by CPWD Mazdoor Union, E-26(Old Qts) Raja Bazar, Baba Kharak Singh Marg, New Delhi.

Versus

Executive Esginеer (Electrical) Electrical Division I, CPWD, I.P. Bhawan, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Nand Lal for the workman

Shri U. M. Kalra for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its order No. L-42012|136|90-I.R. (D.U.) dated 15-2-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of C.P.W.D. Nirman Bhawan New Dehli in not giving wages for the period from 31-12-88 to 16-3-89 to Shri Madhav Nand, Lift Operator is justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. The case was fixed for 12-1-1993 and has been taken up today at the request of the representative for the workman who has stated that the matter has been settled and do dispute award may be passed. The representative for the management Shri U. M. Kalra is also present. In view of this statement no dispute exist between the parties. I, therefore, pass a no dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

2nd December, 1992.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1992

का.आ. 82.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सा.पी.डब्ल्यू.डी., नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-12-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/ 34/90-आई.आर. डी.यू. (पी.टी.)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 17th December, 1992

S.O. 82.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the

Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of CPWD New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on 16-12-92.

[No. L-42012/134/90-IR(DU) (Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA; PRESIDING OFFICER; CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL; NEW DELHI

I. D. No. 16/91

In the matter of dispute between :

Shri Gudaria, Lift Operator,
represented by CPWD Mazdoor Union,
E-26 (Old Qrtr), Raja Bazar,
Baba Kharak Singh Marg,
New Delhi,

Versus

Executive Engineer (Elect),
Vigyan Bhavan Elect. Divn.,
CPWD, Vigyan Bhavan,
Maulana Azad Road,
New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Nand Lal for the workman.

Shri U. M. Kalra for the management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-42012/134/90-I.R.(D.U.) dated 15-2-91 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of CPWD, New Delhi in not regularising the services and not paying the wages from 1-2-89 to 31-3-89 to Shri Gudaria. Lift Operator was justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. This case was fixed for 5-5-93 and has been taken up at the request of the representative of the workman who has stated that the matter has been settled and no dispute award may be passed. The representative for the management Shri U. M. Kalra is also present. In view of this statement no dispute exist between the parties. I, therefore, pass a no dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

2nd December, 1992.

GANPATI SHARMA, Presding Officer

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1992

का.आ. 83.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1839 दिनांक 26 जून, 1992 द्वारा किसी भी खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण, जिनमें सिंथेटिक ईंधन, स्नेहक तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं, के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून, 1992 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर, 1992 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/2/84-डी-1 ए.)]

एस. एस. प्रशर, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd December, 1992

S.O. 83.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour SO No. 1839 dated the 26th June, 1992, the industry engaged in the manufacture or production of mineral oil (crude oil, motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 29th June, 1992;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 29h December, 1992.

[No. S-11017/2/84-D I(A)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1992

का.आ. 84.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-6 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-1-93 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय-5 और 6 (धारा-76) की उपधारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के

किया जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है के उपबंध मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. जिला रतलाम में रतलाम की नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां उक्त प्रावधान पहले ही प्रवृत्त किये जा चुके हैं।

2. जिला उज्जैन में उज्जैन की नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां उक्त प्रावधान पहले ही प्रवृत्त किये जा चुके हैं।

3. जिला सतना में सतना की नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां उक्त प्रावधान पहले ही प्रवृत्त किये जा चुके हैं।

[संख्या एस-38013/20/92-एस.एस-I]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 24th December, 1992

S.O. 84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st January, 1993 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of Section 76 and Section 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Madhya Pradesh namely :—

(i) "Areas comprising of the Municipal limits of Ratlam in Distt. of Ratlam in addition to the areas in which the said provision of the Act have already been brought into force."

(ii) "Areas comprising the Municipal limits of Ujjain in the Distt. of Ujjain in addition to the areas in which the said provision of the Act have already been brought into force."

(iii) "Areas comprising of the Municipal limits of Satna in the Distt. of Satna in addition to the areas in which the said provision of the Act have already been brought into force."

[No. S-38013|20|92-SS.I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993